राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 07

शुक्रवार,

14 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया के किसानों को सब्सिडी का भुगतान

78. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टिब्बी में अनेक किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई व पेयजल हेतु डिग्गी का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त कार्यों के लिए रुपये 03.00 लाख सब्सिडी देने का प्रावधान है? उक्त राशि का लम्बे समय से किसानों को भुगतान नहीं हुआ है? क्या सरकार उक्त सब्सिडी का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टिब्बी में अनेक किसानों द्वारा खेतों में सिंचाई व पेयजल हेतु डिग्गी का निर्माण किया गया है।

जी हां। यह भी सही है कि राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कराये जाने पर कृषकों को अधिकतम 3.00 लाख का अनुदान का प्रावधान है।

31 मार्च, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टिब्बी में कुल निर्मित डिग्गियों में से 42 डिग्गियों की अनुदान राशि 1 करोड़ 25 लाख 67 हजार रुपये का अनुदान भुगतान लम्बित था, जिसमें से 17 डिग्गियों की अनुदान राशि 51 लाख रुपये व 2 डिग्गियों की केवल टॉप-अप अनुदान राशि 2 लाख रुपये, कुल 53 लाख रुपये का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया जा चुका है। शेष 25 डिग्गियों की अनुदान राशि 72 लाख 67 हजार रुपये का

(कृषि मंत्री)
अनुदान भुगतान भारत सरकार से बजट अभाव में लम्बित है। उक्त लम्बित अनुदान भुगतान भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर प्राथमिकता से कर दिया जाएगा।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अंदर टोटल 293 डिग्गियां संगरिया और टिब्बी दोनों के अंदर हैं। इसके अंदर 81 डिग्गियों की पेमेंट हो चुकी है, 212 डिग्गियों की पेमेंट अभी बाकी है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इनकी पेमेंट कब तक हो जाएगी? किसानों ने 24 परसेंट ब्याज पर पैसे लेकर डिग्गियां बनाई हैं, उनको दो साल से पैसे नहीं मिल रहे। कृपया मंत्री महोदय बताएं कि इनको कब तक भुगतान हो जाएगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के टिब्बी तहसील में 2019-20 में 25 डिग्गियों की राशि रुपये 72 लाख 67 हजार का अनुदान भुगतान करना शेष है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि डिग्गी के लंबित भुगतान के लिए कुल 137 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसमें भारत सरकार से लगभग 58 करोड़ रुपये आना शेष है। यह पैसा आने के बाद राज्य सरकार का जो प्रतिशत है, उसमें मिलाकर के इनका भुगतान कर दिया जायेगा और 21 करोड़ रुपये हमारे पास विभाग में मौजूद हैं। जैसे ही भारत सरकार से पैसा आएगा, क्योंकि नार्म्स ऐसे बने हुए हैं तो हम तुरंत इसका भुगतान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री महेन्द्र बिश्नोई। माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): राशि आपको केन्द्र से आनी थी। अब तक केन्द्र से कितनी राशि आ गई? केन्द्र और आपका शेयर क्या है? क्या अब तक जो बंटवारा हुआ, उस राशि के शेयर के आधार पर ही सभी को हुआ है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का शेयर है 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का है 40 प्रतिशत। मैंने बताया कि हमारे पास 21 करोड़ रुपये विभाग में हैं और हमने पत्राचार कर रखा है, अधिकारी सम्पर्क में हैं। मैं मानता हूं कि महीने-बीस दिन में जैसे ही भारत सरकार पैसा जारी करेगी, हम भुगतान कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 21 करोड़ रुपया आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाकी है। आप इक्वल शेयर से जितना आपके पास है, वह तो बांट दें। जब भारत सरकार से आएगा फिर इक्वल बांट देना आप, कम से कम पैसा तो आए और जितना है, उतना तो पहुंच जाए।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें नार्म्स ही ऐसे बने हुए हैं कि भारत सरकार का जो पैसा आएगा, जैसा मेरी जानकारी में है, उसके बाद में ही राशि जारी होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री महेन्द्र बिश्नोई।

लूणी में बजरी परिवहन से क्षतिग्रस्त सड़कें

79. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी में बजरी खनन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त कारण से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक कराने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार जिन सड़कों से बजरी परिवहन होता है, उन सड़कों की मरम्मत करने के लिए बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार की बजरी परिवहन से अन्य राजकीय विभागों या एजेंसियों द्वारा निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत हेतु बजट आबंटित करने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लूणी में खनिज बजरी के खनन हेतु 15 खनन पट्टे तथा 2 अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये गये हैं। यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में खनिज परिवहन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों को समय-समय पर साधारण मरम्मत मद में उपलब्ध बजट राशि से ठीक करवाया जाता है। वर्ष 2019-20 में भारी वर्षा से भी लूणी विधान सभा क्षेत्र के बजरी खनन क्षेत्र में स्थित सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इन क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत हेतु आपदा राहत कोष (SDRF) के अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृति जारी की

(उद्योग मंत्री)

गई, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संवेदक गारंटी अवधि के तहत मरम्मत करवाई गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इन सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(2) भाग संख्या 1 के जवाब में अंकित अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत समय-समय पर साधारण मरम्मत मद में उपलब्ध बजट के तहत करवाई गई है तथा इन सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(3) बजरी परिवहन से अन्य राजकीय विभागों या एजेन्सियों द्वारा निर्मित सड़कों की क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत हेतु अलग से बजट जारी करने की कोई योजना नहीं है परन्तु ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों का पैच/मरम्मत कार्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सम्बन्धित मद से करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो काकानी से लूणी रोड आती है, उसको रिपेयर करने के लिए दो बार टेंडर किये गये थे परंतु किसी ने लिया नहीं, क्योंकि मरम्मत बहुत ज्यादा मांग रही थी। बाढ़ राहत के अंदर वह मरम्मत करनी थी, वह पूरी नहीं हो पाई। आपके जो ओवरलोडेड वाहन बजरी के भरे हुए निकलते हैं, इससे सड़कें पूरी टूट गई हैं। दूसरी, जो गांव की छोटी सड़कें हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): सरकार कब तक रिपेयर कराने की मंशा रखती है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जो क्षतिग्रस्त सड़कें हुई थीं, मैंने अपने उत्तर के भाग-1 में माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध करा दी है और इसमें कहीं भी कोई मरम्मत कराने का या कोई काम कराने का डीएमएफटी फंड होता है, उसके अंतर्गत छोटे-मोटे काम, खनन क्षेत्र के काम कराए जा सकते हैं। बाहर की लिंक सड़कों के, बड़ी सड़कों के नहीं कराए जाते। अगर माननीय सदस्य उसमें कोई खनन क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क है तो मुझे बताएं, मैं विभाग को कह दूंगा, उसकी मरम्मत कराई जाए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): डीएमएफटी फंड का पैसा सिलिकोसिस के अंदर ही पूरा हो रहा है। आप इसको थोड़ा देखकर करवाइए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ में किसानों की कृषि भूमि की नीलामी पर रोक

80. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1 जनवरी, 2018 से 25 जनवरी, 2020 तक कितने किसानों की बैंक ऋण बकाया के कारण कृषि भूमि कुर्की के आदेश दिये गये हैं? नामवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों की जमीन नीलामी व कुर्की से बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के लिये क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों की जमीन कुर्की पर स्थायी रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 840 किसानों को बैंकों का ऋण नहीं चुकाने के कारण कृषि भूमि कुर्की के आदेश जारी किए गए। नामवार, ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण माफी योजना 2018 व 2019 घोषित की गई है, जिसमें अत्यंत जरूरतमंद पात्र लघु व सीमान्त कृषकों को जो सहकारी बैंकों के ऋणी हैं, को ऋण माफी का लाभ दे दिया गया है तथा वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों के ऋणी किसानों की ऋण माफी बाबत एक मुश्त समाधान योजना लाने बाबत एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(3) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार से जवाब आया है, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 840 किसानों की कुर्की के आदेश निकले हैं जबकि ये आंकड़े प्रशासक ने गलत भेजे हैं। फैक्ट आंकड़े 2500 से 3000 के हैं। दूसरा सवाल, नंबर दो पर दीर्घकालीन अल्पकालीन

(श्री गिरधारीलाल)

सहकारी समितियों में लोन माफ किया गया है। जबकि साथ ही, इन्होंने कहा है, सरकार से आया है कि एकमुश्त समाधान योजना लाने वाली कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी गठित करने के बाद में कब तक यह रिपोर्ट आ जाएगी? तीसरा, विशेषकर जहां किसान की जमीन जाती है तो हमारी सरकार से एक आशा होती है, कुर्की रोकने के संबंध में राज्य सरकार इस पर कुछ कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है या सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? यह राजस्थान के किसान का अति आवश्यक मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में माननीय सदस्य ने पूछा है कि ये आंकड़े गलत हैं। अगर आंकड़े गलत हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और सही आंकड़ों से आपको अवगत करा दिया जाएगा, अगर त्रुटि अधिकारियों ने किसी लेवल पर की है। जहां तक ऋण माफी के मामले में कमेटी का गठन है तो सरकार ने अपने लेवल पर तीन मीटिंग कर ली हैं। कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था लेकिन जो बैंक सरकार के अधीन नहीं हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनका ऋण माफी का हमारे हाथ में नहीं है इसलिए यदि एकमुश्त योजना में वह सहमत होंगे तो ही ऋण माफी उनकी की जा सकती है।

प्रश्न संख्या-81

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री अमीन खां। माननीय सदस्य, पता है शिडयूल्ड बैंक से हो नहीं सकता, बार-बार क्या पूछना है।

बंद आवासीय विद्यालयों का पुन: संचालन

82. श्री अमीन खां (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश में 24 आवासीय विद्यालय जिनका संचालन बंद कर दिया गया है, को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): जी नहीं। वर्तमान में

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किसी भी आवासीय विद्यालयों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक ही सवाल का उत्तर चाहता हूं। क्या यह सही है कि 5.08.2013 को सरकार के अल्पसंख्यक विभाग में क्रमांक 86/57 पर राज्य के 12 ज़िलों में माध्यमिक आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल एरिया में खोले थे, जो 21 स्कूल की, उन स्कूलों का अभी तक कोई फंक्शन नहीं है, इसके क्या कारण है? नंबर दो, क्या सरकार इन स्कूलों को पुनः उस आदेश को अमल में लाने का विचार रखती है या नहीं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आदेश क्रमांक बताया, 2013 का बजट आया था, तो बिंदु संख्या 92.1 में आवासीय विद्यालय स्वीकृति के लिए घोषणा की गई थी। 2013 में उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी। 2013 के बाद जैसे ही सरकार बदल गई और दूसरी सरकार आई, उसके द्वारा राज्यपाल अभिभाषण में जरूर कहा गया, पर उसके बाद कोई समीक्षा नहीं की गई। उन्होंने कमेटी बनाई, पर कमेटी ने आगे किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, उसकी वजह से ये विद्यालय नहीं खुल पाए। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अभी जो प्रशासनिक स्वीकृति निकली थी, कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी से हम वापस समीक्षा करवाकर फाइनेंस विभाग को भेजने का विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों का बकाया मानदेय का भुगतान

83. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों का मानदेय, क्रय सामग्री, भवन किराया की कितनी-कितनी राशि कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से बकाया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बकाया राशियों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय

(श्री ज्ञानचंद पारख)

के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें भी अन्य कर्मचारियों की भांति प्रतिमाह निश्चित तिथि को मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) पाली ज़िले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों का मानदेय, क्रय सामग्री, भवन किराया की बकाया राशि की सूचना निम्नानुसार है-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका मानदेय लगभग दिसम्बर 2019 तक हो चुका है।

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका मानदेय

क्र. सं	**परियोजना का नाम**	**भुगतान का माह**	**बकाया राशि (लाखों में)**
1	रोहट	नवम्बर, 2019	25.03
2	पाली ग्रामीण	दिसम्बर, 2019	26.40
3	सोजत	दिसम्बर, 2019	22.50
4	रायपुर	जनवरी, 2020	....
5	जैतारण	दिसम्बर, 2019	24.48
6	खारची	दिसम्बर, 2019	26.00
7	बाली	दिसम्बर, 2019	15.20
8	रानी	दिसम्बर, 2019	11.76
9	देसूरी	दिसम्बर, 2019	11.80
10	सुमेरपुर	दिसम्बर, 2019	16.05

भवन किराया लगभग दिसम्बर 2019 तक हो चुका है।

भवन किराया

क्र. सं	**परियोजना का नाम**	**भुगतान का माह**	**बकाया राशि (लाखों में)**
1	रोहट	अक्टूबर, 2019	0.036
2	पाली ग्रामीण	दिसम्बर, 2018	11.38
3	सोजत	दिसम्बर, 2019	0.044
4	रायपुर	जनवरी, 2020	.....

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

क्र. सं	**परियोजना का नाम**	**भुगतान का माह**	**बकाया राशि (लाखों में)**
5	जैतारण	फरवरी, 2020	3.36
6	खारची	दिसम्बर, 2019	0.036
7	बाली	अक्टूबर,2019	....
8	रानी	जनवरी, 2020	....
9	देसूरी	जनवरी, 2020	....
10	सुमेरपुर	जनवरी, 2020	....

पोषाहार का भुगतान लगभग दिसम्बर 2019 तक हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, लिखा हुआ बोल रहे हैं?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): विस्तृत सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गई है।

पोषाहार

क्र. सं	**परियोजना का नाम**	**भुगतान का माह गरम खाना/ नाश्ता**	**टीएचआर**	**बकाया राशि (लाखों में)**
1	रोहट	दिसम्बर, 2019	सितम्बर, 2019	9.50
2	पाली ग्रामीण	जून, 2019	सितम्बर, 2019	134.00
3	सोजत	दिसम्बर, 2019	दिसम्बर, 2019	15.75
4	रायपुर	जुलाई, 2019	जून, 2019	149.30
5	जैतारण	मार्च, 2019	फरवरी, 2019	275.94
6	खारची	अक्टूबर, 2019	दिसम्बर, 2019	26.50
7	बाली	नवम्बर, 2019	अक्टूबर, 2019	54.10
8	रानी	सितम्बर, 2019	अगस्त, 2019	48.00
9	देसूरी	जून, 2019	नवम्बर, 2019	259.44
10	सुमेरपुर	जुलाई, 2019	नवम्बर, 2019	65.94

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) उक्त बकाया राशियों का भुगतान विभाग को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही करवा दिया जाएगा।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का मानदेय प्रतिमाह नियमित भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में भी है कि मानदेय का भुगतान लंबे समय बाद होता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी जानकारी में लाने के बाद आपने करवा दिया पर आप कोई ऐसी व्यवस्था लागू करें कि प्रतिमाह मानदेय मिल जाए। बीच में 9-9 महीने नहीं मिला था, एक तो मेरा क्वेश्चन यह है। आप पोषाहार का कह रहे हैं, मार्च, 2019 से जैतारण का बाकी है, आपकी सूची देख लीजिए, आपने जो मुझे जवाब दिया। पोषाहार क्रय करने की व्यवस्था अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर है, पंचायत समिति या जिला स्तर पर हो जाए, उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किसी दुकान से उधार लेने की नौबत नहीं आए और सरकार के स्तर पर यह परचेज हो जाए, उसकी व्यवस्था आप करेंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कर रहे हैं या...

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्वेश्चन। 6 बार पत्र लिखे हैं, मानदेय समय पर मिलने के लिए आपने सीडीपीओ को और डीडी को पाबंद किया है। आपके पाबंद करने के बाद भी जिन-जिन सीडीपीओ या डीडी ने समय पर मानदेय नहीं दिया, उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की या करने वाली हैं? इनका जवाब दे दें मुझे।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि कई जगह हमारा भुगतान डिले हो रहा है। उसके लिए विभाग सजग है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल राज पोषण द्वितीय शीघ्र शुरू करें, उसके लिए हमें वित्तीय विभाग द्वारा भी स्वीकृति प्रदान हो गई है, जिससे ऑनलाइन भुगतान पोषाहार के मानदेय कर्मचारियों के भवन किराये, हर चीज के ऑनलाइन भुगतान शीघ्र शुरू हो जाएंगे। विभाग की पारदर्शिता शुरू होगी। आपने पोषाहार की बात रखी है, 2014-15 के अंदर तत्कालीन सरकार द्वारा

(श्रीमती ममता भूपेश)

इस सिस्टम को बदला गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एस एच जी इसका कार्य करेगी। फिर भी आप अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो विभाग निश्चित रूप से उस पर गौर करेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

सांभर झील क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की मौतों की जांच

84. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की सांभर झील क्षेत्र में विगत वर्ष में प्रवासी पक्षियों की मौतें हुई हैं? यदि हां, तो कब व कितने पक्षियों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त त्रासदी की जांच कराई गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा और जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार की त्रासदी से प्रदेश के पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की त्रासदी को रोकने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। सांभर झील में विगत वर्ष में प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की मौत हुई हैं। दिनांक 10.11.2019 को स्थानीय सूत्रों से सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की गई। दिनांक 11.11.2019 से रेस्क्यू कार्य प्रारम्भ किया गया। इस क्षेत्र से संग्रहित मृत पक्षियों एवं रेस्क्यू किये गये पक्षियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत जांच की गई है। पक्षियों की मृत्यु का कारण एवियन बोटुल्जिम पाया गया। जांच की रिपोर्ट परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(3) इस प्रकार की त्रासदी से पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कोई अधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रभावी कार्यवाही एवं निगरानी रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य

(राज्य मंत्री, वन)

आर्द्र भूमि प्राधिकरण (State Wetland Authority) तथा अन्तर विभागीय स्टेंडिंग कमेटी (Inter Departmental Standing Committee on Sambhar) का गठन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और स्पेसिफिक तीन-चार बातें मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। आपके अधिकारी आंकड़े बताते हैं कि 974 पक्षी अभी तक मरे। क्या यह सही है कि विभिन्न न्यूज़ एजेंसी, एनजीओ, वाइल्ड लाइफ एजेंसी द्वारा यह आंकड़ा 50 हजार से 01 लाख तक का बताया गया है। आंकड़ों की गणना है उसको कौनसे विभाग ने जांच किया? ये त्रासदी होने के बाद के आंकड़े हैं या पहले के हैं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आप बताइए कि ये आंकड़े सही हैं या नहीं हैं? न्यूज़ एजेंसिया बता रही हैं, वह आंकड़े सही हैं या आपके आंकड़े सही हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, हमारे खुद के डिपार्टमेंट ने, पशुपालन विभाग ने, नगरपालिका नावां, सिविल डिफेंस, सबने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। बाकायदा गिनती की गई, गिनती करके मृत पक्षी थे उनको दफन किया गया। बिलकुल एक्यूरेट आंकड़े हैं। रेस्क्यू किए गए, उनका भी आंकड़ा सही है। 500 के करीब ठीक करके वापस छोड़े गए, गिनती करके ही उनको दफनाया गया।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आपने अपने जवाब में दिया है कि जयपुर ज़िले में 11 तारीख से रेस्क्यू चालू हुआ, क्या यह सही है? जयपुर ज़िले में इस झील का भाग केवल 20 प्रतिशत है, नागौर में रेस्क्यू आपरेशन चालू हुआ वह 15 तारीख से चालू हुआ, 5 दिन का गैप क्यों है? आंकड़ों के हिसाब से भी नागौर में ज्यादा पक्षी मरे हैं और जयपुर में कम मरे हैं, क्या इससे बीमारी नहीं फैली? इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? इतना लेट क्यों हुआ? जब एक ही झील है, एक ही एडजोइनिंग एरिया है तो पांच दिन लेट क्यों शुरू हुआ? इसका जवाब दें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): झील 3 ज़िलों में है, अजमेर, जयपुर और नागौर में। अजमेर में एक भी पक्षी की मौत नहीं हुई है। जहां

(श्री सुखराम विश्नोई)

तक नागौर, जयपुर का सवाल है, पहले सूचना जयपुर से मिली, वहां से रेस्क्यू किया गया, उनको दफनाया गया। मौत पहले जयपुर में हुई इसलिए 5 दिन का फासला है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने कमेटी के गठन की बात की, इसकी पहली मीटिंग 24.12.2019 को हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ? भविष्य में ऐसी त्रासदी नहीं हो तथा वर्तमान में वहां पर पक्षियों को क्या संरक्षण मिला? सरकार की ओर से उनको खाने-पीने की, दवाई की, मोनिटरिंग की, आज की तारीख में क्या व्यवस्था है? कौनसा विभाग मोनिटरिंग कर रहा है? क्या-क्या व्यवस्था वहां है, कितने लोग काम कर रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): प्रवासी पक्षी हैं, खाने पीने की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप वहां नजदीक रहते हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि जमीन फोरेस्ट की नहीं है, रेवेन्यू लैंड है। कुछ भाग सांभर साल्ट को लीज पर दिया हुआ है। पिछली सरकार ने चंद्रा कंपनी को होटल बनाने के लिए दिया था। वह एक छोटी रेल के अंदर चला रहे हैं। न तो एनओसी फारेस्ट से ली, न एनवायर्नमेंट से ली है, पूरी जांच कर रहे हैं, सांभर साल्ट का और चंद्रा दोनों का एमओयू मंगवाकर पूरी जांच करेंगे।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि कमेटी ने क्या निर्णय लिया, आज की तारीख में कौन मोनिटरिंग कर रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): कमेटी में अवैध....

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सांभर साल्ट में 40 परसेंट राज्य सरकार का हिस्सा है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): अवैध कुएं थे, उनको बंद करवाया गया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उत्तर नहीं सुन रहे। अगला प्रश्न, श्री रामनारायण मीणा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा था उसका तो जवाब आए। आज की तारीख में मोनिटरिंग कौन कर रहा है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामनारायण मीना।

इटावा एवं सुल्तानपुर में स्टेडियमों का विकास

85. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के इटावा एवं सुल्तानपुर में खेल स्टेडियमों की वर्तमान में क्या स्थिति है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त स्टेडियमों में नवीन निर्माण तथा विकसित किये जाने के लिए कोई विचाराधीन कार्यवाही किया जाना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) युवा मामले एवं खेल विभाग/राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का इटावा एवं सुल्तानपुर में कोई स्टेडियम नहीं है।

(2) जी हां। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से युवा और गतिशील और सभी तरह से सक्षम हमारे मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह क्रीड़ा परिषद् और खेल विभाग का कोई स्टेडियम नहीं है, माननीय मंत्रीजी, आपकी दो पालिसी बनी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य। बहुत भूमिका मत बनायें प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): नहीं, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आ रहा हूं, मैं सीधा आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इटावा और सुल्तानपुर में कह दिया, है ही नहीं, तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): इंटीग्रेटेड स्टेडियम प्रोग्राम, 2007-1, उसी में 2015 का भी है। 2007 के बिंदु संख्या 4(3) में है कि हम पंचायत समिति लेवल पर स्टेडियम बनाएंगे। 2015 के 3(4) में है कि हम पंचायत समिति स्तर पर स्टेडियम बनाएंगे, और 2015 के में है 3(5) बिंदु पर कि हम ग्राम पंचायत लेवल पर स्टेडियम बनाएंगे। सरकार इतनी पीछे क्यों चल रही है, यह क्या कारण है। मैं केवल दो पंचायत समिति स्तर की बात कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें आप कैसे बनाएंगे।

दूसरी बात, क्या हमसे सहयोग चाहिये? 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, हम देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपने बताया, वह सही है। पालिसी में है कि ब्लाक स्तर तक स्टेडियम डिपार्टमेंट बनाएगा, पंचायत स्तर पर नरेगा के माध्यम से मदद लेकर स्टेडियम का निर्माण होना चाहिये। निश्चित रूप से साधन की उपलब्धता के ऊपर, सरकार की साधनों की उपलब्धता के ऊपर और गुण-अवगुण को देखते हुए उनको तैयार करवाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मुझे रिलीफ तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: जब प्रश्न है ही नहीं, तो क्या रिलीफ?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। माननीय पानाचन्द मेघवाल।

सुलभ आवास योजना के लाभार्थी

86. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल द्वारा संचालित शुभ शक्ति, सुलभ आवास योजना सहित अन्य कई योजनाओं के लिए सरकार द्वारा बजट आबंटित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश में उक्त योजनाओं के कितने आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खदान श्रमिकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं में लाभान्वित होने के लिए श्रमिक का श्रमिक कल्याण मण्डल में कम से कम एक वर्ष तक पंजीयन होना आवश्यक है?

(5) क्या सरकार उक्त बाध्यता को समाप्त कर पंजीयन के दिन से

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

ही श्रमिक को उक्त योजनाओं हेतु पात्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) विगत 5 वर्षों में प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई? जिलेवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) विभिन्न जिलों में पर्याप्त बजट उपलब्ध रहता है।

प्रासंगिक है कि मंडल की योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों अथवा परिभाषित निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों को ही देय है। परन्तु भिन्न सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापनों में 35 प्रतिशत से अधिक गैर निर्माण श्रमिकों द्वारा पंजीयन कराने एवं अनियमित रूप से योजना का लाभ लेने की स्थिति सामने आयी है।

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना, सुलभ आवास योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है।

(2) मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में लंबित आवेदनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2 (d) में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य को परिभाषित किया गया है। उक्त कार्य में जहां पर कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं, को शामिल नहीं किया गया है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) शुभ शक्ति योजना में 3 माह एवं सुलभ आवास योजना में 6 माह पूर्व का पंजीयन होना आवश्यक है।

(5) जी नहीं। योजना के प्रावधान मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय के आधार पर तय किये जाते हैं। श्रम मंत्रालय भारत सरकार एवं

(राज्य मंत्री, श्रम)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार योजनाओं की पुनर्संरचना का कार्य आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

(6) विभागीय स्तर पर सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने वाले श्रमिकों का विवरण संधारित नहीं किया जाता है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सिलिकोसिस से ग्रस्त होने की स्थिति में मण्डल द्वारा कुल 3526 मृतक आश्रितों को सहायता दी गई। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की इम्पोर्टेंस को आप देखिये, क्योंकि इसमें वे लोग जुड़े हुए हैं जो मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, खान श्रमिक हैं।

इन्होंने जो मेरे प्रश्न के खण्ड संख्या-6 में जवाब दिया, मेरा प्रश्न था, विगत 5 वर्षों में प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई? इन्होंने मुझे इसका जवाब दिया है कि इसका संधारण नहीं किया जाता। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 3526 मृतकों को हमने सहायता दी है। तो क्या ये सिलिकोसिस बीमारी वाले हैं या अन्य वाले हैं, नम्बर एक।

मेरा इसके माध्यम से अगला क्वेश्चन है, पूरे प्रदेश में नये श्रमिक कार्ड बनाने के बहुत सारे पैंडिंग केस चल रहे हैं। निर्माण श्रमिकों का श्रमिक कार्ड बनाने में क्या श्रम विभाग, जहां पर वह काम करते हैं, वहीं पर कैम्प लगाकर उनको तत्काल श्रमिक कार्ड बनाने के लिये प्रयास करेंगे?

दूसरा, जो खान श्रमिक हैं, क्या सिलिकोसिस की बीमारी पत्थर फोड़ने से, क्रेशर पर काम करने से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, तीन प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): आप मरने के बाद तो उसको सहायता देते हो, लेकिन उसका कार्ड नहीं बनाते हो तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि खान श्रमिक हो, बुनकर हो, बीड़ी श्रमिक हो या असंगठित जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, उनको भी क्या श्रमिक कार्ड बनाने के लिये प्रयासरत हैं?

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य। तीन प्रश्न पूछ चुके हैं, क्या आधे घण्टा पूछेंगे आप।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि हमने यह कहा है कि संधारण नहीं किया जाता है लेकिन हमारे यहां कोई एप्लाई करता है तो उसको हम इसकी सहायता देते हैं। जैसे ही वह एप्लाई करता है, सिलिकोसिस पीड़ित है तो उसको दो लाख रुपये की सहायता है। उसकी मृत्यु होने पर तीन लाख रुपये और दिये जाते हैं। मृत्यु होने के बाद हमें एप्लाई करता है तो पांच लाख रुपये हम उसको उपलब्ध कराते हैं।

दूसरा, पैंडेंसी के बारे में जो कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने इन योजनाओं को जल्दी निस्तारण के लिये एक कण्ट्रोल रूम बनाया, जिसमें मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 596000 प्रकरणों का निस्तारण एक वर्ष के अन्दर हमने स्कीमों का किया है और 46986 प्रकरणों का निस्तारण पंजीयन का किया है। पिछले वर्ष के अन्दर चुनाव होने की वजह से, आचार संहिता लागू होने की वजह से पंजीयन नहीं हो पाया था। वह पंजीयन भी अब, क्योंकि स्कीमें भी हमने लगभग पूरी कर दी हैं, अब हमारा जो कण्ट्रोल रूम है, वह पंजीयन पर काम कर रहा है। बहुत ही जल्दी, जो पंजीयन है आने वाले दो या तीन माह के अन्दर इसकी पैंडेंसी लगभग जीरो हो जायेगी। बाकी तो रोजाना नये फार्म आयेंगे, नई एप्लाई होगी, तो लगभग जीरो के आसपास हम इसको कर देंगे।

तीसरा, जो आपने पूछा है कि और लोगों को हम इसके अन्दर सहायता देंगे क्या, ठेले वालों को या और खान श्रमिकों को। उसके लिये मैंने आपको पूर्व में ही अवगत कराया है कि ये भवन निर्माण एवं संनिर्माण श्रमिक का जो एरिया है, वह अलग है, उसको अलग परिभाषित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जो निर्देश हैं, उनके आधार पर और श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के आधार पर उसकी कैटेगरी बनी हुई है। उन कैटेगरीज में जो लोग आ रहे हैं, उनका हम पंजीयन भी कर रहे हैं और उनको हम स्कीमों का लाभ भी दे रहे हैं।

खान जो है, उसके लिये मैंने आपको पूर्व में ही अवगत कराया है कि खान और फैक्ट्री एक्ट, ये जो दो कानून हैं उनके अंतर्गत हमारा विभाग काम नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सिलिकोसिस के लिये सरकार ने नीति बनाई है। इसमें रिकार्ड संधारण करने में क्या प्राब्लम है। हम रिकार्ड संधारण

(श्री अध्यक्ष)

क्यों नहीं कर सकते हैं। जब एक श्रमिक बीमार होता है, अस्पताल में जाता है, तो जब अस्पताल में उसकी बीमारी शुरू होती है तो उसको विभाग के अन्दर रजिस्टर करने में क्या तकलीफ है, जिससे हमें मालूम हो सके कि यह सिलिकोसिस बीमारी है, तो उसका एड्रेस करना शुरू करें बनिस्पत कि हम इंतजार करें कि वह हमारे पास आये।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि सिलिकोसिस की नीति अभी बनी है और उसमें गाइडलाइंस भी जारी हो रही हैं। उसमें कुछ प्रावधानों के अन्दर चेंज भी किया गया। जो सिलिकोसिस नीति है, उसके तहत हम कार्य करेंगे। उस नीति के अन्दर संधारण की बात है तो हम संधारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान में सबसे ज्यादा लेबर माइन्स में अंगेज्ड हैं। क्या विभाग मेडिकल डिपार्टमेंट के जो भी अलग-अलग जगह पर माइन्स के आदमी काम कर रहे हैं, और मेडिकल की जो बीमारियां हैं, उनका सर्वे करवाकर आइडेंटीफाई करेगा कि और कौनसी बीमारी आ रही है? क्योंकि हम सिलिकोसिस के बारे में तो जागरूक हो गये, बहुत बरसों बाद। अब पोटेंशियल जो हो रहा है, उसके बारे में क्या विभाग कोई नीति बनायेगा?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी निरोगी राजस्थान के तहत पूरे राजस्थान के अंदर रिकार्ड संधारण किया जाएगा और उससे रिलेटेड हम भी उसको टाई-अप कर लेंगे, जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, उनका संधारण हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही इन्होंने गलत दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। इस प्रश्न को इतनी महत्ता दे दी, और क्या देंगे? श्री गोविन्द प्रसाद।

सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों के स्थाईकरण की योजना

87. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पुलिस, जेल, आबकारी, वन विभाग

(श्री गोविन्द प्रसाद)

एवं आर.ए.सी. सहित गृह रक्षा के स्थायी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है? यदि हां, तो क्या सरकार सीमा गृह रक्षा दल स्वयंसेवकों की सेवानिवृत्ति आयु को भी 60 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। पुलिस, जेल, आबकारी, वन विभाग एवं आर.ए.सी. सहित गृह रक्षा के स्थायी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित है। राजस्थान होमगार्ड नियम, 1962 के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा दल स्वयंसेवकों का नामांकन 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। गृह रक्षा नियमों में स्वयंसेवकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। उक्त स्वयंसेवकों की नामांकन अवधि 60 वर्ष करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। राजस्थान होमगार्ड नियम, 1962 के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को 05 वर्ष के लिए नामांकन किया जाता है, जिसमें गुणवत्ता के आधार 55 वर्ष आयु सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। राजस्थान होमगार्ड नियम, 1962 में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को स्थायी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि जब राजस्थान होमगार्ड नियम, 1962 के अंतर्गत और सेवाओं में जिस प्रकार से 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति दी जाती है तो आप क्यों न इसमें संशोधन करके 55 वर्ष से 60 वर्ष कर दें और क्या सरकार उनको स्थाई करने का विचार करती है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में होमगार्डों को कितना वेतन एवं कौन-कौनसे परिलाभ एवं सुविधाएं दी जा रही हैं?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सदस्य, मैंने आपको अवगत करा दिया कि नियम, 1962 में जो आपका खण्ड-2 है, उसमें आपको जवाब मिल गया और आपका जो मानदेय का प्रश्न है, वह मैं आपको बता देता हूं। जो बॉर्डर होमगार्ड है जो L-Platoon

(श्री भजनलाल जाटव)

Commandant है, Platoon L-5, उसको 779 और L-3 के लिए 682 और L-1 के लिए 661 हम मानदेय देते हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): और परिलाभ और सेवाएं कुछ नहीं हैं क्या?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): उनको हम लोग वर्दी देते हैं, जूते देते हैं, जूतों की किट देते हैं, यह हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में पशुओं का टीकाकरण

88. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पशुधन बाहुल्य वाले ग्रामों में जो पंचायत मुख्यालय नहीं हैं, उक्त गांवों में पशु उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशुओं में समय-समय पर फैलने वाली मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए उक्त विधान सभा क्षेत्र में निःशुल्क टीकाकरण एवं दवा वितरण के कैम्प प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के निर्धारित मापदंड अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा इसके राजस्व ग्रामों में पूर्व में जहां पशु चिकित्सा संस्था स्वीकृत नहीं हैं एवं न्यूनतम 3000 पशुधन उपलब्ध हैं, वहां नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जा सकते हैं।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(2) पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में समय-समय पर फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशु

(पशुपालन मंत्री)

चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से नि:शुल्क टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्था स्वीकृत नहीं हैं या अक्रियाशील हैं, वहां आवश्यकतानुसार नजदीक के चिकित्सालय/पशुधन आरोग्य चल इकाइयों द्वारा पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर नि:शुल्क पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि जिस गांव में पशु भी अधिक हैं और जो आपने अपने पहले कालम में उत्तर दिया है कि जहां पर पशुओं की संख्या तीन हजार से अधिक हो और राजस्व गांव भी है और पशुओं की संख्या भी अधिक है, आपने जो इस उत्तर में दिये हैं, वह सारे नोर्म्स पूरे करते हैं। जैसे सामोता स्टैंड, दहिया की ढाणी, खारियावास राजस्व ग्राम हैं, बामनवास पंचायत है, ग्राम बबेड़ी है और ग्वाड़ा है तो ऐसे गांवों का सर्वे करवाकर, जहां हमारे वहां पर पशु बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक-एक व्यक्ति के पास में सौ से दो सौ तक की संख्या में पशु हैं तो उनका सर्वे करवाकर आप कब तक नए सेंटर खोलेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में इसी वर्ष ज्ञानपुरा, इन्द्राड़ा व कल्याणपुरा में तीन उप केन्द्र खोले गये हैं जबकि सरकार का हर विधान सभा क्षेत्र में दो उप केन्द्र खोलने का नोर्म्स है पर एक इनको एक ज्यादा दिया गया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): धन्यवाद।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैं सदन के सभी साथियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जहां पर तीन हजार के पशुधन की संख्या है, वहां पर खोलने का प्रावधान है और हम खोल भी रहे हैं। अगले वर्ष भी हम 400 खोलेंगे और इस वर्ष भी हमने 400 खोले हैं और 250 खोल चुके हैं जिनमें से 183 लोगों को वहां पर पदस्थापित भी कर दिया गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बानसूर में तो आपके यहां 1 लाख 73 हजार पशुओं का टीकाकरण भी हो चुका है और 60 कैम्प भी लगाये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, नहीं।

गौवंश के संरक्षण हेतु वित्तीय अनुदान

89. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण हेतु अनुदान राशि गौशालाओं को दी जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में प्रदेश की किस-किस गौशाला को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2019-20 में सरकार ने घोषणा की थी कि गौवंश संरक्षण हेतु राजकीय सहायता के अलावा वित्तीय सम्बल प्रदान करने के लिए सरकार जन सहभागिता एवं CSR Fund से गौशालाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत प्रदेश की किन-किन गौशालाओं को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया) (गोपालन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस योजनान्तर्गत किसी भी गौशाला को अभी तक किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने यह घोषणा की थी कि हम गौशालाओं को 9 माह का अनुदान उपलब्ध कराएंगे तो क्या सरकार 9 माह का अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है और यदि रखती है तो कब तक?

दूसरा, आपने इस जवाब में यह दिया है कि अप्रैल, मई, जून में जयपुर जिले की गौशालाओं को तो हमने अनुदान दिया है तो क्या आपने जनवरी, फरवरी, 2020 के अंदर भी जयपुर जिले की गौशालाओं को अनुदान दिया है और दिया है तो कितना अनुदान दिया है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं में

(श्री लालचन्द कटारिया)

कुल 11 गौशालाएं हैं, जिनमें 1898 गौवंश हैं, जिसमें से कुल 6 गौशालाएं पात्र हैं, उनमें से 5 को अनुदान दे दिया गया है और एक श्याम गौ सेवा समिति, किशनपुरा है, उसका आवेदन नहीं आया है। 2018-19 में दो चरणों में 383.49 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। 2019-20 में आवंटित 271.23 करोड़ रुपये, जिसमें से वितरण 256 करोड़ रुपये का हो गया है। जनवरी से मार्च का सर्वे चल रहा है, भुगतान अप्रैल से कर दिया जाएगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इन्होंने यह घोषणा की थी कि 9 महीने का हम अनुदान देंगे। क्या सरकार 9 महीने का अनुदान गौशालाओं को देने का विचार रखती है?

दूसरा, आपने यह कहा था कि हमने 145 परसेंट वृद्धि, माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह बजट भाषण है और इस बजट भाषण में यह कहा था कि इस वर्ष हमने गोपालन विभाग के बजट में 145 प्रतिशत की वृद्धि की है तो आपने 145 परसेंट की वृद्धि किस आधार पर की है, कौन-कौन से काम किये हैं? आपने यह भी कहा था कि हम सी.एस.आर. से पैसा उपलब्ध कराएंगे और इन्होंने जवाब में यह दिया है कि सी.एस.आर. से हमने एक भी पैसा उपलब्ध नहीं कराया है तो सी.एस.आर. से पैसा कब तक उपलब्ध होगा और आपका क्या उपलब्ध करवाने का विचार है? क्या आप 9 महीने का अनुदान देने का विचार रखते हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सी.एस.आर. से पैसा उपलब्ध कराने की बात सरकार ने कही है और यह प्रक्रियाधीन है, आने वाले समय में इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 9 महीने का देंगे या नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़। माननीय सदस्य, सीनियर सदस्य बैठे-बैठे बोलेंगे क्या?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्रताधारी किसान

90. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रदेश के कुल कितने किसान पात्रता रखते हैं? वर्तमान में कुल कितने किसानों का आधार वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) वर्ष 2019-20 में कुल कितने किसानों के खातों में पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी किश्त की राशि जमा हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रधानमंत्री सम्मान निधि के कुल कितने पात्र किसानों का प्रमाणीकरण सरकार के स्तर पर शेष है? शेष रहे किसानों का प्रमाणीकरण कब तक हो जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्वैच्छिक है एवं योजनान्तर्गत आवेदन करना कृषक की इच्छा पर निर्भर है। दिनांक 06.02.2020 तक 67,10,471 कृषकों द्वारा आवेदन किया गया है। जिला स्तर पर कार्यरत राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरान्त 63,41,441 आवेदन पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं।

भारत सरकार स्तर के पर पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किये गये आवेदन पत्रों के विरुद्ध 62,54,316 कृषकों के आवेदन पत्रों की जांच की जा चुकी है। शेष आवेदन पत्रों की जांच होना भारत सरकार के स्तर पर बकाया है।

50,20,004 कृषकों का आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। शेष कृषकों का आधार वेरिफिकेशन कार्य प्रक्रियाधीन है जो कृषक की इच्छा पर निर्भर है। आधार सत्यापन हेतु जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

विवरण संलग्नक परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2020 तक 47,32,573 किसानों को प्रथम किश्त, 46,50,480 किसानों को द्वितीय किश्त, 36,51,284 किसानों को तृतीय किश्त एवं 15,85,995 किसानों को चतुर्थ किश्त से लाभान्वित किया गया है।

(3) सत्यापन से शेष रहे 1,75,404 कृषकों के आवेदन पत्रों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। सत्यापन का शेष कार्य शीघ्र ही करवाया जा रहा है एवं शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने खण्ड-एक में कहा है कि 62,54,316 कृषकों के आवेदन-पत्रों की जांच की जा चुकी है और उसके बाद इसी खण्ड में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह कहा है कि 50,20,004 कृषकों का आधार वैरिफिकेशन हो गया है, शेष प्रक्रियाधीन है। यह प्रक्रिया आप कब पूरी कर लेंगे? आपने यह भी कहा कि हम जिला स्तर पर शिविरों का आयोजन करेंगे। जिला स्तर पर अब तक आपने कितने शिविरों का आयोजन कर लिया और आगे कब-कब करेंगे, किस तिथि से करेंगे? एक तो मुझे यह बता दें।

नंबर दो, अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि पहली किश्त 6 फरवरी तक 47,32,573 किसानों को मिल गयी। यह पहली किश्त मिलती है जब इनका आधार वैरिफिकेशन और सारे वैरिफिकेशन हो गये तो आप इनकी चतुर्थ किश्त 85,995 को क्यों दिया और यह जो शेष रहे 1,75,404 हैं, इनका सत्यापन आप कब तक पूरा कर देंगे? यह बताने की कृपा करें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आधार वैरिफिकेशन का कार्य सतत प्रक्रियाशील है और 15-15 दिन में कैम्प लगाये जाते हैं और सत्यापन उनका किया जाता है। यह किसान के आने पर निर्भर करता है, क्योंकि किसान आएगा तो ही वैरिफिकेशन हो पाएगा। यह एक स्वैच्छिक स्कीम है। किसान अगर लाभ लेने के लिये आता है, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वह आता है कि नहीं आता है। इस कारण से विलम्ब हो रहा है। बाकी सरकार के स्तर पर शिविर लगाकर हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सत्यापन कर लिया जाए और जो किसानों की फर्स्ट किश्त आयी है, उनका वैरिफिकेशन हो चुका है। बाद में जो आंकड़े दूसरे खण्ड में बता रखे हैं, वह भारत सरकार के स्तर पर भुगतान नहीं आने से, पेमेंट नहीं आने की वजह से थोड़ा उन किसानों को विलम्ब हुआ है। भुगतान आते ही पेमेंट हो जाता है। वैरिफिकेशन तो उनका हो चुका है लेकिन धन के अभाव में उनका भुगतान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। राजेन्द्र जी, आपको पूछना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चतुर्थ किश्त की जो संख्या आप बता रहे हैं 15,85,000 यह चतुर्थ किश्त 15,85,000 जो मिली है, इसका मतलब पहले वैरिफिकेशन के लिये जो डेटा हमारे यहां से जाने चाहिए थे, वह 15,85,000 ही गये इसलिए उनको लगातार किश्तें मिल गयीं और बाकी लोग इससे वंचित इसलिए रहे कि उनके डेटा समय पर जो फीड होने चाहिए थे, वह नहीं हुए और उसके कारण से राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको उत्तर नहीं सुनना क्या? नारे लगाने से क्या होगा? उत्तर तो देगा मंत्री। उत्तर अपने को सुनना ही नहीं है। अपन कह रहे हैं शेम-शेम, तो बात ही खतम हो गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा यह कहना है कि यह जो डेटा 15 लाख का आपने क्लीयर किया था, यही डेटा अगर पहले समय पर सबके क्लीयर हो जाते तो इन सब लोगों को इसकी चारों किश्तें मिल जातीं। केवल हमारी डिले के कारण से यह लोग बाकी किश्तों से वंचित रहे क्या?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तथ्य को भटकाया जा रहा है। फर्स्ट किश्त आयी जब लोक सभा के चुनाव होने थे इसलिए जल्दी-जल्दी धन आ गया। वैरिफिकेशन हो चुका है। बाद में सरकार ने धन भेजना बंद कर दिया इसलिए 15 लाख को ही भुगतान हुआ है। पेमेंट आते ही डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा पेमेंट और वैरिफिकेशन के अभाव में यह काम रूका हुआ नहीं है। धन के अभाव में यह भुगतान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बृजेन्द्र ओला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी, सुनते ही नहीं हैं। आपके लीडर खड़े हैं और आप क्या चाहते हैं? मतलब अजीब सिस्टम कर रखा है हमने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात को इधर-उधर न घुमाएं। आप एक सैकण्ड मेरी बात सुन लो। इससे हमारे किसान को, क्योंकि यह केवल हमारे यहां ही नहीं मिल रहा है, यह सम्पूर्ण देश के किसानों को मिल रहा है और जिन लोगों ने समय पर अपने डेटा फीड कर दिये, उनको उसी समय से किश्तें चार-चार महीने के बाद मिलनी शुरू हो गयीं। हमारा जो पहला डेटा क्लीयर हुआ, वह डिले होने के कारण से इन लोगों को, जो किश्तों में कमी रही, उसका कारण हमारे यहां से प्रशासनिक कमी रही। बाकी यह सब आजकल ऑनलाइन पैसा जा रहा है। कोई किसी सरकार के पास नहीं आता। यह सारा का सारा पैसा सीधा ऑनलाइन उस किसान के खाते में जाता है। ऐसा नहीं है कि यह पैसा आपको दिया और आप उनको दे रहे हो। यह सब ऑनलाइन पैसा जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा डेटा पहले दिन ही यह जो 50 लाख आप कह रहे हैं, अगर यह समय पर वैरिफाई हो जाता तो इन लोगों को चार किश्तें नहीं मिलने के पीछे 15

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लाख का तो फीड कर दिया, लेकिन बाकी का समय पर फीड नहीं होने के कारण से नुकसान हुआ।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया, पैसा सीधा ही कृषक के खाते में जाता है और हमारे यहां से वैरिफिकेशन पूरा है, वह जब चाहें वह भेज सकते हैं। हमारे यहां से वैरिफिकेशन के लेवल पर काम बाकी नहीं है। जिनका प्रक्रियाधीन है, वह कार्यक्रम बराबर जारी है। उनका वैरिफिकेशन के अभाव में नहीं, धन के अभाव में रूका हुआ काम है। आप अपने लेवल पर देख लें, फिर आप जब चाहेंगे तब मैं बात करने के लिये तैयार हूं, लेकिन आप अपने लेवल पर देख लें कि धन के अभाव में रूका है या हमारी प्रशासनिक कमी से रूका हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बृजेन्द्र ओला।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभ का भुगतान

91. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ बकाया हैं? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कितने कर्मचारियों के? आगार-वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया परिलाभों का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) झुन्झुनूं आगार में अप्रैल, 2015 के पश्चात् कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और उनका किस-किस मद में कितना-कितना बकाया है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आगार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी बकाया परिलाभ देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ यथा उपादान राशि, उपार्जित अवकाश, पांचवां-छठवां वेतनमान एरियर, अधिश्रम भत्ता आदि का भुगतान बकाया है। 4103 कार्मिकों के सेवानिवृत्ति परिलाभ बकाया है। आगारवार विवरण परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर बकाया परिलाभों का भुगतान किया जा सकेगा ।

(3) झुन्झुनूं आगार के अप्रैल, 2015 से जून, 2016 तक के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है, जिनकी सूची परिशिष्ट 'दो' पर है तथा जुलाई, 2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का नामवार, पदवार तथा उनके बकाया भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'तीन' पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर बकाया परिलाभों का भुगतान किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि रोकड़ तरलता अनुकूल करने के लिये परिवहन निगम ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और आप स्वयं यह कर्मचारी जब धरने पर बैठे थे तो इनके पास गये थे। हमारी सरकार को आये भी 14 महीने हो गये, इन 14 महीनों में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिये परिवहन निगम ने क्या-क्या काम किये हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी तनख्वाह बंद हो जाती है, और किसी भी तरह के उसको और परिलाभ अपन देते नहीं हैं। क्या सरकार कोई अन्तरिम राहत उसको इन परिलाभों के विरुद्ध उसी दिन देने का विचार रखती है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है। माननीय सदस्य का कहना है कि रोडवेज को घाटे से उबारने के लिये और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, इसके लिये आपने सुधार के क्या काम किये हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आयी, उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा काम किया। जब यह प्रश्न आ गया तब मैं आपको बता रहा हूं। पिछले करीब 12-15 सालों से एक कम्पनी एक करोड़ रुपये महीने का बेवजह उठा रही थी। सहारा नाम की कम्पनी थी। मैंने आते ही रोडवेज के एम.डी. की मीटिंग बुलायी, रोडवेज के अधिकारियों की मीटिंग बुलायी और जब उनसे पूछा कि एक करोड़ रुपया हर महीने किस बात का लिया जा रहा है? पिछली सरकार एक करोड़ रुपया क्यों दे रही थी? मैंने तुरंत वह ठेका कैंसिल किया और आज

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

भी रोडवेज अच्छा चल रही है। एक करोड़ रुपये की बचत तो वहां पर हो गयी। वह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार के रास्ते पर जा रहा था। मैं इस सदन में यह कह रहा हूं कि इसकी जांच भी हम करवाएंगे कि क्या कारण था कि इतने बरसों से एक करोड़ रुपया महीना एक कम्पनी उठाती रही और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रोडवेज को घाटे से उबारने के लिये हमने बड़ा फैसला लिया और जो तरलता ठीक भी होगी। लोक परिवहन सेवा, जो पिछली सरकार के समय शुरू हुई उससे पहले नियम यह था कि रोडवेज की बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती थीं, वह राष्ट्रीयकृत मार्ग रोडवेज के लिये अधिकृत थे। पिछली सरकार के समय राष्ट्रीयकृत मार्गों को खतम करके और रोडवेज से निकालकर उन पर लोक परिवहन सेवाओं को शुरू कर दिया गया। जब हम चुनाव से पहले गये, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि मैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सचिन पायलट जी चुनाव से पहले वहां पर गये, तब हमसे सबसे बड़ा प्रोमिस उन कर्मचारियों ने यह लिया था कि लोक परिवहन सेवा अंदर घुस रही है और अंदर घुसा रहे हैं पुलिस के जरिए, आप हमें यह रिलीफ दोगे। हमने दस दिन के अंदर लोक परिवहन सेवा के परमिट देने पर रोक लगा दी और उसके बाद कोई लोक परिवहन सेवा का परमिट नहीं दिया गया और यह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लोक परिवहन सेवा शुरू की गई थी और वो रोडवेज के अन्दर से चलाना चाहते थे जिससे सरकार और उनके बीच में झंझट हुआ, आन्दोलन हुआ और उसके बाद हमने जो वादे किये थे उनको हमने पूरा करना शुरू किया।

इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत मार्ग इन्होंने अराष्ट्रीयकृत कर दिये थे उन मार्गों को वापस राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है।

इसी में, मैं आपको बता दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए राजस्थान को पता चलना चाहिए, अक्टूबर और दिसम्बर महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम फायदे में भी आये हैं और घाटा भी कम किया है। यह मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

हमारी नीयत पर, नीति पर और सोच पर कोई शक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना कह सकता हूं इस मामले पर इन पिछले पांच वर्षों में रोडवेज को जो घाटा हुआ, वो इतना जबरदस्त घाटा है कि उससे निकलने में तो हमें टाइम लगेगा लेकिन हमने जो काम शुरू किया है उस काम में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आज डिबेट में डिस्कस में डिटेल में बता देना।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, मैं यह बात डिबेट में कर दूंगा, डिबेट में आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न, श्रीमती जाहिदा खान।

महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को चार्ज देने के मानदण्ड

92. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर चार्ज किस-किस अधिकारी को दिया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग में कार्यरत महिला सुपरवाइजर का स्थानान्तरण जिले से बाहर किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या महिला एवं बाल विकास अधिकारी का चार्ज निर्धारित अधिकारियों के अलावा भी दिया जा सकता है? यदि हां, तो किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विभाग में महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर निम्न अधिकारियों में से किसी एक को निम्न क्रम में वरीयता अनुसार दिये जाने की नीति निर्धारित की गयी है-

1. निकटस्थ परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी
2. सम्बन्धित विकास अधिकारी
3. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी

उक्त के अलावा अन्य किसी अधिकारी को बाल विकास परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सक्षम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिया जा सकता है।

(2) जी हां। विभाग में कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों के स्थानान्तरण विभागीय गतिविधियों के सुचारु संचालन एवं प्रशासनिक आधार पर व पर्यवेक्षक द्वारा की गयी प्रार्थना के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

की परियोजना में किया जा सकता है। निर्देश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) इसका प्रत्युत्तर खण्ड 'एक' के अनुसार समाहित है कि जो मैंने पूर्व में बताया कि किन सक्षम अधिकारियों को एम सी.डी.पी.ओज. के चार्ज दे सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि खण्ड तीन में उन्होंने यह क्लैरिफाई नहीं किया है कि सक्षम अधिकारी कौन हैं? दूसरा, उसको किस लेवल पर अनुमोदित किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर और कौन अधिकारी करेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन का जो जवाब माननीय सदस्य पूछ रही हैं, तो विभाग में महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर निम्न अधिकारियों में से, जो यह सक्षम अधिकारी पूछ रही हैं, उनमें से निम्न अधिकारियों में से क्रम में वरीयता अनुसार, सीनियरिटी के आधार पर विभाग में नीति निर्धारण की गई है। निकटतम परियोजना के बाल विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, उक्त के अलावा अन्य किसी अधिकारी को बाल विकास, जो माननीय सदस्या पूछना चाह रही हैं, सक्षम अनुमोदन स्टेट लेवल पर, डाइरेक्टरेट लेवल पर किया जा रहा है, इसकी नीति निर्धारण विभाग द्वारा की गई है।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि आप यह जो बोल रहे हैं कि उक्त के अलावा अन्य किसी अधिकारी को, वो कौन अधिकारी हैं? इनके अलावा आपने बोला है न, तीन के अलावा अन्य किसी अधिकारी को, वो किस लेवल के हैं।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह जो सवाल पूछा है, इनके अलावा ब्लाक लेवल का अधिकारी जो कि एस.डी.एम. तहसील स्तर का या ब्लाक लेवल का अधिकारी है, उसको हमारी नीति निर्धारण के तहत जो अधिकारी आये हैं, उनके हिसाब के बराबर वो अधिकारी सक्षमता रखते हैं कि नहीं रखते,

(श्रीमती ममता भूपेश)

इसका निर्धारण हमारे डाइरेक्टरेट लेवल पर किया गया है। जो ब्लाक लेवल का अधिकारी होना चाहिए, उसको हम इसके अलावा दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

जोधपुर-पाली की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी का फैलाव

93. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर-पाली की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनयुक्त प्रदूषित पानी से जिला बाड़मेर के डोली, अराबा आदि गांवों के आबादी क्षेत्र एवं कृषि भूमि में फैलने से बीमारियां फैल रही हैं व किसानों की फसलें खराब हो रही हैं? क्या सरकार दूषित पानी के फैलाव को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त प्रभावित गांवों में दूषित पानी के फैलाव से पीड़ितों के लिए सीएसआर मद से पानी निकासी हेतु पक्की कैनाल के निर्माण व गांवों के पानी निकासी तथा स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री सुखराम विश्नोई): (1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जोधपुर, पाली की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनयुक्त प्रदूषित पानी से जिला बाड़मेर में (पी.एच.सी., अराबा व सी.एच.सी., कल्याणपुर क्षेत्र में) बीमारियों के बढ़ने की कोई सूचना नही हैं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में इस प्रकार की कोई कार्ययोजना पर्यावरण विभाग में विचारधीन नहीं है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया कि जोधपुर और पाली से प्रदूषित पानी आ रहा है और अराबा, डोली और विभिन्न गांवों में किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं और जवाब मिलता है कि सी.एच.सी. कल्याणपुर और पी.एच.सी. अराबा से बीमारी की कोई सूचना नहीं आई है, तो क्या अपन इन्तजार कर रहे हैं? बीमारी की सूचना नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप पानी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? चैनल बना रहे हैं या जो खराबा हुआ है उन किसानों को मुआवजा दे रहे हैं? अब बीमारी की

(श्री मदन प्रजापत)

सूचना नहीं आई है, बड़ा दु:ख होता है, मतलब बीमारी का इन्तजार कौन कर रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में रीको द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जो पानी निकलता है उसके लिए सांगरिया में द्वितीय चरण में 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. बना दी गई है और 1998 से चालू है। साथ ही 25 बीघा जमीन आबंटन करके, 2017 में नि:शुल्क आबंटन कर दी गई है और 2018 में जोधपुर प्रदूषण निवारण रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा इसका कार्य करवा लिया गया है।

जहां तक पाली का प्रश्न है, पाली में तीन सी.ई.टी.पी. चालू है। साथ ही जोधपुर का जो सीवरेज का मल है उसके लिए भी तीन ट्रीटमेंट प्लांट चालू हैं और एक बासनी में निर्माणाधीन है। जब बासनी का चालू हो जाएगा तो इन्होंने जो डोली, अराबा की बात प्रश्न में रखी है, वहां तक गंदा पानी नहीं पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली का पानी लूणी नदी के माध्यम से बालोतरा, समदड़ी सैकड़ों गांवों में और जोधपुर का पानी तीन पंचायतों तक आया है, डोली, अराबा और कल्याणपुर तक। मेरा निवेदन है कि प्लांट बन रहे हैं, प्लांट बनने के बाद प्रदूषित पानी आया, फैल रहा है तो चैनल के निर्माण की मंशा रखते हैं या कोई कार्ययोजना है या नहीं है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): चैनल के निर्माण की कोई योजना नहीं है, सी.ई.टी.पी. लगा है एक अलग से ताकि जो औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी है वो साफ होकर खेतों में, नदी में डालें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल।

जालौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मुआवजा

94. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला जालौर में वर्ष 2017 व 2018 में हुई अतिवृष्टि का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त हो गया है?

(श्री नारायण सिंह देवल)
यदि हां, तो किस-किस तहसील के कितने किसानों को, कितनी-कितनी राशि का मुआवजा दिया गया? वर्षवार व तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार जालौर जिले में खरीफ 2017 में फसलों में हुए नुकसान के तहत 198 करोड़ 12 लाख रुपये का बीमा क्लेम 2 लाख 9 हजार कृषकों को दिया गया है जिसमें अतिवृष्टि से हुए नुकसान का बीमा क्लेम भी सम्मिलित है। रबी 2017-18 में फसलों में हुए नुकसान के तहत 22 करोड़ 53 लाख रुपये का बीमा क्लेम 30 हजार एक सौ दस कृषकों को दिया गया है।

खरीफ 2018 में फसलों में हुए नुकसान के तहत 254 करोड़ 66 लाख रुपये का बीमा क्लेम 1 लाख 89 हजार कृषकों को दिया गया है। खरीफ 2018 में जालौर जिले में 5 हजार 959 कृषकों का 11 करोड़ 99 लाख रुपये का बीमा क्लेम दिया जाना शेष है जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रबी 2018-19 में कुल 11 करोड़ 69 लाख रुपये का बीमा क्लेम देय है जिसके भुगतान की कार्यवाही बीमा कम्पनी द्वारा की जा रही है।

वर्ष 2017 एवं 2018 का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं पूछना चाहता हूं कि खरीफ 2018 और रबी 2018-2019 में हुए फसलों के नुकसान का क्लेम ऑनलाइन किया जा रहा है और क्लेम पास हुए लगभग आठ महीने हो गये हैं तो खरीफ 2018 के वंचित किसान 5 हजार 959 और रबी 2018-2019 में प्रभावित 11 करोड़ 69 लाख रुपये और किसान हैं 35 हजार 456, इनमें से मात्र तीन ही किसानों को क्लेम मिला है। ऑनलाइन भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उसका क्या कारण है और क्लेम कब तक दिया जाएगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में और सदन को बताना चाहूंगा कि खरीफ 2018 और रबी 2018-2019 के शेष बीमा क्लेमों का भुगतान इसी माह कर दिया जाएगा। खरीफ की टोटल लागत है 11 करोड़ 99 लाख और रबी की है 11

(श्री लालचन्द कटारिया)

करोड़ 69 लाख, टोटल 23 करोड़ 68 लाख का भुगतान इसी माह कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ 2017 का जो मुआवजा है वो चैक से दिया जाता था और रानीवाड़ा विधान सभा में करवाड़ा समेत पांच गांव हैं, मेरे पास लिस्ट है, जिनको चैक इश्यू हो गया है फिर भी उनको पेमेंट नहीं मिला है तो इस विलम्ब के कारण कौन अधिकारी दोषी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आप प्रश्न काल के बाद में पधारें और जो भी जानकारी आप देंगे, मैं उसको तुरन्त दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

अनुपस्थिति अनुमति

प्रमोद भाया, श्री, खान मंत्री को 12 फरवरी, 2020 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रमोद भाया, खान मंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 12 फरवरी, 2020 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान की युवती को फेसबुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग में फंसाकर हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध होने के बावजूद सरकार द्वारा शराब की बिक्री बढ़ाने के प्रावधान किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में आवासन मंडल द्वारा अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा व बूंदी जिले में हाईवे के लिए अवाप्त किसानों की भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. दर से दिए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले में 70 दिनों की नहर बंदी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से दिनांक 12.02.2020 को आयुर्वेद विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बैकलाग को भरे बिना ही नियुक्ति आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा में आयोजित होने वाले सरकारी भवनों व परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक की उपेक्षा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर की विधि महाविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन के दौरान हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विभागों में हाल ही में निकली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में जिला स्तर पर

(श्री अध्यक्ष)

प्रत्येक विभाग की पत्रावलियों का निस्तारण जिला कलेक्टर के माध्यम से न करवाकर विभागाध्यक्ष के स्तर पर करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर में कार्यरत महिला आई.ए.एस. अधिकारियों की छवि धूमिल करने हेतु सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से अजमेर, कोटा, भरतपुर तथा बीकानेर में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में नि:शुल्क वितरण हेतु छपवाई जाने वाली पुस्तकों की निविदा चहेती फर्म को देने हेतु शर्तों में परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के जल स्रोतों, नदी-नालों एवं तालाबों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान की खंडपीठ द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2004 को दिए गए निर्णय की अनुपालना भेदभावपूर्ण तरीके से किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्रीमती अनिता भदेल, श्री संयम लोढ़ा, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री नारायण बेनीवाल को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के 'बी' श्रेणी के आयुर्वेद चिकित्सालय को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से वेणेश्वर धाम में व्याप्त विभिन्न अव्यवस्थाओं का समाधान कर मास्टर प्लान के अनुसार 255 करोड़ की राशि के विकास कार्य करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में भूजल लेवल बहुत नीचे जाने से पेयजल की भीषण समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सीमेंट फैक्ट्री खोलकर स्थानीय जनता को रोजगार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में परमाणाताल में भरे गंदे पानी की निकासी न होने से फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के बीमा का पैसा नहीं मिलने से किसानों को हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में।

(8) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे को सदन में बार-बार घोषणा होने के बावजूद नगरपालिका नहीं बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को सीधे ही ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री चेतन सिंह चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में सरकारी भूमि पर बने निजी महाविद्यालयों को निजी हाथों से मुक्त करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के साधुवाली गांव में गाजर मंडी खुलवाए जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के उपखंड मुख्यालय थानागाजी में मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास को नगरपालिका बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से प्रदेश में डेयरी संघों के लिए होने वाले चुनावों को निष्पक्ष रूप से करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 14 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 27 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 3 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
(1)	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़)	आदित्य बिरला सीमेंट कंपनी द्वारा माइनिंग क्षेत्र भूजल का असीमित दोहन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(2)	श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)	जे.एल.एन. चिकित्सालय में आउटडोर से 2 घंटे पहले ही जांचों का सैंपल लेना बंद कर दिए जाने से रोगियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
(3)	श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी)	बाड़मेर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बिश्नोइयों की ढाणी के छात्र-छात्राओं को डंपर चालक द्वारा कुचल कर मार दिए जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

सूचना

मालवीय नगर, जयपुर में आगजनी की घटना

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मालवीय नगर में थड़ियां लगी हुई हैं। वहां पर गरीब, छोटे वर्ग के लोग अपना व्यवसाय करते हैं। जिनको परमिशन मिली हुई है, उन्होंने परमिशन के लिए जो अमाउंट जमा करना है नगर निगम में, वह नगर निगम में अमाउंट जमा किया हुआ है।

ऐसी स्थिति में परसों रात को वहां आग लगती है। जब आग लगती है तो कल सुबह, अर्ली मोर्निंग वहां के कुछ लोग, थड़ी के लोग, पूर्व में रही हुई महिला आयोग की अध्यक्ष हैं सुमन शर्मा जी, उनके यहां पर पहुंचते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप हमारे यहां पर आकर के देखिए, हमारे कियोस्कों में आग लग गई है। भीषण आग लगी हुई है। वह वहां पर कुछ लोगों को लेकर के जाती है। वहां जब मौके पर जाकर के देखती हैं तो वास्तव में वहां सारे लोग बिलख रहे थे, रो रहे हैं। उनके सारे कियोस्कों में आग लग गई थी। वह सारे बेघर होकर वहां बैठे हुए थे। उस सारी चीज को देखकर के उनके मन में पीड़ा हुई। उन्होंने फोन लगाया मालवीय नगर थाना प्रभारी को और एएसपी को और कहा कि आप लोग आकर के देखिए। इस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां थड़ियों में आग लगा दी। वह पुलिस वाले वहां पर आते, उससे पहले वहां पर कुछ लोगों ने आकर के बिना बात का झगड़ा करना शुरू कर दिया। वहां कहा कि इन लोगों को तुम बचाने का प्रयास कर रही हो, यह गलत है और यहां पर जो आग लगी है वह शार्ट सर्किट से लगी है जबकि वहां पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, कोई वायर्स नहीं जा रहे हैं तो शार्ट सर्किट होने का सवाल ही नहीं है। किसी तरह का कोई कनेक्शन वहां पर नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। अब ऐसी स्थिति में वहां सब लोग जो शांति से धरने पर बैठे थे, उस धरने पर आकर के पुलिस के लोगों ने लाठी चार्ज किया। खास तौर पर वहां के थाना प्रभारी, एएसपी, इन सारे लोगों ने वहां पर शांति से बैठी हुई महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया। उनके कपड़े खींचे गए। कपड़े फाड़ दिए गए। वहां पर उनको दूसरे लोगों ने वापस से शाल दी। इस प्रकार की घटना होना, महिलाओं के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करना, वहां पर एक धर्मा नाम का लड़का था, उसके सिर पर चोट आई है, उसके खून निकला है। आज के अखबारों में फोटो आया है। वह सारी चीजें वहां पर हुई हैं। पुलिस इस प्रकार से लाठी चार्ज करेगी और फिर कहेंगी कि यह तो आदतन अपराधी हैं। आदतन अपराधी हैं तो आप उसे जेल में बंद करो।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन हो गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही चाहूंगी कि सरकार इस पर जवाब दे। उस थानाधिकारी और एएसपी के खिलाफ कार्यवाही करें और उन्हें सस्पैंड करें।

श्री अध्यक्ष: दो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आएंगे, एक तो मालवीय नगर की घटना के सम्बन्ध में। दूसरा, किशनगढ़ के रूपनगढ़ में रिकवरी वालों ने एक छोटे बच्चे को दिन भर रखे रखा है। इन दोनों पर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे।

श्रीमती अनिता भदेल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अजमेर में कार्यरत महिला आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। स्थगन के माध्यम से आपने मुझे यह विषय उठाने का अवसर दिया है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, उनकी गरिमा को जिस तरह से आघात पहुंचाया गया है उससे मोटिवेट होकर कुछ लोग अपनी हिम्मत को और आगे बढ़ाते हुए आजकल सोशल मीडिया का भी जमकर इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अजमेर में जितनी भी महिला आईएएस अधिकारी पोस्टेड हैं, उन सभी महिला आईएएस अधिकारियों के संदर्भ में जिस तरह से अभद्र

(श्रीमती अनिता भदेल)

टिप्पणी की गई और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही गंदी भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया और उसको बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत सारे ग्रुपों में वायरल भी किया गया। मैं कुछ बानगी उसकी आपको बताना चाहती हूं। उसमें जो लिखा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस की एक आदरणीय महिला आईएएस अधिकारी की कामुक और अप्राकृतिक क्रिया की वीडियो क्लिपिंग, राजस्थान में, अजमेर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल और आगे फिर वह महाशय लिखते हैं, भारत की अत्यन्त गरिमामय सेवा में अजमेर में कार्यरत अधिकारी का यह चरित्र देखकर अत्यंत वेदना, मतलब उनको वेदना भी हो रही है, जिन्होंने देखा है और बाद में बोल रहे हैं कि मैंने तो नहीं देखा है लेकिन जिसने भी देखा है, वह इसको न देखे और आगे वायरल न करें। जब उन्होंने देखा ही नहीं है तो इतनी सारी चीजों को सोशल मीडिया पर डालने का क्या हेतु है? बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि आईएएस की सेवाएं आज भी बहुत गरिमापूर्ण सेवाएं मानी जाती हैं, उच्च लेवल की सेवाएं मानी जाती हैं और ब्यूरोक्रेसी में तैनात महिलाओं को भी इस तरह से ब्लैकमेलिंग किया जाएगा ताकि वह अपने कामों को करवा सके, अपने गलत कामों को उनसे मनवा सके, उनसे करवा सके। यह उन चारों महिला आईएएस अधिकारी तैनात हैं, उन चारों ने दो अलग-अलग थानों में मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में 164 के उनके बयान भी हो गए हैं। 164 के बयान होने के बावजूद भी, यह बयान 7 तारीख को हुए और 7 तारीख को बयान होने के बावजूद भी यदि उस व्यक्ति की जगह कोई आम व्यक्ति होता तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय की गम्भीरता को समझिए, कोई भी आम व्यक्ति होता तो उसको तुरंत पुलिस उठाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल देती लेकिन उसको मौका दिया गया कि वह कोर्ट जाए और इस बाबत स्टे ले। उसने स्टे ले भी लिया ताकि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करे तो जब प्रदेश की आईएएस अधिकारी ही इस तरह से मजबूर हैं कि उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी लिख सकता है लेकिन वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकतीं तो एक आम महिला की क्या हिम्मत हो सकती है कि वह पुलिस में जाकर अपनी बात को कह सके और उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के संज्ञान में यह विषय लाई हूं और मेरा निवेदन है कि और लोग इससे मोटिवेट

(श्रीमती अनिता भदेल)

होंगे यदि इस तरह के व्यक्तियों पर कार्यवाही नहीं होगी तो इसलिए इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, जो स्टे वह लेकर आया है उस स्टे के खिलाफ कोर्ट में सरकार जाए, सारे तथ्य प्रस्तुत करे ताकि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो, नहीं तो महिलाओं पर इसी तरह से अत्याचार बढ़ते रहेंगे। जो महिलाएं नौकरियों में हैं उन महिलाओं का भी नौकरी करना दूभर हो जाएगा। इसी तरह से वह ब्लैकमेल होती रहेंगी क्योंकि उन्हें अपने बुरे काम कराने, गंदे काम कराने, जो काम वह नहीं करा सकते, इन अधिकारियों को ब्लैकमेल करवाकर वह करवा सकें। चारों आईएएस महिलाएं जो वहां तैनात हैं, उन सबने एफआईआर दर्ज करवाई है ताकि यह न कह सके कि हमारे खिलाफ आपने, हमने यह तो कहा ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उन्होंने सबके लिए लिखा है इसलिए मेरा आग्रह है कि महिलाओं की सुरक्षा प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, यदि यह जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो इसी तरह से हर महिला पीड़ित होती रहेगी इसलिए महिला विरोधी यह सरकार न बने कम से कम, आधी आबादी इस प्रदेश की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। हो गया आपका।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इस आधी आबादी ने आपको वोट देकर, जिताकर भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि वह इसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही जरूर करें।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

अजमेर, कोटा, भरतपुर व बीकानेर में बिजली वितरण काम निजी क्षेत्र में देना

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बिजली उपभोक्ता को राजस्थान की सरकार दो दशक पहले राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के माध्यम से लाभान्वित कर रही थी लेकिन विश्व बैंक ने हमको ऐसा सपना दिखाया कि राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान यह विद्युत सुधार लागू करके हो जाएगा और राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विखण्डन करके अलग-अलग पांच कम्पनियों का सृजन किया गया। इसमें वितरण के क्षेत्र के अंदर जयपुर, अजमेर और जोधपुर में

(श्री संयम लोढ़ा)

तीन अलग-अलग कम्पनियों का निर्माण किया गया लेकिन विगत दो दशक का अनुभव हमारे सामने है कि विश्व बैंक ने जो हमको सपना दिखाया, न तो छीजत कम हुई, न बिजली की सेवा में सुधार हुआ, न बिजली की बदहाली दूर हुई और जिस अंधेरी गुफा के सामने हमारा बिजली का क्षेत्र राजस्थान का खड़ा हुआ है उसमें अंधेरा दिनोंदिन घना ही होता गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी व्यापक चर्चा के, बिना राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए, बिना राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन को विश्वास में लिए, आनन-फानन में अपने निहित स्वार्थों के चलते अजमेर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर में विद्युत वितरण का काम निजी कम्पनियों को सौंप दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी तय नहीं किया गया कि इन निजी क्षेत्र की जिन कम्पनियों को काम दे रहे हैं, यदि वह मनमानी करेगी तो सरकार उनके खिलाफ किस रूप में कार्यवाही करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यह काम एक साल, दो साल, पांच साल के लिए दिया जाता तो भी समझ में आता लेकिन बीस-बीस साल का वितरण का काम इन निजी क्षेत्र की कम्पनियों को सौंप दिया गया। पिछले चार साल में जिस रूप में राजस्थान का विद्युत उपभोक्ता इन चारों शहरों का प्रताड़ित हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है, हमले हुए हैं, लूट हुई है और यह सारा रिकार्ड पर है, फिर भी न तो पिछली सरकार की नींद खुली, न इस सरकार की नींद खुल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2018 के अंदर कोटा में जबर्दस्त आंदोलन हुआ उस वितरण कम्पनी के खिलाफ, 60 हजार स्मार्ट मीटर तब तक लगाए जा चुके थे, जिन लोगों के एक महीने का बिल 1 हजार रुपये आता था वह बिल 4 हजार रुपये तक पहुंच गया। भयंकर आंदोलन हुआ, उसके बाद में जयपुर में समझौता हुआ तो 60 हजार स्मार्ट मीटर जो लग गए वह लग गए, उसके बाद में स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया गया लेकिन उन मीटरों को बदलने का काम कोई नहीं किया गया। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कम्पनियों का कोई खुद का जनरेशन सिस्टम नहीं है, ये सरकारी कम्पनियों से बिजली खरीदती और सिर्फ अपने बिल बांटने का काम और सप्लाई करने का काम करती है। जयपुर डिस्कॉम में

(श्री संयम लोढ़ा)

एक लाख यूनिट बिजली खरीदती है और बिलिंग तीन लाख यूनिट का कर रही है मतलब, दो लाख यूनिट का घपला कर रही है, उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली कर रही है और सरकार इस बात पर कोई आडिट नहीं करवा रही है कि सरकारी कम्पनियों से इन निजी कम्पनी वाले कितने यूनिट बिजली खरीदते हैं और कितनी बिलिंग कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, वाइण्डअप। यह जनरल डिबेट नहीं है। वाइण्ड अप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, कर रहा हूं। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जांच करवाई। कोटा का नगर निगम जिसका बिजली का बिल साल का दस करोड़ रुपये का आता था इस कम्पनी के आने से पहले, अब साल का बीस करोड़ रुपये आ रहा है जबकि एलईडी लाइट लगाई गई हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइण्डअप करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एलईडी लाइट लगाने से बिजली का उपभोग कम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। यह जनरल डिबेट नहीं है। प्लीज वाइण्डअप करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। यह जनरल डिबेट नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, 32 कनेक्शन ऐसे पाए गए जांच में, सरकार के द्वारा की गई जांच में जिसमें वास्तविक उपभोग की तुलना में 80 लाख यूनिट का बिल ज्यादा भेजा गया, मतलब साढ़े छह करोड़ रुपये का घोटाला गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया, समाप्त करें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र राठौड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप अलग ढंग से आएं, यह जनरल डिबेट नहीं है, स्थगन प्रस्ताव में जनरल डिबेट नहीं होती है। राजेन्द्र राठौड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव की महत्ता को समझें। जनरल डिबेट नहीं है।

नि:शुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की छपाई में अनियमितताएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पारदर्शी सरकार के मजबूत शिक्षा मंत्री के सामने हाल ही में हुए पारदर्शी भ्रष्टाचार की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष राजस्थान में 24 करोड़ पुस्तकें विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क वितरित किये जाने हेतु 225 करोड़ रुपये के बजट से छपायी जाती हैं। ये सारी पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् यानी एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार राजस्थान का पाठ्य पुस्तक मण्डल इन्हें छपाता है। इस बार 16 दिसम्बर, 2019 को एक टेलर मेड टैण्डर बनाकर जिस प्रकार यह निविदा आमंत्रित करके कार्यादेश दिया गया, उसमें शर्त लगा दी कि वर्जिन पल्प पेपर होना चाहिए और जो भी सप्लाई करे उस फर्म की क्षमता 45 हजार टन प्रतिवर्ष की होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें पंजाब की तीन फर्म्स आती हैं- ट्राइडेंट मिल्स, श्रेयान्स और विकास। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये ही फर्म्स राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल को 67.98 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पेपर देती हैं, जबकि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को 59.36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देती है। प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग को 49.68 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् (एनसीईआरटी) को देती है 49 रुपये प्रति किलो के हिसाब से।

अध्यक्ष महोदय, कागज तीन प्रकार से बनता है। लकड़ी से जो बनता है, उसे वुड पल्प कहते हैं। जो सरकण्डा, चावल, भूसी से बनता है, उसे एग्रो पल्प कहते हैं और जो रिसाइकल होकर बनता है, उसे रीसाइकल्ड पल्प कहते हैं। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से वनों का ह्रास कम हो, इसके लिये 29 अगस्त, 2018 को सारी राज्य सरकारों को लिखा कि आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रीसाइकल्ड पेपर का इस्तेमाल करें। अध्यक्ष महोदय, ये जो पेपर हैं, इनकी जांच करने के लिये कानपुर में जो सैंट्रल लैब है, इन सारे पेपर्स को जांच के आधार पर जो आईएसआई मार्क दिया जाता है, वह सबको दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा 59 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पेपर खरीदा जा रहा है, इसकी मात्रा छोटी-मोटी नहीं है, 30 हजार मैट्रिक टन है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम गणना करें, मेरे पास बिल है ट्राइडेंट पेपर्स लिमिटेड का, इसी फर्म से राजस्थान पुस्तक मण्डल 59.98 पर खरीदता है। यही ट्राइडेंट पेपर्स बाजार में 54.18 रुपये में देती है। आप कहें तो मैं पेपर ले कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कब हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर कैसे किया गया, पर राज्य सरकार के सामने समाचार पत्रों में यह बात लगातार प्रकाशित होती रही। वर्जिन पल्प और 45 हजार टन की उत्पादन क्षमता की फर्म्स होनी चाहिए, ये शर्तें लगाकर सीधे-सीधे भ्रष्टाचार को पनाह देने का कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय मेरी बात कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, चाहे शयन मुद्रा में सुन रहे हों, चाहे ऊंघते हुए सुन रहे हों तो निश्चित तौर पर उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लिया होगा। यह कहकर कि उस समय में ये शर्तें थीं, इस समय में ये शर्तें हैं, ऐसा नहीं कह सकते। आप 14 महीनों से सरकार में बैठे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय में अगर कोई बात हुई हो तो जांच बैठाएं और अगर उन शर्तों को आज आप मान रहे हैं तो इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पारदर्शिता से आप गोते लगा रहे हैं। मेरा आरोप है यह।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज। अंकित नहीं होगा।

जल स्रोतों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में भेदभाव

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मेरे द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिये बहुत हार्दिक आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और राज्य सरकार का ध्यान किसानों की एक ज्वलंत और जबरदस्त समस्या

(श्री नारायण बेनीवाल)

की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आशंका है कि यह समस्या भविष्य में और भी विकराल रूप धारण करेगी। देखा जाए तो इस मामले ने हमारे सरकारी सिस्टम और इसकी कार्य प्रणाली की पोल खोलकर रख दी।

नागौर के बालिया गांव से एक व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर करते हैं कि नाडी में सरपंच कोई सरकारी भवन बना रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय चार व्यक्तियों की एक कमेटी बनाकर 2 अगस्त, 2004 को अब्दुल रहमान बनाम सरकार में यह जजमेंट देते हैं- "Referring to the provisions of Rajasthan Land Revenue Act 1956, it is submitted that no Nadi land can be used for any sort of construction." माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक कमेटी बनी है और पूरे राजस्थान में चाहे कैचमेंट एरिया हो, चाहे आगोर हो, चाहे पाइतन हो, नाडी हो, इसमें 1947 की स्थिति आप वापस लागू करें। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया, लेकिन हमारा सरकारी सिस्टम इसकी व्याख्या ढंग से नहीं कर पाया। उसके बाद किसानों की जो जमीनें थीं, जो भूमिहीन किसान थे, उन्हें सरकार ने 1947 के बाद अलाट कीं, उन सारी जमीनों के रैफरेंस बनाये गये। एक नागौर की बात करें तो 2780 मामले ऐसे हैं, जिनमें से 2723 प्रकरण जिला प्रशासन ने राजस्व मण्डल को भेजे। इनमें से राजस्व मण्डल, अजमेर ने वर्ष भर पहले तक 803 में निर्णय देते हुए 27 प्रकरणों की दुबारा सुनवाई करने तथा 776 प्रकरणों में खातेदारी की जमीन को मूल को संधारित करने के आदेश दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन भी करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मामले का आप संज्ञान लें। एक तरफ तो भू-माफिया पूरे सरकारी सिस्टम को धता बताते हुए पूरे शहर में, जैसे नागौर शहर में पूरी आगोर और नाडी की जमीनों पर कब्जे किये बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को आपने बेघर करके जमीन वापस सरकारी सिस्टम में दर्ज कर ली। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले में चाहे रिव्यू पिटीशन लगाये, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए और चाहे सदन में ऐसा कोई संकल्प पत्र लेकर आये जिससे किसानों को यह लगे कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। माननीय राजस्व मंत्री जी से भी मैं अपील करूंगा कि आप चूंकि हमेशा किसानों की बात यहां करते हैं तो यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर आप और हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से प्रयत्न करें ताकि समाज

(श्री नारायण बेनीवाल)

के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति में प्रशासन और शासन के प्रति नकारात्मक भाव पैदा न हो। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री बिहारीलाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नोखा के आयुर्वेद चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना पर बोलने की अनुमति के लिये धन्यवाद। निवेदन है कि उक्त नियम के तहत वर्तमान में नोखा में ''बी'' श्रेणी का आयुर्वेद चिकित्सालय स्वीकृत है। स्थानीय दानदाता परिवार खूमचंद गट्टाणी चैरिटेबल ट्रस्ट, नोखा के मुख्य ट्रस्टी ओमप्रकाश जी गट्टाणी द्वारा उक्त आयुर्वेद चिकित्सालय के लिये भूमि नोखा शहर के मध्य, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपये है एवं उस जमीन पर 4 करोड़ रुपये की लागत से भवन तैयार कर विभाग को सुपुर्द किया जा चुका है।

श्री ओमप्रकाश गट्टाणी वे शख्सियत हैं, जिन्हें अभी हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट (हाउस आफ कॉमन्स), लंदन में ''भारत गौरव सम्मान'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे नोखा ही नहीं, अपितु राजस्थान का नाम रोशन हुआ। अत: ''ए'' श्रेणी में 10 शय्या सहित क्रमोन्नत कर निम्न पदों पर सुविधाओं में अभिवृद्धि करने के आदेश प्रदान करें: पंचकर्म विशेषज्ञ-1, क्षारसूत्र विशेषज्ञ-1, आंचल प्रसूता केन्द्र संचालन हेतु महिला आयुर्वेद चिकित्साधिकारी-1, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र-1, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी-1, पुरुष आयुर्वेद कम्पाउण्डर-4, महिला आयुर्वेद कम्पाउण्डर-2 (कुल पद-6), पुरुष परिचारिक पद-4, महिला परिचारिक पद-2 (कुल पद-6), लिपिक-2, गार्ड-2, कम्प्यूटर मय आपरेटर-2,

मान्यवर, पिछले बजट सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मांग की तो विभाग ने बताया कि प्रतिदिन औसत रोगियों की संख्या न्यूनतम 150 निर्धारित है और इस चिकित्सालय में प्रति दिन औसत रोगियों की संख्या 98 का हवाला दिया। मान्यवर, एक चिकित्सक होने के कारण प्रति दिन औसत रोगियों की संख्या इतनी रहती है, चिकित्सक अधिक होने पर स्वत: ही रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अत: कृपया राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय

(श्री बिहारीलाल)

नोखा को ''ए'' श्रेणी में 10 शय्याओं की स्वीकृति सहित क्रमोन्नत करने का श्रम करें ताकि स्थानीय लोगों को आयुर्वेद पद्धति से उत्तम उपचार हासिल हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

वेणेश्वर धाम में अव्यवस्थाओं का मास्टर प्लान के अनुसार समाधान

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वेणेश्वर धाम के विकास हेतु 255 करोड़ रुपये की राशि का मास्टर प्लान बनाया गया है। उसकी स्वीकृति जारी करायी जाए ताकि वेणेश्वर धाम का विकास हो सके। साथ ही मेवाड़ व बागड़ कुम्भ वेणेश्वर धाम व संत मावजी महाराज की तपो भूमि पर आवश्यक कार्य करवाये जाएं।

वेणेश्वर धाम में सीसी रोड/इंटरलाक ईंटें लगवायी जाएं। पुरुष-महिला के लिये अलग-अलग बाथरूम निर्माण करवाया जाए। बिजली लाइन तार व पोल सिस्टमेटिक की जाए। वेणेश्वर धाम में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। सफाई/कचरा पात्र/सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जाएं। वेणेश्वर धाम में पेड़-पौधे लगवाये जाएं। धाम में रंगमंच को व्यवस्थित किया जाए। वहां पर फायर सिस्टम/एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। नहाने के घाटों पर सीढ़ियां सही की जाएं। नहाने के घाटों पर स्टील की रेलिंग लगवायी जाए। सभी मंदिरों, सरायों व धर्मशालाओं की मरम्मत करवायी जाए।

वेणेश्वर धाम के चारों तरफ रिंगवाल बनाये जाएं, जिससे मिट्टी की कटाई रोकी जा सके। धाम के नये मंदिरों का निर्माण रुकवाकर पुराने मंदिर शिवालय, राधाकृष्ण का सौन्दर्यीकरण किया जाए। धाम पर अतिक्रमण हटाये जाए। धाम पर पार्किंग की सही व्यवस्था की जाए। धाम में आवारा पशुओं पर रोक लगायी जाए। धाम में मेले में दुकानें आबंटन की सही व्यवस्था की जाए। धाम में तीनों पुलों पर मुख्य द्वार बनाये जाएं। धाम में बिना आज्ञा से मंदिर व सराय नहीं बनाये जाएं। धाम के शिवालय के अध्यक्ष को हटाया जाए। धाम में मंदिर परिसर की दुकानों की वसूली सरकार द्वारा की जाए। धाम में प्रोपर्टी

(श्री अमृतलाल मीणा)

संरक्षण रक्षा के लिये गार्ड रखा जाए। धाम के टापू पर हाई मास्ट लाइट्स लगवायी जाएं। धाम परिसर में गंदगी फैलाने पर चालान काटा जाए। वेणेश्वर धाम मेले में माह सुदी एकादशी व पूर्णिमा पर व्यापारियों व दर्शनार्थियों से कोई कर नहीं वसूला जाए। धाम के लिये एक करोड़ रुपये का फण्ड रखा जाए। अत: मेरा अनुरोध है कि उक्त समस्या का अतिशीघ्र समाधान करवाने की कृपा करें। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में भूजल स्तर गिरने से पेयजल समस्या

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट के निवारण के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में अण्डर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है जिसके कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या आने लग गई है। आम आदमी के लिए इस समस्या का निवारण उनके स्वयं के स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही पूरा विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन में है।

पिलानी विधान सभा क्षेत्र को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से पानी दिये जाने की संभावना है जिसके लिए डीपीआर भी सरकार ने बनवाई है, परन्तु इस क्रम में गति अपेक्षा से बहुत कम है। झुन्झुनूं जिले में यह क्षेत्र पेयजल की दृष्टि से गंभीर स्थिति में पहुंचने वाला है। हर परिवार टैंकर से पानी डलवाने की स्थिति में नहीं है। यह क्षेत्र गरीब मजदूरों, किसानों व दलितों का है, अत: इस ओर प्राथमिकता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भी कोई योजना इस क्षेत्र के ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की अभी तक सरकार ने नहीं बनाई है जो तुरन्त बनाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त दोनों योजनाओं की क्रियान्विति में समय लग रहा है अत: उक्त दोनों योजनाओं पर तो तुरन्त कार्यवाही कर पेयजल की योजना इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता से क्रियान्वित की जाए। इस बीच प्रत्येक किसान को एक-एक पेयजल के लिए कुण्ड स्वीकृत किया जाए ताकि वह वर्षा जल का संचय अपने पेयजल के लिए कर सके और अपने संकट के समय में उक्त एकत्रित जल का उपयोग कर सके। शहरी क्षेत्र के लिए भी तुरन्त पेयजल की योजना

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

बनाकर इस संकट की अवधि के लिए प्राथमिकता से तुरन्त उपाय किये जाएं।

साथ ही विनम्र निवेदन है कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के समक्ष शीघ्र ही आने वाले गंभीर पेयजल के संकट के निवारण के लिए उपरोक्तानुसार योजना बनाकर उसे तुरन्त क्रियान्वित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार का प्राथमिकता से उपाय करने हेतु मैं एतदद्वारा ध्यान आकर्षित करता हूं। आशा है प्राथमिकता से तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री हरेन्द्र निनामा। श्री अभिनेश महर्षि। माननीय सदस्य, लिखा हुआ बोलना पड़ेगा।

रतनगढ़ में गन्दे पानी से व्याप्त बीमारियां

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि रतनगढ़ शहर स्थित परमाणाताल में महीनों से भरे हुए गंदे पानी की निकासी नहीं होने से आने वाले समय में मच्छर व कीटाणुओं के कारण फैलने वाली महामारी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कलेक्टर व नगरपालिका को निर्देश दिये जाएं जिससे इसकी तुरन्त निकासी की जाए व आने वाली विपत्ति से जनता को बचाया जाए। साथ ही वार्ड नम्बर एक में भी कई महीनों से गन्दा पानी भरा हुआ है और अगर इसका भी निस्तारण नहीं होगा तो बीमारियां फैल जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, इसमें करंट आता है।

श्री अध्यक्ष: करंट तो आप खड़े होते हैं जब आता है।

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ है जिसमें 49 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 39 ग्राम पंचायतें चौमूं विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं। विगत 5 वर्षों में अनेक योजनाओं, जिनमें सांसद निधि, विधायक निधि, जिला परिषद्, पंचायत समिति, स्थानीय ग्राम पंचायत के कोटे में विभिन्न कार्य जिनमें सड़क, चारदीवारी, नालियां आदि हैं उनके निर्माण के सभी विकास कार्य की गुणवत्ता

(श्री रामलाल शर्मा)

को देखें तो ये सभी कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से मानदण्डों पर कहीं पूरा नहीं होता। कई विकास कार्य तो ऐसे किये हैं जो एक वर्ष में ही सड़कें टूट गई हैं तथा नालियां पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के कई अभियांत्रिकी अधिकारी जिनमें ए.ईएन. व जे.ईएन. पदस्थापित हैं लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्य की निगरानी नहीं होने के कारण घटिया निर्माण किया गया जिसमें करोड़ की राशि का दुरुपयोग हुआ है।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सभी विकास कार्यों की जिला स्तर पर एक कमेटी बनाकर जांच करायें तथा दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालय के तीनों अध्यक्ष एक साथ बैठे हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, इनका मन नहीं लगता इसलिए इनकी सीट एक जगह कर दो।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम मेघवाल।

झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से खराब फसलों का बीमा क्लेम

श्री कालूराम (डग): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि झालावाड़ जिले में हुई अतिवृष्टि से फसल 70 से 90 प्रतिशत खराब हो गई और सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई जिसकी गिरदावरी भी की गई मगर राज्य सरकार द्वारा अभी तक मुआवजा की राशि नहीं दी गई। अतिवृष्टि के कारण ग्रामीणों के मकान गिर गये जिसका मुआवजा कुछ ग्रामीणों को मात्र 3000 या 3200 रुपये मिले, कहीं ग्रामीणों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली। जिन ग्रामीणों के मकान गिरे उनका सर्वे के अनुसार प्रधान मंत्री आवास में प्राथमिकता से नाम जुड़वाया जाए ताकि गरीब ग्रामीणों को रहने के लिए आवास मिल सके। जो फसल खराब हुई है उसका बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम दिलवाया जाए। किसानों ने बैंकों में बीमा करवा रखा है मगर बीमा कम्पनी पिछले 2-3 वर्षों से कोई बीमा क्लेम नहीं दे रही है। पिछले वर्ष रबी की फसल में ओलावृष्टि के कारण डग व गंगरार तहसील में पूर्णत: फसल बर्बाद हो गई थी, उसका भी बीमा क्लेम अभी तक एसबीआई कम्पनी ने नहीं दिया जबकि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया। बीमा कम्पनी ने बीमा क्लेम क्यों नहीं दिया?

(श्री कालूराम)
माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम दिलवाया जाए या कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि झालावाड़ जिला अभावग्रस्त है, यहां पर बिजली के बिल माफ किये जाएं और बैंकों की वसूली रोकी जाए तथा राजस्व वसूली भी रोकी जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों के कृषि कनेक्शन काटे जा रहे हैं व ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं तो अगली फसल आने तक ट्रांसफार्मरों को उतरवाना रुकवाया जाए। इसके अलावा बैंकों में किसानों का कृषि ऋण जमा नहीं होने के कारण बैंकों द्वारा किया जाने वाला प्रधानमंत्री फसल बीमा बैंकों द्वारा करवाये जाने के आदेश सरकार करे ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

भोपालगढ़ में नगरपालिका की स्थापना

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे को, जो तहसील मुख्यालय एवं विधान सभा मुख्यालय भी है, नगरपालिका बनाने की घोषणा इस सदन में बार-बार की जा चुकी है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बजट 2012-13 एवं भाजपा सरकार ने बजट 2017-18 में घोषणा की थी उसके बावजूद नगरपालिका नहीं बनाना, यह जनता के साथ सीधे तौर पर कुठाराघात है। भोपालगढ़ कस्बे की आबादी करीब 30 हजार है। उक्त कस्बा नगरपालिका बनने के सभी मापदण्ड पूरे करता है परन्तु हमेशा से ही सत्ता पक्ष की अनदेखी के कारण आज ऐसे हालात बन गए कि जनता सरकार की घोषणा पर भरोसा नहीं करती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भोपालगढ़ कस्बा माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जिले में होने के बाद भी ऐसी उपेक्षा होना सरकार की कार्यशैली की स्थिति दर्शाती है जो विचारणीय है। कभी-कभी ऐसा देखकर एक मारवाड़ी कहावत याद आती है कि 'तीजो चावल हिके' देखना होगा। अब भोपालगढ़ नगरपालिका के लिए तीसरी बार यह चावल कांग्रेस के द्वितीय बजट में हिजता है या फिर नगरपालिका नहीं बनकर ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। इसलिए उक्त महत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन के माध्यम से शासन से प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- निवेदन है कि राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत के कार्यकाल में राज्य में पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने पर आर्टिकल 243(ई) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष की समयावधि में पंचायत चुनाव सम्पन्न कराना अनिवार्य हो गया और चुनाव कराना भी प्रारम्भ कर दिया।

वर्तमान सरकार ने सारे संवैधानिक प्रावधानों एवं नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं पंच के नामांकन पत्र दाखिल होने के पश्चात् उन्हें सीज कर दिया, जिस कारण से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति हास्यास्पद बन गयी है एवं पचांयत समितियों, जिला परिषदों में प्रशासक लगा दिये गये हैं, जो कि लोकतंत्र का मजाक है।

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग से सीधी राशि हस्तांतरित होती है। यह पहला अवसर है जब 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दिनांक 25.10.2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दूसरी किस्त की राशि रुपये 1840 करोड़ रुपये 3 माह पश्चात् भी ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से आवंटित नहीं किये गये जबकि वित्त आयोग की सिफारिशों में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही 10 दिन में पंचायती राज संस्थानों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाए।

अत: मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के जो पैसे केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं, उसे 8 दिन में ग्राम पंचायतों को सीधा हस्तान्तरित करें एवं भविष्य में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही नियमानुसार निश्चित अवधि अर्थात् 10 दिन में हस्तान्तरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन सिंह चौधरी।

डीडवाना में सरकारी भूमि पर बने निजी राजकीय महाविद्यालय का स्थानांतरण

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि डीडवाना में सरकारी जमीन पर भामाशाहों के सहयोग से महिला महाविद्यालय निर्मित किया गया है। इस महाविद्यालय में आज भी नि:शुल्क शिक्षा के नाम पर गरीब किसान वर्ग की बालिकाओं से फीस वसूली की जाकर व्यक्ति विशेष द्वारा आर्थिक पूंजी वसूल की जा रही है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1, डीडवाना शहर की 11031.521 वर्गमीटर भूमि, जो कि दिनांक 5 मार्च, 2014 को एक निजी संस्थान डीडवाना विकास समिति द्वारा लीज पर ले ली गई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजकीय भूमि को निजी संस्था को स्थानांतरित करने के क्या नियम हैं, समिति की आड़ में लीज/रजिस्ट्री किसी निजी व्यक्ति के नाम से कर दी जाती है और सरकारी जमीन को जिस निजी संस्थान को सौंपा गया है, वो निजी महिला महाविद्यालय सरकारी शर्तों का पालन न कर छात्राओं से भारी फीस लेती है तो सरकार को सरकारी जमीन पर निर्मित डीडवाना महिला महाविद्यालय को राजकीय डीडवाना महिला महाविद्यालय घोषित कर देना चाहिए ताकि आम गरीब तबके की बालिकाओं को शिक्षा का लाभ मिल सके, क्योंकि शिक्षित समाज के द्वारा ही विकसित प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अगर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है तो वो भी किया जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने निजी संस्था को लाभ पहुंचाने व सरकारी जमीन को निजी संस्था द्वारा हड़प करने की मंशा से कई दशकों से संचालित राजकीय विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित कर विद्यालय भवन एवं भूमि को किराये के नाम पर निजी महिला महाविद्यालय के कब्जे कराने वाले अधिकारियों व सिफारिश करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही के आदेश प्रदान कर महिला महाविद्यालय को राजकीय महिला महाविद्यालय घोषित कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र (अनुपस्थित)। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी के उपखण्ड मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का भवन निर्माण

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के उपखण्ड मुख्यालय थानागाजी पर मिनी सचिवालय के भवन निर्माण की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि उपखण्ड थानागाजी के विभिन्न कार्यालय आबादी के मध्य हैं, जहां पार्किंग एवं आमजन को अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही तहसील कार्यालय, उप अधीक्षक कार्यालय इत्यादि कार्यालयों के भवन वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। आमजन की कठिनाइयां, उपखण्ड स्तरीय विभागों में आपसी सामंजस्य और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए थानागाजी उपखण्ड स्तर पर मिनी सचिवालय बनाये जाने की अति आवश्यकता है। इस मिनी सचिवालय में निम्नलिखित कार्यालयों को शामिल किया जाए:-

1. उपखण्ड अधिकारी 2. पुलिस उपाधीक्षक 3. तहसीलदार कार्यालय 4. नगरपालिका 5. आयुर्वेद अस्पताल 6. पशु चिकित्सालय 7. पंचायत समिति 8. उपकोष अधिकारी कार्यालय 9. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी 10. बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय 11. उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के आवास हेतु सिविल लाइन का निर्माण 12. सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि मिनी सचिवालय भवन हेतु अपेक्षित भूमि नगरपालिका थानागाजी में खसरा नं. 317 है, जो सरकारी भूमि है, कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर, 17.50 बीघा है जिससे सभी ब्लाक स्तरीय कार्यालय का निर्माण हो सकता है। इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य बजटीय मद से वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में उपर्युक्त कार्यालय आबादी क्षेत्र के मध्य होने के कारण इस भूमि का मूल्य लगभग 50 करोड़ से अधिक है तथा इस भूमि को बिक्री कर प्राप्त राशि से मिनी सचिवालय हेतु अपेक्षित भवन का निर्माण किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास को नगरपालिका का दर्जा

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहती हूं कि बामनवास कस्बे को बार-बार मांग किए जाने के बावजूद आज तक नगरपालिका से वंचित रखा गया है। नगरपालिका के अभाव में मेरे क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बामनवास कस्बे की जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं जनजाति भौगोलिक दृष्टि होने से नगरपालिका बनाये जाने के सभी मापदण्ड पूर्ण करता है। बामनवास को नगरपालिका का दर्जा देने हेतु क्षेत्र की जनता द्वारा सरकार को अनेक बार ज्ञापन भी दिये जा चुके हैं। सरकार की नगरपालिका बनाने की सभी आवश्यक शर्तों को बामनवास पूर्ण करता है। अगर बामनवास को नगरपालिका का दर्जा दिया जाता है तो क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी और क्षेत्र का विकास हो सकेगा।

अत: इस अत्यन्त एवं जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि बामनवास को नगरपालिका बनाने के आदेश जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश पारीक।

डेयरी संघों के निष्पक्ष चुनाव

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया। राजस्थान डेयरी संघों में चुनाव हेतु आम जनता की भावना व निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु:-

(1) राजस्थान के सभी जिलों में दुग्ध समितियों पर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल व महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो।

(2) सभी जिला संघों में बोर्ड मेम्बर का चुनाव वार्ड वाइज करवाये जाएं।

(3) पूरे राजस्थान की डेयरी संघों में वार्ड में चुनाव है, केवल 3 संघ ही अपनी मर्जी से सीधा चुनाव करवाते हैं। उन तीनों संघों में भी वार्ड से चुनाव करवाये जाएं।

(4) पूर्व में पूरे राजस्थान की सभी दुग्ध संघों में बोर्ड मेम्बर का

(श्री राकेश पारीक)

एससी, एसटी का आरक्षण लागू था। उसको समाप्त कर दिया गया, उसे वापस लागू किया जाए।

(5) राजस्थान की सभी दुग्ध संघों में चुनाव लड़ने वाली समितियां, केवल 'ए', 'बी' श्रेणी की चुनाव लड़ सकती हैं, 'सी' श्रेणी वाली समितियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए।

(6) राजस्थान में सभी रजिस्टर्ड समितियों को वोट देने का अधिकार दिया जाए।

(7) सभी जिला संघों में अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण से चुनाव हो।

(8) आरसीडीएफ के अध्यक्ष हेतु भी आरक्षण प्रणाली से चुनाव हो।

(9) राजस्थान के सभी जिला दुग्ध संघों के संचालक मण्डल स्वयं ही नीति निर्धारण तय कर चुनाव करवाते हैं, जो नियम विरुद्ध है। संचालक मण्डल को इस निर्णय से हटवाया जाए।

(11) संघों के चुनाव में पारदर्शिता बनाने हेतु एक अलग से समिति का गठन किया जाए।

अत: इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सांभर, फुलेरा, नरेना, किशनगढ़-रेनवाल कस्बों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में प्रतिदिन जो पेयजल की सप्लाई की जा रही है वह बहुत ही कम मात्रा में की जा रही है। उक्त कस्बों में 48 घंटे से पानी दिया जा रहा है जिससे यहां की जनता बहुत परेशान एवं आक्रोशित है। वर्तमान में सर्दी के मौसम में ही अगर पेयजल की यह व्यवस्था है और अभी से यदि व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो आगामी गर्मी में स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। गत वर्ष भी जनता द्वारा आंदोलन, धरने प्रदर्शन किए गए थे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का डर पैदा हो गया था।

इसके अतिरिक्त विभाग में मेंटिनेंस का सामान भी उपलब्ध नहीं है जिससे अगर कोई लाइन लीकेज हो जाती है, पाइप फट जाते हैं तो ठीक

(श्री निर्मल कुमावत)

कराने में मुश्किल होती है। विभाग द्वारा भी जनता की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिससे जनता में रोष व्याप्त हो रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वर्तमान में की जा रही पानी की सप्लाई को बढ़ाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें तथा मेंटिनेंस का सामान भी वहां पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि जनता को पानी की समस्या से राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आदित्य बिरला सीमेंट कम्पनी द्वारा माइनिंग क्षेत्र में भूजल का असीमित दोहन

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ पूरा जिला सीमेंट फैक्ट्रियों का एक हब है। अच्छा है, रोजगार भी मिल रहा है पर वह माइनिंग लीज का मामला आता है। वह लाखों हैक्टेयर जमीन हमारी माइनिंग लीज में है और माइनिंग की जमीनें माइंस से काफी गहरी हो गई हैं, 300-400 फिट हो गई हैं। इस बार अच्छी बारिश भी हो गई है। बारिश होने की वजह से पानी भी भर गया है, ट्यूबवैल्स भी भर गए हैं, कुए भी भर गए हैं पर उसमें जमीन दोहन के द्वारा 300-400 और 1000 हार्स पावर की मोटरें चलाई जा रही हैं और उस पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है, उसके कारण से हमारे कुए सूख गए हैं, ट्यूबवैल्स में पानी कम पड़ गया है और एग्रीकल्चरल जमीनों को पानी पिलाने की भी दिक्कत हो रही है और गांवों में पीने के पानी की दिक्कत हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पानी को उन कुओं में डालें या उस पानी को भी तालाब बनाकर उसका उपयोग करें या उस पानी को गांवों में पाइप लाइन के द्वारा उपयोग करें या किसानों को पिलाने के लिए उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि हमारे किसानों की हजारों बीघा जमीन उसमें चली गई है और इस कारण जमीन भी हमारे पास कम बची है और उस जमीन के उपयोग के कारण पानी की हमारे को काफी दिक्कत हो रही है। उस पानी को उपयोग करने के लिए, उस पानी का अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, किस माध्यम

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

से आप बताएं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट की जो माइंस है वह काफी गहरी भी है वह उस पानी का उपयोग अच्छी तरह से कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार ध्यान दे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

जे.एल.एन. चिकित्सालय में आउटडोर के समय में कटौती से मरीजों को परेशानी

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल एक संभागीय अस्पताल है और वहां पर पूरे संभाग से लोग आते हैं। इस समय आउटडोर का इस अस्पताल में समय 9:00 बजे से 3:00 बजे तक का रहता है और प्रतिदिन लगभग 3000 से अधिक रोगी आउटडोर में आते हैं। इस तरह से दूरदराज के गांवों से आने वाला मरीज लगभग 11:00 बजे तक पहुंचता है और फिर पर्ची की लाइन में लगता है वह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करता है और आउटडोर में रोगियों की लगने वाली लंबी लाइनों से चिकित्सक से परामर्श लेने तक 1:00 बजे का समय हो जाता है। वहां जो सेंट्रल लैब है उसमें सैंपल लेने का समय केवल 1:00 बजे तक ही है। 1:00 बजे बाद जब रोगी चिकित्सक के द्वारा लिखी गई जांचें करवाने के लिए लैब पहुंचता है तो उसको सैंपल लेने के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसे में रोगी को दोबारा अगले दिन फिर अस्पताल आना पड़ता है। अतः उस गंभीर बीमार को दो बार अस्पताल में आने में परेशानी तो होती ही है और उसकी जांच रिपोर्ट भी एक दिन के बाद मिलती है। साधारणत: लैब में व्यवस्था है कि सैंपल लेने के बाद 5:00 बजे बाद उसको रिपोर्ट मिलेगी तो जो पहले दिन उसका सैंपल नहीं लिया तो वह अगले दिन सैंपल देगा फिर 5:00 बजे बाद उसको रिपोर्ट मिलेगी इस तरह 2 दिन उसके उपचार में देर हो जाती है। जिस तरह से आज एसएमएस अस्पताल है वहां सैंपल लेने का समय 2:00 बजे तक है और उसकी रिपोर्ट भी ऑनलाइन मिल जाती है। अतः हमारे इस हास्पिटल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था को सुधारा जाए। आउटडोर में चिकित्सक चूंकि 3:00 बजे तक बैठते हैं अतः रोगियों को लिखी गई जांचों के सैंपल भी 3:15 बजे तक लेने की व्यवस्था जरूरी है, ताकि रोगी को उस दिन सायं 5:00 बजे तक उसकी रिपोर्ट मिल सके। जांच रिपोर्ट के आधार पर गंभीर स्थिति सामने आने पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसको इलाज तत्काल उपलब्ध हो सके। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए चिकित्सालय में आवश्यक उपकरण व अन्य संसाधनों के साथ ही तकनीशियनों के पद भी भर करके उसकी व्यवस्था की जाए। परसों ही एक मरीज राजोसी गांव से भंवर खान 1:05 बजे पहुंचा और उसको कह दिया गया कि तेरी अब कल जांच होगी तो उस आधार पर वह बेचारा मरीज गंभीर था उसे 2 दिन इंतजार करना पड़ा। अतः मैं सरकार से, हालांकि चिकित्सा मंत्री जी बातचीत में व्यस्त हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं आपसे संबंधित महत्वपूर्ण विषय को ले रहा हूं, आप उस पर विचार करके इन व्यवस्थाओं को ठीक करें।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

बाड़मेर के रा.मा.वि. विश्नोइयों की ढाणी के बच्चों की डम्पर की टक्कर से मृत्यु

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 फरवरी को यानी परसों बाड़मेर जिले में विश्नोइयों की ढाणी के गांव से माध्यमिक विद्यालय से 6 बच्चे पढ़कर लौट रहे थे और एक ही परिवार के थे। एक नशे में धुत डंपर चालक तेज गति से चलाता हुआ आया और छह के छह बच्चों को रौंद दिया। उनमें से तीन बच्चे मौके पर ही मर गए हैं। यह बच्चे देवासी परिवार के थे। बहुत गरीब परिवार से हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 10,000 लोग मर रहे हैं और यह सड़क दुर्घटना है, अधिकांश लोग शराब पीकर के जो चलाते हैं उसके कारण से अधिकांश दुर्घटनाएं हो रही हैं और मेरा अनुमान है कि 50,000 लोग लगभग इससे घायल हो रहे हैं उनमें से 10,000 से भी ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में तड़प रहे हैं या बेहोशी की स्थिति में हैं।

श्री अध्यक्ष: बाड़मेर के बारे में बोलें, माननीय सदस्य। जनरल नहीं, बाड़मेर के बारे में।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब पीकर के चलाने के कारण से कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, 10,000 से ज्यादा लोग तो अस्पतालों में तड़प रहे हैं। 10,000 लोग मर गए हैं और 40,000

(श्री मदन दिलावर)

लोग अपंग हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार ने यातायात नियमों में सख्ती की थी और भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान किया था, लेकिन यह निकम्मी सरकार लगातार यह कहती रही...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। बाड़मेर की बात पर कहां पहुंच रहे हैं। आप डिबेट में भाग लेना दिन में।

श्री मदन दिलावर: 000

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मदन प्रजापत।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहद् पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बस काफी है। बैठें आप। मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के दो कस्बे क्रमशः बालोतरा एवं सिवाना, जैसलमेर जिले के कस्बा पोकरण तथा बाड़मेर जिले के क्रमशः 386, विधान सभा क्षेत्र शिव, बायतू, पचपदरा एवं सिवाना के क्रमशः 8, 194, 81 एवं 300 ग्राम एवं जैसलमेर जिले के 177, इस प्रकार कुल 563 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना वृहत् पेयजल परियोजना हेतु जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(अ) विभागीय नीति निर्धारण समिति की 162वीं बैठक दिनांक 29.3.2005 द्वारा राशि रुपये 966.77 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

(ब) विभागीय नीति निर्धारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 27.9.2011 द्वारा राशि रुपये 1,454.20 करोड़ की प्रथम संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(18.00 बजे)

उक्त पेयजल परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु इसे 7 पैकेजों में विभक्त कर 4 पैकेजों क्रमश: पैकेज एस.पी.आर. 01, पैकेज एस.पी.आर. 2अ, पैकेज एस.पी.आर. 3ब एवं पैकेज एस.पी.आर. 4अ का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस परियोजना के पोकरण कस्बे को पैकेज 3अ एवं बालोतरा कस्बे को पैकेज 2अ के अंतर्गत आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया है तथा बाड़मेर जिले के 234 (विधान सभा क्षेत्र शिव, बायतू एवं पचपदरा के क्रमश: 8, 192 एवं 34 ग्राम) ग्रामों को परियोजना के पैकेज 4अ के अंतर्गत तथा जैसलमेर जिले के 70 ग्रामों को परियोजना के पैकेज 3ब के अंतर्गत पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर जिले के 70 ग्रामों को पैकेज एस.पी.आर. 3अ के अंतर्गत आंशिक रूप से लाभान्वित किया जाकर इनमें स्वच्छ नहरी पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

उक्तानुसार बाड़मेर जिले के पैकेज 4ब के शेष रहे 152 ग्रामों में से विधान सभा क्षेत्र बायतू के 2 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के 47 ग्राम एवं विधान सभा क्षेत्र सिवाना के 103 ग्रामों को उक्त पेयजल परियोजना से लाभान्वित किया जाना वर्तमान में शेष रहा है। इन ग्रामों को उक्त पेयजल परियोजना के आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के पैकेज संख्या 2ब के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पैकेज एस.पी.आर. 2ब एवं 4ब की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

एस.पी.आर. 2ब (संतरा भाकरी से सिवाना एवं सिणधरी तक आधारभूत संरचनाओं के कार्य):- इस पैकेज के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड गुड़गांव को राशि रुपये 187.01 करोड़ (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 183.10 करोड़ एवं 10 वर्ष के परियोजना के संचालन व संधारण कार्य हेतु राशि रुपये 3.75 करोड़) का कार्यादेश दिनांक 14.09.2012 को जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार इस पैकेज की परियोजना का कार्य दिनांक 23.03.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित था। अनुबंधक फर्म द्वारा माह जनवरी, 2020 तक इस पैकेज का 76 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया है। इस पैकेज के कार्य निर्धारित तिथि पर पूर्ण नहीं किये जाने का मुख्य कारण अनुबंधक फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से करना एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रोरेटा प्रगति नहीं दिया जाना रहा है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पैकेज के कार्य की प्रगति नहीं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

देने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म को कार्यों की गति बढ़ाने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता, परियोजना बाड़मेर एवं मुख्य अभियंता, परियोजना जोधपुर द्वारा समय-समय पर नोटिस भी जारी किये गये हैं। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अनुबंधक फर्म द्वारा पैकेज के कार्यों की प्रगति नहीं देने के कारण अनुबंध के क्लाज 2 एवं 3 के तहत विभाग द्वारा रुपये 6.94 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित कर रोक ली गई है। इस पैकेज की परियोजना के कार्यों की वर्तमान प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए इसका कार्य माह दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

एस.पी.आर. 4ब (बाड़मेर जिले 2 कस्बे बालोतरा एवं सिवाना तथा 152 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पूर्ण रूप से लाभान्वित करने का कार्य):- इस पैकेज के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु मैसर्स गेमन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई को राशि रुपये 392.66 करोड़ (मुख्य निर्माण कार्यों की लागत रुपये 367.14 करोड़ एवं 10 वर्ष के परियोजना के संचालन व संधारण कार्य हेतु राशि रुपये 25.52 करोड़) का कार्यादेश दिनांक 18.09.2013 को जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार इस पैकेज की परियोजना का कार्य दिनांक 27.09.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था। अनुबंधक फर्म द्वारा माह जून, 2019 तक इस पैकेज का 58 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया जाकर इसके उपरांत कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इस प्रकार अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त योजना का कार्य बंद कर देने एवं पुन: प्रारम्भ नहीं करने के कारण उक्त पैकेज के कार्य को रिसाइंड किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सक्षम स्तर पर निर्णय होने के उपरांत उक्त अनुबंधक फर्म की रिस्क एंड कोस्ट पर इस पैकेज के कार्य अन्य किसी फर्म से कराये जाने हेतु नवीन निविदा आमंत्रित की जाकर इसका कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव हो सकेगा। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अनुबंधक फर्म द्वारा पैकेज के कार्यों की प्रगति नहीं देने के कारण अनुबंध के क्लाज 2 एवं 3 के तहत विभाग द्वारा रुपये 18 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि आरोपित कर रोक ली गई है।

उपरोक्तानुसार परियोजना के पैकेज 2ब में सम्मिलित आधारभूत संरचनाओं के कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है तथा इस पैकेज के पूर्ण किये गये कार्यों से पैकेज 4ब में सम्मिलित कस्बों/ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। पैकेज 4ब के कार्य को सक्षम स्तर से रिसाइंड किये जाने के निर्णय के उपरांत अनुबंधक फर्म की रिस्क एंड कोस्ट

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पर इस पैकेज के कार्य अन्य किसी फर्म से कराये जाने हेतु नवीन निविदा आमंत्रित की जाकर इसका कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहत् पेयजल परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु एक वृत्त कार्यालय एवं 3 खण्डीय कार्यालय सृजित किये गये हैं तथा इनमें अधीक्षण अभियंता का 1 पद, अधिशासी अभियंता के 4 पद एवं सहायक अभियन्ता के 16 पद स्वीकृत हैं तथा इस स्वीकृति के विरुद्ध पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

अधीक्षण अभियंता, वृत्त पोकरण

क्र. सं.	**पदनाम**	**पदों का विवरण**		
		कुल स्वीकृत	**पद स्थापित**	**रिक्त**
1.	अधीक्षण अभियंता, वृत्त पोकरण	1	1	0
2.	अधिशासी अभियंता,(तकनीकी सहायक, वृत्त कार्यालय पोकरण, परियोजना खण्ड बालोतरा, पोकरण एवं नाचना)	4	4	0
3.	सहायक अभियंता (वृत्त कार्यालय पोकरण-1, परियोजना खण्ड बालोतरा, पोकरण एवं नाचना प्रत्येक खण्ड में 5, कुल 15)	16	0	16

उक्त पेयजल परियोजना के पैकेज संख्या 2ब एवं 4ब का कार्य परियोजना खण्ड बालोतरा द्वारा निष्पादित किया जा रहा है तथा इस खण्ड में सहायक अभियंता के स्वीकृत समस्त 5 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। सहायक अभियंता के पद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से क्रमश: 50:50 के अनुपात में भरे जाते हैं। सहायक अभियंता के विभाग में सीधी भर्ती के 312 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 5.4.2018 को विज्ञप्ति जारी कर मुख्य परीक्षा माह दिसम्बर, 2019 में आयोजित की जा चुकी है तथा चयन की कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता के पदोन्नति कोटे से भरे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जाने वाले रिक्त पदों पर चयन हेतु वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 की डीपीसी के प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अंतर्गत सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से चयनित होने वाले सहायक अभियंताओं को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार पदस्थापन किया जाकर इन पदों को भरा जा सकना संभव हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायक अभियंता के 16 के 16 पद खाली हैं। कुछ जगह तो पानी आ रहा है लेकिन सिवाना भी मेरे विधान सभा का बड़ा कस्बा है और हालात यह है कि लोग धरने पर भी हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें सवाल राजनीति का नहीं है, मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, तुरंत पूरा हो ताकि जनता को लाभ मिले, मेरा मकसद यही है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में सिवाना कस्बे में 5 ट्यूबवैल स्वीकृत किये हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी उनको इजाजत दे दी गई है कि जहां-जहां पानी नहीं है वहां ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पिलाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि 2015 में यह जो 2ब का काम था उसकी 10 किलोमीटर पाइप लाइन बिछ गई थी किन्तु यह जो फर्म है एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा, यह बीच में काम छोड़ गई और गेमन कंपनी भी 2ब का काम छोड़ गई, इसके कारण से इन कस्बों को नहीं जोड़ा जा सका है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किये, हमने भी आने के बाद बहुत प्रयत्न किये। हमने उनके पैसे रोके, उनकी बैंक गारंटी, एक की 39.2 करोड़ और एक की 14 करोड़ हमने रोक रखी है और जल्दी ही यह काम नहीं करेंगे तो हम इसे रिस्क एंड कोस्ट बेसिस पर कराने का काम करेंगे। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक यह व्यवस्था नहीं होती है सिवाना, बालोतरा और इनके संबंधित गांवों में पीने का पानी पहुंचाने का विभाग जो भी स्थानीय सोर्सेज हैं उसके आधार पर पानी पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, बात जो सुनने में आ रही है, मामला बजट का है और बजट की तुरंत व्यवस्था होगी तो यह कार्य प्रगति पकड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती इन्द्रा।

दिनांक 01.04.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों को आउटडोर मेडिकल सुविधा

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको इसी प्रश्न का जवाब अतारांकित प्रश्न के रूप में 11 तारीख को मिल चुका है। आज फिर लगा दिया गया है। खैर, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रदेशवासियों के लिए, जिसमें राज्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, राजकीय चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज उपलब्ध है, जिसमें मुफ्त जांचें और दवाइयों की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

दिनांक 01.04.2004 के पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारी और उन पर आश्रित परिजनों पर राज्य मेडिक्लेम बीमा पालिसी लागू है। इसमें इनडोर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उक्त मेडिक्लेम पालिसी के तहत प्रति कर्मचारी एवं उसके नियमानुसार आश्रित परिजनों हेतु कुल बीमा राशि तीन लाख रुपये हैं। प्रति कर्मचारी एक हजार रुपये के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 01.04.2004 व उसके पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को आर.पी.एम.एफ. में शामिल किये जाने का कोई विचार नहीं है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, टी.बी आदि बीमारियां यदि एक बार किसी व्यक्ति के घर कर जाती हैं, तो उन्हें जीवन भर दवाइयां लेना अनिवार्य हो जाता है। क्या सरकार उक्त बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को जो दिनांक 01.04.2004 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त हुए हैं, उन्हें आउटडोर मेडिकल बिलों के पुनर्भरण की सुविधा देने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार का इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल मीणा।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ की रिपोर्ट (वर्ष 2018-19)

1. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-2019; एवं

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2018-19)

2. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-14 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19.

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन, श्रीमती अनिता भदेल।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति 2019-20 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन, श्री छगनसिंह।

याचिका

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

आहोर में गोदन से बीछावाड़ी तक सड़क निर्माण

1. विधान सभा क्षेत्र आहोर में गोदन से बीछावाड़ी तक सड़क निर्माण करने बाबत; एवं

आहोर स्थित बड़ो के बेर पर बने एनीकट का पुन: निर्माण

2. विधान सभा क्षेत्र आहोर स्थित बड़ो के बेर पर बने एनीकट का पुन: मजबूत निर्माण करने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में रोडवेज व ग्रामीण बसों का संचालन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कतिपय स्थानों पर रोडवेज व ग्रामीण बसों का संचालन करवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

समदड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 25 केवीआर के जनरेटर की मांग

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समदड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 25 केवीआर का जनरेटर लगाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा, श्री प्रताप सिंह जी प्रस्ताव रखेंगे।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19) पर विचार

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ज्यादा सदस्य भाग ले सकें, इसलिए दस-दस मिनट में अपनी बात कहें। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसका नाम परिवहन है, आज भी आम व्यक्ति जब स्टैण्ड पर खड़ा होता है, जब बसों का इंतजार कर रहा होता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान तब दिखायी देती है, जब सरकारी बस आती है क्योंकि आम व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है और उसका विश्वास रहता है कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अगर रोडवेज बस में बैठाकर भेजूंगा तो वे अपने स्थान पर सुरक्षित जाएंगे। उसका विश्वास बना हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता। वर्षों के बाद किसी प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है और यहां पर अधिकारी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आ जाएंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्योंकि आम आदमी का विश्वास सरकार के साधन पर है और वह अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं सरकारी रोडवेज बस में बैठकर जा रहा हूं। रोडवेज एक ऐसा अतिमहत्वपूर्ण सब्जैक्ट है, जिसमें सरकार जितना काम करे, उतना कम है। इंसान और परिवहन एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर सरकारी रोडवेज नहीं होगी तो आम आदमी, एक आम व्यक्ति का आवागमन किस तरह से होगा, यह सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रोडवेज बस गरीब की रथ मानी जाती है। सरकारी बसें हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती हैं।

(13.07 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

वर्तमान में परिवहन मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देंगे कि जो नये-नये आयाम परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोफिट में लाने के लिए और आमजन को सुविधा देने के लिए स्थापित किये गये हैं, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है क्योंकि निगम द्वारा स्वयं के मोबाइल पर ऑनलाइन भुगतान किया जाना, टिकटें जारी करना, यह सुविधा आमजन को जो सरकार ने पहुंचायी है, वह इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। चाहे वाईफाई के माध्यम से जोड़ना और परिचालक द्वारा ई.टी.आई.एम. मशीन के द्वारा देखकर तुरंत ही चालू आरक्षण टिकट जारी किये जा सकते हैं। व्यक्ति को अपने आरक्षित टिकट के लिए जगह-जगह पर जाकर चक्कर नहीं काटने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पड़ते, उसको परेशान नहीं होना पड़ता है। ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार बनने के बाद शुरू हुई हैं। निगम के सभी बस स्टैण्डों के अकाउंट्स पर, आरक्षित टिकटों का मिलना, टिकटों का ऑनलाइन मानिटरिंग करना, स्मार्ट कार्ड, आर.एफ.आई.डी. तकनीक पर आधारित किये गये हैं और लाखों की संख्या में विभिन्न श्रेणी के कार्ड जारी किये गये हैं, जो कि सरकार की एक उपलब्धि के रूप में प्रचारित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों को रियायती दरों में नि:शुल्क यात्राओं के लिए पुनर्भरण राशि का पोर्टल के माध्यम से स्वत: ही आकलन होता है। यह एक नया आयाम है, जिसमें किसी के भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इससे किसी के बीच में बेईमानी करने का जो अंदेशा था, वह खतम हो रहा है। स्वचालित यात्रा उद्घोषणा प्रणाली निगम के प्रत्येक जिले में संचालित की गयी है। निगम की लंबी दूरी वाले जो वाहन हैं, उनमें मनोरंजन के लिए एल.ई.डी. को लगाना, जिससे कि यात्री परेशान नहीं हों। बड़े-बड़े मेलों में यात्रियों को 30 प्रतिशत तक की छूट, जिसमें कि राजस्थान में एक आम यात्री को, ग्रामीण क्षेत्र वालों को एक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। चाहे पुष्कर मेला, कैला देवी हो, रामदेवरा हो, रणथम्भौर हो, ऐसे अनेक जो बड़े मेले लगाये जाते हैं, उनमें इस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगी हमारे अलवर में चाहे शीतलनाथ का मेला हो, गरबा जी का हो, हनुमान जी का पांडुपोल का मेला हो, भर्तृहरि जी का हो, उनमें भी ऐसी सुविधाएं आप उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बस स्टैंड को आप पहले देखते और अब वर्तमान में देखें तो उसमें रात-दिन का फर्क आ रहा है। पहले उस बस स्टैंड को पीपीपी माडल पर दिए जाने की बात पिछली सरकार की चल रही थी। इनकी मंशा थी कि जो सरकार द्वारा आम व्यक्ति के लिए एक गरीब रथ माना जाने वाला वाहन, उसको समाप्त करना, निजीकरण में देना था लेकिन धन्यवाद है कि हमारी सरकार बनने के बाद राजधानी का जो बस स्टैंड है, वहां वाईफाई की सुविधा मिली है, स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, प्रतीक्षालय, रेस्टोरेंट, एलईडी, सोलर प्लांट जैसे अनेक कार्य किये गये हैं, जो दर्शाता है कि राजधानी के बस स्टैंड पर सरकार बदलने के बाद में किस तरीके से नये काम किये गये हैं। सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

सभी बस स्टैंडों का नवीनीकरण किया गया है। नई बसें खरीदने का जो सरकार काम करने जा रही है, इससे पूरे राजस्थान को लाभ मिलेगा। लोगों की जो मंशा थी कि हमें प्राइवेट बसों में जाना है, वह मंशा खतम होती जा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रही है, 876 नई बसें खरीदेंगे। नये रूटों पर बस चलाने का काम किया जाएगा। लोक परिवहन, जो आए दिन एक्सीडेंट का सबब बनती जा रही हैं, सरकारी रोडवेज के आगे भाग-भाग कर लगाती हैं और कितने एक्सीडेंट इन लोक परिवहनों के कारण हुए हैं। ये पिछली सरकार की बड़ी नाकामी थी। निगम कर्मचारियों को ईएसआई सुविधा से जोड़ना जिससे रोडवेज का कर्मचारी कभी कोई हारी-बीमारी हो तो अपना ईएसआई कार्ड बनाकर सुविधा प्राप्त कर सके, अपना इलाज करा सके, अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करा सके और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाना। वर्तमान में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके कारण एक्सीडेंट में भी रूकावट आई है। पिछले दिनों अनेक रूट पर जो सरकारी या ग्रामीण बसें बंद कर दी गई थीं पिछली सरकार के द्वारा, बानसूर में पहले अनेक रूट पर ग्रामीण बसें जो चल रही थी, वह पिछली सरकार ने आनन-फानन में बंद कर दी थीं। जब हमने प्रश्न लगाया तो एक-दो दिन के लिए सरकारी रोडवेज बस चला ली और यह लिखकर बंद कर दी गई कि यहां पर सवारियां नहीं बैठती हैं। यह एक नाकामी रही थी।

मैं अनुरोध करूंगी कि बानसूर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां छात्र-छात्राओं का ज्यादा आवागमन रहता है। प्राइवेट कालेज हैं, तकनीकी कालेज हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। कई विधान सभा लगते हैं चाहे बहरोड़ कोटपूतली, मुण्डावर, अलवर, थानागाजी, विराटनगर, छात्र-छात्राएं जीप में बैठकर जाते हैं। इस कारण कई बार परेशानी होती है और कई बार बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बानसूर में ग्रामीण बसें जैसे पहले हमारी सरकार में चलती थीं, वे ग्रामीण बसें चलाने का आप कष्ट करें। पिछली सरकार ने जिन रूट पर रोडवेज सरकारी बसें चलाकर बंद कर दी, जैसे आलनपुर से बानसूर, बानसूर से नारायणपुर और बानसूर से जयपुर के लिए इस रूट से जो बसें चलती थीं..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट, माननीय सभापति महोदय। एक अति महत्वपूर्ण नीमूचाना, जो किसानों के लिए जाना जाता है, इतिहास में अंकित है, ऐसे जो बड़े रूट हैं, उन पर बसें चलाई जाएं। सर्वे करवा कर बानसूर में दोनों जगह, दोनों ब्लाक्स में बस स्टैंड नहीं है क्योंकि बानसूर में हमारे जीते हुए प्रतिनिधि बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री रहे थे और मंत्री रहते हुए झूठी घोषणाएं करना और वहां पर लंबे रूट पर रोडवेज बस का

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

संचालन नहीं किया, एक भी रोडवेज बस स्टैंड नहीं बनाया गया और खाली घोषणाएं कर दी गई।

सभापति महोदय, एक छोटा-सा उदाहरण दूंगी कि पिछली सरकार ने यह कहा कि केन्द्रीय बस स्टैंड, अलवर के लिए सभी विधायक पांच-पांच लाख रुपये देंगे। विपक्ष की होने के बाद भी मैंने पांच लाख रुपये दिए। यह कहा गया, लिखित में दिया गया कि आपके अलवर रूट पर हरसोला वाले पर, बानसूर वाले पर रोडवेज बस चलाई जाएगी। न तो केन्द्रीय बस स्टैंड का नवीनीकरण हुआ, न ही बसें चलाई गईं।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जिन आंकड़ों की यह बातें करते हैं, आंकड़े उठाकर देखें कि कितने झूठे वादे किये गये थे।

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्य जो विराजमान हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि करीब 30 सदस्य बोलने वाले हैं। आसन से माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि आप सभी दस-दस मिनट बोलेंगे। मेहरबानी करके दो मिनट पहले ही मैं आपका नाम पुकारूंगा, उसके बाद आवश्यक रूप से आप दस मिनट में समाप्त करेंगे। 30 माननीय सदस्य हैं, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो सभी का नंबर आना मुश्किल होगा। इसलिए सभी से आग्रह है कि सभी सहयोग करेंगे। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, सभापति महोदय। राजस्थान रोडवेज राजस्थान में परिवहन की लाइफ-लाइन है। आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत उपयोगी और आवश्यक सेवा है। जब रोडवेज पर बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मैं सदन को एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने बारे में बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरी आधी जिन्दगी रोडवेज की बसों में कटी, 17 साल की उम्र से सफर कर रहा हूं। पहले संघ के कार्यकर्ता के रूप में किया, बाद में विधायक के रूप में किया। आज भी मैं ट्रेन के बजाय रोडवेज की बस में सफर करना प्रिफर करता हूं। जब मैं बस में बैठा होता हूं तो बस के कंडक्टर और ड्राइवर से लगातार मेरा संवाद रहता है। उनसे मैं फीडबैक लेता रहता हूं। इसलिए मेरी जो जानकारियां हैं वह बिलकुल धरातल की हैं। रोडवेज घाटे में है, यह बहुत ज्यादा हाइलाइट किया जाता है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सैद्धान्तिक तौर पर रोडवेज नफा कमाने के लिए है ही नहीं, रोडवेज सेवा देने के लिए है लेकिन घाटा भी नहीं होना चाहिए, यह भी अपनी जगह महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदय, जो घाटा होता है, उसमें कई स्तर हैं। घाटे में सबसे बड़ा कारण जो होता है, वर्तमान में दिखाया जाता है कि यात्री भार कम मिल रहा है, लेकिन गहराई में जाएंगे तो घाटे का बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। मैंने रोडवेज के कंडक्टरों को पूरी की पूरी बस भी बिना टिकट ले जाते हुए देखा है। मैंने रोडवेज के ड्राइवरों को डीजल चुराते हुए देखा है मैंने रोडवेज के मैकेनिक्स को रोडवेज की कार्यशाला से पार्ट्स और टायर बेचते हुए भी देखा है। ये नीचे के स्तर का भ्रष्टाचार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जब नीचे के स्तर के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का सच्चे मन से आह्वान किया गया और उनकी जिम्मेदारी तय की गई और उनको व्यवस्था के साथ जोड़ा गया, कई बार योजनाओं के माध्यम से उनको नफे में भागीदार भी बनाया गया तो उन्हीं कंडक्टर्स को मैंने एक-एक सवारी के लिए लड़ते हुए भी देखा है, उन्हीं कंडक्टर्स को मैंने गाड़ी के आगे लगने वाली प्राइवेट बसों और जीपों से लड़ते हुए भी देखा है। उन्हीं ड्राइवरों को मैंने एक-एक किलोमीटर का एवरेज सुधारने के लिए अपनी कई सारी स्किल्स लगाते हुए भी देखा है। जब भी कभी कर्मचारी को ढंग से आह्वान करके, उनकी भावनाओं को जगाकर रोडवेज के साथ जोड़ने की कोशिश की गयी, रोडवेज का नुकसान कम करने के लिए उनका आह्वान किया गया तो उन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार ऊपर से हमेशा आता है। जितना भ्रष्टाचार रोडवेज के कंडक्टर या ड्राइवर ने किया होगा, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार ऊपर होता है, हैड आफिस में होता है। डिपो मैनेजर से लेकर हैड आफिस, एमडी, सीएमडी तक बड़ा भ्रष्टाचार होता है। वह ज्यादा घाटा देते हैं।

बसों को खरीदने में भ्रष्टाचार होता है, बसों के टायर खरीदने में भ्रष्टाचार होता है, बसों के पार्ट्स खरीदने में भ्रष्टाचार होता है। उन पर हम कितना अंकुश लगा पाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि रोडवेज घाटे में रहेगी या फायदे में रहेगी। यात्री भार बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अपना यात्री भार 78 प्रतिशत चल रहा है, यानी कि हर बस में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लगभग 11 सीटें खाली जाती हैं। उसको भरने के लिए आपने ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन टिकट से बहुत अच्छी सुविधा हुई है। ऑनलाइन टिकट के कारण आपका यात्री भार बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है लेकिन ऑनलाइन टिकट के लिए आपने जिस एजेंसी को काम दिया है, उसको 5 करोड़ से अधिक का कमीशन जा रहा है। उसके बदले टिकट कितने बन रहे हैं, रोडवेज में प्रतिदिन 8 से 10 लाख टिकट टोटल कटते होंगे, उनमें से ऑनलाइन टिकट मुश्किल से 1000 कट रहे हैं। 1000 टिकट के लिए हम उसको 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं। रोज के 1000 टिकट के लिए हम उसको 5 करोड़ का कमीशन दे रहे हैं। इन टिकटों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उसका कमीशन कैसे कम किया जाए, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आपने टिकट मशीनें कंडक्टर के हाथ में दे रखी हैं, वह मशीनें आपके ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को पिछले 15 साल से कह रहा हूं, जब से मशीनें आई हैं, तब से कह रहा हूं, इनको ऑनलाइन जोड़िए। इनको ऑनलाइन क्यों नहीं जोड़ रहे? पर ऑनलाइन जोड़ने की व्यवस्था नहीं हो रही है। कंडक्टर को पता ही नहीं होता है कि ऑनलाइन कहां-कहां से, कितने टिकट बुक हो गए। चलती बस में कंडक्टर जो टिकट काट रहा है ऑनलाइन सिस्टम में वह इन्क्लूड नहीं हो पाता है। कई बार ऐसी नौबत आती है कि एक ही सीट पर कंडक्टर ने पहले किसी को टिकट दे दिया और अगले स्टाप से कोई अन्य ऑनलाइन टिकट लेने वाला आकर खड़ा हो जाता है और वहां पर झगड़े की स्थिति पैदा होती है। कंडक्टर के हाथ में जो मशीनें हैं, अगर उनको ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया जाए, तो आपके यात्री भार में बढ़ोतरी होने की बहुत अच्छी गुंजाइश बनती है।

प्राइवेट बस वाले हैं, वह कम्पीटिशन करते हैं, उस कम्पीटिशन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। रोडवेज बस से 5-10 मिनट पहले कोई प्राइवेट बस निकलती है और सारी की सारी सवारियां ले जाती है और रोडवेज की बस खाली जाती है। अधिकारी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार अधिकारी उनसे मिले हुए होते हैं। कई बार अन्य स्तर पर भी उनके साथ मिलावट हो जाती है। मैं बहुत अफसोस के साथ माननीय मंत्री महोदय, एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, जोधपुर में राईका बाग बस स्टैंड के बाहर फ्लाईओवर बना हुआ है उस पर एक बस लगती है।

श्री सभापति: रोडवेज में तो सवारियां ज्यादा हो जाती हैं और सीटें कम हो जाती हैं इसलिए बैठते हैं, आप सब की तो सीटें अलग-अलग हैं। रोडवेज का माडल आप लोग यहां क्यों दिखा रहे हो? सबको अलग-अलग सीटें दी हुई हैं, फिर भी आप एकजुट होकर बैठ गए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जोधपुर से जालौर के लिए जो बस निकलती है उससे 10 मिनट पहले एक प्राइवेट बस निकलती है। वापस जब जालौर से वही बस चलती है 10:00 बजे के आसपास, उसके 10 मिनट पहले फिर वह बस निकलती है, शाम को फिर आती है, वह बस दो राउंड करती है। वह बस कहां खड़ी रहती है, उसका नंबर क्या है, किस की बस है, वह सारी जानकारी मैंने मंत्री महोदय को दी थी। मंत्री महोदय, उस बात को 6 महीने हो गए हैं, वह बस अब भी वहीं पर खड़ी रहती है, यह आपकी मोनिटरिंग है। वह किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं नहीं सोचता कि ऐसा किया हुआ होगा लेकिन लगता है कि मंत्री मंत्री महोदय भी दबाव में आ गए होंगे। यह लिहाज मत रखिए। यह लिहाज रहेगा तो आप रोडवेज को फ़ायदे में नहीं ला सकेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपने अनुबंधित बसें लगा रखी है, उन पर भी मोनिटरिंग की जरूरत है। उनका ड्राइवर कितना अनुभवी है, कितना प्रशिक्षित है, इसकी चिंता की जानी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार मेरे खुद पर अनुबंधित बस चढ़ते-चढ़ते बची। मैं जोधपुर से जालौर कार से जा रहा था, जालौर से रोडवेज की अनुबंधित बस आ रही थी, बिना बात उस ड्राइवर ने कट मारा, मेरे ड्राइवर ने बचाने के लिए जब कार को थोड़ा साइड में किया तो एक मोटरसाइकिल वाला मेरी कार से टकरा गया। उस समय मैंने शिकायत भी की, उसको सबक भी मिला। निगम की 3700 बसें चलती हैं, उनके द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं 187 और उसमें 77 लोग मरते हैं उसकी तुलना में, 3700 बसों की तुलना में केवल 1000 के करीब अनुबंधित बसें चल रही हैं। 187 की तुलना में 230 एक्सीडेंट करती है, 77 की तुलना में 97 लोगों को मार देती है। इसका मतलब अनुबंधित बसों के ड्राइवर हैं वह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अनुभवी नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं, लापरवाह हैं, जिम्मेदार नहीं हैं, उसकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप में व्यवस्था में सुधार होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं बसों के खरीद की बात कर रहा था... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कनक्लूड कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह तो भ्रष्टाचार निपटाने में है, और बसों का यात्री भार बढ़ाने में हमारा लोअर केटेगरी का स्टाफ है, कंडक्टर और ड्राइवर लेवल का, उन पर विश्वास किया जाए और उनका सहयोग लिया जाए, उनका इन्वाल्वमेंट बढ़ाया जाए, भावनात्मक रूप से उनको जोड़ा जाए। उनको रोडवेज सेवा भी दें। उनको तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है। उनके मेडिकल बिल पास नहीं होते। हैड आफिस में बैठे हुए सारे आफिसर्स के मेडिकल बिल हाथों-हाथ पास हो जाते हैं, एक दिन भी नहीं रुकते हैं। डिपो मैनेजर और उनके सहयोगी अफ़सरों के मेडिकल बिल एक दिन भी नहीं रुकते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर के मेडिकल बिल सालों तक पैंडिंग पड़े रहते हैं। 6-6, 7-7 महीने, साल-साल, दो-दो साल तक पैंडिंग पड़े रहते हैं। उनको ओवरटाइम का भुगतान नहीं होता है।

श्री सभापति: कनक्लूड कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अफसर जरा-सा कहीं जाता है, उसको तुरंत ओवरटाइम मिल जाता है, लेकिन रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर को ओवरटाइम का भुगतान नहीं होता है। एरियर और वेतन वृद्धि जब भी लागू होती है, एरियर बनता है, उसका भुगतान सालों बाद जाकर होता है और टुकड़ों-टुकड़ों में होता है, जबकि अफसरों को हाथों-हाथ हो जाता है। इस तरह आप अपने स्टाफ को डिमोरलाइज करेंगे तो वह कभी भी आपको कमाकर नहीं देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले टेन ईयर में ग्रामीण परिवहन बस सेवा शुरू की थी, बहुत आदर्श व्यवस्था थी। गांव गांव में रोडवेज की डिमांड है...

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा। विराजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अंतिम है। ग्रामीण परिवहन बस सेवा गांव

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

में जाकर सेवा दे रही थी। वह बस सेवा वापस लागू की जाए। वह सिस्टम भी बहुत अच्छा था, उसके कारण जनता को बहुत अच्छी सेवा मिल रही थी। मैं पुरज़ोर शब्दों में मांग करता हूं कि उस बस सेवा को पुनः बहाल करने की सरकार व्यवस्था करे। मंत्री जी मुझे साल भर से आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन वह कर नहीं पा रहे हैं। सरकार करे तो जनता को निश्चित रूप से अच्छी सेवा मिलेगी और रोडवेज जनता को और अच्छी सेवा दे पाएगी। इसी के साथ आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रतिवेदन पर विचार और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। गत साल भर से जिस तरह का रोडवेज में, सभी पाइंट पर, एक सकारात्मक इजाफा हो रहा है, उसके लिए मैं सरकार, मुख्य मंत्री जी, मंत्री जी को, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने काफी सुधार किए हैं। मैं डांग क्षेत्र से आता हूं, शहरी क्षेत्र है, समतल है, वहां तो सभी तरह के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, प्राइवेट बस भी मिल जाती हैं, जीप भी मिल जाती है। जो डांग क्षेत्र है, जहां पर बहुत कम सवारियां निकलती हो, वहां केवल और केवल एकमात्र रोडवेज की बस का ही साधन होता है। रोडवेज की बस उस आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बिल्कुल पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ है। गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कमजोर वर्ग से होते हैं, जो पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं। सरकार ने 876 बस खरीदने का प्रावधान किया, उसमें 51 बस तो आबंटित ही हो चुकी हैं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इन बसों से हमको फायदा होने वाला है, वह बहुत ही सराहनीय होगा क्योंकि रोडवेज़ की स्थिति अपन सुनते आए हैं, देखते आए हैं, काफी खस्ता हो गई है, कमजोर है, लेकिन जिस तरह के सुधार हुए हैं ऑनलाइन सिस्टम है, उससे काफी फायदा हुआ।

दूसरा, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा कि जिस तरह का ऑनलाइन सिस्टम से काम बढ़ा है, तो जिस तरह से फ्लाइट मोड पर रिजर्वेशंस होते हैं, सीटों के आधार पर अगर इन बसों में भी और वोल्वो वगैरह बसों में भी यह और किया जाये तो मैं सोचता हूं काफी फायदेमंद होगा क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार वोल्वो बसें 5-5, 6-6 सवारी लेकर भी निकलती हैं। अगर प्रोपर

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

तरीके से इसको समझा जाये और यह देखा जाये कि सीटों की संख्या के आधार पर 25 प्रतिशत इस रेट में हों, 50 हो जाएं तब यह रेट हो जाये, 75 हों तब इस रेट पर हो जाएं, और जब पूरी भरें तो उस रेट पर हो जाएं तो मेरे ख्याल से गाड़ी के किराये का जो पूरा का पूरा हिसाब है, वह भी बहुत अच्छा बैठ सकता है। सवारियां भी ठीक मिल सकती हैं और आम आदमी को भी फायदा मिल सकता है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में तो यही चीजें हैं जो जितना जल्दी पायेगा, आज मैं जाना चाहता हूं, आज अगर कोई फ्लाइट में जाएगा तो उसको हो सकता है दिल्ली के लिये 5000 रुपये, 4000 रुपये जमा कराने पड़ें, लेकिन अगर वह 15 दिन पहले कराता है तो वही व्यक्ति 1800 और 2000 में भी अपनी यात्रा कर सकता है तो उसका फायदा हमको देना चाहिए, जिससे आम आदमी को फायदा मिले। मेरा यही निवेदन है।

अभी स्वचालित यात्री घोषणा और यात्री मनोरंजन के लिये जिस तरह के सरकार ने प्रावधान रखे हैं, उससे इन लोगों को फायदा मिला है। वहां पर जब यात्री वेट करता है तो उसको मनोरंजन के साधन मिलते हैं और आटोमेटिक घोषणाएं होती हैं, उससे भी उसको फायदा मिलता है।

शौचालय निर्माण को लेकर भी काफी सुधार हुए हैं। उसमें मैं तो यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो छोटे रोडवेज बस स्टैण्ड हैं, वहां भी सुलभ शौचालय जैसी सुविधा देने का सरकार काम करे तो इससे भी जनता को ज्यादा फायदा मिल सकता है।

अभी मेरे साथी ने ग्रामीण सेवा की बात की। यह वास्तविकता में एक अच्छी योजना है। इसको लगातार कंटीन्यू रखना चाहिए। ग्रामीण परिवहन से वह स्थान, जहां कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे डांग क्षेत्र को मिलता है, हमारे विधायक मलिंगाजी बैठे हुए हैं, हमारा पूरा का पूरा ही डांग, ऐसा क्षेत्र है जिसमें केवल और केवल ग्रामीण सेवा ही सफल हो सकती है क्योंकि यह जो प्राइवेट बसें हैं, उनको पैसा चाहिए और अच्छी जगह चाहिए। सरकार का नियम है और सरकार की जो नीति है, उसमें हम ही लोगों को और हमारे लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक सेवा की बात आई है और सरकार की मंशा भी है। आज अख़बार में भी इस मामले में कुछ छपा है, कुछ हर्डल लगा है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस ओर आप विशेष ध्यान रखें। प्रदूषण को खतम करने के लिये इलेक्ट्रिक सेवा को तो आगे बढ़ाना ही होगा, और खास कर पहले हमारी जो

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

रोडवेज की बसें बीकानेर हाउस से चलती थीं, उनको कोर्ट की वजह से वहां से हटाया गया है। अगर इलेक्ट्रिक बसें होंगी तो मेरे ख्याल से वापस उनके परिचालन में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हर्डल्स हैं, उनको आप खतम करें और इस ओर अपना आगे काम करें।

अभी जो योजना सरकार लाई है और जो कर रही है, उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज जो देखने को मिली है, कर्मचारियों को तनावमुक्त करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं, पूरा का पूरा ही घर से बाहर रहते हैं। घर से बाहर रहने के बाद में उनको कंटीन्यूएशन में जिस तरह से बसों में रहना पड़ता है, तो एक तनावमुक्त होना और घर की समस्या खतम होना और उसके साथ-साथ, मेडिक्लेम को सरकार, जो एक नये तरीके से कैशलेस के तरीके से लाये हैं, वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है।

एक जो सबसे बड़ा राजस्थान सरकार का मिड-वे हुआ करता था बहरोड़, पता नहीं किन कारणों से और कैसे यह क्यों खुर्दबुर्द हुआ। आज हम जब जाते हैं तो देखते हैं, क्योंकि मैं भी रोडवेज में सफर करता हूं तो कभी किसी होटल पर रुकते हैं, कभी किसी में रुकते हैं। एक जमाना हुआ करता था, जहां बहरोड़ का जो मिडवे है, इतना बेहतरीन पोजीशन में चल रहा था और इतनी अच्छी खुशबू थी कि हर आदमी, हर व्यक्ति, लम्बी लाइन लगती थी गाड़ियों की, अच्छा आहार वहां उपलब्ध होता था। मैं चाहूंगा मंत्रीजी से कि उस मामले में सरकार बहुत अच्छी पहल करके जल्दी से जल्दी उसको करे। इससे रोडवेज को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। एक बहुत बड़ी प्रोपर्टी, जो मिडवे है, वह भी सुचारु रूप से चल पायेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो एरिया है, उस एरिया में काफी बसेज बंद हुई हैं, कुछ हम चलाना चाहते हैं। उसमें ऐसे-ऐसे एरियाज हैं, अगर आप नोट करेंगे और वहां पर उन बसों का आप परिचालन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत, सबसे ज्यादा फायदा हमारे ग्रामीणों को, हमारे डांग क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जिसमें बसेड़ी से नादनपुर होते हुए सरमथुरा की बस है। एक बसेड़ी-धौलपुर-आगरा-भरतपुर की बसें हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि बसेड़ी से धौलपुर बसें, जो अभी बीच में बंद की गई हैं, उनको पुनः चालू किया जाये। डांग क्षेत्र में बसेड़ी से बाड़ी, मदनपुर, गोलारी, दोंध और सेवरपाली, डोमपुरा, चलाचोंध, यह ऐसा रूट है, जिसमें पूरा का पूरा ही डांग क्षेत्र है। मेरे ही नहीं, बाड़ी क्षेत्र को भी इसका फायदा मिलेगा। एक बोरसा बस चला करती थी, जो

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

बसेड़ी से बहुत ही लोकप्रिय सेवा है। उसको पुनः चालू करने की कृपा करेंगे।

दूसरा, एक लम्बे रूट की बस हुआ करती थी, पहले चलती थी धौलपुर से सीकर वाया बसेड़ी-बयाना, क्योंकि यह ऐसा आफ-रूट है, यहां अगर दिन में बस मिल जाये तो, ट्रेन का भी कोई रूट नहीं है, ऐसे अगर ये चलेगी तो हमको बहुत बड़ा फायदा होगा।

दूसरा, अभी मेरे यहां माननीय गहलोत साहब ने, सरकार ने एक महाविद्यालय खोला है, कृषि महाविद्यालय। उसका काम चालू हो गया है, एडमिशन चालू हो गये हैं, बच्चों की पढ़ाई चालू हो चुकी है। उसके लिये, क्योंकि वह आफ-रूट पर है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस कृषि महाविद्यालय के लिये एक बस, जो बच्चों को सूट करती हो, वह चलाई जाये, जो कि धौलपुर से होते हुए सेपऊ, बसेड़ी और खेमड़ी तक वह पहुंचे, जिससे बच्चों का आवागमन कमप्लीट हो सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बसेड़ी-भरतपुर वाया जगनेर-रूपवास क्षेत्र है, इसको भी राष्ट्रीयकृत घोषित करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद। सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पर चर्चा के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं यह कहना चाहता हूं, परिवहन सेवाओं में राजस्थान की जनता का अगर विश्वास है तो वह राजस्थान रोडवेज है। जहां भी, जिस भी रूट पर राजस्थान रोडवेज की अगर बस उपलब्ध है तो राजस्थान की जनता सबसे पहले प्रिफर करती है राजस्थान रोडवेज की बस में सफर करना। उसका सबसे बड़ा कारण बहुत सारी सुविधाएं और सुरक्षा है। यात्रियों को, हमारी आम जनता को लगता है कि राजस्थान रोडवेज की बस में सफर करने से हम सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और हम निजी गंतव्य पर जरूर पहुंचेंगे।

साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारी दिक्कतें भी हैं जिनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस चर्चा में भाग लेते हुए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत सारे नवाचार इसमें किये हैं, और जो समय रहते-रहते होने भी चाहिए थे। आपने जैसे, जी.पी.एस. सिस्टम, सी.सी.टी.वी. कैमरा, इन चीजों को जोड़कर जनता

(श्री सुरेश टाक)

का विश्वास राजस्थान रोडवेज के प्रति और बढ़ाया है। जनता बहुत स्वतंत्र होकर अपनी सुरक्षा को महत्व देते हुए रोडवेज में सफर करने को अधिक महत्व देगी।

साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां-जहां भी रोडवेज के बस स्टैण्ड हैं, वहां तो सुविधाएं बढ़ाई जाएं और जहां पर रोडवेज के बस स्टैण्ड नहीं हैं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की बात करता हूं, अभी एक नया रोडवेज बस स्टैण्ड बना है, वह वहां के एक भामाशाह आर.के. चैरिटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट की तरफ से बना है। वह बहुत ही शानदार रोडवेज बस स्टैण्ड बना है। मैं इसी तरह चाहता हूं कि राजस्थान में और भी जगहों पर ऐसे भामाशाहों को आगे किया जाये और रोडवेज की सुविधाओं को बढ़ाया जाये ताकि बस स्टैण्ड आधुनिक बनें और जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

किशनगढ़ में पुराना बस स्टैण्ड बना हुआ है, लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, आप उसकी स्थिति देखिये, वहां पर शौचालय तक नहीं है। अगर है तो वह ऐसी स्थिति में है कि वहां एक सैकण्ड के लिये भी खड़ा नहीं रहा जा सकता। वहां बस स्टैण्ड के अन्दर सड़क नहीं है, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। आज भी बहुत सारी बसें वहां से संचालित हो रही हैं। ग्रामीण परिवहन तो अधिकतर वहीं से ही संचालित हो रहा है। उसके बावजूद वहां पर शौचालय नहीं हैं, न महिलाओं के लिये और न पुरुषों के लिये। न ही बैठने के लिये अच्छी चैयर्स हैं, न ही वहां अंदर कोई सड़क बनी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने इसमें लिया है, बहुत सारे शौचालय निर्माण और सुविधाओं के लिये, तो किशनगढ़ को प्राथमिकता दें कि किशनगढ़ के पुराने बस स्टैण्ड पर शौचालय का निर्माण हो और वहां अन्दर की जो सड़क टूटी हुई है, उस सड़क की मरम्मत हो या वह सड़क नई बने। उसकी साफ-सफाई सुनिश्चित हो, ऐसी व्यवस्था भी आप वहां पर करें।

जब आप इतनी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं तो सबसे पहली सुविधा स्वच्छता है। उसका आप पूरी तरह ध्यान दें, ताकि वहां की सुविधाएं बढ़ें। अभी सभी मेरे से पूर्व जितने भी माननीय सदस्य हैं, सबने ग्रामीण परिवहन बस सेवा के लिये आपको बोला है। मैं भी यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ग्रामीण परिवहन की जो सेवा है, उसको बहुत अधिक स्तर पर बढ़ाया जाये क्योंकि शहरों में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, गांवों में किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं हैं, जहां पर छात्र-छात्राओं को, मजदूरों को, बहुत

(श्री सुरेश टाक)

सारे किसानों को आने-जाने की सुविधाएं मिलें और उसके लिये राजस्थान रोडवेज की बस उनको उपलब्ध हो। विगत दो-तीन वर्षों से बहुत सारी बसें जो किशनगढ़ के लिए बंद कर दी गई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसी बसों को वापस चालू किया जाए।

विशेष तौर से, अजमेर-किशनगढ़ के बीच में एक शटल सेवा चालू थी जो कम से कम आठ से दस फेरे लगातार अजमेर और किशनगढ़ के बीच में करती थी पर आज वह केवल दो फेरे कर रही है। उसके पीछे क्या कारण है, वह मुझे समझ में नहीं आता परंतु इतनी सवारियां इंतजार करती हैं, इसकी वजह से अवैध परिवहन चालू है। जो प्राइवेट बसें हैं, वह उसका फायदा उठा रही हैं। प्राइवेट टैक्सियां उनका फायदा उठा रही हैं, इससे रोडवेज को राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है लेकिन साथ में आम जन को संसाधन उपलब्ध नहीं होने से एक प्रकार से परेशानी भी खड़ी हो रही है तो मैं यह चाहूंगा कि किशनगढ़ और अजमेर के बीच जो शटल सेवा थी, उसको पुन: चालू करें और उसके कम से कम आठ से दस फेरे हों, क्योंकि इतने यात्री मिल रहे हैं कि आप आराम से आठ से दस फेरे अजमेर-किशनगढ़ के बीच में कर सकते हैं तो इसको वापस नियमित रूप से चालू किया जाए।

साथ में, बहुत सारे जो ग्रामीण रूट हैं उन पर मेरी बसें बंद हो गई हैं। मैं यह चाहूंगा कि उन बसों को भी आप चालू कराएं जिससे रेवेन्यू का फायदा भी विभाग को मिले और साथ में ग्रामीण लोगों को आवागमन का साधन भी उपलब्ध हो, छात्र-छात्राओं को अपने कालेज में, अपने विश्वविद्यालयों में जाने के लिए साधन उपलब्ध हो, किसानों को मंडियों में आने-जाने का साधन उपलब्ध हो।

पहले अजमेर से सांभर एक बस चलती थी, विगत तीन साल से वह बस चालू नहीं है। इस बस से मेरे कई गांव जुड़े हुए थे ग्राम नलू, कांकनियावास होती हुई यह बस जाती थी, जो सांभर पहुंचती थी। यह बस बहुत दिनों से बंद है, इस बस को चालू कराएं।

अजमेर से रामनेर की ढाणी चलने वाली बस जो वाया किशनगढ़ होकर जाती थी, वह भी बंद कर दी गयी है। बहुत सारा रेवेन्यू इससे मिलता था। बहुत सारे लोगों को साधन उपलब्ध होता था, वह नहीं मिल रहा है।

अजमेर से नौसल चूंकि, मेरा विधान सभा क्षेत्र तीन-चार विधान सभा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है पुष्कर, किशनगढ़, केकड़ी, अजमेर, नसीराबाद, इस प्रकार

(श्री सुरेश टाक)

से बहुत सारे विधान सभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं यह सब मेरे विधान सभा क्षेत्र के आस-पास हैं और इन पर आने-जाने के लिए हमारा किशनगढ़ एक सेंटर है, जहां पर सब लोग आना चाहते हैं तो यह जो अजमेर-नौसल चलने वाली बस है, वह किशनगढ़ होते हुए ग्राम बबायचा, कुचील, सलेमाबाद होकर चलती थी, वह भी बंद कर दी गई है, इसे चालू कराया जाए।

अजमेर से मालपुरा हर तीस मिनट में एक बस जाती थी जो आज तीन घंटे अंतराल में यह बस जा रही है जबकि इतने जबरदस्त यात्री आपको वहां पर मिलेंगे, उसके बाद भी यह बसें पता नहीं किस कारण से बंद कर दी गईं। यह नहीं पता लेकिन अब आज जब आप रोडवेज बेड़े में 876 बसें शामिल करने जा रहे हैं, ग्रामीण परिवहन की बसें बढ़ाने जा रहे हैं तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों को विशेष रूप से जोड़ा जाए।

अजमेर से डिग्गी चलने वाली बस बंद कर दी गई है। अराई, सपोंदा वाली बस बंद कर दी गई है। किशनगढ़ से नसीराबाद जो बसें चलती थीं वाया गोदीयाना, श्रीनगर होते हुए, यह भी बंद कर दी गई।

अजमेर-सिनोदिया, वाया सलेमाबाद, रूपनगढ़ होती हुई बसें जा रही थीं, वह बसें बंद कर दी गईं।

अजमेर-हरमाड़ा, किशनगढ़ होकर जो बसें जा रही थीं, वह बंद कर दीं।

अजमेर-सरवाड़ वाया आकोडिया, लाम्बा, ढसूक होती हुई जो बसें जा रही थीं, वह बंद हो गईं।

जयपुर से बोराड़ा चलने वाली बस जो कि वाया लाम्बा, दांतरी, आकोडिया होते हुए जाती थी, वह बंद कर दी गई।

अजमेर से बोराड़ा चलने वाली दो बसें जो कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ती है, यह बंद कर दी गई।

अजमेर से कोटा चलने वाली बस जो कि ग्राम बोराड़ा व डबरेला होते हुए जाती थी, उसको भी बंद कर दिया गया है।

हमारे पास में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र है, जहां पर मनोहरपुर पंचायत मेरे लगती है और बोराड़ा पंचायत लगती है, बहुत नजदीक के क्षेत्र हैं। केकड़ी लोगों का आना-जाना बहुत रहता है। मैं यह चाहूंगा कि केकड़ी से दो बसें

(श्री सुरेश टाक)

चलाई जाएं, जिससे मेरा विधान सभा क्षेत्र जुड़ जाए और मेरे लोगों को केकड़ी के आवागमन के लिए साधन उपलब्ध हो जाए।

मेरा आपसे आग्रह है कि काफी समय से बंद उक्त सभी बसों का संचालन यदि आप पुन: शुरू करा देंगे तो किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों, व्यापारियों, छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों एवं अन्य सभी यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे।

साथ में, मैं यह चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसें चलती हैं उनका जो बस स्टाप है, जैसे आज जो बस स्टाप बोराड़ा हो रहा है, उसको अगर मनोहरपुर कर दिया जाए तो बीच के सारे गांव जुड़ जाएंगे और मनोहरपुर से आने वाले जो लोग हैं, उनको भी साधन मिल जाएगा तो इन बसों का स्टाप बढ़ा दिया जाए ताकि रात्रि स्टापेज को आगे कर दिया जाए ताकि दो-तीन गांव आपको और मिल जाएंगे और आपको रेवेन्यू का भी लाभ होगा और संसाधन भी लोगों को मिल जाएंगे।

एक विशेष बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि रात्रि के समय अजमेर से जयपुर चलने वाली बसें अभी तक बाई पास से निकल रही हैं, यह बाई पास से नहीं निकले क्योंकि अजमेर से जयपुर का बहुत सारा यात्री भार है जो किशनगढ़ में भी है। किशनगढ़ एक औद्योगिक नगरी है और लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा जयपुर और अजमेर के लिए होता है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह बसें जो रात को आठ बजे से सुबह सात बजे तक बाई पास होकर निकलती हैं, उनको किशनगढ़ शहर के अंदर से निकाला जाए ताकि यात्री भार के साथ-साथ यात्रियों को सुविधाएं भी मिलें और आपको रेवेन्यू का लाभ भी मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी किशनगढ़ में एयरपोर्ट भी बन गया है और रेलवे स्टेशन भी किशनगढ़ से बाहर बन गया है जो कि एन.एच. 79 पर है। वहां पर यात्रियों को आने-जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। अगर वहां पर आप बस स्टाप स्वीकृत कर दें तो मैं किसी भी एन.जी.ओ. से बस स्टाप बनवा दूंगा लेकिन केवल आप वहां पर स्वीकृत कर दें ताकि रोडवेज की बस वहां पर रुके और यात्रियों को ले ले। जो रेलवे से सफर करने वाले यात्री हैं, उनको वहां पर उतरने और चढ़ने का मौका मिलेगा और जो एयरपोर्ट आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एयरपोर्ट में जाने वाला यात्री रोडवेज में सफर नहीं करेगा। अगर साधन उपलब्ध है तो वह जरूर करेगा और

(श्री सुरेश टाक)

वहां पर बहुत सारी कालोनियां हैं, जो इसके आस-पास पब्लिक रहती है, उनको भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो मजदूर और व्यापारी आते हैं, उनको भी यह सुविधा मिल जाएगी। बस स्टाप तो मैं एन.जी.ओ. से बनवा दूंगा लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप वहां पर बस स्टाप की स्वीकृति कराएं।

माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आज यहां पर अपने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के ऊपर यह चर्चा रखने की अनुमति दी और जिस पर आज यह चर्चा हो रही है और बहुत सारे ऐसे अच्छे सुझाव जो हमारे राज्य सड़क परिवहन विभाग को मिलने चाहिए और कुछ कमियां हैं, वह उसकी उजागर भी हो और उसमें सुधार भी हो, इसी अपेक्षा के साथ मैं भी अपने विचार यहां पर रखना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक जन घोषणा पत्र इस चुनाव से पूर्व जारी हुआ था और कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया था कि यह जन घोषणा पत्र यही हमारा प्रोग्राम होगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसी के अनुसार सारे काम करेंगे और उसके बाद में उसको एक आफिशियल डाकूमेंट भी बना दिया गया। इसमें सड़क एवं परिवहन के लिए जो लिखा गया था, उसमें कहा गया था कि ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों एवं ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना। यह उसके अंदर लिखा था, हम यह काम करेंगे।

इसके अलावा, इन्होंने यह कहा था कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को यथावत चालू रखा जाना, निगम के कर्मचारियों की मांगों के समाधान पर सकारात्मक निर्णय तथा निगम की बसों की संख्या एवं मार्गों में वृद्धि तथा निगम को सुदृढ़ बनाने हेतु ठोस नीति का निर्धारण करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 14 महीने हो गये इनकी सरकार को आये और इन 14 महीने में जो स्थितियां बनी हैं वह हम सबके सामने है। मुझसे पहले भी कई वक्ताओं ने यह सारी बातें कही हैं और बताया है कि किस प्रकार से जो स्थितियां आज रोडवेज की हो रही हैं, बसें नहीं मिल रही हैं, गांवों के अंदर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, सड़कें इतनी अच्छी बन गई, उसके बाद में भी बसें नहीं चलना, यह सारी चीजें हैं।

हमारे माननीय मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं भी आपके माध्यम से उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहती हूं। लोक परिवहन सेवा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी इन्होंने इसको बंद कर दिया क्योंकि हाईवेज के ऊपर जहां पर रोडवेज के पास में बसें नहीं थीं, वहां पर यह लोक परिवहन की सेवा शुरू की गई थी और जिसके माध्यम से जनता को बस की एक सुविधा मिल रही थी लेकिन यह जो प्राइवेट बसें चलती थीं, उन पर प्राइवेट बसें वाले टैक्स भी देते थे। एक-एक बस के ऊपर तीस हजार रुपये तक का टैक्स भी सरकार को मिलता था लेकिन यह इन्होंने बंद की और यह कहा कि हम लोग नई बसें खरीदेंगे। नई बसें खरीदेंगे, इसके स्टेटमेंट्स भी आते रहे, हम लोग भी बड़े खुश थे कि मंत्रीजी के अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक हजार नई बसें खरीदी जाएंगी लेकिन इन 14 महीनों में एक भी नई बस अभी तक नहीं खरीदी गई है और लोगों को उस सुविधा से वंचित रखा गया। एक तरफ तो जो योजना चल रही थी, उसको तो आपने तुरंत बंद कर दिया। आप बसें खरीद लेते उसके बाद में बंद करते तो समझ में आता।

आज यह स्थिति है कि अगर मैं मेरे राजसमन्द जिले की ही बात करूं तो वहां पर जब पहले 47 बसें हमारे वहां पर डिपो में थीं, आज वहां पर मात्र 20 से 22 बसें रह गईं, यानी 50 परसेंट से भी कम बसें अवेलेबल हो गईं। आज स्थिति इतनी खराब है कि आज गांव का हर व्यक्ति उतने पैसे वाला नहीं होता है कि वह अपनी कार मैन्टेन करे और गाड़ी से आए-जाए लेकिन जो एक बस थी, जिस बस से माताएं-बहनें भी अपने आ-जा सकती थीं और भी लोग आ-जा सकते थे लेकिन इन्होंने यह सारी बस की सेवाओं को, बहुत ही ज्यादा एक तरह से वह प्रभावित हो गई और स्थिति बहुत खराब हो गई।

जो इनका एस.आर.टी., आप जो स्पेशल रोड टैक्स लेते थे, वह 300 किलोमीटर के ऊपर 300 रुपये पर सीट इन्होंने किया था फिर जब हमने पिछली बार इनसे रिक्वैस्ट की थी तो इन्होंने 300 से घटाकर उसको 250 रुपये किया था और 150 किलोमीटर जो हम लोगों ने कहा था आपको कि गांव के अंदर जब बसें चलती हैं तो 150 किलोमीटर का मिनिमम यह रहता है तो उस 150 किलोमीटर के ऊपर आपने 250 रुपये किया। माननीय सभापति

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि उस 150 किलोमीटर को 250 रुपये नहीं करके उसको 150 रुपये ही करें और फिर उसको हर 25 किलोमीटर में आप बढ़ाइए। अगर आपका 175 किलोमीटर चलता है तो आप 175 रुपये पर सीट ले लें। अगर आपका 200 किलोमीटर चलती है तो 200 के हिसाब से 200 रुपये पर सीट ले लें लेकिन यह 150 किलोमीटर के ऊपर 250 रुपये पर-सीट यह बहुत ही मंहगा हो रहा है, जिसकी वजह से यह प्राइवेट बसें चलने में बड़ी परेशानी आ रही है।

(14.00 बजे)

दूसरा, एक उप-नगरीय मार्ग जो आपने घोषित किये हैं, यह उप-नगरीय मार्ग, माननीय सभापति महोदय, यह सभी संभाग मुख्यालय को इन्होंने लिया है। सातों ही संभाग मुख्यालय पर उप-नगरीय मार्ग दिये हैं, जो नेशनल हाईवेज के ऊपर ये बसेज चल सकती हैं और इसके साथ ही इन्होंने दो जिले और जोड़े हैं, जो भीलवाड़ा और अलवर है और उसके पीछे उन्होंने रीजन यह दिया है, क्योंकि वह औद्योगिक क्षेत्र है वहां नेशनल हाईवे के ऊपर, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि राजसमंद जिला, जो हमारा है, वह भीम से शुरू होता है और देलवाड़ा तक, जहां पर हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी की कांस्टीट्यूएंसी से होते हुए हम उदयपुर जब जाते हैं तो वहां तक पूरा नेशनल हाईवे एन एच 8 के ऊपर चलता है। इसी प्रकार अगर हम कुंभलगढ़ एरिया से लें तो कुंभलगढ़ से लेकर गंगापुर तक यह नेशनल हाईवे 76 है, जिस पर पूरा राजसमंद जिला चलता है। टोटल नेशनल हाईवे के ऊपर यह राजसमंद जिला है और उसको भी उप-नगरीय मार्ग के अंदर विशेष छूट देकर जैसे आपने भीलवाड़ा और अलवर को लिया है, उसी प्रकार राजसमंद को भी इसके अंदर दिया जाए और उप-नगरीय मार्ग यहां के लिये घोषित किया जाए। इसकी मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करती हूं।

साथ ही, एक योजना है ग्रामीण क्षेत्र योजना, जिस ग्रामीण क्षेत्र योजना के अन्दर एक तहसील के अंदर ही वह रूट चलेगा। आपने कहा कि उन बसेज के चलने की परमिट मिलेगी वह उस तहसील के अंदर ही होगा, यह ग्रामीण क्षेत्र योजना के अंदर है। हमारी आपसे रिक्वैस्ट यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्र को तहसील से दूसरी तहसील तक भी उसको जोड़ दें। अगर राजसमंद को हम लेते हैं तो राजसमंद से रेलमगरा एक तहसील से दूसरी तहसील आ जाती है। अब वहां जो रूट की बसेज आप कह दोगे कि राजसमंद तहसील के अंदर राजसमंद की बसेज ही चलें और रेलमगरा तहसील में रेलमगरा का रूट ही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ओपन होगा तो यह न होकर वह रूट ओपन हो जाए इंटर-तहसील, जो आज की तारीख में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्राइवेट बसेज जो सुविधाएं गांवों के अंदर दे सकती हैं, गांवों में बसेज चला सकते हैं, वह उनको परमिट नहीं मिलने की वजह से बहुत ज्यादा प्राब्लम में आ रहे हैं तो इस रूट को आप खोलें और इसके अंदर आप एक तहसील से दूसरी तहसील के अंदर भी करें, क्योंकि बहुत सारी बसेज पहले राजसमंद के अंदर 1100 प्राइवेट बसें चलती थीं, आज स्थिति यह है वह 250 बसों के ऊपर आ गये। मात्र 250 बसें पूरे जिले के अंदर लें तो सिर्फ 250 हैं, तो क्यों यह इतनी गिरावट आयी। प्राइवेट बस मालिकों को प्रोफिटेबिल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसको तहसील के अंदर ही बांधकर रख दिया। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक उसको जोड़ने की बात करें कि हर तहसील से वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के ऊपर आ सकता है तो वह इंटर-तहसील भी हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जुड़ने के रूट्स दिये जाएं।

ऐसे ही जो यात्राओं के लिये बसें जाती हैं और जो बारातों के अंदर बसें जाती हैं, उनके लिये कहा जाता है कि वह स्पेयर बसेज होती हैं, जिनके लिये कोई रूट की परमिट नहीं ली जाती है लेकिन वह स्पेयर बसेज में होती हैं, इन स्पेयर बसेज के ऊपर आपने बहुत ज्यादा टैक्स रखा है। एज ए रिजल्ट, यह जो स्पेयर बसेज हैं, वह टैक्सेज इतना ज्यादा पे करना, फिर सीजन के अंदर ही उनकी बारात के लिये वह बसेज यूज में आती हैं या यात्राओं के लिये वह बसेज यूज में आती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें क्या करना होता है कि वह कोई न कोई रूट का परमिट लेते हैं फिर उस रूट के ऊपर चलाने की परमिट लेते हैं, क्योंकि रूट पर चलाने की परमिट का टैक्स कम है और यह जो स्पेयर बसेज हैं इनका जो चार्जेज है, वह ज्यादा है तो इस वजह से उसका परमिट लेकर फिर वह चलाते नहीं हैं और उसके बाद में जब वह चलाएंगे तो उनको यात्रा पर ले जाना है या कहीं और ले जाना है।

मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना है कि संभाग मुख्यालय के लिये इनको परमिट दे दें। यह जो स्पेयर बसेज हैं, एक तो उनका टैक्स कम करिए। जो टैक्स आप ले रहे हैं, वह उनके ऊपर कम होने चाहिए और साथ ही उनको जो परमिट दें, वह संभाग का परमिट दे दें। उससे क्या होगा माननीय सभापति जी, कि जो यात्रा पर जाते

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैं, जैसे आज मातृकुण्डिया यात्रा पर हम लोग जाते हैं, आज चारभुजा जी यात्रा पर अगर राजसमंद से कोई जाता है तो यह यात्रा की जो बसें हैं, वह कम से कम एक संभाग के अंदर, त्रिपुरा सुंदरी जाना है तो वह पूरे संभाग को कवर कर लेगी तो उनकी वह जो स्पेयर बसेज हैं, उन स्पेयर बसेज का फायदा मिलेगा, वहां के लोगों को उसका फायदा मिलेगा और वह सुविधा उनको उपलब्ध होगी।

इसी तरीके से इनके यहां पर विभाग में 2016 से जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, वह ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भी उनको नहीं मिल रही है इतने सालों से और इसके साथ-साथ उनके अवकाश के बदले में जो नकद पैसा मिलना चाहिए था, वह भी उनको नहीं मिल रहा है, जो लगभग 400 करोड़ के करीब है। वह भी जल्द से जल्द भुगतान उनका होना चाहिए। ऐसा भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

दूसरा क्लस्टर रूट्स जो सरकार में 2008 से 2013 में निकाले थे और उन क्लस्टर रूट्स के अंदर यह कहा गया था कि जो भी बस मालिक, जिसके पास कम से कम 25 बसें हैं, वह उन 25 बसों को क्लस्टर रूट्स पर गांवों के अंदर वह चला सकेगा। उन गाड़ियों के लिये गवर्नमेंट ने अनुदान दिया। गवर्नमेंट की बसेज वहां पर चलीं और वह अनुदान सरकार के माध्यम से दिया गया और उसके बाद में वह जो बसेज चलीं, वह इन्होंने एस आर कंपनी से बसेज खरीदी थीं। जब 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और जो बसेज चल रही थीं, वह सारी ऐसी कंडम स्थिति में थीं कि वह बिलकुल खतम हो गयी थीं। अब वह वापस उसी क्लस्टर रूट्स को चलाने की यह बात कर रहे हैं। फिर से नई बसेज खरीदनी हैं। फिर से सरकार से अनुदान उनको देना है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात तो पूरी हो जाने दें।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपके माध्यम से यह रिक्वैस्ट है कि अगर आप प्राइवेट बस मालिक को ही वही 12 रुपया पर किलोमीटर अनुदान देंगे तो आपको नई बसें नहीं खरीदनी पड़ेंगी और वहां पर ग्रामीण क्षेत्र

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के अंदर वह बस की सुविधाएं उनको मिल जाएंगी और उसमें ऐसी कोई अनिवार्यता मत रखिए कि कम से कम 25 बसों का मालिक होगा, वही चला सकेगा। आप उसको छोटा करिए, क्योंकि जो छोटे बस मालिक हैं, तीन से पांच बसेज जो रखते हैं, ऐसे बस मालिक भी उन बसेज को चलाएंगे तो हमारा मेन मकसद यह है, माननीय सभापति महोदय, कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बस की सुविधा मिले। वह बस की सुविधा नहीं मिल पाने पर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और जब कभी भी अपने क्षेत्र में जाते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्या, प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माता-बहनें एक ही रिक्वैस्ट करती हैं कि हमारे यहां बस की सुविधा दो। हम लोग कैसे जिला मुख्यालय पर पहुंचें।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना। प्लीज सहयोग करिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कन्क्लूड कर रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, इसको कन्क्लूड कर देते हैं। एक आडिटर आफ जनरल से आडिट हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने स्पेसिफिक बात कही है। माननीय सभापति महोदय, इसमें उन्होंने कहा है कि "however, the physical verification of land and building was not conducted" जो सबसे इम्पोर्टेंट है।

श्री सभापति: अब आप धन्यवाद दीजिए। प्लीज सहयोग कीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गवर्नमेंट की लैण्ड और बिल्डिंग का किसी तरीके का फिजिकल वैरिफिकेशन नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री गोपाल लाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: मैं फिर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं 10 मिनट में आपको आवश्यक रूप से समाप्त करना है। 30 से ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है और उसमें मुझे भी आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया,

(श्री गोपाल लाल मीना)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान परिवहन निगम, जो पिछली सरकार में बीमार हो गया था, हमारे मुख्य मंत्री और आदरणीय हमारे मंत्री महोदय ने परिवहन निगम को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि आपको पता है कि 2012 में ग्रामीण बस सेवाएं चालू की गयीं, लेकिन पूर्व सरकार ने इन्हें बंद कर दिया जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसान, मजदूर, छात्र, युवा इनको बहुत बड़ी परेशानी हुई। मैं तो सरकार ये सही निवेदन करना चाहूंगा और आदरणीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आपको काम करना है तो ग्रामीण बस सेवाएं पुन: चालू की जाएं ताकि उन दूर-दराज बैठे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। राजस्थान का जो गरीब तबका है, वह परिवहन से जुड़ सके। आज नई बसेज खरीदने का राज्य सरकार ने काम किया है और आगे करने जा रही है। इलेक्ट्रोनिक बसें खरीदने का काम कर रही है और जो बस स्टैंडों पर सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है, उनको नये बस स्टैंड पर शौचालय बनाने का काम किया जा रहा है। यह तमाम चीजें आपके परिवहन निगम को फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं।

मैं समझता हूं कि यात्रियों का भार धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो 2018-19 में 73 प्रतिशत था वो 2019-20 में 76.05 परसेंट बढ़ा है। इससे लग रहा है, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय को यह पता है, क्योंकि वो पहले प्राइवेट बसों के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको पता है कि किस प्रकार बसें चलाई जाती है और राजस्थान के इस बस ढांचे को निश्चित रूप से सुधारेंगे और इस परिवहन निगम को जो आज घाटे में चल रहा था उसको फायदे में पहुंचाकर रहेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। इनको काम करने का तरीका भी है क्योंकि आपको पता है, अभी दो-तीन दिन पहले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे थे तो कोई भी सदस्य बोल रहा था तो उनको यही बात कह रहे थे कि आपके बस लग जाएगी तो यह विश्वास होता है, आत्म-विश्वास होता है और अगर कोई लोगों का विश्वास जीतता है तो मैं समझता हूं कि निगम आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है।

जो ग्रामीण क्षेत्र की बसें पिछले पांच साल में बंद हुई हैं, सभी सदस्यों ने यह मांग रखी है, मैं भी यह मांग रखता हूं कि पांच साल में जो बसें बंद हुई हैं उनको पुनः चालू किया जाए ताकि पूरे राजस्थान के जो गरीब, मजदूर, युवा और छात्र हैं, इनको सबको आने-जाने की सुविधा हो सके।

राजस्थान परिवहन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। राज्य में ग्रामीण

(श्री गोपाल लाल मीना)

सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग से, जहां से बसें चलती हैं, जहां प्राइवेट बसें हैं वो आगे-आगे चलती हैं और बसें इसलिए बंद करवाते हैं कि, साहब, इसमें हमारा पूरा पैसा नहीं आ रहा है इसलिए मैं परिवहन निगम से और मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्राइवेट बसों का जो समय देते हो उस समय को आप इस तरीके से दो ताकि इस बस और उस बस में कम से कम आधा घंटा या एक घंटे का अन्तर हो। अगर वे प्राइवेट बसें चलाकर उन बसों के आगे चलती हैं तो निश्चित रूप से उन पर जुर्माना होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए दिक्कत आती है और कर्मचारी यह कहकर दूर हो जाते हैं कि हमारा तो इसमें पूरा पैसा नहीं आ रहा है इसलिए बस को बंद कर दिया गया है। मैं रोज देखता हूं कि जो बसें जाती हैं उससे प्राइवेट बस पांच रुपये, दस रुपये कम लेती है तो यात्री उसमें बैठ जाते हैं और सरकारी बस खाली चली जाती है इसलिए इनका रेवेन्यू कम होता है और रेवेन्यू नहीं आने से बस वापस बंद करने की बात होती है तो परिवहन विभाग प्राइवेट बसों का टाइम उसी हिसाब से दे ताकि सरकारी बसों का रेवेन्यू भी पूरा आ सके।

दूसरा, मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। हमारे शाहपुरा आगार नया खुला है, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र से जो बसें जाती हैं और अगर शाहपुरा आगार से कोई बस खराब हो जाती है हमारे जयपुर में तो शाहपुरा आगार के आने में बहुत समय लगता है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं, हर व्यक्ति यह कहता है कि हमारे विद्याधर नगर से वापस जोड़ा जाए। और बाकी क्षेत्र उधर के जोड़ दो और जमवारामगढ़ क्षेत्र को पुन: विद्याधर नगर आगार से जोड़ा जाए ताकि बसों में आने-जाने में दिक्कत नहीं हो। एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे क्षेत्र में भी काफी बसें बंद हुई हैं, उनको आप पुन: चालू करवा दें ताकि क्षेत्र में जो परेशानी हो वो परेशानी नहीं रहे। डगोता-बस्सी से दौसा तक वाया नीमला नाभावाला बस की शुरुआत की जाए क्योंकि उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक ऐसी जगह नहीं है और डगोता नई पंचायत बन गई है इसलिए आपको वहां बस चलानी है और यह डगोता-बस्सी से दौसा तक की जो बस सेवा है यह चालू की जाए। वहां लोगों के आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं।

मैं कई बार जाता हूं तो देखता हूं कि कोई कार होती है तो कम से कम 30-40 व्यक्ति उस कार में लटककर जाते हैं तो ऐसी जगह दुर्घटना के भी कारण बढ़ते जाते हैं, वो कारण भी कम होंगे अगर बसें चालू होंगी तो।

(श्री गोपाल लाल मीना)

ग्रामीण बसों का तो मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि अगर ग्रामीण बस चालू हो जाती है तो वो जो छोटी मिनी बस है और वो धीरे-धीरे हर ग्राम को जोड़ती हुई आती है। लोग इतने खुश होते थे, हमारे ग्रामीण बस पुन: चालू हो और चुनाव में भी हमसे सबसे बड़ी मांग यही थी क्योंकि हमारा क्षेत्र दूर-दराज में है, कि आप तो ग्रामीण बस चला देना तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय से बार-बार यही निवेदन करूंगा कि आप ग्रामीण बसें चलाएं और हमारे क्षेत्र में जो तमाम जगह बसें बंद की गई हैं, उनको आप पुन: चालू करवाएं।

आपने जिस प्रकार से इस निगम को आगे बढ़ाने का काम और जिम्मा लिया है उसको आप निश्चित रूप से आगे बढ़ायेंगे।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस परिवहन निगम को आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी और राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि लम्बे अर्से के बाद इस सदन में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम पर चर्चा करने का एक अवसर माननीय सदस्यों को दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो यह यह चतुर्थ सत्र में अभिभाषण पढ़ा गया उसके बिंदु 103 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, 'आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2019-20 में 876 नई सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू लाइन बसों की खरीद हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। प्रदेश में पहली बार 48 इलैक्ट्रिक बसें अनुबंध पर लिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज के राजस्थान पत्रिका में रोडवेज के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट छपा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। रोडवेज चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव का कहना है कि इलैक्ट्रिक बसों के टेण्डर प्रक्रिया शुरू करने से पहले बोर्ड की अनुमति लेनी चाहिए लेकिन पूर्व एम.डी. आलोक ने बिना बोर्ड की अनुमति के ही बसों के टेण्डर जारी कर दिये। पिछले ही दिनों फाइल मेरे पास आई है, जो रेट लगी है उससे रोडवेज को नुकसान होगा। उसी दिन चेयरमैन ने टेण्डर प्रक्रिया ही रोक दी। बोले, बिना बोर्ड

(श्री संयम लोढ़ा)

अनुमति एम.डी. ने किये टेण्डर, जिस दिन मंत्री बोले, भले ही दस इलैक्ट्रिक बसें लाओ ताकि बीकानेर हाउस शुरू हो।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल का यह अभिभाषण जिसमें राज्यपाल महोदय ने कहा है कि बसें खरीदने के आदेश जारी किये गये, कैबिनेट के द्वारा एप्रूव होता है, महामहिम राज्यपाल के द्वारा सदन में पढ़ा गया है, इस सदन में चर्चा के बाद उस अभिभाषण को पारित किया गया है। क्या रोडवज के चेयरमैन के इस वक्तव्य से राज्यपाल ने अपने जिस संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन किया है उस पर प्रश्न चिह्न नहीं खड़ा किया गया? क्या राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन की गरिमा पर इस वक्तव्य से प्रश्न चिह्न नहीं खड़ा किया गया?

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें जब यह बतायें कि क्या यह सारा अभिभाषण असत्य पर आधारित है? क्या आपने जो इस सदन में पढ़ा है उसमें कोई सत्यता नहीं है? आपका एक अधिकारी इसके ऊपर प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहा है और अगर यह सत्य पर आधारित है और अभिभाषण के तथ्य सही हैं और अधिकारी ने गलत वक्तव्य दिया है तो मैं आपको परामर्श दूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से सलाह करके इसी सदन में उस अधिकारी के खिलाफ आज कार्यवाही करने की घोषणा करें।

सभापति महोदय, रोडवेज राजस्थान सरकार के लिए कोई धन कमाने का उपक्रम नहीं है। इसके जरिए रोडवेज हमारे नागरिकों को एक सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ अपने सामाजिक कर्तव्य का भी निर्वहन करता है। हम जानते हैं कि कई सालों से सैकड़ों करोड़ रुपयों के घाटे में रोडवेज है लेकिन इसके बावजूद विमंदित, मानसिक रोगी, फ्रीडम फाइटर, विकलांग, आदिवासी छात्र-छात्राएं, अलग-अलग वर्ग के लोगों को रोडवेज रियायती दर पर निःशुल्क, 75 फीसदी दर पर, 50 फीसदी दर पर, 25 फीसदी दर पर यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। इस तरीके से अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करता है।

सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि यह रोडवेज सदा से घाटे में ही रहा है। रोडवेज लाभ में भी रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, लगातार रोडवेज लाभ में रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता 1990 में पहली बार चुनकर के आए। सही कह रहा हूं? इनके परम मित्र यातायात मंत्री बने। तब से यह घाटे का सिलसिला शुरू हुआ है।

(श्री संयम लोढ़ा)

उसके बाद में सिर्फ 5-6 साल ऐसा अवसर आया, जब कि राजस्थान में ब्रोड गेज का काम चला तो रोडवेज को ज्यादा यात्री भार मिला। रोडवेज लगातार 5-7 साल लाभ के अंदर चला।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक जमात है, जिसने हमेशा जब-जब भी सत्ता में आई, चाहे दिल्ली की हुकूमत में आई, चाहे प्रदेश की हुकूमत में आई, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कमजोर करने का काम किया या इनको बेचने का काम किया। अभी भी पीछे इनकी सरकारें आई तो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ने रोडवेज का बंटाढार कर दिया। पूरी की पूरी परिवहन सेवा को निजी क्षेत्र में ले जाकर के खड़ा कर दिया। राजस्थान में भी इनकी इसी तरह की प्लानिंग थी। यह इसी पर काम कर रहे थे। इन्होंने अपनी पूरी व्यूह रचना कर ली थी कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर रोडवेज को खतम करके निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाए। बेचने की तैयारी थी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): कांग्रेस पार्टी ने किया।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया इनके खिलाफ और संघर्ष किया। उससे यह पीछे हट गए कि यह तो उलटा पड़ जाएगा। इससे यह राजस्थान का रोडवेज यथावत रूप से कायम रहा। इनकी अगर नीयत ठीक होती तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि 5 साल में आपने एक भी रोडवेज का डिपो खोला था? खोला हो तो बताइए? जो 2013 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार छोड़कर के गई थी, आपने बंद करने के काम जरूर किए होंगे, वह की वह 52 की संख्या मौजूद है।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे यातायात मंत्री होते थे छोगाराम बाकोलिया। अपने विधान सभा क्षेत्र रेवदर में डिपो खोला था। जैसे ही इनकी सरकार आई, बंद कर दिया।

सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में रोडवेज का सेवा मार्ग 2009 में 2728 किलोमीटर था। 2018 में इन्होंने कहां लाकर के खड़ा कर दिया? 2230 किलोमीटर पर। जो आय 2017 में इनके शासन में ही 2193.36 करोड़ रुपये थी, 2018 में एक साल बाद में, आपके आखिरी साल में आप कहां पर आ

(श्री संयम लोढ़ा)

गए? 2160 करोड़ पर। आपकी आय घटी। रोडवेज 2014 में 6262 लाख किलोमीटर की यात्रा प्रोवाइड करवा रहा था। उसको घटाकर के 2018 में 5433 लाख किलोमीटर पर ले आए। जो वाहन निजी क्षेत्र के अंदर 2014 में सिर्फ 172 अनुबंध पर थे, उसको बढ़ाकर के 1025 पर ले गए लेकिन इसकी तुलना में निगम के वाहन बढ़ाने का काम इन्होंने नहीं किया।

सभापति महोदय, जो यात्री भार 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी 73 परसेंट था, उसको घटाकर के 2018 में 73 परसेंट पर लाए। मैं राजस्थान के परिवहन मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इनके मार्गदर्शन में 2019-20 में रोडवेज का यात्री भार फिर से 76.5 परसेंट पर आया। 2017 में आपका डीजल औसत प्रति किलोमीटर क्या था, 5.10, और 2018 में क्या रहा, 5.03 था। यह जो अभी डीजल बेचने की बात कर रहे थे। यह अपने आपमें आंकड़े कह रहे थे कि आपका डीजल कहां जा रहा था।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, प्रति किलोमीटर व्यय जो 2013-14 में 33.91 था, वह बढ़ाकर के एक्सपैंडिचर 2018-19 में 41.18 हो गया। इसका मतलब आपका न तो सुपरविजन था, न आपका ध्यान था। कहां पैसा जा रहा है, कहां पैसा लग रहा है, इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। इसी कारण से रोडवेज का घाटा लगातार बढ़ता गया।

यह कर्मचारी विरोधी तो सदा से हैं। दिल्ली में इनकी सरकार आ गई पूर्ण बहुमत की पहली बार तो न्यू पेंशन स्कीम लाकर के पूरे हिन्दुस्तान के कर्मचारियों का गला घोंटने का काम इन्होंने किया। रोडवेज का भी मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोडवेज में 21384 कर्मचारी थे। जो 2018-19 में जब इनकी विदाई की वेला आ रही थी, मात्र 15279 कर्मचारी रह गए।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं बस खतम ही कर रहा हूं। प्रति वाहन कर्मचारी अनुपात 2013-14 में जब 4.64 था, वह 2018 में घटकर के 2.89 हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारियों का यह शोषण कर रहे थे। 2013 में परिचक्र रोडवेज के 10635 थे, वह घटकर 2018-19 में 9574 रह गए। यात्री भार 2013 में 9 लाख 50 हजार था, वह घटकर के 2018-19 में 8 लाख 57 हजार रह गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माउंट आबू राजस्थान की पर्वतीय राजधानी है। खुद महामहिम राज्यपाल अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको बनाते हैं। 27 लाख लोग हर साल माउंट आबू में आते हैं। मेरी आपसे विनती है कि वहां के बस स्टैंड का एक बार दौरा करें। आप देखें कि यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है? आए दिन टूरिस्ट के साथ मारपीट की घटना होती है। बहुत अच्छा होगा कि आप रोडवेज के कर्मचारियों को प्राणिक हीलिंग का लाभ दें या इनको विपश्यना में भेजें जिससे कि इनका बिहेवियर सुधर सके। हमारे रोडवेज के एम्प्लायी, हमारे कंडक्टर पैसेंजर फ्रेंडली नहीं हैं। इस कारण से भी दिक्कत होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी विनती करना चाहूंगा कि सिरोही का बस स्टैंड बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। आपसे विनती करुंगा कि उसके लिए भी धन उपलब्ध कराएं। 70 साल के बाद में राजस्थान की 9894 पंचायतों में से 5991 पंचायतों को हम रोडवेज की सुविधा का लाभ नहीं दे रहे हैं, करीब 6 हजार पंचायतों को। हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परिवहन सेवा का लाभ पहुंचाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसके अलावा भी आपकी जो बसें चलती हैं, बिना फिटनेस के, बिना इंश्योरेंस के, खस्ताहाल बसें हैं, जो कि आए दिन दुर्घटना का शिकार बनती हैं। ज्यादा दुर्घटनाएं आपकी बसों के कारण होती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करूंगा कि सिरोही से मड़िया होकर के जो अहमदाबाद की बस बंद हो गई है, उसको आप चालू करें। सिरोही से सूरत बस चालू करें जिससे जो हमारे हजारों की तादाद में प्रवासी वहां पर रहते हैं, उन सबको भी रोडवेज की सेवा का लाभ मिल सके, आपका घाटा दूर हो सके। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रतिवेदन पर बहुत अरसे बाद आप चर्चा करवा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान रोडवेज की सबसे सुंदर बस और ग्रामीणों

(श्री बिहारीलाल)

का जिस पर विश्वास है, राजस्थान की जनता का जिस पर विश्वास है, वह आज संकट के दौर में है। उसको संकट के दौर में से निकालने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की है। माननीय मंत्री जी का नाम प्रताप सिंह है। यह नाम बड़ा प्रतापी है। मंत्री जी के लिए यह बड़ी चुनौती का विषय है। उन्हें रोडवेज की दशा को भी सुधारना है और नाम की सार्थकता को भी सिद्ध करना है। माननीय मंत्री जी, मंत्री से पहले दूसरी भूमिका में थे, वह प्राइवेट बस आपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष थे।

अब निगम की बसों के मुखिया हैं इसलिए दोनों जगह पराक्रम दिखाएंगे, तरीका अलग-अलग है। इस ओहदे पर भी माननीय मंत्रीजी खरे उतरेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। निगम पूंजी में स्टेट और केन्द्र का जो पूंजीगत अंशदान इस प्रतिवेदन में पढ़ा कि वह 2:1 है। दोनों ने ही नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे रोडवेज बेड़े की उपयोगिता जो वर्ष 2014-15 में 92 प्रतिशत थी वह अब काफी घट गई है, उसको भी सुधारने का चैलेंज है। माननीय मंत्रीजी, आपसे आग्रह करूं कि बीकानेर और जयपुर के बीच में मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा से होकर दस-बारह गाड़ियों की हमेशा सेवा हुआ करती थी जो अब मात्र घटकर एक या दो पर आ गई है। इस पूरे रास्ते में देशनोक की करणी माता का विश्व प्रसिद्ध पूजा स्थल, पर्यटन स्थल पड़ता है। इस पूरे रास्ते में पर्यावरण गुरु जम्भेश्वर भगवान का आस्था स्थल, मुकाम पड़ता है। इस पूरे रास्ते में विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मंदिर भी पड़ता है और इसी रास्ते में हारे के सहारे बाबा श्याम का दरबार भी लगता है तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बीकानेर से जयपुर के बीच में वाया नोखा होते हुए चलने वाली सभी बसों को पुनः शुरू किया जाए, यह आपसे आग्रह करता हूं।

माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में लोक परिवहन की सेवाओं का आप जिक्र कर रहे थे, शायद 1400 के लगभग अनुज्ञा पत्र जारी किए गए थे लेकिन आज सड़कों पर शायद 14000 के लगभग इस तरह की बसें दौड़ रही हैं, उनका भी सत्यापन करवाइए, वेरीफिकेशन करवाइए। उनमें प्रशिक्षित स्टाफ लगे, ट्रेंड ड्राइवर हों, ताकि जो यह लोक परिवहन की दुर्घटनाओं का सिलसिला जो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, ये 'लोक परिवहन' से 'परलोक परिवहन' बन चुकी हैं। इनको भी सुधारने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए।

(श्री बिहारीलाल)

राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों का जो लम्बा धरना चला 18 दिन का और 18वें दिन आप और आपके वर्तमान उप मुख्य मंत्री दोनों वहां पहुंचे और वादा करके आए कि हमारी सरकार आएगी तो हम सारी इन बातों पर गौर करेंगे, इनको लागू करेंगे, 14 महीने हो गए आपको आए हुए माननीय मंत्रीजी और आपकी सरकार को, तो कर्मचारियों की मांगों की जो आप बात करके आए थे, सातवें वेतन आयोग से वंचित रखा है उनको, पांच-पांच वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान बकाया है। कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और आपके पास नया स्टाफ नहीं है। रोज आपकी गाड़ियां बंद हो रही हैं, ये चुनौतियां आप स्वीकार करें, इनको सही करें।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर, नागौर, जोधपुर डिपो की सभी बसें जो नोखा होकर गुजरती हैं उन सभी बसों का स्टोपेज नोखा क्षेत्र के हाईवे पर स्थित रासीसर, पारवा, भामड़सर, नोखा गांव बीकासर, चरकड़ा चौकी पर होना चाहिए। यह हमारे ग्रामीणों की मांग है, यह मांग आपके सामने रख रहा हूं माननीय मंत्रीजी।

ग्रामीण परिवहन सेवा की जो बात की गई, उसके अनुसार भी हमारे नाथूसर, कम्बासर, तूम्बासर, सरमाणकसर, रातड़िया, साठी, धरणोक, साइसर को रोडवेज से जोड़ना चाहिए। बीकानेर में जसरासर जो बड़ा गांव है। बीकानेर से जसरासर वाया नापासर जो बसें है उनको जसरासर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

नोखा कस्बे का जो रोडवेज बस स्टैंड है उसकी दशा सुधारी जाए। यात्रियों के बैठने की व्यवस्था को सुधारा जाए, वहां शौचालय भी बनवाए जाएं। पांचू जो नोखा का सबसे बड़ा गांव है, वहां भी बस स्टैंड को बनाया जाए और सुविधायुक्त किया जाए, यह आपसे आग्रह है।

बीकानेर से जयपुर और जयपुर से बीकानेर चलने वाली एकमात्र वोल्वो बस है उसके समय में भी परिवर्तन किया जाए। जो 6 बजे बीकानेर से चलकर दस बजे तक जयपुर पहुंचा दे और जयपुर से शाम को छह बजे बाद चले, इस तरह की सुविधा की मांग मंत्रीजी आपसे करता हूं।

अंत में माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि कल सदन में सत्ता पक्ष के माननीय विधायक अपने सचेतक महोदय, उप सचेतक महोदय से आग्रह कर रहे थे कि रोडवेज में मेरा नाम लिखना। हम विपक्ष के लोग आग्रह कर रहे थे हमारे उप नेता प्रतिपक्ष से कि हमारा नाम भी रोडवेज की बहस में लिखना। अब इन दोनों ने कितनों का

(श्री बिहारीलाल)

नाम लिखा है, लेकिन रोडवेज हम माननीय दो सौ सदस्यों का नाम बरसों से अपने अंदर लिखवाकर चल रही है, आदर के साथ, गरिमा के साथ चल रही है। यदि इस तरह से रोडवेज हमारा नाम लिखे हुए चल रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, सदन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम रोडवेज की दशा को सुधारें और जो भी सहयोग इसमें कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक खण्डार।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और हमारे मंत्री महोदय को भी, उन्होंने इस रोडवेज को पुनर्जीवन दिया है। राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति और नेक इरादे इस बात को दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी ओर से 8700 लाख का राज्य सरकार द्वारा ऋण लेकर इस रोडवेज को जीवनदान दिया है। पिछली सरकार में इस रोडवेज का बंटाढ़ार कर दिया गया, रोडवेज के कर्मचारियों में हताशा थी, एक तरह से उनको लग रहा था कि सरकार रोडवेज को बेचकर जाएगी तो हम लोग कहां जाएंगे? हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने काफी लम्बे समय तक धरने दिए, आंदोलन किए। उस वक्त हम विपक्ष में थे और हमारे मंत्री महोदय ने उस वक्त प्रदेशाध्यक्षजी के साथ जाकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हम आपकी रोडवेज को नहीं बिकने देंगे। हमारी सरकार अगर आती है तो रोडवेज को नया जीवनदान देकर आपके और लोक हितों की रक्षा करेंगे। आज वह समय आया और हमारी सरकार ने आकर रोडवेज को नया जीवनदान दिया है और जिस इरादे के साथ में पुनर्जीवन देने के लिए काम कर रहे हैं, 876 बसें नई लेने का वादा किया था। अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं कि एक भी बस पर्चेज नहीं की जबकि 51 बसें तो आबंटित की जा चुकी हैं आगारों को, इतना असत्य बोलना सरासर, हर चीज के अंदर असत्य बोलकर कैसे सदन को गुमराह करते हैं जबकि 51 बसें तो चालू हैं, आगारों में चल रही हैं।

माननीय सदस्य संयम लोढाजी ने जो विषय उठाया है, निश्चित तौर पर समझने का फर्क है, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है, निविदाओं के मामले में निर्णय चल रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने सरकार ने जो कहा है वही कहा है, एक-एक बात पर सरकार खरा उतरेगी, हर वादे को निभाएगी, वादे के साथ और इरादे के साथ।

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से री-शिड्यूल करके आपने हमारी रोडवेज का राजस्व बढ़ाने में योगदान दिया है, आप जिस तरह से रेलवे में री-शिड्यूलिंग हर ट्रैक पर वाहन चलते हैं, रेल चलती है, उसका सेंट्रल लेवल पर सबको पता होता है कि किस तरह से किस रूट पर कौनसी ट्रेन किस नम्बर की चल रही है और कहां किस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी तो आप भी कृपा करके कोई ऐसी हाईटेक कम्पनी से कांट्रेक्ट करके इस तरह का एप बनवाइए, इस तरह का सिस्टम बनवाइए कि वह बसें हमारे हर रोडवेज डिपो पर जाए तो दूसरी बस रोडवेज वाली नहीं टकराए, अन्यथा समय एक ही होने से उनमें आपस में ही कम्पीटिशन हो जाता है, फिर तीसरी तरफ लोक परिवहन बस भी मारामारी करती है। पिछली बार लोक परिवहन बसों का जिस तरह से खेल हुआ और जिस तरह से माफियाओं ने कब्जा किया लोक परिवहन के माध्यम से, मैं समझता हूं कि बड़ा भारी खेल था और उन्हीं के दबाव में आकर रोडवेज को बेचने का काम भी सरकार करने जा रही थी परंतु इनके इरादे पूरे नहीं हुए। मैं तो बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत सरकार रेल को बेच रही है एयर इण्डिया को बेच रही है, मुझे लग रहा था कि हमारी सरकार नहीं संभाल पाए और रोडवेज बिक जाए, परंतु आपके इरादे सच्चे हैं। इस देश में एक-एक चीज हमारी जनता ने बनाई है। (व्यवधान) इसमें भारत पेट्रोलियम को बेच दो, ओएनजीसी को बेच दो, एयर इण्डिया बेच दो, आखिर में आपने रोडवेज को रोककर पुनर्जीवन देकर और इसकी 55 साल की गौरवमयी गाथा को पुन: लिखने का काम किया है, मैं तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बेचुओं से और फेंकुओं से इस देश को, प्रदेश को बचाया है। आपका धन्यवाद है। भाई नरेन्द्र दास मोदी, हमारे बड़े प्रधान मंत्री हैं, कभी एयर इण्डिया को बेचते हैं, कहते हैं आपने क्या बनाया, 70 साल में आपने कुछ नहीं किया। जो बेच रहे हो वह हमने ही बनाया है भाई। ये सारे बेचने का धंधा कर रहे हो, यह सारा हमने ही बनाया है। रेल हमने बनाई है, एयर इण्डिया हमने बनाया, एयर पोर्ट हमने बनाए, एम्स हमने बनाया, आईआईटी हमने बनाई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आज तो दिन में ही?

श्री अशोक (खण्डार): आपके साथ में हूं और आप मेरे साथ हो, आप ध्यान रखिएगा।

(श्री अशोक)

अब जो चीजें हमने बनाई हैं, उनको बेचने का काम आप कर रहे हो, फिर कहते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया और आप बेचने का काम कर रहे हो। मैं आपसे आग्रह करूंगा राठौड़ साहब से कि इस बेचने वाले काम को आप मना करके आओ, अन्यथा देश आप पर विश्वास करना भूल जाएगा कि ये लोग तो देश को बेचने का काम करते हैं। बेच कर, फकीर की तरह झोला लेकर चले जाएंगे, जाना है तो जाओ, मना कौन कर रहा है पर हमारे देश को मत बेचो। आपने रोडवेज नहीं बेची, आपका धन्यवाद। आप कृपा करके वोल्वो बस जो हमारे राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस जाती है, वह पिछली सरकार ने होटल बेच दी बीकानेर हाउस, पता नहीं किस सेठिया को बेची और उसके दबाव में बसें बंद करवा दीं। अब बसें पांच-पांच, दस-दस सवारी लेकर आती हैं रोडवेज की, वोल्वो की, खाली आती हैं, घाटे में है, उसकी टाइमिंग को भी री-शिड्यूल करवाएं। धौला कुआं पर आकर जो लोग बैठते हैं, लोग इस असुविधा की वजह से वॉल्वो में बैठना पसंद नहीं करते, इसके कारण वोल्वो बसें घाटे में हैं। एक तो थोड़ा टाइम री-शिड्यूल करवा दो, धौला कुआं में यात्रियों को सुविधा की प्रोब्लम है तो सरकार को आप लिखें। भाई नरेन्द्र दास मोदी तो कुछ करेंगे नहीं, गंदगी का आलम है, भयंकर गंदगी है, शौचालय नहीं है, टायलेट नहीं है, परेशान हैं यात्री, गंदगी का आलम है। आप केजरीवाल जी को लिखकर दे दें कि वहां जन सुविधा के लिये शौचालय बनवाएं और यात्रियों के बैठने की सुविधा करवाएं ताकि हम लोग वहां आराम से जाकर बैठ सकें। बीकानेर हाउस से आप चलाएं। तब तक आप इलेक्ट्रिक बसेज परचेज कर लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बीकानेर हाउस से कराएं ताकि वोल्वो बसों को पुनर्जीवन मिल सके। वोल्वो बसों का घाटा बढ़ता जा रहा है। लोक परिवहन की नयी बसेज आप परचेज करें तो मेरा आग्रह है कि नये बेरोजगार नौजवानों को उसमें मौका दें। एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे रोजगार के अवसर भी मिलें। पिछली बार लोक परिवहन बसों पर पंजाब वगैरह के, हिन्दुस्तान भर के लोगों ने, पता नहीं कहां-कहां के लोगों ने आकर कब्जा किया था। पुराने परिवहन मंत्री जी को पूरी गाथा याद है। मेरा आपसे निवेदन है कि लोक परिवहन बसों पर कृपा करके आप नौजवान बेरोजगारों को अवसर दें।

बस स्टैण्डों पर अगर जगह चिह्नित करें तो वहां पर कुछ लोगों को रोजगार के लिये कियोस्क का आबंटन कराएं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोक

(श्री अशोक)

परिवहन बसों का रूट अभी नहीं है, वहां चालू कराएं। मेरा खण्डार क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, इसलिए वहां पर लोक परिवहन बसों का संचालन सुनिश्चित कराएं। हमारे यहां रणथम्भौर का मेला भरता है, चौथ माता का लक्खी मेला भरता है, वहां पर मेलों में अच्छी सुविधाएं कराएं। मैं यह आग्रह करूंगा कि रोडवेज बसों को आप नया जीवनदान देकर परिवहन निगम को सुदृढ़ करेंगे और राजस्थान की इस गौरवमयी गाथा में निगम को आगे बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के इस प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। अभी खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सुन रही थी और वे माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त कर रहे थे और धन्यवाद दे रहे थे कि कम से कम आपने इसे बेचने से बचाया, पर बेच कौन रहा था, यह भी तो बता देते।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में जनता के सौभाग्य से 2003 से लगातार आ रही हूं। 2003 के कार्यकाल में भी मैंने देखा, 2008 से 2013 के कार्यकाल में भी मैंने देखा। उस 2008 से 2013 के कार्यकाल में तो आप ही की सरकार थी, फिर आपने क्या किया? उस समय क्यों नहीं किया? अब यह नौबत क्यों आ रही है? पहला प्रश्न तो यही उठता है। रोडवेज ठीक ढंग से चले, यह सार्वजनिक परिवहन का उपक्रम है और यह सार्वजनिक परिवहन का जो उपक्रम है, वह निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करता है। यह हम सब जानते हैं।

सार्वजनिक परिवहन से एक तो प्रदूषण नहीं होता और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। हमारे सड़क मार्ग जिस यातायात के दबाव से आये दिन टूटते हैं, इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं और उन दुर्घटनाओं से जो परिवार खतम होते हैं, उन्हें जाकर के हम पूछें तो निश्चित रूप से उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, अगर किसी परिवार में अकाल मृत्यु होती है तो पूरी पीढ़ी लग जाती है, लेकिन वह परिवार खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि कमाऊ सपूत जब खतम हो जाता है तो फिर परिवार सड़क पर आ जाता है।

सार्वजनिक उपक्रम का यह जो हमारा निगम है, यह जब अपनी

(श्रीमती अनिता भदेल)

सेवाएं उपलब्ध कराता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक सुरक्षा का भाव महसूस करता है और उसे लगता है कि मैं सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हूं। मैं भी मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आपने निश्चित रूप से एक इच्छा शक्ति, एक आशा की किरण जगायी है। यह सही बात है, पर ऐसा भी नहीं है कि सारी समस्याओं का ही समाधान हो गया है। उसमें समय लगेगा।

खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य नरेन्द्र मोदी जी का नाम ले रहे थे कि वे एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, हमने ही सब चीजों का विकास किया है। ये सब हवाई बातें हैं। यदि आपने ही सब चीजों का विकास किया है तो 70 साल में देश में 30 एयरपोर्ट बने थे और पिछले पांच साल में वे 30 से 60 एयरपोर्ट हो गये। जस्ट डबल हो गये। यदि इस स्पीड से करते तो जितनी समस्याएं आज हैं, उतनी समस्याएं शायद रहती नहीं। बच्चा पैदा होता है तो धीरे-धीरे समयानुसार तो बढ़ता ही है। उसे बढ़ाने के लिये मां-बाप सिर्फ भोजन ही तो देते हैं। जिसे जैसी क्वालिटी का भोजन प्राप्त होता है, वह वैसे ही बढ़ता है। यदि अच्छा, पौष्टिक भोजन होगा तो वह हृष्ट-पुष्ट बढ़ेगा और नहीं होगा तो वह कुपोषित बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर।

हमारा देश इस कुपोषण के साथ बढ़ा है इन 70 सालों में। अच्छा, पौष्टिक विकास होता तो शायद कुपोषण नहीं होता और उसी के लिये आज हम परेशान हो रहे हैं। आज हम परेशान हो रहे हैं सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिये। माननीय सभापति महोदय, आज ही मंत्री महोदय ने बोला कि 4 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें हम सेवानिवृत्ति के बाद कोई परिलाभ नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उप मुख्य मंत्री जी और आपने अक्टूबर, 2018 में स्वयं ने जाकर उनसे वादा किया था कि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हम करेंगे। उस समाधान के लिये आपने कुछ उपाय भी किये हैं, पर मंत्री महोदय, वे उपाय नाकाफी हैं। बहुत तीव्र गति से उन उपायों को आपको करना पड़ेगा। जितने रोडवेज में लीकेज हैं, उन्हें आपको खतम करना पड़ेगा।

अभी बसों की खरीद की बात हुई। आपने इस अभिभाषण में लिखा 876 या 878 बसें आपने खरीदी हैं, लेकिन जो बसें आपने खरीदी हैं, वे नयी कम्पनी की बसें हैं। पुरानी कम्पनी की बसें जो पहले रोडवेज में चल रही थीं, उन बसों में जो आइटम्स लगते हैं और जो उनकी डिपो में रिपेयर होती है तो अब अलग भण्डारण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो नयी बसें आपने खरीदी हैं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

उनका मेंटिनेंस भी ज्यादा है और एवरेज भी कम है। माननीय सभापति महोदय, अब ऐसी स्थिति में आप बताएं कि नयी बसें जो खरीदी गयी हैं, उनका मेंटिनेंस ज्यादा है और एवरेज कम है तो इससे घाटा बढ़ेगा या कम होगा?

दूसरा, पहले से जो रोडवेज की बसें चल रही हैं, उनके पार्ट्स अलग हैं। इन नयी बसों के पार्ट्स अलग हैं। जो पहले से भण्डारण किये हुए पार्ट्स हैं, उनका क्या होगा? क्या उन्हें नीलामी से बेचेंगे और नये भण्डारण करेंगे? दो तरह की बसें एक डिपो में चलेंगी। इसका समाधान कैसे होगा, यह एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और इसे दूर करें और इससे रोडवेज को नुकसान न हो, रोडवेज को घाटा न हो, इसकी व्यवस्था आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपने जो नयी बसेज ली हैं, आप उनका ठीक ढंग से उपयोग कर पाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अजमेर केन्द्रीय वर्कशाप जो है, उसमें बसें जाती हैं और मेंटिनेंस का काम होता है। आपको तो अच्छे से पता ही है, लेकिन पिछले छह-आठ महीने से मैं आपको गिनाती हूं एक-एक पार्ट। गियर बाक्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बस स्टार्टर और सैल्फ सिस्टम वहां दिया नहीं जा रहा है। मैंने इस मामले में ध्यानकर्षण भी लगाया है और सैंट्रल वर्कशाप में जो भी चीजें इंजन के मेंटिनेंस में काम आती हैं, वे कोई भी पार्ट्स नहीं जा रहे हैं। ईवन सीटों का जो रैग्जिन होता है, वह भी नहीं मिल रहा है। उससे सीटों की रिपेयर भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जो पुरानी खटारा बसें हैं, उनमें से कुछ-कुछ पार्ट्स निकालकर इन बसों में काम चला रहे हैं।

कई बार तो बसें रास्ते में ही खड़ी हो जाती हैं। यदि रिपेयरिंग का सामान आप नहीं उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा नुकसान होगा और मेंटिनेंस ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा तो जो रोडवेज की बसों को जितनी दूरी तय करनी थी, वे तय नहीं कर पाएंगी। आप प्लीज इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये बसें चल पाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि अजमेर सम्भाग मुख्यालय है। वहां से बहुत सारे लोग आते-जाते हैं, क्योंकि सम्भाग मुख्यालय पर ही लोग आते हैं और वहीं से बस पकड़कर फिर जाते हैं। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था और वह बस चालू भी हुई थी। अजमेर से हरिद्वार तक की बस। वह बस यदि मिल जाएगी, क्योंकि एक ही

(श्रीमती अनिता भदेल)

ट्रेन है, एक उदयपुर से आने वाली ट्रेन और एक अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन और निश्चित रूप से उनकी भी बुकिंग रहती है तो जो हरिद्वार जाने वाले लोग हैं, उन्हें जाने की सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए अजमेर से हरिद्वार आप कोई भी वोल्वो बस चलाएं या साधारण एक्सप्रेस बस चलाएं तो निश्चित रूप से उन यात्रियों को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

माननीय मंत्री महोदय, दो-तीन छोटी-छोटी चीजों का सुझाव देकर आपसे निवेदन करना चाहूंगी। रोडवेज बसेज सार्वजनिक उपक्रम हैं। इन रोडवेज बसों में आप देखिए, कोई भी विज्ञापन करने वाली कम्पनी अपने विज्ञापन डैस्कबोर्ड पर चिपका देगी, सीट पर चिपका देगी, सामने चिपका देगी। इतनी गंदी बसें हैं कि किसी यात्री को उनमें चढ़ने का मन नहीं करेगा। चिपकाने पर भी कोई अपराध नहीं है। कई बार हम निगम के लोग ही निगम की तरफ से ही नयी-नयी बसों पर अनाप-शनाप कुछ भी फोन नम्बर चिपकाएंगे, कुछ भी पोस्टर्स चिपकाएंगे, इसे बिलकुल अलाउ न करें आप इस तरह से चिपकाने के लिए। जितने भी वर्क्स-शाप्स हैं, उन वर्क्स-शाप्स की मोनीटरिंग हो। आप ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम चालू करिये जिससे पूरी की पूरी मोनीटरिंग ठीक ढंग से हो सके और जो रोडवेज में लीकेज हैं, जो चोरी के लीकेज हैं, जो डीजल की चोरी के लीकेज हैं, जो कल-पुर्जों की लीकेज के मैटर्स हैं वह लीकेज किसी न किसी तरह से रुके ताकि इसके जो नुकसान हैं, इसका जो घाटा है उस घाटे को हम किसी भी तरह से पूरा कर पायें।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक मेरा आपसे और निवेदन है। अभी मिड-वे की बात हुई। माननीय सभापति महोदय, कई बार बस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तय है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी और बीच में उसका कोई स्टापेज नहीं है लेकिन कई बार जल्दी जाने के चक्कर में या स्टापेज के चक्कर में वे एक स्थान से दूसरे स्थान यदि एक घंटे में जानी है तो आधा घंटे में स्पीड से लेकर जाएंगे और बीच में दो-तीन जगह अन-आफिशियली स्टापेज पर रोकेंगे। अब ये क्यों रोकते हैं यह पता नहीं। यदि ऑनलाइन का सिस्टम हो जाएगा, जीपीएस सिस्टम कुछ बसों में लगा देंगे तो हमें यह जानकारी मिल जाएगी कि बस कितनी देर कहां रुकी और क्यों रुकी। इसके अलावा रूट भी तय हो जाएगा कि इस रूट पर जाना है, इसलिए मेरा निवेदन है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक मेरा और आग्रह है। आप रोडवेज को बढ़ाना चाहते हैं, रोडवेज के कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले, समय पर उनका भुगतान हो, यह सब आप करना चाहते हैं पर जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लोगे, जब तक यह तय नहीं करोगे कि यह उपक्रम आपका खुद का है, यह सरकारी नहीं। जहां भी सरकारी शब्द लग जाता है उसका मतलब तो कूड़ेदान का, डस्टबिन का पात्र है। इसे सरकारी उपक्रम न मानते हुए वह उनका है, यह उनकी कमाई का साधन है, उनकी जीवनचर्या इससे चलती है, रोजी-रोटी इस रोडवेज की बस से चलती है, ऐसा भाव जब तक हम उन कर्मचारियों में पैदा नहीं करेंगे तब तक हम इसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह प्रोफिट में नहीं चले उसकी कोई चिंता नहीं कि इसको प्रोफिट में चलाना है पर यह नुकसान में भी न चले क्योंकि किसी भी सरकार का उद्देश्य प्रोफिट कमाना नहीं होता है, लोगों को सुविधाएं देना होता है। इसलिए प्रोफिट में नहीं आए, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन यह नुकसान में भी न जाए, सरकार के घाटे में भी न जाए, इसकी चिंता हमें करनी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको आग्रह करूंगी कि पिछली बार भी सरकार ने बहुत कोशिश की कि यह रोडवेज किसी तरह से प्रोफिट में आ जाए और लगभग 45 करोड़ रुपया प्रतिमाह मुख्य मंत्री जब माननीय वसुन्धरा जी थीं तो उन्होंने रोडवेज को दिया। उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी तरह से पेंशन मिल सके, कैसे इस रोडवेज को हम आगे चला सकें, इसकी व्यवस्था की। सरकार के बजट से उन्होंने उसकी व्यवस्था की।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): निश्चित रूप से आप इसको कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ ये जो कमियां मैंने बताई हैं, जो सुझाव मैंने दिए हैं उन सुझावों का पालन करते हुए इसको आगे कैसे लेकर जाना है, इसको कैसे हम फुल-फ्लेज्ड रूप से चलाएं।

हम गांवों में रोडवेज की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गांवों की बहुत बड़ी समस्या है। हम तो सम्भाग मुख्यालय से आते हैं इसलिए हमें इतनी समस्या नहीं है पर गांवों से आने वाले जिनके पास सिर्फ यही एक

(श्रीमती अनिता भदेल)

विकल्प है, आवागमन का एक यही साधन है वे इसके बगैर प्राइवेट बसों में जाने को मजबूर होते हैं और प्राइवेट बस वाले जिस प्रकार से मनमर्जी करते हैं और यदि उनसे बचाना है तो आपको रोडवेज की सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा, रोडवेज के रूटों का मार्ग बढ़ाना पड़ेगा....

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्या। प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक हजार बसों से कुछ नहीं होने वाला है, इसको कम से कम आप चार गुना संख्या में खरीदेंगे तब जाकर आपका यह काम चलने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, अगर सबने हार्लिक्स पी लिया हो कुपोषण से बचने के लिए जो 70 साल में आपने कुपोषित विकास किया तो मैं शुरू करूं? सभापति महोदय, देश लोकतांत्रिक है, राज्य की परिकल्पना है लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा करने का एक आयाम है। इसलिए, मंत्री महोदय ने जो प्रयास किए हैं, सरकार ने जो प्रयास किए हैं इसको उबारने के लिए, हम समझते हैं कि ये हार्लिक्स दिन में दो बार पिएं और जनता को बढ़िया बस में खूब आरामदायक सवारी कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मेरे साथियों ने बार-बार आगाह भी किया है कि रोडवेज में लीकेज हैं, रोडवेज में जो ड्राइवर गियर लगाता है वह बहुत झटके देता है और रोडवेज न सिर्फ सवारियों को झटके देती है, रोडवेज मंत्री के मंत्री उछाल देती है। पिछली सरकार के कई मंत्री यहां मौजूद हैं उनको तो हम उलाहना दे सकते हैं पर रोडवेज का तो मंत्री आया नहीं, रोडवेज के मंत्री को झटका लग गया।

सभापति महोदय, दिक्कत यह हुई कि राजस्थान रोडवेज जो दिल्ली में, अहमदाबाद में, सूरत में, चंडीगढ़ में, हिमाचल में कहीं भी जाती है छा जाती है पर अब धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों साल-दर-साल इसमें निजीकरण बढ़ा, उससे बसें कम हुईं, कर्मचारी कम हुए, उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं हुआ और जो बस 6 साल, 10 साल फायदे में चली, वह बस घाटे में चलती गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जिस तरीके से किसान का खेत फसल से भरा है, उसके खेत में दाने पैदा हुए हैं, अनाज पैदा हुआ है लेकिन फिर भी

(श्री बलवान पूनियां)

खेती से उबर नहीं पा रहा है, खेती में घाटे से उबर नहीं पा रहा है, उसी तरह से रोडवेज की बसें सवारियों से भरी हुई हैं फिर भी रोडवेज घाटे में है। रोडवेज में मुख्यत: राष्ट्रीयकृत मार्गों में निजी बसों का अनधिकृत संचालन बढ़ा है और ऐसा बढ़ा कि रोडवेज के आगे प्राइवेट बस का संचालन, रोडवेज के आगे लोक परिवहन बस का संचालन, दो मिनट आगे, पांच मिनट आगे होता है। सरकार के बड़े-बड़े अफसरों ने या मंत्रियों ने उनके रूट दिये होंगे जिसकी वजह से सवारी प्राइवेट बस उठाकर ले गई, लोक परिवहन की बस उठाकर ले गई और रोडवेज उसके मुंह की तरफ ताकती रह गई।

सभापति महोदय, बसों में कर्मचारियों का जो इंडेक्स बता रहा है कि 2018-19 में 2.89 प्रतिशत कर्मचारी बचे हैं, बाकी कर्मचारी घटते गये हैं। हम मांग करते हैं कि रोडवेज में 8 हजार से अधिक कर्मचारियों की अभी लगाने की जरूरत है उसमें ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिकों की संख्या बढ़ाने की मांग बार-बार संगठनों की भी रही है, यूनियनों की भी रही है। जिस धरने की बात बार-बार हर वक्ता अपने भाषण में कर रहा है उनकी यही मांग थी कि बसों के कर्मचारियों की संख्या पूरी करो, रोडवेज में कम से कम एक हजार बसें खरीदो, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो धन की कमी है, सरकार उस धन की पूर्ण पूर्ति करे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले चार वर्षों से जो भुगतान बकाया हैं उसका भुगतान करे। इन मुद्दों को निपटाने के जो आश्वासन दिये गये थे, वे आश्वासन सरकार पूरा करे और प्राइवेट बसों की दादागीरी को कम करे।

जो कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार रोडवेज में है उसी का परिणाम है कि हनुमानगढ़ जिले में 33 बसें आज अनुबंधित हैं और 70 रोडवेज की बसें चल रही हैं लेकिन सारे महत्वपूर्ण रूट का अगर हम जिक्र करें, जहां सवारी ज्यादा है उन सारे रूटों पर अनुबंधित बसें ही जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में अभी 17 बसें अनुबंधित आ रही हैं, 15 रोडवेज की बसें आ रही हैं और भादरा में नाइट सिर्फ पांच बसें करती हैं जिनमें से 4 अनुबंधित बसें लगा दीं और सिर्फ एक रोडवेज बस नाइट करती है। वहां के ड्राइवर और कंडक्टर की हालत यह हो गई कि वो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अनुबंधित बसों के ड्राइवर और कंडक्टर जिनके रूट पहले अबोहर हुआ करते थे, संगरिया हुआ करते थे, उन रूट के ड्राइवर और बसें हमारे भादरा में स्टापेज करने लग गईं। हमारे कुछ रूट ऐसे हैं जो मनमर्जी से चल रहे हैं। हनुमानगढ़ से रायसिंहनगर का रूट है जो राजस्थान रोडवेज से पहले लोक परिवहन को दे

(श्री बलवान पूनियां)

दिया। लोक परिवहन का रूट गांवों से होकर था लेकिन वह गंगानगर होकर निकलते हैं, गांव के रूट पर वे बिल्कुल नहीं चलते हैं। हनुमानगढ़ से पदमपुर का रूट था उसकी हालत भी यही है। हनुमानगढ़ से खाजूवाला का रूट था उसकी हालत भी यही है। हनुमानगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण रूट थे, सब पर लोक परिवहन की बसें चली हैं जिससे राजस्थान रोडवेज में गड़बड़ हुई।

सभापति महोदय, हमारे यहां से जयपुर से हिमाचल बस जाती है वाया भादरा, वह इतनी महत्वपूर्ण बस थी लेकिन उस बस के आगे भी लोक परिवहन की बस चला दी गई। सभापति महोदय, भादरा से होते हुए जयपुर के लिए वाया झुन्झुनूं बस आती थी, इतनी सवारियां आती थीं, उस बस का स्टैण्डर्ड था लेकिन उस बस को बंद कर दिया गया। सभापति महोदय, हम मांग करते हैं कि ये बसें वापस चलाई जाएं।

सभापति महोदय, हमें जो इंडेक्स दिया गया उसमें जो खर्चों का विवरण आया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 22 प्रतिशत डीजल और आयल पर खर्च होता है लेकिन 22 प्रतिशत ही अन्य खर्च है। अन्य खर्च क्या हैं, किसी ने कोई वर्गीकरण इस पूरी की पूरी किताब में नहीं बताया है। यह लीकेज है, यह भ्रष्टाचार है। टायर खरीदने पर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसमें दर्ज किया गया है कि दुबारा टायर पुराने चढ़ाएंगे, टायर पर एक रबर चढ़ाकर फिर टायर चढ़ाएंगे, फिर रोडवेज का टायर फूट जाता है।

सभापति महोदय, दुर्घटना का जो इंडेक्स दिया गया है उसमें यह कतई डिफाइन नहीं किया गया कि रोडवेज की बस से दुर्घटना हुई या लोक परिवहन जिसको परलोक परिवहन बता रहे थे बिहारी जी, उस परलोक परिवहन से दुर्घटना हुई, यह भी वर्गीकरण अलग से नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि रोडवेज में बैठने वाला, हर नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करे, हर विधायक की उस पर जो लगी हुई होती है, यह विधायक की सीट है, विधायक भी उसमें यात्रा करे। मैं तो एक मांग और करता हूं हर विधायक के गांव से राजस्थान रोडवेज की बस जरूर चले, ताकि विधायक से यह साल दर साल पूछें कि तेरी रोडवेज कैसे चल रही है।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, रोडवेज को जिस तरीके से हम छाती के नहीं लगाएंगे, प्रेम से उसको नहीं चलाएंगे, अपना करके नहीं चलाएंगे, रोडवेज आगे

(श्री बलवान पूनियां)

नहीं बढ़ पाएगी। रोडवेज के कर्मचारी को सिर्फ हम यह ज्ञान देते रहे कि तू, तेरा मानकर इसको चला, नहीं सभापति महोदय, उसको टाइम पर सुविधा देनी पड़ेगी, उसको पेंशन भी देनी पड़ेगी, उसको इजाफे भी देने पड़ेंगे, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भी उसको वेतनमान देना पड़ेगा, उसको बीमारी के इलाज में भी देना पड़ेगा। इसमें पूरा का पूरा इंडेक्स बताया गया है। इंडेक्स के अनुसार उसमें ये तय किया गया है कि ये-ये सुविधाएं उस कर्मचारी को मिलेंगी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं राजस्थान रोडवेज उन कर्मचारियों का ख्याल भी रखेगी, सवारियों का ख्याल भी रखेगी और लीकेज भी निकालने का काम करेगी और लोक परिवहन को पूर्ण बंद करेगी।

मैं मंत्री महोदय का थोड़ा-सा ध्यान करवाना चाहूंगा कि सागड़ा से हनुमानगढ़ एक बस चलती थी मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैंने महोदय को पहले भी निवेदन किया, वह बस बहुत इम्पोर्टेंट 15 साल चली है, बहुत सवारियां बनती थीं, वह बस बंद कर दी, नाहक बंद कर दी। वह बस वापस चलाई जाए और मेरे गांव से लेकर हनुमानगढ़ तक के लिए भी, मलखेड़ा से लेकर हनुमानगढ़ तक के लिए भी बस चलाई जाए। मंत्री महोदय, अगर मेरे ससुराल में बस चला दें तो मैं बहुत-बहुत आभारी रहूंगा, कुछ जुंहारी ज्यादा मिल जाएगी। सभापति महोदय, मुझे याद है आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री रीटा चौधरी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया और एक आप हार्डकोर एचएम की तरह बिलकुल मेरी सीट के सामने विराज रहे हैं, अपनी कृपा मुझ पर रखें।

श्री सभापति: आप मेहरबानी करके, समय का ध्यान रखेंगी, बड़ी कृपा होगी आपकी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): बिलकुल सभापति महोदय। आज से तीस-चालीस साल पहले हम लोगों की प्राथमिकता जो होती थी वह रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान होती थी और समय के साथ-साथ धीरे-धीरे जब परिवर्तन आया और समय बदला तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा भी उसमें शामिल हुई। सभापति महोदय, आज के इस आधुनिक युग के अंदर हमारे जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह इसका एक अहम हिस्सा

(सुश्री रीटा चौधरी)

बन चुका है और जिस जिले से मैं आती हूं वह शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत अग्रणी रहा है और है। वहां पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और झुंझुनूं जिले का कर्मचारी चाहे आप जैसलमेर चले जाओ, चाहे आप बाड़मेर चले जाओ, चाहे आप जालौर चले जाओ, सिरोही चले जाओ, हर जगह झुंझुनूं के कर्मचारी आपको मिलेंगे। इस लिहाज से भी इस विषय पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं प्रतिवेदन देख रही थी और अमूमन प्रतिवेदन में कहा जाता है कि विभाग की कार्य प्रणाली और उसके आय-व्यय का हिसाब और उसमें आने वाली योजनाओं को एक शब्द में, एक लाइन में मैं कहूंगी तो इतना कहूंगी ''नई सरकार, नये मंत्री और बम्पर नवाचार''। बहुत शानदार रहा यह एक साल का सफर रोडवेज का और नये मंत्री ने आते ही इसको अपने हाथों में लिया इस विभाग को और इसको गति दी। हमारा जो घोषणा पत्र था, महामहिम का अभिभाषण था, उसमें भी एक महत्वूपर्ण बिन्दु जिस पर मैं सिर्फ चर्चा करना चाहूंगी, वह है ग्रामीण परिवहन बस सेवा।

सभापति महोदय, हमारे दूर दराज में ग्रामीण इलाके के अंदर, ढाणियों के अंदर लोग बसे हुए हैं और हम जब-जब वोट मांगने जाते हैं तो उन लोगों से वादा करते हैं कि आपके यहां पर, ढाणियों के अंदर, वे सब सुख-सुविधाएं मुहैया होंगी, जो एक शहर के अंदर बैठे व्यक्ति को मिलती हैं। आज भी जिस इलाके से मैं आती हूं, मंडावा विधान सभा क्षेत्र, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, फ्लोराइड पानी का इलाका है, खारे पानी का, रेगिस्तानी इलाका है और गांव में, ढाणियों में, खेतों में दूर दराज में लोग बसे हुए हैं। उस दृष्टि से भी हमारे लिए ग्रामीण परिवहन सेवा बहुत उपयोगी है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, झुंझुनूं के अंदर ग्रामीण परिवहन सेवा के अंदर मात्र पांच बसें हैं। एक खेतड़ी बस डिपो से चलती है और चार झुंझुनूं से। हमारे मंडावा के अंदर 57 ग्राम पंचायतें हैं और झुंझुनूं के अंदर 347 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। लोगों की हमेशा डिमाण्ड रहती है कि ग्रामीण बस सेवाएं चालू की जाएं, आवागमन का साधन वहां पर नहीं है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ग्रामीण इलाके के अंदर बस सेवाएं चालू कर रहे हैं तो कृपया मेरे क्षेत्र का भी ध्यान रखें। राजसमंद से आने वाली हमारी माननीय सदस्या कह रही थीं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि तहसील की जगह इंटर

(सुश्री रीटा चौधरी)

तहसील को भी हम उसके अंदर लें ताकि एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक, एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड के अंदर लोग आ-जा सकें और आवागमन कर सकें।

सभापति महोदय, मैं देख रही थी, मैंने बहुत से लोगों को सुना और यह वार्षिक प्रतिवेदन भी देख रही थी और बहुत से आमूलचूल परिवर्तन इसके अंदर किये हैं। निगम के अंदर आते ही हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बहुत से फैसले भी लिये हैं, बसों की स्थिति को सुधारने को, इस निगम को घाटे से कैसे निकाला जाए, उस संदर्भ में भी।

सभापति महोदय, मेरा यह मानना है, हम कोई भी सेवा जन सुविधा के लिए चालू करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं तो हम लोग घाटा और नफा नहीं देखते हैं। हमारा एक लक्ष्य होता है कि लोगों को सुविधा मिल सके और जो घाटे में हमारा यह निगम चल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसे कहते हैं करप्शन, मेंटीनेंस नहीं है, बसों के अंदर और तीसरा प्राइवेट बसों का संचालन है, वह भी अवैध रूप से।

सभापति महोदय, विधायक बनने से पहले मेरी भी प्राइवेट बसें चलती थीं, मैं खुद संचालन करती थी और मुझे पता है कि किस स्थिति से हम लोग भी गुजरते और रोडवेज बसें भी निकलती हैं। लेकिन, मैंने देखा है कि प्राइवेट बसों के अंदर हम लोग बैंक की किस्त भी देते हैं, डीजल का खर्चा भी निकालते हैं, कर्मचारियों का खर्चा भी निकालते हैं और जो टैक्स लगता है गाड़ी के ऊपर, उसका टैक्स भी निकालने के बाद उसमें बचत होती है। रोडवेज बस के अंदर इस चीज की कमी है और कहीं न कहीं यह सोचने का विषय है। रोडवेज बसों को लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत सुविधा वाली भी है और हम अपने आपको बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी प्राइवेट बसों का, अवैध बसों का संचालन बंद नहीं हुआ, लेकिन अपने निगम को आगे बढ़ाने के लिए, घाटे से उबारने के लिए, उनको काम में लिया जा सकता है। मैं इस सदन में अपने कुछ जो मुझे लगता है, सुझाव काम आ सकते हैं, मैं देना चाहूंगी।

सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि रोडवेज बसों के लिए, रोडवेज डिपो के लिए बहुत महंगी जमीन, बहुत जगह ली गई है। चाहे आफिस बनाने के लिए या डिपो बनाने के लिए और इतनी कीमती जमीनें हैं, उसको हम लोगों को व्यावसायिक रूप से काम में लेना

(सुश्री रीटा चौधरी)

चाहिए, उपयोग लेना चाहिए जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। सरकार को रोडवेज को इसके उपयोग की इजाजत देनी चाहिए और पीपीपी मोड पर मॉल या मार्केट वहां पर बनाना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, दिल्ली में मैट्रो के लिए जो स्थान है वहां पर पार्किंग वगैरह की सुविधा दी है प्राइवेट लोगों को और वहां से आमदनी होती है, सरकार को और बोर्ड और निगम को।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगी हमारी प्राइवेट बसों के अंदर बहुत बड़ा कार्गो का संचालन होता है, बहुत से पार्सल आते-जाते हैं, लेकिन हमारी रोडवेज के अंदर हम लोग किस बात से डरते हैं। यह सुविधा हमने एक बार शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, वो इसको आगे नहीं चला पाए और इसको बंद दिया। हमें एक इच्छा शक्ति करनी होगी, कुछ कड़े फैसले हमें लेने होंगे और बहुत-सी दिक्कतें जब हम नए फैसले लेते हैं तो हमें निश्चित तौर पर आती हैं, लेकिन यह कार्गो और पार्सल की सेवा अगर हम हमारे रोडवेज के अंदर शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी रोडवेज जो घाटे के अंदर चल रही है उसमें कुछ हद तक हम लोग उसकी पूर्ति कर पाएंगे और जो प्राइवेट बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड के आस-पास होता है, हम लोग देखते हैं। बस स्टैंड पर जाते हैं, हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भी वहीं पर नजदीक है। वहां पर प्राइवेट बसें खड़ी रहती हैं उसके आसपास तो क्यों नहीं, हम लोग उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन उन प्राइवेट बसों के लिए हमारे जो बस स्टैंड हैं हमारे जो बस डिपो हैं उनके अंदर एक हिस्सा उनको हम लोग कमर्शियलाइज्ड तौर पर उनसे किराया लेकर उनको वह सुविधा दे दें, क्योंकि सबको कमाने का अधिकार है, हम लोग बसें जो प्राइवेट चलती हैं उनको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे अपनी आय के स्रोत बढ़ाकर हमारे जो निगम घाटे में चल रहे हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कनक्लूड करें।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी, सभापति महोदय, और जो नवाचार किया है जिसकी हम लोग बात करते हैं जैसे शादी समारोह में रोडवेज ले जाएं, धार्मिक यात्राओं में ले जाएं, वह बहुत स्वागत योग्य है और अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि 70 साल के अंदर 30 एयरपोर्ट्स बने और अब 60 बन गए हैं। अगर आप इसी स्पीड से काम करते तो कहां से कहां पहुंच जाते। मैं यह कहना चाहूंगी कि स्पीड से काम किया हमारे देश के प्रधान मंत्री ने तभी तो नोटबंदी जैसे, जीएसटी जैसे और सीएए जैसे फैसले किए जिससे आज हमारे देश की, हमारे

(सुश्री रीटा चौधरी)

हिन्दुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह बिलकुल धरातल पर आ गई है। कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला करते हैं उसके लिए हमें जनमानस जानना होता है और मैं हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी, इन्होंने हमारे झुंझुनूं में नयी बसें दी हैं। करीबन 5 नयी बसें आई हैं और वह सब लग गई हैं, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली और लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। आगे भी इसी तरीके से आप इस रोडवेज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसी आशा के साथ सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2018-19 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सभी सदस्यों के विचार मैं अभी सुन रहा था। ज्यादातर सदस्यों का कहना था कि रोडवेज अच्छे रूट्स पर नहीं चल रही है प्राइवेट बसेज उसकी कमाई को ले गई। सभापति महोदय, मैं भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं प्राइवेट बसेज के बारे में। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्राइवेट जो ऑपरेटर होता है उसको जब रोडवेज जिस रूट को छोड़ देती है या नहीं चलती है तब उस रूट का सर्वे होता है आरटीओ से और वहां उसको परमिट दिया जाता है। मैं चंद प्रभावशाली आपरेटर्स की बात अगर नहीं करूं तो मोस्टली लोगों को उन रूट्स पर परमिट दिया जाता है जिन रूट्स पर रोडवेज चलने को तैयार नहीं है। फिर भी वह आपरेटर गाड़ी में डीजल भी भराता है, अपना जो भी स्टाफ है शाम को उसका पसीना सूखने से पहले, ड्यूटी से उतरने से पहले उसको उसका वेतन दे देता है और वह अपने बच्चों को भी पालता है उसी बस से। क्या कारण है कि रोडवेज बस न समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन दे पा रही है, जो रिटायर हो जाते हैं उनका पैसा, मुझे जानकारी मिली है तकरीबन 2016 से अब तक जो रिटायर हुए हैं उनका पैसा नहीं दिया गया है। नए कर्मचारियों की भर्ती भी नहीं हो रही है 6-7 साल से। मैं सिर्फ अपने सुझाव देना चाहूंगा। मंत्री महोदय भी काफी जानकारी रखते हैं प्राइवेट बसेज के बारे में भी और अब रोडवेज के बारे में भी तो ऐसी चीजों को हमें जानना पड़ेगा कि कौन से कारण हैं जिससे प्राइवेट ऑपरेटर सब कुछ खर्चे चुका कर भी अपना घर चला रहे हैं यानी थोड़ा प्रोफिट हो, लेकिन प्रोफिट में चला रहा है और रोडवेज लगातार घाटे में आ रही है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ छोटी-छोटी चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूं। रोडवेज के अंदर जो

(श्री बलजीत यादव)

टायर के ऊपर रबर चढ़ाया जाता है, कोल्ड टायर रिट्रेडिंग प्लांट काफी लगे हुए हैं। सभापति महोदय, रबर उस टायर के ऊपर अगर चढ़ाया जाए इस प्लांट में पुराने टायर पर तो वह 60 हजार से 70 हजार किलोमीटर तक चल लेता है। नया टायर खरीदते हो तो उसकी लाइफ इससे ज्यादा से ज्यादा होगी तो 5 से 8 परसेंट ज्यादा होगी। नया टायर खरीदती है रोडवेज तो उसकी कोस्ट होती है 15,000 रुपये। यह जो टायरों पर रिट्रेडिंग प्लांट में रबर चढ़ाया जाता है इसकी कोस्ट आती है 4,000 रुपये। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना घाटा रोडवेज को होता होगा कि उसके अपने प्लांट हैं वह उन टायरों को तैयार कर सकते हैं लेकिन नहीं करके, हो सकता है कुछ अधिकारी लोगों का कमीशन आता हो टायर खरीदने में इसलिए वह उस प्लांट का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। 30 परसेंट से भी कम यूज़ हो रहा है उन प्लांट्स का।

दूसरी चीज, रोडवेज के अंदर भरी सवारियों में बस चलती है। सभापति महोदय, शहर में मिनी बसें चलती हैं, कोई भी मिनी बस का मालिक दिन में अपनी बस को दो बार देखकर यह बता देता है कि यह चक्कर, सांगानेर से कोई बस चल रही है और मुरलीपुरा जाएगी तो इस बस का यह चक्कर इतने रुपये का आएगा। भांकरोटा से बस चलेगी आमेर जाएगी तो आज यह चक्कर इतने का आएगा और शाम को मेरी बस में इतनी बचत आ जाएगी वह साथ नहीं चलता है तो भी, तो ऐसी कोई मोनिटरिंग अपने को इस ढंग से करनी पड़ेगी कि रोडवेज भर के चल रही है फिर भी पूरी तरह से रेवेन्यू नहीं आ पा रही है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय को काफी गहराई से इन चीजों की नालेज है तो आशा रखता हूं कि बहुत अधिक सुधार रोडवेज में आ पाएगा और कुछ आता भी अभी दिखाई दे रहा है। नई बसें खरीदने का जो निर्णय सरकार ने लिया है वह निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है और मैं समझता हूं कि उससे बहुत ज्यादा जनता को राहत मिलेगी।

इसके अलावा, एक सुझाव मैं और भी देना चाहता हूं सरकार को। देखिए ऐसा नहीं है कि रोडवेज सरकार सिर्फ प्रोफिट कमाने के लिए ही चला रही है, रोडवेज के अंदर फ्री पास से चलते हैं, रोडवेज के अंदर जो कंसेशन के अंदर हैं, वह सवारियां चलती हैं तो इन सब चीजों से भी रोडवेज को घाटा होता है और गरीब एक निम्न स्तर का आदमी बिलकुल यह मानकर चलो कि गरीब, वह आज रोडवेज या मिनी बस या कोई भी बस की सवारी करता है इसलिए सरकार को यह देखना चाहिए कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति

(श्री बलजीत यादव)

है वह इसकी सवारी कर रहा है रोडवेज की और वह बेचारा अपने घर से और अपने जहां पर मजदूरी करता है, काम करता है वहां पर पहुंचता है या कोई भी अपना काम धंधा करता है या पढ़ाई करता है, गरीब का बच्चा तो कालेज-स्कूल उस रोडवेज बस से जाता है इसलिए सरकार को यह चाहिए, आप जगह -जगह सब्सिडी देते हो कि इस पर सब्सिडी, उस पर सब्सिडी, मैं बताऊंगा बजट पर चर्चा के दौरान कि कहां-कहां घोटाले, कितने-कितने घोटाले सब्सिडीज में होते हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं आप डीजल पर वैट लगाते हो तो यह कम से कम रोडवेज जो इतना लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है इस रोडवेज के लिए डीजल पर से वैट हटा दिया जाए, उस पर वैट नहीं लिया जाए।

दूसरा, मैं उसके साथ ही कहना चाहूंगा कि करीब 20 परसेंट रोडवेज, सभापति महोदय, चलती ही नहीं हैं और वह चलती किसलिए नहीं हैं, मैं दिल्ली से वोल्वो बस तक की बता रहा हूं कि अगर उसका टायर पंक्चर हो गया या किसी का टायर फट गया तो वह बस खड़ी रह जाएगी, किसी दूसरी बस का टायर खोलेंगे कर्मचारी और उस बस में फिट करेंगे और उस बस को पहुंचाएंगे। 20 परसेंट से ज्यादा रोडवेज बसें चल ही नहीं पा रही हैं आपके टायर-वायर के चक्कर में ही, छोटी-छोटी चीजों के चक्कर में। छोटे से पार्ट्स के अभाव में आपकी बस खड़ी रह जाती है तो इसलिए सरकार अगर मदद करे रोडवेज की, सरकार अगर थोड़ी-सी आर्थिक सहायता करे रोडवेज की तो जैसे होता है न कि कोई गांव का व्यक्ति, मैं गांव का आदमी हूं, मैं गांव में देखता हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर कर्जा चढ़ जाता है, कई एग्जाम्पल मेरे ध्यान में हैं कि उस गरीब आदमी के ऊपर अगर एक लाख या दो लाख रुपये का कर्जा चढ़ गया तो दो लाख रुपये वह बेचारा ब्याज पर लेकर आता है 2 रुपये सैकड़े के ऊपर। अब उसका 4000 रुपये ब्याज चालू हो गया, उसकी इनकम भी चार हजार ही की होती है, वह उसकी सारी इनकम ब्याज में जाती रहती है और वह कभी भी नहीं उबर पाता। धीरे- धीरे उसको कोई और जरूरत पड़ गई और चीज का नुकसान हो गया तो वह पांच रुपये सैकड़े पर ब्याज पर लेकर आ जाएगा, इस तरह वह फिर माइनस में जाता जाएगा और उसका घाटे पर घाटा बढ़ता जाएगा और अंत पंत उसको अपनी जमीन जायदाद बेचकर उससे पिंड छुड़ाना पड़ेगा। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि रोडवेज की हालत इतनी खराब हो गई है तो सरकार उसको पैसा देकर एक बार यह कोशिश करे कि आपको नये टायर नहीं लेने हैं, इसके पीछे अधिकारी लोजिक

(श्री बलजीत यादव)

देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो जो रबर आता है, हमें चढ़ाना है, उसका पैसा नहीं दिया तो वह हमें रबर नहीं दे रहे। रबर का पैसा नहीं है और नये टायर खरीदने का आपके पास पैसा है। सरकार के पास फिर भी कमी है तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह रोडवेज को पैसा दे कि आप अपने रबर भी खरीद लो और कोई पार्ट्स खरीदने हों, वह भी खरीद लो। यह जो 20 परसेंट बसें खड़ी रहती हैं, इन बसों को भी चलाओ तो रोडवेज को और ज्यादा इनकम होगी। जहां पर लीकेज ज्यादा होता है, मंत्री जी, उनको अगर रोकेंगे तो उससे भी निश्चित रूप से बेनिफिट होगा।

मैं समझ पाता हूं कि इन बसों के बारे में जितनी नोलेज मंत्री जी को है कि आने वाले साल में रोडवेज बहुत ही अच्छी स्थिति में आ पायेगा और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो बसें बंद हो गई हैं, जैसे हमारे यहां बहरोड़ में बहुत-सी बसें चलती थीं, गांवों में हम जाते हैं, इलेक्शन में भी गये तो गरीब, मजदूर की बच्चियां बोलती थीं कि हम पढ़ने के लिये स्कूल, कालेज में रोडवेज की बसों में जाती थीं, रोडवेज बंद हो गई। प्राइवेट बस है नहीं, और कोई सुविधा है नहीं, उसके पास खुद का साधन है नहीं तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है। इसलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा रोडवेज की बसें खरीदें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि गांव-गांव तक बस की सुविधा हो जिससे गरीब, किसान, मजदूर को लगे कि....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बस एक मिनट में खतम कर रहा हूं। सरकार उसकी भी चिंता कर रही है और मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि अशोक गहलोत जी की सरकार निश्चित रूप से उस गरीब किसान, मजदूर को राहत देगी।

मेन हाईवे एनएच 8 पर बहरोड़ है और वहां पर कोई बस स्टैंड नहीं है। सवारियां परेशान होती रहती हैं। मैं मंत्री जी से भी मांग करूंगा कि वहां पर बस स्टैंड का निर्माण करवाया जाये, जगह हम उपलब्ध करवा देंगे, वहां पर बस स्टैंड बनाया जाये। इससे भी ज्यादा से ज्यादा रोडवेज को लाभ होगा, ज्यादा से ज्यादा सवारियां बैठेंगी, यह मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

मेरे बहरोड़ में अलवर से कोहराणा होते हुए नारनोल रोडवेज की बस जाती थी, वह बंद हो गई। अलवर से नीमराना होते हुए माजरी, कायसा होते हुए नारनोल बस जाती थी, वह बंद हो गई। कुंड रोड पर प्राइवेट बसें चल रही हैं, बहुत ही प्रोफिट वाला रूट है लेकिन रोडवेज नहीं चलती है। ऐसे रूट पर

(श्री बलजीत यादव)

रोडवेज बसें चलायेंगे, यह मेरे को पूरा पूरा विश्वास है। मैं शुभकामना देता हूं और मुझे पूरी आशा है कि निश्चित रूप से आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा जनता को रोडवेज की सुविधाएं मिलेंगी और रोडवेज भी अपनी स्थिति को उबार पायेगी और सरकार रोडवेज की मदद करेगी।

सभापति महोदय, मुझे एक बार का उदाहरण ध्यान है कि विजय माल्या की एयरलाइंस डूबने लगी तो यह बात आई थी कि इसको सब्सिडी दे दी जाये, आर्थिक मदद की जाये ताकि यह किंगफिशर एयरलाइंस डूबे नहीं। उसका विरोध हुआ था कि एक आदमी है, सरकार किसलिये मदद करे, यह बात रखी गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह रोडवेज तो जनता की है, इसकी मदद करने में, इसको आर्थिक सहायता देने में कौनसा नुकसान है, इसको किया जाना चाहिये। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सड़क मार्ग से आवागमन का सर्वश्रेष्ठ साधन रोडवेज है। मैं तो सामान्यत: रोडवेज में ही यात्रा करता रहता हूं। रोडवेज की बसों की हालत बहुत खस्ता है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास लगभग 3560 बसें हैं, उनमें से 1400 बसें खराब पड़ी हैं और लगभग 350 बसें प्रतिदिन ब्रेकडाउन हो जाती हैं, फिर उनको ठीक करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, रोडवेज बसें लगातार घाटे में जा रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और कारण भी बताये हैं कि क्यों घाटे में जाती हैं, लेकिन मेरे जो ध्यान में आता है उसमें सबसे बड़ा घाटे का कारण वर्कशाप है। वर्कशाप में पता ही नहीं चलता, जनता के ध्यान में ही नहीं आता और विभाग के लोग भी नहीं देखते। जो वर्कशाप के जानकार हैं, उन्हीं को ही जानकारी रहती है कि कौनसे पार्ट्स लाते हैं, कौनसे लगाते हैं। कौनसा पार्ट्स खोलकर कहां लगा दिया, यानी बहुत कीमती पार्ट्स बाहर चले जाते हैं और बहुत हल्के पार्ट्स अच्छे पार्ट्स के नाम पर खरीदकर वहां लगा दिये जाते हैं और उसके कारण से सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। इसकी मोनिटरिंग होती है या नहीं होती है, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मुझे जितनी जानकारी है और मैंने जितनी जानकारी की है, उसके हिसाब से इसकी प्रोपर मोनिटरिंग नहीं हो पाती है, इसके कारण से बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। इसमें हम सबसे ज्यादा दोष चालक और परिचालक को देते हैं। मैं मानता हूं चालक-परिचालक का कुछ दोष हो सकता है लेकिन इतना दोष नहीं है जितना

(श्री मदन दिलावर)

वर्कशाप संभालने वालों का है, जितना गाड़ियों को ठीक करने वालों का है। मैं छोटी से छोटी बात बताना चाहता हूं गाड़ी को डिपो से सब तरह से चैक करके निकलना चाहिये, उसका सब तरह से परीक्षण होना चाहिये, उसकी साफ सफाई होनी चाहिये। लेकिन देखा गया है कि इसका परीक्षण नहीं होता। परीक्षण हुआ होता तो मैं कई बार जब बस में बैठता हूं तो बैठने के बाद 20 किलोमीटर जाकर गाड़ी खड़ी हो जाती है। बोलते हैं कि इसका तो टायर पंक्चर हो गया है, यह तो ब्रेकडाउन हो गई है, इसका यह खराब हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको चैक करने की जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी, वह उन्होंने नहीं की और इसके कारण से वह गाड़ी दिनभर वहां खड़ी रही। दूसरी गाड़ी उसकी सवारियां लेकर जायेगी या जो पीछे से गाड़ी आ रही है, वह उसकी सवारियां लेकर जायेगी तो जो आगे सवारियां मिलने वाली थीं, उससे जो रेवेन्यू आने वाला था, उसका लोस हो गया। इसलिए हमें मोनिटरिंग पर जोर देना चाहिये कि जब वर्कशाप से गाड़ी निकलेगी तो बिलकुल कमप्लीट होगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी उसमें नहीं होगी।

मैं कई बार बस में बैठता हूं तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। इतना सारा कचरा पड़ा रहता है। मैं जब कंडक्टर-ड्राइवर से पूछता हूं कि इसकी सफाई क्यों नहीं है तो कहते हैं कि अंदर वालों ने नहीं की या कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। कई बार सवारियां भी ऐसा फील करती हैं कि हम कैसे गंदगी में बैठे हुए हैं। जब हमारी गाड़ियों में गंदगी रहेगी तो हमारी सवारियों को भी बैठने में थोड़ी-सी हिचक महसूस होगी और वह दूसरी गाड़ियों की ओर बढ़ेंगे। वैसे मैंने पहले ही कहा कि सड़क मार्ग से आवागमन का यह सर्वश्रेष्ठ साधन था और होना चाहिये, इस पर बड़ा विश्वास है। हम जो टिकट के बदले पैसा लेते हैं, उसमें एक रुपया बीमा का जोड़ते हैं। पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने लोगों को बीमा का लाभ मिला होगा। यह सच है कि जो एक्सीडेंट में मर गया होगा, उसको मिला होगा लेकिन जो एक्सीडेंट में घायल हो गया होगा, जिसका कुछ नुकसान हो गया होगा, जो कुछ दिन भर्ती रहा होगा, उनको तो किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती जबकि इस बात का भी बीमा होता है, हर टिकट में अपने आप एक रुपया जुड़ा रहता है कि इसमें आपको बीमा का लाभ मिलेगा लेकिन वह नहीं दिया जा रहा है। कई बार तो टिकट काटने वाला ही एक सीट पर दो-दो टिकट दे देता है, इससे बस में झगड़े होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि ऑनलाइन न होने के कारण

(श्री मदन दिलावर)

से या मशीन कम्प्यूटर से नहीं जुड़े होने के कारण से होता हो परन्तु इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार से ओवरलेपिंग न हो ताकि सवारियों में आपस में झगड़े न हों। मैं यह झगड़े लगातार देखता रहता हूं, ऐसा होता है।

जब हम रोडवेज की बात करते हैं तो रोडवेज के परिवार का ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा क्योंकि रोडवेज को चलाने वाले लोगों की, संभालने वाले लोगों की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखेंगे तो वह मन से काम नहीं कर पायेंगे और जब मन से काम नहीं कर पायेंगे तो रोडवेज ठीक ढंग से नहीं चल पायेगी, यात्रियों से उनका व्यवहार ठीक नहीं रह पायेगा। इसलिए हमको चाहिये कि उनका ओवरटाइम टाइम पर दें। उनका मेडिकल बिलों का भुगतान ठीक समय पर करें। उनका एरियर वगैरह टाइम पर दें, पर ऐसा हो नहीं रहा है। कई बार हमें ड्राइवर, कंडक्टर मिलते हैं वह इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि साहब हमको तीन साल से नहीं दिया है, कोई कहता है कि चार साल से नहीं दिया है, कोई कहता है कि पांच साल से नहीं दिया है तो लोग कैसे काम करेंगे?

फिर हमको भी देखना चाहिए कि दुर्घटनाएं होती हैं। मैंने दुर्घटनाओं को देखा है। दुर्घटनाओं के अधिकांश कारण ये होते हैं कि कई बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण भी कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं इस कारण भी होती हैं कि हमारे पास ड्राइवर कम हैं। एक ड्राइवर को हम कई किलोमीटर चलवाते हैं, जितना तय है कि एक दिन में एक ड्राइवर को इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए फिर भी उससे चलवाते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्राइवर नहीं हैं। कई बार उसको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारे एक ड्राइवर की कमी के कारण से कई बार हम 50 सवारियों का जीवन खतरे में डाल देते हैं। जबरदस्ती करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ही जाना पड़ेगा। मुझे ऐसे ऐसे ड्राइवर मिले हैं, जिन्होंने कहा कि साहब, मैं 24 घंटे से गाड़ी चला रहा हूं। 24 घंटे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपनी सवारियों को कैसे सुरक्षित रख सकता है? इस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? हम केवल पैसे के लिए लड़ते रहते हैं। यह घाटा जा रहा है, यह लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लेकिन हमें जनता की सुविधाएं और उनके जीवन के खतरों को भी देखना पड़ेगा। उनको खतरों से दूर रखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, 22 हजार पद स्वीकृत हैं और साढ़े सात

(श्री मदन दिलावर)

हजार पद रिक्त हैं। इन रिक्त साढ़े सात हजार पदों में बड़ी संख्या में चालक/परिचालकों के पद भी रिक्त होंगे। यदि चालक और परिचालकों के पद रिक्त हैं तो फिर गाड़ियों को कौन चलाता है? इसका मतलब एक ड्राइवर गाड़ी को कभी 24 घंटे, कभी 30 घंटे रेगूलर चलाता है, इस कारण बड़ी परेशानियां होती हैं। उसके परिवार में भी झगड़े होते हैं, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। परिचालकों में चिड़चिड़ापन होता है तो सवारियों से झगड़े होते हैं और फिर सवारियों से उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है। इसलिए हमको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अभी मेरी जानकारी के अनुसार केवल 1950 बसें ठीक हालत में रोड पर चल रही हैं। जहां हमारे पास 6 हजार के आसपास बसें होनी चाहिए, वहां 1950 बसें हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं कोटा जिले से आता हूं। कोटा जिले में भी वहां से आता हूं जहां कोटा स्टोन की चमक है और जहां पर एशिया की धनिये की सबसे बड़ी मण्डी है, लेकिन वहां पर रोडवेज की बहुत कम बसें जाती हैं। एक चेचट बस चलती थी, वह बस कैसे चलती है। जिस दिन ड्राइवर छुट्टी नहीं करेगा, उस दिन बस चलेगी। जिस दिन ड्राइवर ने छुट्टी कर ली, उस दिन बस नहीं चलेगी। उनको कैसे सवारियां मिलेंगी? दो दिन बस चलेगी, तीन दिन नहीं चलेगी। तीन दिन चलेगी, एक दिन नहीं चलेगी तो कैसे सवारियां चलेंगी। ऐसी ही खेड़ा रूद्दा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे रूटों की बसें बंद की हुई हैं, खेड़ा रूद्दा बस है, चेचट बस है, आलोद बस है, सांपलखेड़ी बस है, इन बसों को चालू करना चाहिए। क्योंकि आप मुझे टोक देते हैं, इसलिए मैं क्यों अपने को टोकवाऊं? मैं तो बैठ जाता हूं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि बैठो। बोलूं?

श्री सभापति: मेरी आपको यह व्यक्तिगत सलाह है कि आप यह उदासीन भाव छोड़िए। उदासीन भाव छोड़कर आप कहीं तो अच्छाई देखिए। आपको सब जगह केवल बुराई ही बुराई दिखायी दे रही है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं तो रोडवेज के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं। हमें रोडवेज के परिवार के बारे में सोचना चाहिए। चार हजार लोगों को जो परिलाभ देने थे, वे नहीं मिले हैं। मैं उसके बारे में विचार कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही कहा है कि यह सड़क मार्ग से आवागमन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है।

श्री सभापति: मैं जब भी आपको बोलते हुए देखता हूं तो केवल उदासीन भाव आपके चेहरे पर छाया रहता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपका चेहरा देखकर मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। मैं क्या करूं? साहब, आप थोड़ा मुस्कुराकर रहा करो।

श्री सभापति: आपको दो मिनट का समय और दिया, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप मुस्कुराकर रहा करो।

श्री सभापति: आप तो प्रसन्न भाव से बोलें, चाहे आपको पांच मिनट और बुलवाना पड़े।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अच्छा तो मैं प्रसन्न भाव से बोलता हूं। अब मेरी प्रसन्नता देखिए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि रोडवेज और प्राइवेट बसों में जो कम्पीटिशन है, उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण ये हो सकते हैं कि उनकी बस शाम को जब पहुंचती है तो उसकी धुलाई होती है, सफाई होती है, सब प्रकार से होती है। वह साधन हमारे यहां नहीं है। हम यह अपेक्षा करें कि वह ड्राइवर ही धोयेगा, ड्राइवर ही सफाई करेगा, ऐसा नहीं, उनके पास खलासी होता है। आपके जो डिपो हैं, जहां रात्रि को बसें स्टे करती हैं, जहां रहना पड़ता है, वहां पर भी कुछ इस प्रकार की चाहे टेम्प्रेरी या कैसे भी प्रकार से करें कि वहां बसों की अच्छी धुलाई हो, अच्छी सफाई हो, ताकि हंसता और मुस्कुराता यात्री उसमें यात्रा करे। कई बार मन मसोस कर यात्रा करता है, मजबूरी है, जाना है, इस रूट पर कोई बस नहीं है, इसलिए हमको जाना ही पड़ेगा, जैसी भी हो।

कई बार हमारी नासमझी के कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप तो जानते हैं कि बिजली के तार बहुत लटके रहते हैं, ढीले रहते हैं, पर हमको सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार रोडवेज की बसें नीचे से खाली रहती हैं और ऊपर सवारियां बैठी रहती हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पर यात्री ऊपर न बैठकर जाएं। यदि यात्री ऊपर बैठकर नहीं जाएंगे तो कई बार जो दुर्घटना होती है, वह बच सकती है। उससे मानव जीवन भी बचेगा और उससे रोडवेज की बदनामी भी नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कभी-कभी आप लोग रोडवेज की बसों में बैठकर यात्रा किया करें तो आपको सारा ध्यान आएगा। (व्यवधान) साइकिल की तो कह रहा हूं। साइकिल में न चलें, रोडवेज की बस में चलें।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुस्कुरा दीजिए तो मैं बैठ जाता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज रोडवेज के ऊपर काफी माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं। देश की आजादी के बाद नाममात्र के साधन थे और इन गत सालों में देश ने प्रगति की। रोडवेज सेवा उन आवश्यक सेवाओं में है, जैसे पानी, बिजली, रेल है, उसी तरह यह है। आप सभी जानते हैं कि अमीर आदमी तो लग्जरी गाड़ियों में घूमता है और गरीब आदमी का पुष्पक विमान यही है। जो एक भाई को बहन के पास, एक बेटे का मां तक पहुंचाने का काम रोडवेज करती है। जब बात घाटे और मुनाफे की बात आती है, यह कोई व्यापार नहीं है, यह जनसेवा है, नर सेवा है। अपना पहला उद्देश्य यह हो कि हम आम आदमी को कैसे सुविधा दे सकें, उनका ज्यादा से ज्यादा तंत्र कैसे विकसित हो।

वैसे अभी कई बातें हो रही थीं कि हमने तेज गति से विकास किया है। माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 12-13 महीने हुए हैं, अगर इतनी तेज गति से आपने विकास किया है तो तेरह महीनों में कौनसा पहाड़ टूट गया और कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी ने इतना किया है। मैं मानता हूं कि रोडवेज एक महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान) रोडवेज की ही बात कर रहा हूं। इतना कुछ हुआ है तो इसमें 60 साल लगे हैं, यह एक दिन में नहीं हुआ है। अब हालात यह हो रहे हैं, रोज अखबारों में, मीडिया के माध्यम से कि आज रेल की यह तैयारी हो रही है, हवाई जहाज की वह तैयारी हो रही है, न जाने क्या-क्या हालात हैं? लेकिन अपना एक ही दायित्व है और हमें खुशी भी है कि राजस्थान के रोडवेज की स्टेयरिंग हमारे बाड़मेर के दामाद के हाथ में है। हमें पूरा भरोसा है। आज जो लोग बात कर रहे थे कि खटारा। मैं मानता हूं कि कोई बस खटारा नहीं होती, उनका मैनेजमेंट करने वाला मजबूत हो तो। हमारे प्रताप सिंह जी मजबूत हैं, वे एक भी बस खटारा नहीं रखेंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है बस खटारा नहीं होती, उनको मैनेजमेंट करने वाले खटारा हो सकते हैं। आज देश में जो बातें हुईं। आज रोडवेज बस, चाहे रक्षाबंधन के ऊपर हो, चाहे छात्रों के लिए, कई रियायतें, कई सब्सिडियां। हम जानते हैं कि रोडवेज ही नहीं, सरकार ने और भी, चाहे गैस के ऊपर हो, डीजल के ऊपर हो, कई सब्सिडी देकर जनता को सुविधा देने का काम किया है। इसी

(श्री मदन प्रजापत)

तर्ज पर जो रोडवेज है, यह जनसेवा के लिए है। हम सबका दायित्व बनता है कि हर सुझाव अमूल्य सुझाव है। ये मुनाफे में भी आए, कोई गलत सुविधा और सेवा का मतलब यह नहीं कि कोई बदमाश अंदर घुस जाए और जड़ें कमजोर करे। हम सबका दायित्व है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो कि इस सेवा का विस्तार कैसे हो? यह मुनाफे में चले, ये सब अमूल्य सुझाव देना हम सबका दायित्व है। बातें तो कई हो रही थीं लेकिन सरकार चलाने में और जुबान चलाने में अंतर होता है। लोग जुबान चला लेते हैं लेकिन जनता ने अब अहसास किया कि सरकार नहीं चल सकती। सरकार तो चलाने वाला ही चला सकता है। आज माननीय गहलोत साहब की सरकार ने ग्रामीण बस सेवा शुरू करके गांवों में सुविधाएं दीं। गत सरकार में लोगों में ऐसे भाव प्रकट हुए कि लोक परिवहन के नाम से कोई सैटिंग क्या हुई कि उसको रोडवेज के आगे खड़ी करके एक षड्यंत्र रोडवेज को कमजोर करने का किया गया लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि रोडवेज को मजबूत करें।

माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बालोतरा में शानदार बस स्टैंड बना हुआ है। बस स्टैंड में जो रोडवेज का कैबिन आफिस है, वह रोडवेज बस स्टैंड के बाहर रखा हुआ है जिससे लोगों में गलत संदेश जाता है कि जब बस स्टैंड बना हुआ है तो वह बाहर क्यों है? आप मेहरबानी करके पता करवाएं और बस स्टैंड में शिफ्ट किया जाए। करीब 150-200 फिट दूरी पर बाहर रखने का कोई तुक नहीं है।

इसके अलावा, कई अमूल्य सुझाव आए हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी ने भी कहा था और पूरे बाड़मेर जिले की भावना है कि जयपुर से गडरारोड जो बस है, यह सबके हित में है, किसी एक तहसील या एक विधान सभा के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए सबसे सस्ता सफर जयपुर टू गडरारोड और गडरारोड से जयपुर है।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बालोतरा टू पाली वाया समदडी जो रूट है, इसके ऊपर चल गई तो आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा जोधपुर से बाड़मेर, बालोतरा से बाड़मेर तो प्राइवेट बसें नहीं चलतीं। जोधपुर और बालोतरा के बीच में अगर लग्जरी सुविधाएं कर दी जाएं और प्राइवेट के ऊपर सख्त पाबंदी हो तो दावे के साथ कह सकता हूं कि रोडवेज शानदार मुनाफे में आ सकती है। यह शानदार रूट है और रोडवेज के हित में हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यात्री भार के अगर हम आंकड़े देखें तो आपकी काबिलियत और मेहनत की वजह से आज 76.5 प्रतिशत बढ़ा है। हर क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि मुनाफे के साथ में आम जन के हित को देखते हुए चाहे बसों की खरीद का मामला हो, चाहे इलैक्ट्रिक बसें हो, शानदार प्रबन्धन आपने किया है, आगे भी करेंगे। हमारी सरकार में शानदार रोडवेज चले क्योंकि आम आदमी की नजर है कि सरकारी बस आएगी और मैं मेरे घर तक या जहां भी जाना है, वहां जाऊंगा। इन सब बातों के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आज आपने मुझे इसके ऊपर समय दिया। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पर चर्चा करने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को और माननीय मंत्री यहां बैठे हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की तकलीफ को देखते हुए इन्होंने876 बसें खरीदी है। परन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो नई बसें खरीदी हैं, ये गांव में तो जा नहीं पाएंगी, इसलिए मंत्री महोदय आपने 876 बसें खरीदी हैं तो 876 मिनी बस भी खरीदें, जो हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिन ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिले। अगर यह खरीदो तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, यह जो यात्री भार बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये राजस्थान परिवहन निगम की बसें तो चल ही रही हैं, इसके साथ में जो लोकल बसें चल रही हैं, इनकी मोनिटरिंग के लिए भी आप करें कि कितनी गाड़ियों के पास में तो परमिट हैं और कितनी गाड़ियां बिना परमिट के चल रही हैं? मेरी जानकारी में आया है कि एक गाड़ी का परमिट है, लेकिन उसके साथ आठ-दस गाड़ियां फ्री में चल रही हैं। यहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, ये लोक परिवहन बस का जो परमिट जारी हुआ है, शायद यह राजस्थान स्टेट के लिए है लेकिन ये बसें हरिद्वार, दिल्ली तक भी जा रही हैं। इन गाड़ियां की मोनिटरिंग आप कीजिए ताकि इन गाड़ियां की मानिटरिंग होगी, ये गाड़ियों रूकेंगी तो हमारा यात्री भार भी बढ़ेगा।

(श्री कान्ति प्रसाद)

मंत्री महोदय, सिन्धी कैम्प के आसपास सुबह के टाइम पर देखिए या शाम के टाइम पर देखिए, वहां चींटियों की तरह बसें खड़ी रहती हैं। वहां बसों की क्या व्यवस्था है? उनके परमिट किस-किस को, कहां से आरटीओ ने दे रखे हैं, इन बसों का भी आपको पता करना चाहिए। जयपुर से ग्वालियर जा रही है, जयपुर से भोपाल जा रही है, जयपुर से अहमदाबाद जा रही है और जयपुर से आगरा जा रही है और आपकी जो सरकारी बसें हैं, वे वहां की वहां खड़ी हैं। सिन्धी कैम्प के आसपास आपका सरकारी अड्डा है, वहीं आसपास सारी बसें खड़ी रहती हैं और ये सौ-दौ सौ रुपये किराया कम रखती है इसलिए सारी सवारियां इनमें बैठकर जा रही हैं। इन बसों को परमिट भी अगर आपने दे रखा है तो सिन्धी कैम्प बस स्टैंड से कम से कम दो-चार किलोमीटर दूर इन बसों का स्टैंड होना चाहिए ताकि जो सवारियां जाएं, वे राजस्थान रोडवेज की बसों में बैठकर जाएं और यह बैठेंगी तो इन बसों का यात्री भार बढ़ेगा।

मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जो लीकेज की बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान रोडवेज के डिपो में जो भी चीफ मैनेजर हैं, ये ड्यूटी लगाने के लिए कंडक्टर से पैसे लेते हैं, ड्राइवर से पैसे लेते हैं। उनसे पैसे लेकर उनकी मनमर्जी के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगती है और उसी हिसाब से जाते हैं। इस संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी फिक्स ड्यूटी की जाए। चाहे एक महीने का टाइम उनको दिया जाए, चाहे दो महीने का टाइम दिया जाए, एक या दो महीने फिक्स ड्यूटी कर दी जाएगी फिर बाद में बदलेगी तो शायद उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा और यात्री भार भी हमारा बढ़ेगा। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी को बूंदी जिले का जो बस स्टैंड है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी क्योंकि चर्चा रोडवेज बस पर हो रही है और एक गरीब का, एक तरह से कहा जाए तो ये ही रथ है और इसी में बैठकर अपने गन्तव्य तक गरीब पहुंचता है। वर्तमान में बूंदी की जो स्थिति है, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय चांदना जी तो यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी भी जानकारी में है कि बिल्डिंग वर्तमान में पूरी टूटी हुई है। जो स्टेट टाइम की बिल्डिंग थी, उसकी अगर दुर्दशा देखें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि बूंदी का ऐसा बस स्टैंड हो सकता है। दूसरा, वहां पर सड़क

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी यात्री जाते हैं, इतनी धूल उड़ती है कि उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आधे से ज्यादा स्टाफ रिक्त है। इससे बहुत ज्यादा परेशानी रोडवेज बस को चलाने में हो रही है। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि आपका जो निगम मंडल है, उसको एक प्रस्ताव भेजा गया था कि इस बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट किया जाए। निगम मंडल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद लोकल स्तर पर इसकी शिफ्टिंग का चल रहा है। मेरा निवेदन है कि या तो हम नया बस स्टैण्ड बनाएं, उसमें इसको शिफ्ट करें या पुरानी धान मंडी में ही इसको शिफ्ट किया जा रहा है तो इससे जनता को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है, दूरी भी बढ़ेगी।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि आप कुछ नई बसें चला रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। पिछली बार मैंने एक बात यहां उठाई थी कि रोड टैक्स को कम किया जाए और वह आपने किया था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगी लेकिन जिस रोडवेज़ बस पर सब विश्वास करते हैं और खासकर महिलाओं को तो बहुत विश्वास होता है, उसका एक जीता जागता नमूना शनिवार को कोटा हाड़ौती के अखबारों में बहुत बड़ेबड़े शब्दों में आया कि एक महिला टीचर जो कोटा से सुकेत झालावाड़ अपने स्कूल में पढ़ाने जाती है, वह बस में बैठी, उस महिला टीचर के साथ बस चालक ने किस तरह अभद्रता की। मैं मानती हूं कि यह बहुत गलत है। उसको 2 किलोमीटर पहले ही रास्ते में जबरदस्ती उतारकर चला गया। पूरे मीडिया में यह सुर्खियां बनी हुई थी। निश्चित तौर पर ऐसे कर्मचारी हैं उन पर भी हमारा कहीं न कहीं कुछ अंकुश हो, इस पर भी हमें कुछ करना चाहिए। उस महिला ने आपके डिपो मैनेजर साहब को रिपोर्ट दी, मुझे लगता है कि उसको कुछ राहत मिलेगी। बस नंबर है RJ20- TA 439. माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात सुनें। एक महिला टीचर के साथ आपके बस चालक ने अभद्रता की है, शनिवार का पेपर हमने देखा, मीडिया में सुर्खियों में था, बस का नंबर RJ20- TA 439. आप इसकी जांच करवाइए। आपके डिपो मैनेजर साहब को लिखित में उस महिला ने शिकायत दी है।

मेरा दूसरा निवेदन है, हमारे यहां केशोरायपाटन में संवीदी नाम से जो बस चलती थी, उस बस का अता-पता नहीं है। पिछले एक वर्ष से वह बस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

वहां पर नहीं चल रही है, इससे गरीबों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। चौतरा का खेड़ा रूट पर भी हमारी कोई बस नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि जो बसें पूर्व में चल रही थीं, कम से कम उनको तो चलाया जाए।

दूसरा, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रोडवेज़ को करोड़ों रुपये की सब्सिडी देने के बावजूद भी हमें यह बात सोचनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि जनता को इसका कितना लाभ मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि रोडवेज बस परमिट के अनुसार विभाग की समय सारणी है। जिस प्रकार हम निजी बस संचालकों को देते हैं, निजी बसों पर समय सारणी लिखी होती है, उसी तरह से हम रोडवेज बस में क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने समय सारणी का किया तो जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। हम लोग लगातार घाटे में चल रहे हैं।

साथ ही, मेरा आपसे निवेदन है रोडवेज़ बस को आप परमिट देते हैं, उस पर भी अगर बस नंबर लिखेंगे तो कहीं न कहीं करप्शन रुकेगा, बसों की सुविधा है, हमारी रोडवेज बसें चलती हैं, उसका अच्छा संचालन होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा लाभ होगा। उसमें रोड नंबर डालेंगे तो और ज्यादा ठीक रहेगा ताकि जनता भ्रमित नहीं हो। जनता हमेशा इससे भ्रमित होती है। यह प्राइवेट बसों में भी है और हमें भी करना चाहिए।

एक और मेरा निवेदन है कि कंडक्टर के साथ जो स्टेपनी कंडक्टर चलते हैं, अव्यवस्था ज्यादातर इन्हीं की वजह से हो रही है। मैंने विगत 2 वर्ष पूर्व भी देखा था चेचट की, हमारे दिलावर जी भाई साहब बात कर रहे थे, एक कंडक्टर की वजह से हमारी बस लोस में चलती है। उनके व्यवहार की वजह से वह बस लोस में चलती है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि खासकर रोडवेज बस में स्टेपनी कंडक्टर रखे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हम यात्री भार की बात कर रहे हैं। चाहे मेरी विधान सभा में लाखेरी नगरपालिका को ले लें, चाहे केशोरायपाटन को ले लें, हम यात्री भार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यात्री भार बढ़ेगा कैसे। आप देखिए, बस स्टैंड तक हमारी बसें नहीं जा पातीं। जनता लगातार आंदोलन करती है, संघर्ष करती है और बाईपास रोड से बसें निकल जाती हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमने बस स्टैंड बनाए, उन बस स्टैंड तक हमारी बस जाएगी तो यात्री भार पूरा हो जाएगा।

अभी-अभी गर्ग साहब बोल रहे थे 5 करोड़ रुपये 1000 टिकट ऑनलाइन काटने के दे रहे हैं। हमारे विभाग की यह कितनी बड़ी कमजोरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी। यह हालत इस विभाग की हो रही है, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। दूसरा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, पूरे कोटा संभाग की बात करें तो देखिए....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, इतने इम्पोर्टेंट मैटर पर माननीय सदस्या बोल रही हैं, लेकिन मंत्री महोदय को फुर्सत ही नहीं है कि उनकी बात को सुनें। एक महिला यहां इतना अच्छा बोल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिए। अंकित नहीं होगा

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: न केवल वह सुन रहे हैं, बल्कि आपके वक्ता हैं उनको भी सारा कुछ समझा रहे हैं, यह परेशानी है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मुझे लगता है मंत्री जी शायद दोनों की ही सुनेंगे। हमारे कोटा संभाग में रोडवेज़ की इतनी बसें हैं और कितने परमिट हैं, अगर बस कम और परमिट ज्यादा होंगे तो मुझे लगता है कि यह भी एक तरह से हमारे लिए रेवेन्यू लोस है। मंत्री जब जवाब दें तो इस बात को बताएं कि डबल से ज्यादा परमिट और बसों की संख्या बहुत कम, इस लोस को हम किस तरह से रोकें, इस ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ, बस नंबर और समय सारणी उसके साथ अटैच करेंगे तो यह बहुत अच्छा हो सकता है। रेवेन्यू वसूली भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं।

साथ ही, मेरा निवेदन है कि हैड आफिस में अनेक बार देखने को मिला है, अधिकारियों की कहीं न कहीं जवाबदेही होनी चाहिए। लगातार वसूली की बात आती है। हम लोगों के पास भी फोन आते हैं। हम किस तरह से अधिकारियों की जवाबदेही रखें, इसके लिए भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, विभाग का ध्यान जाना चाहिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत सारी बस संचालन का भी किया है। मात्र और मात्र बूंदी में अभी वर्तमान में रोडवेज़ की 65 बसें चल रही हैं। आप नई बस खरीदने की बात कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहती हूं कि हमें कुछ बसें बूंदी ज़िले को और पर्टिकूलर मेरी विधान सभा क्षेत्र में देंगे तो गरीब जनता को इसका लाभ मिल सकता है, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

हमने देखा है कि ठेकेदारी में चलने वाली कंडक्टर की बसें हैं, उनको आज तक कभी भी चेक नहीं किया गया है, यह विभाग की बहुत बड़ी खामी है। मुझे लगता है कि यह भी जबरदस्त लोस का कारण बन रहा है, इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, पूर्व में हमारी रोडवेज़ की बस कोटा ग्वालियर वाया श्योपुर व कोटा-खंडवा बुरहानपुर, ओंकारेश्वर की रोडवेज़ बस चलती थी, उसको बंद कर दिया गया है। कोटा की जनता को, पूरे संभाग की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था। पुनः उसको चालू करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा काम हो पाएगा। बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे अहम मुद्दा, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने रोडवेज़ निगम को सुधार कर निगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। गत एक साल में जो कदम उठाए हैं, जो काम किए गए हैं, वह बहुत सराहनीय कदम है। 31 मार्च, 2020 तक 876 नई बसें क्रय कर रोडवेज़ में शामिल करने का लक्ष्य है, उसमें 51 बसें आगारों को आवंटित की जा चुकी हैं, यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, अमीर आदमी तो अपनी निजी गाड़ी से भी सफर कर लेता है, लेकिन गरीब आम आदमी रोडवेज़ के लिए यात्रा करने का बहुत ही सुलभ साधन है। इसमें सुविधाएं बढ़ाना आमजन को फायदा पहुंचाने के लिए होगा। मैं हमारी सरकार, मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि

(श्री हाकम अली खां)

इन्होंने अल्पकाल में ही रोडवेज़ पर ध्यान देकर, रोडवेज़ के बंद होते बेड़े को जिंदा करने का लक्ष्य लिया है। सभापति महोदय, लंबी दूरी की बसों में यात्रियों को मनोरंजन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार द्वारा लंबी दूरी के 2000 वाहनों में एलईडी टीवी लगाने के लिए 8 वर्ष का एक फर्म से अनुबंध किया है जिसके तहत अब तक लगभग 700 वाहनों में एलईडी टीवी लगाई जा चुकी है। इस फर्म को 75:25 के अनुपात से एयर टाइम आबंटित किया गया है, जिसमें 75 प्रतिशत समय में मनोरंजन और 25 प्रतिशत समय में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, विज्ञापन का प्रसारण किया जाएगा जिससे निगम को प्रतिवर्ष तकरीबन तीन करोड़ रुपये की गैर संचालन आय प्राप्त होगी तथा निगम को किसी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, निगम की राजस्व बढ़ोतरी के लिये और खर्चों पर नियंत्रण के उपायों में हमारी सरकार ने जयपुर-सीकर एवं जयपुर-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली समानान्तर मल्टीपल सेवाओं की तार्किक एवं वैज्ञानिक तरीके से री-शिड्यूलिंग कर गत तीन माह में प्रतिदिन राजस्व में औसतन 30 लाख की वृद्धि एवं संचालन व्यय में लगभग तीन से चार करोड़ रुपये की मासिक बचत की है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

यह रोडवेज बचेगी तो आमजन को फायदा होगा, गरीब को फायदा होगा। लास्ट छोर के ऊपर गरीब बसता है, उसको भी सफर करने का लाभ मिलेगा। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने पहले 2013 में सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड नया बनाने का जो शिलान्यास किया था, वह पांच साल तक बनने का इंतजार करता रहा। मैं हमारी सरकार से, हमारे मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोग पहले बनाना तो दूर, सिंधी कैम्प को बेचने के लिये भी तैयार हो गये थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा रोडवेज कर्मचारियों को कि उन्होंने आंदोलन करके सिंधी कैम्प के बस स्टैण्ड को बचा लिया। अब उस सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड पर भी ध्यान दिया जाये और उसको तैयार किया जाये।

महोदय, पूर्व में रोडवेज निगम में बस आपरेटरों से बसें अनुबंध पर ली जाती थीं, जिससे सब बस मालिक अपनी एक या दो बसें अनुबंध पर लगा देते थे तथा अपनी रोजी-रोटी कमाते थे परन्तु गत भा.ज.पा. सरकार ने किसी रसूखदार बड़ी कम्पनी से बसें हायर करके महंगी दर पर गाड़ियां अनुबंध पर लेकर

(श्री हाकम अली खां)

निगम का तो घाटा किया ही, इसके साथ ही छोटे-छोटे बस आपरेटरों का रोजगार छीनने का काम किया था, इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाये कि पहले की तरह छोटे बस आपरेटरों से वाहन अनुबंध पर लिया जाये और उनको रोजगार दिया जाये।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि रोडवेज निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पिछले 4-5 साल से, जो उनका पे-लाभ है, वह नहीं मिल रहा है और कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो उनके परिवार का लालन-पालन, पोषण कैसे होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हीं की राशि में से कोई योजना बना करके उनको कुछ दिया जाये तो उनका परिवार चल सके।

सभापति महोदय, गत भा.ज.पा. सरकार ने रोडवेज निगम को बिलकुल बंद करने की मंशा बना ली थी। बिना कोई सोचे-समझे लोक परिवहन बसों को परमिट जारी किये थे। इन बसों को जरूरत से ज्यादा परमिट जारी कर दिये। इससे हर रूट पर आगे-पीछे बसें लगी रहती हैं तथा समय कम मिलने के कारण, यह वाहन बहुत तेज गति से चलते हैं, जिसके कारण आये दिन लोक परिवहन बसों की दुर्घटनाओं के समाचार मिलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था लोक परिवहन बस का, 11 मौतें एक साथ हुई थीं। थोड़े दिन पहले डूंगरगढ़ के पास एक लोक परिवहन बस का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 13 मौतें एक साथ हुई थीं। आये दिन अख़बार में पढ़ने को मिलता है कि लोक परिवहन बस के एक्सीडेंट में दो आदमी मर गये, एक आदमी मर गया। इसका कारण है कि लोक परिवहन बसों को टाइम कम दिया गया था और वह सवारियां उठाने के चक्कर में एक के पीछे एक, आगे-पीछे भागते हैं। बस अनकण्ट्रोल होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कई जिंदगियां लील लेती है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस लोक परिवहन को परलोक का नाम दिया गया। इस परलोक पर ध्यान दिया जाये, जिससे आने वाले समय में कई जिंदगियां बच सकती हैं तो इसके लिये कोई कठोर नियम बनाये जायें, जिससे इन बसों को संचालित करने में दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो निजी बसें संचालित हैं वे दिन-ब-दिन बंद होती जा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिये शहर में जब वे आते हैं, तहसील कार्यालय में या एस.डी.एम. कार्यालय में या शहर-बाजार में कोई

(श्री हाकम अली खां)

सामान लेने के लिये तो वे बसें बंद होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद होने का कारण यह है कि एक तो डीजल महंगा हो गया, ऊपर से टैक्स की उसके ऊपर इतनी मार कर दी और महंगाई, जैसे अभी बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि टायर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, टैक्स हो गया, तो मैं निवेदन करूंगा, उनको राहत देते हुए टैक्स में उनको कुछ छूट दी जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रूट्स पर वापस निजी बसें संचालित हों, वे बसें चलें और आमजन को फायदा मिल सके। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, 55 साल का लम्बा गौरवमयी इतिहास, ये केवल बस नहीं, यह राजस्थान के करोड़ों लोगों की हृदय की धड़कन है। अभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार अपने-अपने हिसाब से व्यक्त किये लेकिन हम सबको व्यक्तिगत रूप से यह मानना पड़ेगा कि इस धड़कन की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो रही है।

माननीय मंत्री जी अभी यहां विराजमान नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यही निवेदन करूंगा कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। थोड़ी देर पहले सिरोही से चुनकर आये वरिष्ठ विधायक महोदय ने, जिनका हर क्षेत्र में बहुत लम्बा अनुभव है, बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी बताईं। हम धन्यवाद भी देते हैं कि कहीं न कहीं अनुभव का लाभ भी मिलता है। मैं चूंकि प्रथम बार चुनकर आया हूं और मैंने जो पिछले इस पूरे सप्ताह में, चाहे वह महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, चाहे दूसरे जो भी, सदन जो चल रहा था, मैंने यहां कई चीजें महसूस भी कीं। सत्ता पक्ष में भी कई वरिष्ठ विधायकों ने बहुत अच्छी संतुलित विचारधारा की बातें कहीं। हमारे माननीय विपक्ष के नेता गुलाबजी ने जो अपने अनुभवों की बातें कहीं, ईमानदारी से इन सब बातों पर सोचने का वक्त आ गया है।

देश को आजाद हुए 70 साल हो गये, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी, सत्तापक्ष के अनेकों लोगों ने, जो आज देश के अन्दर

(श्री नारायण बेनीवाल)

निजीकरण बढ़ रहा है, जो नवरत्न कम्पनियां धीरे-धीरे निजीकरण की तरफ जा रही हैं, उस पर भी अपने विचार व्यक्त किये। आपने बड़े तीखे अंदाज में यह भी कहा कि हमने नवरत्न कम्पनियां बनाईं। मैं तो कहता हूं, धन्यवाद, कि आपने आई.आई.टी. बनाया, आपने आई.आई.एम. बनाया, इसरो बनाया, एयर इंडिया, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की कम्पनियां, आपने बनाईं, उनके लिये भी धन्यवाद। लेकिन एक चीज हमें महसूस करनी पड़ेगी कि कितना भी सुन्दर शरीर बना लो, लेकिन कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी उस शरीर को लग गई तो सुन्दर शरीर का कोई महत्व नहीं है। भ्रष्टाचार भी पिछले लम्बे समय से है। इस भ्रष्टाचार का जो मुख्य मुद्दा है, उस पर भी विचार-विमर्श इस सदन के अन्दर होना चाहिए कि आखिर यह जो रोग है, यह क्यों बढ़ा? इसके लिये कौन उत्तरदायी रहा? यह तो शुक्र करो कि दिल्ली के चुनावों का रिजल्ट आ गया। जो अभिभाषण की मुख्य बातें थीं, जो इस प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसके हित के जो मुद्दे थे, उनको हम भूल गये। अधिकांश समय विपक्ष के लोगों ने सत्ता पक्ष के लोगों को और सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्ष के लोगों को, सिर्फ दिल्ली के चुनावों के परिणामों पर अपना समय खराब किया। किसी ने कहा कि शाहीन बाग़ का रिजल्ट था, किसी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा था, किसी ने नोटबंदी की बातें कहीं, उसके लिए सारा सिस्टम दिल्ली के अंदर मौजूद है, उसकी चर्चाएं वहां पर होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर साढ़े सात करोड़ लोग आज टकटकी लगाये बैठे हैं कि हमारे जन-प्रतिनिधि सदन के अंदर गये हैं, बजट सैशन चल रहा है तो कोई न कोई बड़ी योजनाएं हमारे लिए आएंगी लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि हमने अधिकांश समय ऐसे मुद्दों पर जाया किया जिसकी मेरे हिसाब से यहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर हम एक नजर में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का विश्लेषण करें तो मार्गों की संख्या 2009 में 2728 से 2018-19 में 2421 हो गयी। 2009 में मार्गों की संख्या जो 2728 थी वह वर्ष 2013-14 के अंदर 2438 हो गयी, उस समय सरकार किसकी थी? इन सब बातों पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। देखिए, समय की जो आवश्यकता है वह सच सुनने और सच बोलने का माद्दा पैदा करने की आवश्यकता है। इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हम

(श्री नारायण बेनीवाल)

सब लोग नैतिक रूप से कमजोर हुए हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि सिर्फ राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ही नहीं, हम पूरे प्रदेश की बात करें। हम 200 लोग हैं, जिनको जनता ने सिर आंखों पर चढ़ाकर, हमें एक जन-प्रतिनिधि बनाकर इस सदन में भेजा है और सामने अधिकारी दीर्घा है। ईमानदारी से यदि हम लोग नैतिक जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे तो ऐसा कोई विभाग नहीं जो घाटे के अंदर जाए। कमी कहीं न कहीं हमारी है। इस कमी को दूर करने की मुख्य चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस चीज पर आज तक किसी वक्ता ने, यदि एक-दो वरिष्ठ विधायकों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा।

मैं इस प्रतिवेदन के जो पृष्ठ संख्या-23 के अंदर है, निर्माण अभियांत्रिकी, आगार कार्यशाला/कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य, जो आबंटित 150 लाख का बजट जो था, उसमें 14.84, यात्री सुविधाएं, स्थाई शैड, बस स्टैंड, प्याऊ, शौचालय इत्यादि का निर्माण 2100, 2100 के अगेंस्ट में 123.15, और तो और मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए जो 150 लाख का आबंटित बजट था, उसके विरुद्ध 71.47 लाख रुपये ही खर्च कर पाए। हम जब आबंटित बजट ही खर्च नहीं कर पाए, मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या हैं? मंत्रीजी चूंकि, विश्वविद्यालय की राजनीति में भी हमेशा बहुत ही आक्रामक लगते थे और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप उसी आक्रामक तरीके से यह जो बेड़ा राजस्थान सड़क परिवहन निगम का है, इसको आप बहुत दबंगता से आगे ले जाने की कोशिश करें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा।

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कई बातें अच्छी भी कहीं। निश्चित रूप से हम सबका यह परम दायित्व है कि कोई भी वरिष्ठ सदस्य यदि सिस्टम को लेकर अच्छी बात कहता है तो उसको मानना हमारा परम धर्म है। मण्डावा से आने वाली माननीय सदस्या ने जो पी.पी.पी. माडल की बात कही, माननीय सभापति महोदय, मेरा सहकारी तंत्र में लंबा अनुभव रहा है। आपको जहां पर भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो सम्पत्ति है और जो काम नहीं आ रही है, उसको आपके निगम के ही पूर्व कर्मचारी या ऐसे लोग जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं या ऐसे लोगों की एक सहकारी समिति बनाकर पी.पी.पी. माडल, एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं और निजीकरण यदि आपने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): पी.पी.पी. माडल है तो यह निजीकरण की पहली सीढ़ी है तो इसके बजाय आप सहकारी संस्थाएं ऐसी बना के उन लोगों को आप वहां पर जरूर रोजगार दें ताकि वह भी आगे बढ़ेंगे और उनका कल्याण भी होगा।

यात्री भार बढ़ाने की बात थी तो हम एक मिनट के लिए यदि इस सदन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस मान लें, मैं पिछले पांच दिन से यह देख रहा हूं कि ज्यों ही सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सदन के अंदर आये तो यात्री भार बढ़ गया। अधिकारी दीर्घा जो हमने अक्सर खाली देखी, उसके अंदर पांव रखने की जगह नहीं थी, इसका मतलब यह देश व्यावहारिक रूप से आज भी हमारा जो साहित्य है, हमारे धर्म शास्त्र हैं, भय बिन प्रीति न होए गुसाई, उसी सिस्टम पर चल रहा है।

माननीय मंत्री महोदय, आप जहां भी जाएं, उसकी पहले सूचना नहीं होनी चाहिए कि सड़क परिवहन मंत्री किस जिले में कब आ रहे हैं। आप देखिए कि कर्मचारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उनका आकस्मिक निरीक्षण कीजिए, तब आगे बढ़ेगा वर्ना भाषणों से 70 साल से इस देश में कल्याण हुआ नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद पर इसके अलावा मेरे थोड़े से कुछ सुझाव भी हैं कि बसों में जो नवाचार है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह आप लिखकर मंत्रीजी को भिजवाइये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, बिलकुल भिजवा देंगे।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): एक नागौर से हरिद्वार की जो बस है, मैं भिजवा दूंगा लेकिन यह मेरा निवेदन है कि यह लाभ में भी चल रही थी, उसको बंद कर दिया तो आप उसको चालू कराएं। मुझे इस महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज

(श्री वासुदेव देवनानी)

सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने लगभग 30-35 वर्षों के बाद इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से हर प्रतिवेदन पर चर्चा होगी, हम लोग भी उसको पढ़ेंगे अदरवाइज तो प्रतिवेदन आ जाते हैं और सामान्यत: हम लोग उसको रख देते हैं। उस प्रतिवेदन के बारे में जानकारी कराने का यह जो उन्होंने अवसर दिया, इसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा और चिकित्सा के बाद व्यक्ति की आवागमन की आवश्यकता रहती है और उसमें भी यह विशेष रूप से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आवागमन की यह सुविधाएं हर ग्रामीण क्षेत्र को, हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, यह हम सबका दायित्व बनता है लेकिन फिर भी 70 साल के बाद आज भी 9894 ग्राम पंचायतों में 5986 ग्राम पंचायतें रोडवेज की सुविधाओं से वंचित हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है आखिर 70 साल के इस समय के बाद इतनी सारी ग्राम पंचायतें यदि हमारी इस रोडवेज की सुविधाओं से वंचित रहे तो यह निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है। हालांकि, इन बसों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा। मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं लेकिन राजनीति नहीं करूंगा कि इस समय हमारी सरकार के मंत्री ने यह किया, आपकी सरकार के मंत्री ने यह किया, हर कोई भी सरकार आती है तो उसका परिवहन मंत्री बनता है। कोई नहीं चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट घाटे में जाए। हर मंत्री प्रयास करता है लेकिन उसको अधिकारियों के साथ सहयोग कितना मिलता है? आज भी हमें बड़ी पीड़ा हुई हालांकि, युवा नेता, छात्र नेता रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि यह भी बराबर अधिकारियों पर सवारी करेंगे। जनता की सवारी तो यह करते हैं लेकिन आज भी जब अख़बार में पढ़ा कि इनके प्रमुख शासन सचिव ने इनके निर्णय पर ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया तो निश्चित रूप यह कहीं न कहीं अधिकारियों को संकेत देना चाहिए कि जो कुछ जन-प्रतिनिधि, मंत्री ने तय किया, वह ही वहां पर लागू होगा। इस प्रकार की स्थिति होगी तो इनके सारे निर्णय निश्चित रूप से सही दिशा की ओर जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज के पास 3700 बसें हैं, 950 अनुबंधित हैं फिर भी घाटा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है जबकि डेढ़ करोड़ रुपये प्रतिदिन का घाटा है। इसका कारण जो मैं देख पाया कि यात्री भार की

(श्री वासुदेव देवनानी)

लगातार कमी होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है फिर भी रोडवेज की बसों में जो यात्री भार कम हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। वर्ष 2009 में 10.37 लाख दैनिक यात्री थे और 2018 में जाकर यह 8.51 लाख दैनिक यात्री हो गये और इस दौरान राजस्व में भी 6.64 प्रतिशत की कमी आई, इसका कारण क्या है? निश्चित रूप से आम जन, यह व्यक्ति का स्वभाव है कि जहां पर कम किराया लगेगा, वहां पर जाएगा। आज प्राइवेट बसों में कम किराया है और रोडवेज में ज्यादा है। सुविधाएं उनकी ज्यादा हैं तो रोडवेज बस स्टैंड के बाहर आखिर जब प्राइवेट बसें खड़ी रहेंगी तो निश्चित रूप से आदमी जहां कम किराया लगेगा उसकी ओर आकर्षित होकर जाएगा। कई बार योजनाएं बनती हैं कि प्राइवेट बसें रोडवेज बस के बाहर नहीं जाएंगी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मिलीभगत के कारण, मैं अजमेर में देखता हूं कि प्राइवेट बसें रोडवेज के ठीक बाहर मिलती हैं। यात्री आ रहे होते हैं रोडवेज बस स्टैंड की ओर तो वहां से ही वह सवारी उठाकर चले जाते हैं तो आपका यात्री भार तो निश्चित रूप से कम होगा।

साथ में, रोडवेज बसों में सुविधाएं कौन देगा? कर्मचारी देगा। प्रति वाहन कर्मचारी 2009 में 4.43 थे और आज वह घटकर 2.89 हो गये। जब वह कर्मचारी ही नहीं होंगे, प्रति वाहन कर्मचारी कम होंगे तो निश्चित रूप से जनता की चिंता भी कम होगी, उनको इस प्रकार रेस्पोंस भी नहीं मिलेगा। आज भी लगभग 50 प्रतिशत स्टाफ कम है और आपकी कोई नई नीति की किसी प्रकार की कोई योजना अभी नहीं है तो उस पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों है? आपके मार्ग भी कम होते जा रहे हैं। 2009 में 2,728 मार्ग थे और 2018 में 2,230 हो गये, आज की तारीख में और भी कम हो गये होंगे। इसी प्रकार से किलोमीटर भी कम होते गये। इधर कुल आय भी निश्चित रूप से बढ़ी है तो व्यय भी इसके अनुपात में बढ़ा है जिसके कारण से यह घाटा बढ़ता जा रहा है। घाटे का एक कारण ध्यान आता है कि हर सरकार आती है और अपनी लोकप्रियता के कारण, जनता की आवश्यकताओं के कारण कई इस प्रकार की घोषणाएं कर देती हैं लेकिन उन घोषणाओं के कारण जो पुनर्भरण होना चाहिए, वह पुनर्भरण नहीं होता। पुनर्भरण के कारण से रोडवेज घाटे में है। मैं रोडवेज के कर्मचारियों और नेताओं से चर्चा करता हूं तो वे कहते हैं कि क्या करें? सरकार ने कह दिया कि इस कैटेगरी को आधा फ्री

(श्री वासुदेव देवनानी)

होगा, इसको पूरा फ्री होगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री होगा, अच्छा है फ्री करें, लेकिन यह सरकार उसका पुनर्भरण तो रोडवेज को करेगी तभी तो उसकी पूर्ति होगी। फिर दिनों-दिन आय तो कम, लेकिन आपके विज्ञापन और प्रचार पर दुगुना व्यय होता जा रहा है। उस व्यय को भी कहीं-न-कहीं कम करने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन की चर्चा हुई। ऑनलाइन की कम्पनी को आप पांच करोड़ देते हैं जबकि वह एक हजार से ज्यादा टिकट नहीं काटता। क्या उसमें संशोधन होकर जितने टिकट काटेगा, उतना ही उसको कमीशन मिलेगा। उसके साथ यह जोड़ेंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा टिकट काटने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही आपके पांच करोड़ की जगह जो भार होगा, वह कम होगा। आपने कांट्रेक्ट कर लिया या जिस भी परपज से आपने सिस्टम से कर दिया, आज पांच करोड़ रुपये हमारे बेकार के जा रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं कमी करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण बस सेवा के पुन: प्रयास किये जाएं और सबसे बड़ी हमारे यहां एक माननीय सदस्य ने चर्चा की भ्रष्टाचार की। वास्तव में भ्रष्टाचार की बात आती है तो हम एक-दूसरे की सरकार पर आरोप लगाते हैं लेकिन वह भ्रष्टाचार कहां है, वह नीचे के लेवल तक पहुंच गया है और नीचे के लेवल पर इसीलिए है चाहे वह कंडक्टर के लेवल पर हो, चाहे वह ड्राइवर के लेवल पर हो, वे कहते हैं साहब, हमको ऊपर देना पड़ता है। ऊपर कहां देते हैं, यह तो आपका विषय है, आप पता लगाएं। इसके लिये आवश्यक है कि हम लोग इसकी चिंता करें और चिंता करने की जो आवश्यकता है, उसमें सबसे पहला है कि हम कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करें और कर्मचारियों का विश्वास कब होगा, जब उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वह उसकी पूरी हों।

अभी चर्चा आई कि 2016 से लगभग साढ़े तीन हजार कर्मचारी रिटायर हुए हैं। उनको आज तक रिटायरमेंट के परिलाभ नहीं मिले हैं। समय-समय पर आन्दोलन करते हैं। हमारी सरकार के समय में भी उन्होंने मांग की, प्रदर्शन किये और आज भी कर रहे हैं, तो इसकी भी कहीं-न-कहीं चिंता करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिये जरूरी है ड्यूटी लगाना, उसकी जांच आये। वहां का डिपो मैनेजर ड्यूटी लगा देता है, उसके पास पैसा पहुंच जाता है, यह लाभ का मार्ग है, यह हानि का मार्ग है। मार्ग तो सब मार्ग होते हैं लेकिन उसका भी यदि कोई सिस्टम आप बनाएंगे तो इससे भ्रष्टाचार पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहीं-न-कहीं अंकुश लगा पाएंगे। आज आपको आय के साधन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें मैं मांग करूंगा कि तीर्थ-स्थलों के लिये यदि आप पर्याप्त बसें प्रारम्भ करेंगे तो आपको लाभ होगा। यात्री भार भी मिलेगा और उसके आधार पर आपको निश्चित रूप से कहीं-न-कहीं आय में वृद्धि होगी और लंबी दूरी की जो बसें हैं, वह समय का पालन नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, आज घाटे में चल रही रोडवेज को सहारा देने के लिये राज्य सरकार इनके रोड टैक्स माफ करे। यदि रोड टैक्स माफ हो गया तो आपको लगभग 10 करोड़ से अधिक की राशि लाभ में मिलेगी और घाटे के अंदर कमी होगी। साथ में एम.एल.एज. को यदि टोल टैक्स से माफी दी जा सकती है, एम.पीज. को दी जा सकती हैं, दूसरे सरकारी वाहनों को दी जा सकती हैं तो क्यों नहीं रोडवेज बसों का भी यह जो टोल टैक्स है, इसको माफ करेंगे और पूर्ण छूट मिलेगी तो इससे आपके घाटे में कमी ही होगी। रोड टैक्स और टोल टैक्स, दोनों माफ किये जाएं और साथ में यात्रा बढ़ाएं और रोडवेज के पास...(व्यवधान)

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो मिनट लूंगा। कुछ सुझाव ही दे रहा हूं। रोडवेज के पास जो उपलब्ध रिक्त भूमि है उस भूमि पर हम दुकानें या मॉल का निर्माण कराकर, जिस प्रकार एयरपोर्ट हैं या दूसरी चीजें हैं, वहां पर दुकानें निर्मित हो गयीं, उससे भी रोडवेज की आय बढ़ायी जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे अजमेर का जो बस-स्टैंड है, वह इस समय दुर्दशा का शिकार है। यात्रियों के लिए दुपहिया और चौपहिया वाहनों की पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। बस-स्टैंड परिसर में स्थित दुकानों ने आगे अतिक्रमण कर रखा है, उसके कारण से भी यात्रियों को कठिनाई आती है। आप वहां से अतिक्रमण को दूर कराएं और पार्किंग का स्थान बनाएंगे तो लोग आटोमैटिक आगे बढ़ेंगे और बस-स्टैंड पर जो सुलभ शौचालय है, वह काफी पुराना होने के कारण बिलकुल क्षतिग्रस्त अवस्था में है। वहां यात्रियों की सुविधार्थ नया काम्पलेक्स बनाये जाने की आवश्यकता है। वहां पर कोई वेटिंग रूम नहीं है इसलिए वहां वेटिंग रूम बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार इन सुविधाओं को बढ़ाएंगे तो यात्री भी बढ़ेंगे और अवैध बस-स्टैंड अजमेर बस-स्टैंड के बिलकुल सामने से अवैध रूप से निजी वाहन और टैक्सियां धड़ल्ले से सवारियां बैठाती हैं, उसको स्थानीय प्रशासन यदि नो पार्किंग जोन निर्धारित

(श्री वासुदेव देवनानी)

कर दे, वहां पर कोई पार्किंग नहीं होगी, उसके सामने ही पुलिस गुमटी भी है, यदि इस प्रकार की व्यवस्था करे तो हम आगे बढ़ेंगे।

दूसरा, रोडवेज कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करने के लिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं एक बात कहूंगा, आज रोडवेज के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अन्य राज्य कर्मचारियों को तो 300 पी.एल. संचय करने की सुविधा है, जिसका सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी किया जाता है, लेकिन रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनको केवल 60 पी.एल. ही रहती है, अत: उस पी.एल. को बढ़ाया जाए तो यह चीजें आगे बढ़ेंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो-तीन बातें कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सुविधाओं को बढ़ाएं, सहूलियतों को बढ़ाएं तो समय पर वेतन व डी.ए. कर्मचारियों को दें। अंतिम सुझाव कि इसके लिये विधान सभा की एक समिति बनाएं जिसमें पुराने यातायात परिवहन मंत्री हों, नये भी हों, आपस में मिलकर तय करें कि किस प्रकार से रोडवेज को लाभ में लाया जा सकता है और घाटे से बचाया जा सकता है। सर्वदलीय समिति बनेगी, सबके सुझाव आएंगे। कोई भी हममें से नहीं चाहता कि रोडवेज घाटे में चले लेकिन हम सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। यह घाटे में न जाए इसलिए आप और हम, सब मिलकर इस प्रकार के सुझाव एक साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और वह विधान सभा में आये तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि रोडवेज फायदे में जाएगी। आइए, हम राजनीतिक बातों को छोड़कर रोडवेज को किस प्रकार से लाभ में लाएं, सर्वसम्मति से हम इस दिशा में कुछ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो आज घाटा हो रहा है, वह राजकोष का हो रहा है, उससे हम बच सकेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सड़क परिवहन प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पर चर्चा के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुतसी पालिसीज नई बनायी गयीं। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस सरकार ने हर बोर्डों का गठन करने, उसमें सम्पत्ति जुटाने, बसें खरीदने और

(श्री रफीक खान)

तमाम तरीके के काम किये और एक पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की। राजस्थान जो कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान रोडवेज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अलग-अलग जगह बसें पहुंचाने की और यात्रियों को लाने-ले जाने की। कांग्रेस सरकार ने एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया और उसमें बहुत सारी नई चीजें इन्होंने अनाउंस कीं, उसके लिये मैं हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखिए। माननीय विधायक, आप अपने स्थान पर जाइए, आपका नंबर भी आने वाला है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): स्व-संचालित यात्री उद्घोषणा प्रणाली, मनोरंजन प्रणाली, यात्री मनोरंजन प्रणाली और काफी सारे काम मंत्रीजी ने किये, मैं इनको धन्यवाद और बधाई दूंगा। अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी बहुत सारी बातें कह रहे थे और बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन भी दे रहे थे कि रोडवेज को घाटे से उबारा जाए। घाटे से कैसे उबारा जाए? तीन हजार करोड़ रुपये का घाटा तो इन्होंने पिछले पांच सालों में बुक कर दिया। हमारे मंत्रीजी ने आने के बाद में इसमें बहुत बड़े सुधार का काम किया और मैं यह गर्व से कह सकता हूं कि करीब 500 करोड़ रुपये का पर-ईयर घाटा इन्होंने कम किया है। 700-750 करोड़ रुपये का घाटा पर-ईयर इनके पूरे पांच सालों के राज में था, जो इस साल घटकर पौने दो सौ पर आ गया है तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि एक बहुत बड़े आर्थिक सुधारीकरण के ऊपर रोडवेज जा रहा है और हम सबको मिलकर इनका सहयोग करना चाहिए।

जहां तक इकोनोमिक रिसेशन की बात आ रही थी, अनिता भदेल जी बोल रही थीं। इन्होंने तो प्राइवेट उपक्रम बेचने में कसर ही नहीं छोड़ी और आप सबको शायद मालूम नहीं होगा कि जहां आज मैरियट होटल बनी हुई है, रेडिसन होटल बनी हुई है, वह रोडवेज डिपार्टमेंट की जगह थी। इन्होंने 2003 से 2008 के कार्यकाल में वह सारी जमीन बेच दी और बेचकर खा गये और उसके सारे पैसे को कहां ले गये, कोई नहीं जानता। वह सारी की सारी सम्पत्ति रोडवेज डिपार्टमेंट की थी। वह अकेली सम्पत्ति होती तो रोडवेज घाटे से बरी हो चुकी होती। बहुत सारी कम्पनियां आजकल हम सुनते हैं, चाहे रेलवे का मसला हो, चाहे बी.पी.सी.एल. का मसला हो, एयर इंडिया का सब जानते हैं, किस तरह से एयर इंडिया को घाटे में लाया गया और किस तरीके से उसको बेचा जा रहा है।

(श्री रफीक खान)

मैं इस बात का गवाह हूं कि जब टिकट मांग रहे हैं जब एयर इंडिया की टिकट बुक करने जा रहे हैं तो एयर इंडिया टिकट देने से मना करता है, बुकिंग करने से मना करता है और यह कहते हैं कि, साहब, फ्लाइट फुल है। जब फ्लाइट में जाकर बैठते हैं तो आधे से ज्यादा फ्लाइट खाली पड़ी है। तो इन्होंने जान-बूझकर षड्यंत्र करके एयर इंडिया को घाटे में बनाया ताकि इसको बेचा जा सके। चाहे एल.आई.सी. का मसला हो, चाहे एम.टी.एन.एल. का मसला हो, चाहे बी.एस.एन.एल. का मसला हो, नोर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको), सीसीआई, कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया, टीएचडीसी यह सब ऐसी कम्पनियां हैं जिनको यह सरकार बेचने जा रही है। इनको जगाना चाहिए, इनको समझना चाहिए।

श्री सभापति: विषय पर आइये आप, विषय पर आइये। माननीय सदस्य, विषय पर बोलिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं एक शेर से इनको जगाने की कोशिश करता हूं,

'वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है,
तेरी बर्बादियों के मश्वरे हैं आसमानों पर,'

हम सुनते आये हैं कि बाड़ ही खेत को खा जाएगी, राजेन्द्र राठौड़ जी, आपणे तो शेखावाटी की कहावत है, बाड़ ही खेत न खा जावैगी तो खेत को के होवैगो? जब हमारे केन्द्र सरकार के मुखिया हैं वो ही ब्लू चिप कम्पनियों को बेचने में लग जाएंगे ...

श्री सभापति: आप विषय पर बात करिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जिन कम्पनियों को बड़ी हार्ड वर्किंग से, बड़े दृढ़ निश्चय से उनको कंस्ट्रेक्ट किया गया, उनको खड़ा किया गया, ये उनको बेचने में लगे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि ये लोग सरकार को बेच दें और हम यहां विधान सभा में खड़े हैं, अगर बी.जे.पी. का राज होता तो क्या पता विधान सभा की भी बोली लग जाती।

देवनानी जी ने प्राइवेटाइजेशन की बात की, चले गये, अभी मौजूद नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये तो रोडवेज की बसेज को, रोडवेज को बेचकर खतम कर देते, यह तो इनकी सरकार चली गई, इनकी चली नहीं और आज पोजिशन यह है कि हम पर-ईयर 500 करोड़ का घाटा कम कर पाये हैं।

(श्री रफीक खान)

जो एवरेज 3500 करोड़ का घाटा पांच साल में था, बिलो 200 करोड़ आ गया है, तो इसके लिए मैं हमारे मंत्री जी को बधाई दूंगा।

एक बात मंत्री जी से आग्रह करूंगा चूंकि हमारी विधान सभा का मसला है, आज अख़बार में भी आया है। हम काफी दिनों से, एक साल से इंतजार कर रहे हैं कि बसें मिलेंगी, जयपुर को इलैक्ट्रिक बसें मिलेंगी। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो गई, मुख्य मंत्री जी ने उस पर अपना जवाब दे दिया और यह तय हो गया कि हम नई बसेज खरीद कर देंगे, 51 नई बसेज आएंगी, आज फिर कोई आई.ए.एस. अधिकारी बीच में उठते हैं और उसमें सौ तरह के आब्जेक्शन लगाते हैं। मंत्री जी, इस पर विस्तृत जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये बसेज हमें मुहैया करायी जाएं ताकि हम जनता को जो कमिटमेंट कर चुके हैं उनकी पूर्ति कर सकें और उनको जवाब दे सकें।

अनिता भदेल जी ने कहा कि कु-प्रबंधन था। कु-प्रबंधन पिछले पांच सालों में था, एक साल में कु-प्रबंधन नहीं है। एक साल में, रिकार्ड पर कह रहा हूं 500 करोड़ का घाटा कम हुआ है पर्स-ईयर।

मंत्री जी का हौसला अफजाई के लिए मंत्री जी के लिए एक कविता बोलना चाहूंगा, मंत्री जी, गौर फर्माना,

'चल रहे हो तुम, चल रहा है कारवां,
बनो तो तुम, पथिक बनो ताकि लोग सुना सकें तुम्हारी दास्तां,
एक सफर नामुमकिन सा असीम चुनौतियों भरा, पग-पग पर हो कठिनाई,
तुम निकल पड़ो कुछ अलग करने को, तुम्हारे पीछे पडा है सारा कारवां।'

बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा। श्री लक्ष्मण मीणा नहीं हैं। (अनुपस्थित) श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन, 2018-19 पर में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

मेरे से पूर्व वक्ता इतनी बड़ी संस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसके बारे में सुझाव दे रहे थे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इस

(श्री आलोक बेनीवाल)

राजस्थान का सबसे बड़ा जो देश का भू-भाग है उसको इस कौने से लेकर उस कौने से जोड़ने का काम यह संस्था करती है। आप भलीभांति जानते हैं, मैं पहली बार इस विधान सभा में जीत करके आया हूं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उन पर आमजन का सबसे बड़ा विश्वास होता है और जो यह हमारा राजस्थान राज्य सड़क पथ परिवहन निगम है, राजस्थान की जनता इस पर बहुत बड़ा विश्वास करती है, अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है लेकिन दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकार ने, जो आज बातें कर रहे हैं अगर थोड़ा-बहुत भी उस पर ध्यान देते तो आज इसकी स्थिति यह नहीं होती जो आज यह करके गये हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को कि इस इतने बड़े सार्वजनिक उपक्रम को बचा करके, यहां इसके घाटे की बात कर रहे थे, इसके प्रोफिट की बात भी कर रहे थे और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री महोदय पर कि इस संस्था को, निश्चित तौर से जनता से जुड़ी हुई यह संस्था है इसको घाटे से भी उबारेंगे और जनता में इसके प्रति जो विश्वास है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे, यह मैं जानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम जब पहले विधायक तो नहीं थे लेकिन सार्वजनिक जीवन में थे, रहे हैं और जब पिछली सरकार के समय परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने लगातार बहुत बड़े-बड़े आन्दोलन करे, रैलियां कीं लेकिन पूर्ववर्ती सरकार को जितना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए था नहीं किया, आज वह सारा भार हमारी सरकार पर आया है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इसका जिक्र अच्छे से किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार करके इसको उबारने का भी और इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम भी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं।

चाहे बस खरीदने का मामला हो, चाहे इलैक्ट्रिक बस खरीदने का मामला हो, चाहे कर्मचारियों को पेन्शन देने का मामला हो, चाहे उनके रिटायरमेंट के बाद जो अधिकार बनते हैं, उसको परिलाभ देने का मामला हो, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप उसके ऊपर भी ध्यान दें।

साथ ही इस विभाग में, इस निगम में मेरा क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की एक यूनिट काम करती है और लगभग 1975 में इसकी शुरूआत हुई थी। 2013 में डिपो बना, इसको

(श्री आलोक बेनीवाल)

पहले बंद कर दिया गया, इसको कोटपूतली से जोड़ा गया, 2013 में पुन: इसकी शुरूआत की गई, उसके बाद से लगातार यह यूनिट मेरे शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में काम कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस यूनिट ने इस निगम को अच्छी आमदनी करके दी है। लगातार वह इस विभाग और निगम को प्रोत्साहित करके और निगम के जो टारगेट हैं उनको पूरा करने का काम कर रही है। जब भी इस निगम ने जो टार्गेट दिए हैं उससे अबव जाकर इस यूनिट ने काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने उनसे पहले भी निवेदन किया था, आज भी मैं अपनी तरफ से उनको निवेदन करुंगा कि यह जो यूनिट है, इसको आप डिपो बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका कोई ज्यादा वित्तीय भार इस पर नहीं आएगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए, वह वहां मौजूद है। डिपो बनने के बाद में जो रेवेन्यू और सुविधाएं आम जनता को चाहिए वह पूर्ण रूप से आपको वहां मिलेगी। वह आज भी मिल रही हैं और आगे भी मिलेगी।

सभापति महोदय, आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, तब बसें अलाट हुई थीं। उसके बाद पूरे 5 साल निकल गए, लेकिन इस यूनिट को एक भी बस अलाट नहीं हुई है। मेरी इस यूनिट को भी आप बसें अलाट करें और डिपो बनाएं। साथ ही मेरे यहां रेनवाल से दिल्ली, दौसा से दिल्ली, शाहपुरा से सीकर, शाहपुरा से श्रीमाधोपुर, शाहपुरा से बहरोड़, शाहपुरा से जयपुर, झुंझुनूं, अलवर, यह कई सेवाएं हमारे यहां चलने की स्थिति में हैं, लेकिन हमारे पास बसें उपलब्ध नहीं हैं।

मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कर्मचारी वर्ग हमारी इस यूनिट में काम कर रहा है, वह दिल से काम कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर हमें 20 बसें और देंगे तो इससे भी ज्यादा अच्छी रेवेन्यू कलेक्ट करके निगम को देने में हम विश्वास रखते हैं। आपका सहयोग सदा हमारे साथ रहा है। इस सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। मेरी इस मांग को आप निश्चित रूप से पूरी करेंगे, यह आशा है।

मैं इस बात को कहते हुए इतना जरूर कह सकता हूं कि जो यूनिट जो डिपो आपको लगातार प्रोफिट दे रहा है, आप उसका विश्लेषण करें बैठकर कि वह डिपो और यूनिट आपको कैसे प्रोफिट दे रही है। आप उन कर्मचारियों से, अधिकारियों से बैठकर अगर डिस्कस करेंगे तो फायदा होगा। जो डिपो राजस्थान में घाटे में चल रहे हैं, वह किस कारण से चल रहे हैं, उसका अगर

(श्री आलोक बेनीवाल)

आप आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं आपको कमी नजर आएगी। उसको अगर आप दुरुस्त करेंगे तो वह डिपो भी आपको लाभ में मिलने लग जाएंगे। इससे जनता को सुविधा मिलेगी।

राजस्थान प्रदेश की जनता रोडवेज पर बहुत बड़ा विश्वास करती है। चाहे सरकारी संस्थाएं कोई भी हों, पहला विश्वास सरकारी संस्थाओं पर ही किया जाता है। चाहे वह बैंक हों, चाहे राजस्थान आवासन मंडल जैसी संस्थाएं हों, ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं जिन पर आम जनता सबसे पहले विश्वास करती है। जब उनको वहां सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब जाकर वह प्राइवेट के ऊपर आश्रित होता है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, हमारे से जो भी सहयोग होगा इस निगम को आगे बढ़ाने में, उसके लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका, मेरे दल के नेता, प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेन्द्र जी राठौड़ का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, आज 14 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक एक साल पहले इसी 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुबह-सुबह एक आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत दी। मैं इन पंक्तियों के साथ उन वीर जवानों ने जो शहादत दी, उसके लिए उनको पूरे सदन की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं,

'उन आंखों की बूंदों से समंदर भी हारे होंगे,
जब मेहँदी वाले हाथों ने अपने मंगलसूत्र उतारे होंगे'।

उन मां, बहन, बेटी के जज्बातों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं।

सभापति महोदय, आज चूंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी है। प्रेम के प्रतीक का यह दिन है। हो सकता है कि वर्तमान समय में हम लोगों ने

(श्री अविनाश)

इसकी परिभाषा को बदल दिया हो। लेकिन इस दिन का महत्व अगर हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल के अंदर सोचें तो यह वैलेंटाइन डे बच्चों का माता-पिता के प्रति, भाई का बहन के प्रति, पति का पत्नी के प्रति और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बीच में प्रेम होना, इन वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक बन गया है।

सभापति महोदय, मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन की तरफ लौटूंगा। यहां इस विभाग के मंत्री भी विराजमान हैं। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आपने इसी वार्षिक प्रतिवेदन में अंकतालिका 5 और 8 में बताया कि कुल राजस्व यातायात का जो प्राप्त हुआ है, 2017-18 में 184530 लाख रुपये और 2018-19 में 172274.92 लाख रुपये, अगर इन दोनों की तुलना करें तो गत वर्ष से यह 6.64 प्रतिशत कम रहा। इसके अलावा आप ही के विभाग के 31 तारीख तक के जो आंकड़े आपने दिए, उनमें वर्ष 2017 में आपने जो मार्ग संख्या बताई वह 2274 और 2018-19 में 2346 और 2019 में घटकर पुन: 2230 हो गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में माइनस 4.94 प्रतिशत रहा।

सभापति महोदय, कुल मार्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो 2017 में 4.79 लाख किलोमीटर और 2018 में 4.97 लाख किलोमीटर और 2019 में 4.71 लाख किलोमीटर रहा। यह भी घटकर 5.23 प्रतिशत पिछले वर्ष 2018 से कम रहा। कुल शिड्यूल संख्या की बात करें तो वर्ष 2017 में 4185, 2018 में 4395 और 2019 में पुन: घटकर 4214 रह गई। इसका मतलब माइनस 4.11 प्रतिशत रहा।

सभापति महोदय, अगर दैनिक शिड्यूल की बात करें तो उसी अंक तालिका में, इसी वार्षिक प्रतिवेदन में वर्ष 2017 में 17.02 लाख किलोमीटर का फेयर, 2018 में 17.69 लाख किलोमीटर और 2019 में पुन: घटकर 17.3 लाख किलोमीटर रहा। अगर इसकी प्रतिशत में बात करें तो माइनस 3.75 प्रतिशत रहा।

सभापति महोदय, आपने कहा कि पिछले वर्ष साढ़े 3 हजार करोड़ का घाटा था। इस बार यह कम हुआ। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में माननीय परिवहन मंत्री जी, आपकी सरकार और हम सब मिलकर यह कोशिश करेंगे कि यह घाटा भी कम हो।

सभापति महोदय, लेकिन क्या कारण है कि हमारा रोडवेज घाटे में चल रहा है? जहां तक रोडवेज के घाटे में रहने का प्रमुख कारण हम सभी को

(श्री अविनाश)

लगता है, वह असामाजिक तत्वों द्वारा छोटी-छोटी बातों पर जो पथराव किया जाता है, आगजनी की जाती है, उसकी वजह से विभाग को उन बसों के नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रोडवेज को घाटे से बाहर निकालना है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर आप भी यह प्रयोग करें कि जिन असामाजिक तत्वों द्वारा इन राजकीय बसों में, रोडवेज में तोड़-फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है, उनको चिह्नित करके, उनकी सम्पत्ति को सीज और जब्त कर, उसकी भरपाई उन्ही लोगों से करेंगे तो रोडवेज का घाटा भी कम होगा और नुकसान की भरपाई भी होगी। इससे आने वाले समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रोडवेज में आगजनी और तोड़-फोड़ करने की सोचेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में सरकार बनने के पिछले बारह महीने के बाद में लगभग सवा साल इस सरकार को होने वाला है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी रूट की बसें थीं जिनको यह सरकार बनने के बाद से बंद कर दिया गया। चूंकि आप मेरे जैतारण क्षेत्र में पिछली 5 जनवरी को एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर पधारे थे। मेरे क्षेत्र के ग्रामवासियों ने आपका हृदय से स्वागत किया, अभिनन्दन किया और मैंने सार्वजनिक मंच से आपको निवेदन किया था कि मेरे ग्रामीणों की डिमांड है चूंकि मेरा आधा क्षेत्र मगरा इलाका है और आधा मैदानी इलाका है, अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं, वहां आवागमन के साधन नहीं हैं।

मैं आपसे इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र की जो परिवहन बस पिछले दिसम्बर तक चल रही थी, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद, मैं नहीं कहूंगा कि आपने बंद की है आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपको असत्य रिपोर्ट देकर उनको बंद करवाया होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पाली डिपो में आगार प्रबन्धक से भी बात की, ब्यावर डिपो में बात की, कुछ बसें ऐसी थीं जिनको बंद करके पुन: चालू किया गया। मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने बार-बार निवेदन करने के बाद एक रूट पर बस को शुरू किया। 15 दिन के बाद में उस बस को वापस बंद कर दिया गया, जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रेवेन्यू का घाटा हो रहा है, मैंने पूछा किस बात का घाटा हो रहा है, अगर आपने मुझे

(श्री अविनाश)

बताया होता, मैंने डिपो प्रबन्धक से बात की, जब भी आप इस बस को शुरू करें तो कम से कम मुझे इत्तिला करें, तीन-चार दिन तक मैं उसकी मोनिटरिंग करूंगा, तीन-चार दिन तक मेरे अन्य गांव वाले हैं, वह मोनिटरिंग करेंगे और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि जो चालक, परिचालक हैं, वह टिकट बराबर देते हैं कि नहीं देते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो पूर्व का समय था उस बस का, उसको चेंज कर दिया, लोगों को पता ही नहीं चला कि दस दिन के अंदर बस चली थी क्या और फिर वह की वह बात की, टिकट पूरे नहीं देने की वजह से मात्र 30 प्रतिशत जो मेरे खयाल से लगता है कि 30 प्रतिशत टिकट तो देने हैं जो मिनिमम सीमा होती है टिकटों की, वह काटकर उस रूट पर चलाया गया, जिससे पुन: घाटा हुआ और इस वजह से इस बस सेवा को बंद कर दिया गया। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जैतारण क्षेत्र में ब्यावर-मेड़तासिटी वाया रास लाम्बिया बस जो पहले चलती थी उसको बंद कर दिया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और।

पाली-बोरूंदा, पाली-जैतारण-पाटवा होते हुए पाली-करमावास-जोधपुर, पाली-बाबरा, पाली-बूटीवास, मेड़ता वाया बलूंदा-आनंदपुर-कालु होते हुए जो दस-पन्द्रह के करीब प्रतिदिन बसें चलती थीं, उनको भी बंद कर दिया गया। जैतारण से रामावास, लोटुकी, निम्बोल, खराड़ी दिगरना होते हुए जैतारण-पालकिया-घोड़ावड़-बलाड़िया-राजसेवदिया-कुड़की-धनेरिया-लाम्बिया से जैतारण, ब्यावर-सेंदड़ा-झाला की चौकी, काणूजा, कलाळिया, कोट, गिराणा भीम, अगर ये बसें आप पुन: शुरू कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी।

अंत में माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रोडवेज को घाटे से उबारना है तो निश्चित रूप से अभी पूर्व के वक्ता ने बताया था, रोडवेज बसें जितनी भी चलती है उनको राजकीय मार्ग हो, चाहे नेशनल हाइवे हो, चाहे स्टेट हाइवे हो, किसी भी मार्ग पर चलती हैं उनका टोल टैक्स अगर आप माफ कर देंगे सभी सरकारी बसों का तो उससे भी रोडवेज को मुनाफा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिदिन एक गाड़ी का लगभग 2500-3000 रुपये टोल टैक्स चुकाते हैं। अगर आप महीने का हिसाब लगाएंगे तो 80-90 हजार रुपये उनका टोल टैक्स जाता है। यही 80-90 हजार रुपये अगर

(श्री अविनाश)

उसी बस के चालक परिचालक के सैलरी में दे देंगे तो कम से कम इतना तो आपका फायदा होना ही होना है।

माननीय सभापति महोदय, विभाग की बसों का किराया निजी बसों के बराबर अगर आप कर देंगे, आजकल क्या होता है कि प्राइवेट बस वाले पांच रुपये, दस रुपये कम में राजकीय बसों के आगे चलते हैं, उससे भी रोडवेज को घाटा होता है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि राजकीय बस परिवहन की सेवा यह कोई नफे का, नुकसान का सौदा नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ, रोटी, कपड़ा और मकान जितनी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके साथ में यह भी एक आवश्यक सुविधा है, लोगों के आवागमन के अंदर अपने को सुविधा मिलेगी, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय मंत्रीजी, हमें आपकी क्षमता पर कोई शंका नहीं, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान रोडवेज घाटे से बाहर निकलेगा और आपके कुशल मार्गदर्शन में, आपके मंत्री काल में हम चाहेंगे कि यह राजस्थान रोडवेज करोड़ों रुपये के मुनाफे में पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

श्री रोहित बौहरा।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पर विचार

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

(श्री रोहित बौहरा)

आपने मुझे रोडवेज पर चर्चा करने का मौका दिया उसके लिए आपका तहेदिल से धन्यवाद। अध्यक्ष जी का धन्यवाद, इतनी ज्वलंत समस्या पर जहां इतने लोग बोल रहे हैं, रोडवेज पर चर्चा कराने के लिए, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जो बीजेपी ढर्रा बिगाड़ कर गई थी रोडवेज का, उस रोडवेज के बिगड़े ढर्रे को सुधारने के लिए यात्री भार में वृद्धि की, 2016-17 की तुलना में 2019-20 में करीब 7 प्रतिशत यात्री भार में वद्धि हुई इसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, रोडवेज इज ए कामर्शियल आर्गेनाइजेशन, इसको कामर्शियल आर्गेनाइजेशन की तरह से चलाना पड़ेगा नहीं तो हम इस आर्गेनाइजेशन को बहुत दिन तक खींच नहीं पाएंगे। हमें नवाचार करना पड़ेगा रोडवेज में, हमें नई तकनीक रोडवेज में लानी पड़ेगी कि किस तरह से आप चोरी रोक सकते हैं। आपका सबसे बड़ा नुकसान है कि किस तरह से आप चोरी रोक सकते हैं। आज आप चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए आपका घाटा है। आप बसों में कैमरा लगाएं, कैमरा लगाएंगे उससे कम से कम चोरी खतम होगी और आप महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपने नए ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली चालू की, लेकिन उससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कई जगह आपके जो छोटे-छोटे बस स्टैंड हैं वहां पर आपने एजेंट अपोइंट कर रखे हैं वहां आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि आपका क्या हिसाब है क्योंकि आपकी जो आडिट होती है वह एक साल, डेढ़ साल बाद आडिट होती है और जहां चोरी होती है वह आपको पता ही नहीं पड़ता है। जब तक कि आप पूरे सिस्टम को ऑनलाइन नहीं करेंगे। जैसे अभी सरकार ने आते ही मुख्य मंत्री महोदय ने...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, किस चीज की बहस करा रहे हो? सदन में कोरम ही नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सरकार खुद गम्भीर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बीस से ज्यादा सदस्य नहीं हैं।

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) कृपया विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): किस बात की बहस करा रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आप संख्या तो देखो, कोरम ही नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। एक भी शब्द अंकित नहीं होगा इनका।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: इनका कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सदस्य, रामलालजी, आप बैठ जाएं। बहस होने दो। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी आपका यह आचरण है, यह बिलकुल ठीक नहीं है। (व्यवधान) विराजिए। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) विराजिए आप। माननीय श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, यदि हमको रोडवेज को घाटे से उबारना है और हमें सोचना है कि किस तरह से आज मंत्रीजी ने 876 बसें जो कामर्शियली इन्होंने खरीदी हैं, बीजेपी वाले सदस्य बहस कर रहे थे कि आपने ऐसी बसें ले ली हैं कि उनकी वर्कशाप ही नहीं चलेगी। उनका ज्ञान बढ़ाना जरूरी है कि जो बसें ली हैं वे टाटा की बसें ली हैं और टाटा की बसों का आधा बेड़ा रोडवेज के पास है वह टाटा की बसों का है और आधा बेड़ा अशोक लीलेण्ड की बसों का है। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो भी बोलें ऐसा बोलें वह समझ में आए लोगों को और ठीक सत्य की तरह से बोलें, ऐसा अनर्गल आरोप नहीं लगा किसी के ऊपर। मैं उनको बताना चाहूंगा कि टाटा की जो बसें ली हैं और टाटा की नई पालिसी है जो लेटेस्ट माडल की बसें जो ली हैं वे इनको करीब-करीब एक लाख किलोमीटर और पांच साल की गारंटी इनकी पूरे बसों की रहेगी। जिनकी देखभाल मेंटीनेंस का काम पूरा टाटा की कम्पनियां करेंगी, यह एक बहुत अच्छा फायदा इनको मिलेगा क्योंकि आज इनके वर्कशाप्स पुराने हो चुके हैं। मंत्री महोदय, आपको मेरा एक

(श्री रोहित बौहरा)

सजेशन रहेगा कि आपके जितने ओईएम सप्लायर्स हैं, जो कि बसों का माल देते हैं, जो टाटा के ओईएम सप्लायर्स हैं, अशोक लीलेण्ड के ओईएम सप्लायर्स हैं उनको टेंडर से मत निकालिए, टेंडर से कुछ आना जाना नहीं होता है। टेंडरों में मिलीभगत हो जाती है, वह आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पूल सिस्टम हो जाता है, इससे आपको राइट रेट्स नहीं आती। आप कोई भी छह ओईएम सप्लायर्स चुन लीजिए और उनकी रिवर्स बिडिंग कराइये। यह एक नया नवाचार इस देश में आना शुरू हो गया है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि रिवर्स बिडिंग से आपकी जो कास्ट आफ परचेज है, that will come down by at least 20-25 percent. आज आटोमोटिव सैक्टर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यह जो बीजेपी की सोई हुई सरकार है, इन्हें पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या इन्हें बजट में लाना था और क्या नहीं लाना था। इनका तो एक ही मुद्दा है कि इन्हें 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपये डिस-इन्वेस्टमेंट से इस साल लाना है, नहीं तो आपकी सरकार ही नहीं चलेगी। न सेंटर की सरकार चलेगी और न ही प्रदेशों की सरकार चलेगी। खोखली सरकार हो चुकी है। इन्हें यह पता ही नहीं है कि हम पैसा कहां से लाएंगे।

इस साल का ये डिस-इन्वेस्टमेंट से पैसा लाए 65 हजार करोड़ रुपये और अगले साल का टारगेट दिया है 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपये। ये क्या कर रहे हैं? एलआईसी का डिस-इनवेस्टमेंट करेंगे और डिस-इन्वेस्टमेंट करेंगे एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस का। उससे ये सोच रहे हैं, इनके पास पैसा आ जाएगा, पर इण्डियन एयरलाइंस...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विषय पर बोलिए आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं विषय पर ही आ रहा हूं। मैं इसे विषय में ही कन्वर्ट कर दूंगा। जो ये बेचेंगे, इन्हें यह पता ही नहीं कि वह पैसा नहीं आएगा। सरकारों के पास आप देख रहे हैं कि जीएसटी के रूप में पैसा नहीं आ रहा। हम सब यहां जो बहस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे वायबल बनाएं। जब सरकार इसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेंटर से सरकार को पैसा नहीं आएगा, जब हम ऐसे सोशल इम्पोर्टेंस के आर्गनाइजेशंस को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, पूरे प्रदेश में बसेज चलाना, It's a social organization, but यह बीजेपी की सेंटर की सरकार है, वह इस ऑर्गनाइजेशन को हमें सोशली नहीं चलाने देगी। We have to convert it into a commercial organization. तभी यह चलेगा।

विगत पांच सालों में इन्होंने बसों पर एक नया इनवेस्टमेंट नहीं

(श्री रोहित बौहरा)

किया। डीजल की खपत ज्यादा हो रही है, क्योंकि बसें पुरानी हो चुकी हैं। मेंटेनेंस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अल्टीमेटली इनकी जो सोच है, जो मैं परिपत्र से पढ़ रहा था, इन्हें यही करना पड़ेगा कि किसी तरह से पुरानी बसों को ये नीलाम कर सकें, उससे जो आय अर्जित हो, उससे ये नयी बसें खरीदें। मेरा दूसरा सजेशन रहेगा कि आप ये जो भी काम कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि 2.29 persons आपके पास हर बस पर है, which is huge as compared to the private sector. आपके पास दो आदमी से ज्यादा एक बस पर नहीं होने चाहिए यदि इसे आपको कमर्शियली वायबल तरीके से चलाना है।

ये टिकट सैंटर्स वगैरह सब आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। आप इसमें ई-मित्र का सहारा लीजिए। ई-मित्रों से टिकट कटाना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से हास्पिटल्स में अभी हमने इस्तेमाल किया है। धौलपुर पहली डिस्ट्रिक्ट है, जहां ई-मित्र के जरिये हास्पिटल में पर्चियां कट रही हैं। हम वैसा ही प्रयोग राजस्थान रोडवेज में भी कर सकते हैं ई-मित्र के जरिये। ई-मित्र छोटे-छोटे गांवों में आ गये हैं। जहां पर आपको टिकट चाहिए, वे आप ई-मित्र के जरिये खरीद सकते हैं। यह एक सजेशन है जो मैं मंत्री महोदय को देना चाहूंगा और यह सजेशन यदि ये ले लेंगे तो इससे इन्हें कमर्शियली काफी फायदा होगा।

दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सैक्टर की। आज आप नारायण सिंह सर्किल का हाल देख लीजिए। क्या हाल बना हुआ है। हम वहां से अपनी गाड़ियों से निकल नहीं सकते रात को एक बजे तक भी। हमें कुछ न कुछ सिस्टम सैट करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं, इसमें व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी। जो आपका मेन बस स्टैण्ड है, सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड, उसके चारों तरफ घेरा लगा हुआ है प्राइवेट सैक्टर की बसों का। यह सब देन पिछली सरकार की है कि इन्होंने इतनी अनुबंधित बसें खड़ी कर दीं। बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं को इतनी बसें दे दीं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली इन्हें वायबल बनाना था। इन्हें यह लग रहा था कि रोडवेज को खतम कर दें और किसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दें।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें आप एक मिनट में अपनी बात।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पांच मिनट लूंगा साहब। इनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि किसी तरह से ये राजस्थान रोडवेज कारपोरेशन बंद हो जाए

(श्री रोहित बौहरा)

और इनके कार्यकर्ताओं को किसी तरह से ये अनुचित लाभ पहुंचा सकें। इनका सिर्फ यही उद्देश्य था। मेरा मंत्री महोदय से यही अनुरोध है। अभी मेरे धौलपुर की विधायक भी बैठी थीं, मेरे धौलपुर के बस स्टैण्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसी के पीछे आपका वर्कशाप बना हुआ है।

मैं चाहता हूं धौलपुर बस स्टैण्ड और वर्कशाप को एक कर दिया जाए, क्योंकि आधी बस स्टैण्ड की जमीन रोड में चली गयी है। यदि आप उसे एक बना देंगे और आप अपना वर्कशाप रीको इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि वहां से सिर्फ दो किलोमीटर है, वहां उसे भेज देंगे तो एक तो आपकी वहां पर शाप्स उठ जाएंगी और शाप्स उठ जाएंगी तो आपको वह कमर्शियल वायबिलिटी दे देगा, जिससे कि आपके बस स्टैण्ड का यह जो पैसा है, जो शाप्स से आ जाएगा, वह बस स्टैण्ड आपका एक नया स्वरूप ले लेगा जिला हैडक्वार्टर में।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं, राजाखेड़ा, धौलपुर और राजाखेड़ा, आगरा, ये एकदम वायबल रूट्स हैं। इन रूट्स पर यदि आप एक-एक बस दे देंगे जो 8-8, 9-9 फेरे दिन में करेंगी तो उसमें पूरी ये पैक रहती हैं, इनका कभी भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा करौली का मेला है...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): लास्ट ईयर, करौली के मेले में जब बीजेपी की सरकार थी, हमें बसें नहीं मिली थीं। इन्होंने प्राइवेट बसों का इंतजाम किया था। मैं चाहता हूं कि ऐसे धार्मिक आयोजनों पर आप दूसरे आगारों से बसें मंगाकर करौली वगैरह की जो बसें हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, ये पूरे राजस्थान में होते हैं, वहां पर बसों का इंतजाम कर दें, जिससे कि आम आदमी को कोई तकलीफ न हो। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज परिवहन पर रोडवेज की जो स्थिति है, इसके बारे में सभी सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्य दिये। सभी सदस्यों ने अपने वक्तव्य में रोडवेज की जो स्थिति है, इस विभाग में जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह रुकने का नाम नहीं

(श्री राजकुमार रोत)

ले रहा है। क्या कारण है? इसी के साथ में अभी साल भर का कार्यकाल निकला तो मंत्री जी ने काम किया है कुछ नयी रोडवेज बसों के लिये, हमारे डूंगरपुर के लिये भी शायद कुछ रवाना की हैं, उनके लिये हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है, वह पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। पूरे राजस्थान से अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका और जो घाटियों वाले रास्ते हैं, वे कहीं न कहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इलाके में हैं। उस इलाके में जब हम बचपन में थे तो यह सोचते थे कि यदि कहीं जाना है, यात्रा करनी है और रोडवेज बस में बैठेंगे तो वह सही सलामत पहुंचा देगी। अगर कुछ घटना भी होती है तो दवाई का पैसा मिल जाएगा। लोगों की यह मानसिकता रहती थी, लेकिन कुछ समय से हमारे इलाके में अब मानसिकता में परिवर्तन हो गया है कि रोडवेज बस का इंतजार करेंगे तो वह आएगी ही नहीं और आएगी तो रास्ते में कहीं न कहीं दम तोड़ देगी।

दस साल पहले डूंगरपुर जिले की बात करें तो 110 बसें चल रही थीं और वर्तमान में अभी 58 बसें चल रही हैं तो आबादी भी बढ़ी, जनसंख्या भी बढ़ी, इधर-उधर घूमने की जो स्थिति थी, वह भी बढ़ी, लेकिन बसों में कटौती की जा रही है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से अपील करना चाहेंगे कि उस इलाके में रोडवेज बसों को अधिक से अधिक चालू किया जाए।

आज हम प्रतापगढ़ की तरफ जाते हैं, बांसवाड़ा की तरफ जाते हैं तो उस इलाके में जो छोटे-छोटे टैम्पू चलते हैं, आटोरिक्शा चलते हैं, उनमें चार से पांच लोगों के बैठने की लिमिट होती है, लेकिन उसमें 15, 20, 25 लोग बैठे रहते हैं। कहीं न कहीं भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि पहले जो ग्रामीण बसें चलायी गयी थीं, वे भी कहीं न कहीं बंद कर दी गयी हैं। भविष्य में कोई घटना न हो और लोगों में रोडवेज के प्रति जो मानसिकता बदली है, उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन लाया जाए। क्योंकि मैं आज उस क्षेत्र से एक विधायक के तौर पर चुनकर आया हूं और उस इलाके में सबसे ज्यादा लोग जो आटोरिक्शा होती है, उस पर भरोसा करते हैं। अधिकतर सफर लोग आटोरिक्शा में करते हैं। यह आटोरिक्शा 50 से 60-60, 70 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है, एक रूट तय करती है। मैं किस्मत वाला हूं कि मैं जिस चुनाव चिह्न से जीतकर आया हूं, उसका चिह्न भी आटोरिक्शा ही था।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): वाह, क्या बात है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय मंत्री महोदय, आपके ध्यान में लाना चाह रहे हैं। एक जो विशेष मसला है, पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने आदिवासी क्षेत्र में भ्रमण किया था। भ्रमण के दौरान 2008 में उन्होंने एक घोषणा की थी कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें आदिवासी समाज के लिए साधारण बस सेवाओं में 25 परसेंट छूट दी जाए। उनका हम स्वागत करते हैं लेकिन इसके बाद जो स्थिति की गई, विभाग का जो आदेश निकला और उसके जो मापदण्ड रखे गये कि टिकट प्राप्त करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए तो विभाग ने उसमें बताया कि चुनाव आयोग का फोटोयुक्त पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। हमने जो जाना कि जो वोटर लिस्ट है, पहचान पत्र है उसमें कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है, राशन कार्ड है उसमें भी कहीं जाति का उल्लेख नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाति प्रमाण पत्र लेकर रोडवेज में सफर करे। लेकिन, मैंने जो आंकड़ा प्राप्त किया 2008 से लेकर 2019 तक उसमें भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। आदिवासियों के नाम से जो योजना शुरू की, उस योजना के नाम से कहीं न कहीं सिस्टम ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है जिससे मैं अवगत कराना चाह रहा हूं।

आदिवासी यात्रियों की संख्या का जो आंकड़ा है वह 2008-09 में 41595 था और तीन साल के बाद 2011-12 का देखते हैं तो वह घटकर 4716 रह जाती है। दूसरी तरफ 2013-14 में आदिवासी यात्रियों की जो संख्या है जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया वह एक लाख 66 हजार 453 लोगों ने लाभ लिया लेकिन हम 2018-19 का आंकड़ा देखते हैं तो 81 हजार 267, मतलब एक लाख कम लोग पांच साल के बाद योजना का फायदा उठा पा रहे हैं। हमने जो एनेलेसिस किया उस इलाके में कंडक्टर के पास जाएंगे तो कंडक्टर बोलेगा कि वह टिकट डिपो मैनेजर के वहां मिलेगा और वहां जाएंगे तो वह बोलेगा कि वहां मिलेगा। उस नाम से कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अगर 25 रुपये भी एक पैसेंजर के मानें तो कम से कम मैंने जो एनेलेसिस किया है तो 2 से 3 करोड़ रुपये का सालाना घोटाला हुआ है। कभी भी कुछ भी बात होती है तो अधिकारियों में कागज ही चलते हैं और उस इलाके की बात आती है, उस योजना की बात आती है तो कागज कहीं न कहीं फारवर्ड होते हैं क्योंकि वे ध्यान नहीं देते हैं, डर नहीं रहता है। हमारे क्षेत्र से जो चुनकर आते हैं वे नहीं बोल पाते हैं, किसी चीज का मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, किसी का आब्जैक्शन नहीं कर पाते हैं इसलिए इस योजना के नाम से

(श्री राजकुमार रोत)

बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जब 2018 में वहां के कुछ संगठनों ने इसका प्रचार प्रसार किया और इस योजना का फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को आगे किया तो 2018 में विभाग एक आदेश निकालता है कि रोडवेज बसों में 25 परसेंट की जो छूट मिल रही है उसके लिए आबूरोड आगार, चित्तौड़गढ़ आगार, डूंगरपुर आगार, बांसवाड़ा आगार और उदयपुर आगार वालों को लैटर लिखा जाता है कि इस योजना का लाभ दिया जाए। 2008 में जो योजना चली उसके लिए 2018 में लैटर लिखा जाता है। यह जो घटना हुई है उसमें हमें मंत्री महोदय पर पूरा विश्वास है क्योंकि आज सुबह ही बता रहे थे कि सालाना जो एक करोड़ का घोटाला होता था उसको मैंने बन्द किया है तो इसमें भी ये लोग हैं उनको फायदा पहुंचाएं। आपसे निवेदन है कि अधिकारियों को पाबन्द किया जाए कि इसके जो पात्र लोग हैं उनको इस सुविधा का फायदा मिले और नहीं मिलेगा तो कठोर कार्यवाही की जाए, ऐसा कोई प्रावधान किया जाए।

राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा, उसमें आज तक रेल नहीं गई है। अभी एक खुशखबरी केन्द्र सरकार से आई, राजस्थान पत्रिका में बड़े पेज पर छपा था कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सांसद डूंगरपुर-बांसवाड़ा की रेल परियोजना के लिए एक हजार रुपये लाये। फरवरी में केन्द्र सरकार की बजट घोषणा हुई उसमें सिर्फ एक हजार रुपया दिया। आपको भी सुनकर अजीब लगेगा, मुझे भी पढ़कर अजीब लगा था लेकिन यह हकीकत है कि एक हजार रुपया दिया। वह 2400 करोड़ की योजना है और एक हजार रुपया केन्द्र सरकार ने दिया। यह जो रेल परियोजना है यह मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तीन राज्य के लोगों को जोड़ती है, उन तीन राज्य के लोगों को फायदा पहुंचाती है। इस योजना में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, शायद दस साल पहले कांग्रेस सरकार ही थी, उन्होंने 200 करोड़ रुपये दिये थे।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): बिलकुल, सर। अब हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात राज्य से सटा हुआ है और वहां पर तीन बसें बन्द कर दी गई हैं। माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि जो चिखली, बड़गमा, डूंगर सारण, गलियाकूंट के लिए बसें चलती थीं उनको वापस शुरू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर से जयपुर के लिए कोई भी वोल्वो बस नहीं है और हम जो जन-प्रतिनिधि हैं, हमको भी आना पड़ता है तो उदयपुर आकर बस में बैठना पड़ता है इसलिए

(श्री राजकुमार रोत)

डूंगरपुर से जयपुर के लिए एक वोल्वो बस शुरू की जाए। डूंगरपुर का जो डिपो है वहां पर भी पर्याप्त जमीन कुछ समय पहले थी लेकिन कहीं न कहीं वहां पर भी अतिक्रमण हुआ है इसलिए उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए।

सभापति महोदय, पूरे उदयपुर सम्भाग में, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है और पूरे पहाड़ी इलाके में ग्रामीण बसें हैं उनको वापस शुरू किया जाए। गुजरात का जो बोर्डर है, बांसवाड़ा में मध्य प्रदेश का जो बोर्डर है उस बोर्डर से सटे हुए गांवों, सभी ब्लाकों में रोडवेज बसों की सुविधा की जाए। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल जी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, हमारे परिवहन मंत्री किसी जमाने में बहुत धुआंधार बैटिंग करते थे। अभी भी हमारे माननीय उप नेता जी और परिवहन मंत्री जी की मिलीभगत से ये जो वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 का पेश किया है, आप मंत्री हो गये और चूरू से ही इनकी गाड़ी ले ली। ली है या नहीं ली है? यह जो ऊपर गाड़ी है इसमें है चूरू डिपो। बाकी मैं आपका, हमारे उप नेता जी का और सामने बैठे उप सचेतक महोदय हैं, किसी जमाने में आपको सारा अनुभव है, टेम्पो का अनुभव है, ट्रकों का अनुभव है, बसों का अनुभव है, आंदोलन करने का भी अनुभव है और रोडवेज को सुधारने का भी अनुभव है। मंत्री जी, क्या आपने मंत्री बनने के बाद कभी रोडवेज में यात्रा की? सबसे बड़ा सवाल यह है। आप हमारे परिवहन मंत्री बने, राजस्थान सरकार के मंत्री बने, लेकिन 14 महीनों के बीच में आपने कभी रोडवेज बस में बैठकर यात्रा की या नहीं? पहले की होगी, अभी नहीं की है, ऐसा हमें महसूस होता है। हर मंत्री अगर बस में बैठेगा तो शर्मिन्दा महसूस करेगा। हम उस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और अधिकतर रोडवेज बस में ही बैठकर आते हैं। आज मुझे रात के साढ़े नौ बजे जाना था पर मुझे बड़ा दु:ख हुआ कि विधान सभा में हमारे लिए रोडवेज की टिकट बुक करने का स्थान नहीं है। होगा तो हमारे को जाने के समय नहीं मिला और हमें रोडवेज में आदमी भेजकर साढ़े नौ बजे की वोल्वो की टिकट बुक करानी पड़ी। कहीं न कहीं हमारे विधायक महोदय को, जन-प्रतिनिधियों को जाना ही पड़ता है तो मेरा एक तो यह निवेदन है। जो विधान सभा में आरक्षण का है वह हो जाना चाहिए।

दूसरा, मेरा यह उत्तर जरूर दें कि उन्होंने रोडवेज में यात्रा की या नहीं की?

(श्री अमृतलाल मीणा)

तीसरी बात मैं एक राय के तौर पर कहना चाहूंगा कि हम रोडवेज में बैठते हैं, जाते हैं तो आपकी रोडवेज की बस बस-स्टैण्ड पर नहीं उतारती है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे रोड है वहां उतार देती है। यह बहुत भारी समस्या है और इस विषय पर कोई आया ही नहीं। सभापति महोदय, भी शायद इस बारे में सहमत होंगे, आप भी होंगे और शिक्षा मंत्री भी सहमत होंगे हैं कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है अभी माननीय चौरासी से आने वाले विधायक, उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में बसें ही नहीं हैं। मैंने दो लैटर आपको दिये थे। जिसमें एक आपकी विधान सभा की कुर्सियां का कलर है, जैसा लैटर है आपका। दोनों में मैंने निवेदन किया था कि साहब, उदयपुर डिपो की बसें जो हमारे सलूम्बर, मेरे वहां से हाडारानी की पवित्र भूमि से स्टार्ट होती है और खटारा बसें, 22/10 को श्रीमान के निवास पर जाकर, वैसे आप संजीदा, प्रेमी हैं, चंचल भी हैं, हंसमुख भी हैं, उधर वाले भी चाहते हैं और इधर वाले भी चाहते हैं। लेकिन, आपने मुझे 18/11 को उत्तर दिया कि हम विचार कर रहे हैं। ये जो बसें हैं, सलूम्बर से बड़ौदा जा रही हैं, डूंगरपुर डिपो की है, खटारा बस है। उस क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं, अहमदाबाद बड़ौदा जाने के लिए। दूसरा मैंने निवेदन किया था, यह जो आपका हरे कलर का है, कुर्सियों जैसा, मैंने आपसे निवेदन किया था 22/10 को दोनों कागज श्रीमान के निवास पर, बंगले पर जाकर दिया, चाय पानी की व्यवस्था भी आपने कराई, अंदर भी बुलाया, प्रेम से बैठाया भी सही और 22/10 का जो लैटर, शिक्षा मंत्री जी, 22/10 का दिया हुआ, एफिशिएंसी बढ़िया है, 876 आप बसें चला रहे हैं, 316 को जारी कर दिया।

मेरा एक निवेदन है विधान सभा की एक टीम बनाई जाए पक्ष विपक्ष की, वाकई में ये बसें जारी की हैं या नहीं की हैं। ताकि, उसको हम देख लें, ताकि ये आरोप-प्रत्यारोप जो प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी, जो इस प्रकार पेपर में आता है। रोडवेज बस किसी गांव में, किसी पंचायत मुख्यालय पर जाती है तो वहां गांव वाले गर्व महसूस करते हैं। आज हमारे गांव में सरकारी रोडवेज बस आई है। रोडवेज बस को हल्के में मत लीजिए, कोई गलत मत मानिए, लेकिन हर क्षेत्र में रोडवेज बस जाएगी, तो उसका मान-सम्मान और राज्य का भी मान-सम्मान बढ़ेगा, उस गांव का भी बढ़ेगा, उस गांव की इज्जत भी बढ़ेगी कि आपके गांव में रोडवेज बस आ रही है। शादी की बात नहीं है। आप उधर आकर के देख लीजिए, अगर रोडवेज चलती है, बहुत मोटी बात हो जाती है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय राठौड़ साहब ने मना कर रखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर नवीन रोडवेज बस, जो सलम्बूर से चलाने का निवेदन किया था और सलम्बूर से अहमदाबाद मार्ग पर सलूम्बर से बड़ौदा, इटाली खेडा, रठौडा, भोराई, टोकर, कल्याणपुर, खैरवाड़ा, बिछिवाड़ा, रतनपुर, शामलाजी, हिम्मत नगर, मैम नगर होते हुए, अगर एक बस मिल जाती है। सभापति महोदय जी, मुझे कहना बहुत था, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो बस का निवेदन किया है, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरा पूरा जनजातीय क्षेत्र है। बसों के लिए उदयपुर आते हैं, सम्भाग में आते हैं, तब ग्रामवासी सरकारी रोडवेज बस का दर्शन करते हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं, जिन्होंने रोडवेज बस देखी भी नहीं है।

सभापति महोदय, एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरी एक नठारा ग्राम पंचायत जो 28 किलोमीटर की परिधि में है। मैं निवेदन कर रहा हूं नई बस चलाने के लिए अगर आपका सहयोग हो जाता है, थोड़ा निर्देश हो जाएगा तो 100 प्रतिशत करेंगे। उस दिन भी आपने ऐसा ही कहा था, कर दूंगा, लेकिन पता नहीं राठौड़ साहब, थोड़ा निवेदन है कि उदयपुर से अदवास, जावद, सेभाल, मिथूडी, अथरदा, गिगला, गुडेल, इडाणा, लोदा, खरखा, सराडी, कडूणी, ओडवडिया, करावली, गामडापाल, इसरवास, सलूम्बर अगर नई बस चलाई जाती है तो वह क्षेत्र जहां विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, जयसमंद उसकी परिधि में अगर जाता है तो वहां के यात्री को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

दूसरा, उदयपुर से पलोदड़ा, उमरपुरा, डींगरी, झाडोल, सल्लाडा, बड़गांव, थरोड़, मल्लाडा, बड़ाबली, इटाली, खेड़ा, डागर, धारोद सलूम्बर अगर जुड़ता है, बस देने की बात है।

मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी सलूम्बर बस स्टैण्ड बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके में है। बस स्टैण्ड नहीं है, ऐसे ही बसें ठहरती हैं, क्योंकि एसडीएम हैडक्वार्टर है। आपका बहुत प्राचीन उपखण्ड है लेकिन सरकारी बस ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको बिलकुल शहर के बाहर कराया जाए। हमारे माननीय पड़ौसी विधायकों ने मुझे सुझाव दिया, उसको भी अगर आप मानते हैं तो ठीक रहेगा..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, एक-दो मिनट। एक डूंगरपूर से बनकोड़ा, आसपुर, साबला, निठाउआ, जो बस बंद कर दी हैं, उसको चालू किया जाए। उदयपुर से सोम जो बाबुलाल जी झाड़ोल से विधायक आते हैं, उन्होंने कहा है कि उदयपुर से सोम अगर रोडवेज बस जाती है और वहां रात्रि विश्राम करके सुबह उठती है तो पूरी बस भरी हुई आएगी, क्योंकि वापस मजदूर लोग आते हैं, उनको फायदा मिलेगा। उदयपुर से ओगण रात्रि विश्राम, उदयपुर से वाया पिपलवाडा और सलूम्बर से मैंने निवेदन कर ही दिया है।

एक मेरे नेशनल हाइवे पर परसाद एक बड़ा गांव है। वहां से अहमदाबाद जाते हैं, उदयपुर आते हैं और बांसवाड़ा के लिए जाते हैं। वहां कस्बे में टिकट की खिड़की खुल जाती है तो लोगों को फायदा होगा, यही मेरा निवेदन है। बस स्टैण्ड खैराड़ में बस रोकी जाए, बस्सी में भी रूके, यही निवेदन है, ज्यादा मेरी आपसे उम्मीदें हैं। राठौड़ साहब, और आपमें आपस में इशारा हो ही गया है, शायद संभावना बहुत ज्यादा हो रही है। बसें जरूर मिलेंगी धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, उपस्थापन, डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 13)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14 फरवरी, 2020 को मध्याहन पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2020 से गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2020 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :

(डॉ. महेश जोशी)

सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2020	1- स्वास्थ्य विभाग की निरोगी राजस्थान नीति पर विचार; 2- डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी, 2020	1- राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020; एवं 2- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020; पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2020	1- राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण; 2- प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यशैली पर विचार।
गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-2021 का उपस्थापन।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(सहमति)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई। श्री अमीन खां।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पर विचार

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, रोडवेज आम जनता के विश्वास और सहयोग का डिपार्टमेंट है, जो राजकीय उपक्रम भी है। इस उपक्रम

(श्री अमीन खां)

को मजबूत करना राजस्थान राज्य के हित में है, न किसी पार्टी का हित है। सभी पार्टियों को मिलकर अपने-अपने स्थान पर रोडवेज को कमजोर नहीं होने देना चाहिए इसका इलाज मंत्री जी आप जानते हो। आपके सुपरविजन करने वाले अधिकारी जवान, ईमानदार और सतर्क होने चाहिए। उनकी वजह से आपका रोडवेज नफे में आएगा। अगर वे आदमी गलत रहते हैं फील्ड में तो रोडवेज हमेशा घाटे में रहा है और आगे भी घाटे में रहेगा। घाटे में इस उपक्रम को रखना राज्य के लिए एक भारी चिंता का विषय हम महसूस करते हैं। पिछले इन दो-तीन महीनों में मैं जहां-जहां गया हूं आपके रोडवेज डिपोज ने हर जगह बस रूट्स पर रोडवेज की बसें बंद की हैं और वह उन प्राइवेट आपरेटर्स से मिले हुए हैं और उनके धंधे का सहयोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपको सतर्कता से कार्यवाही करनी चाहिए और रोडवेज के ईमानदार कर्मचारी, अधिकारियों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए इनाम और प्रमोशन भी देना चाहिए। हमारा यह सुझाव है कि रोडवेज अगर कमजोर होता गया और कमजोर होते-होते यह डिपार्टमेंट खतम हो गया तो राज्य को भारी नुकसान है और राज्य की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसलिए हम सब रोडवेज के समर्थन में आपके साथ हैं। आप अपनी हिम्मत से और ईमानदारी से इसको मजबूत करें। हमारे जिले में बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर से मेरा गांव 80 किलोमीटर दूर है उससे आगे एक खुरानी गांव आता है और 90 किलोमीटर है। मैं 5 बार एमएलए रहा हूं और रोडवेज की बस में सफर करने का ज्यादा आदी हूं तो एक तो बाड़मेर से खुरानी वाया रामसर आप रोडवेज की नई बस चालू करें। पहले एक बस थी बाड़मेर से पाबूश्री वाया खलीफे की बावड़ी, यह बंद कर दी है आपके डिपो ने, इसको पुन: चालू करना चाहिए। शरणार्थी बीकानेर, जैसलमेर, कोलायत इनमें ज्यादा बसते हैं। इनकी सुविधा के लिए बीकानेर से एक बस चलती थी सरगीलाज तहसील गडरा रोड के गांवों तक, वह भी बंद हो गई है उसको भी पुनः चालू की जाए यही मेरा कहना है। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर मुझे बोलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, जिस तरह से परिवहन पर विधान सभा की चलती कार्यवाही में आज पूरे दिन सभी माननीय सदस्यों ने

(श्री जगसी राम)

अपनी-अपनी चिंता जाहिर की है और इस मौके पर मैं भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो रोडवेज के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही कि रोडवेज घाटे में है, घाटे में है, अपन एक दूसरे को कहते रहेंगे लेकिन जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। रोडवेज की हमेशा अपन देखते हैं कई बार, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि हम खुद इसमें आते हैं और जाते हैं लेकिन मैं भी पिछले लंबे समय से आबू रोड से जयपुर तक आने के लिए लगभग-लगभग रोडवेज की बसों में आया करता हूं और जालौर, सिरोही के माननीय सदस्य भी रोडवेज की गाड़ियों में आते हैं, लेकिन इस समय को देखते हुए मैं सारी बातों का जिक्र करना चाहता हूं। कई बार रोडवेज की खुद की बसें अखबारों में भी छपता है कि खटारा हो रही हैं, उनका रखरखाव नहीं होने की वजह से सरकार भी बदनाम होती है और विभाग भी बदनाम होता है इसलिए मैं मेरी बात को और विशेष तौर से मंत्री जी से, मंत्री जी अभी पधार गए हैं, उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए हमारे विभाग के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं और उन पर जो मानिटरिंग करने वाले हैं उनकी पूरी जो टीम है उनको देखने की आपको महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि जो सरकार की गाड़ियां हैं मंत्री जी, अभी कुछ समय बाद में बताएंगे कि हम इतनी गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं अखबारों में भी छपा है कि हम इतनी गाड़ियां खरीदेंगे लेकिन उसके बाद में भले ही कितनी ही वीआईपी वोल्वो की गाड़ी हो या सामान्य बस हो उनके अंदर रखरखाव का ध्यान नहीं रखेंगे तो 2 साल के बाद में वह गाड़ी खटारा होकर खड़ी रहेगी। कई बार अपन देखते हैं कि गाड़ियों को पैसेंजर धक्का देते हैं और उनके वर्कशाप में जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कागजों में रजिस्टर मेंटेन होते हैं और उसके बाद में लास्ट में हजारों-लाखों रुपये उसके अंदर फर्जी बिल बनाकर वहां से उठता है तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा विधान सभा के अंदर कि जो इनकी कमेटी है देख-रेख, निगरानी करने वाली, उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा और विशेष तौर से समय-समय पर यह अधिकारी, कर्मचारी धरने पर क्यों बैठते हैं क्योंकि इनको समय पर वेतन भत्ता नहीं मिलता है इसलिए उनको मजबूरन बैठने की नौबत आती है तो सरकार को समय पर ध्यान देकर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन- भत्ते देने पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

(श्री जगसी राम)

मैं यहां पर कहना चाहता हूं अभी काफी माननीय सदस्यों ने बात कही है कि सुचारु रूप से चलने वाली बसें उनका शेड्यूल तय होने के उपरांत भी काफी बसें बंद कर दी जाती हैं। मैं हमारे विधान सभा क्षेत्र रेवदर की बात करना चाहूंगा कि लंबे समय से जो बस सिरोही आगार की सिरोही-अहमदाबाद वाया रेवदर-मंडर रात्रि 10:00 बजे चलती थी और भरपूर यानी कि उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं थी उसके उपरांत भी अभी बंद कर रखी है। यह बहुत पुरानी बस थी।

दूसरी आबूरोड आगार की जो बस थी आबू रोड से वाया मंडर-रेवदर और अंबाजी और अंबाजी से एक आबूरोड-भीनमाल वाया रेवदर-मंडर-रानीवाड़ा और भीनमाल यह बसें सुबह भीनमाल जाती थीं और रिटर्न में आबूरोड और अंबाजी तक जाती थीं। वहां सुंधा माता जाने वाले और अंबाजी आने-जाने वाले सभी यात्रियों को काफी फायदा होता था और एक डूंगरपुर आगार कि जो बस थी डूंगरपुर और बाड़मेर-डूंगरपुर से चलती हुई बाड़मेरखेड़ब्रह्मा-अंबाजी-आबूरोड़-रेवदर-मंडर-रानीवाड़ा और बाड़मेर वहां डूंगरपुर से निकलकर बाड़मेर तक यह पूरा शेड्यूल था। पूरी बस भरी हुई जाती थी और उसके उपरांत वापस अंबाजी जाकर डूंगरपुर जाकर इसका स्टे होता था।

तीसरी बात है सिरोही से बस रवाना होती थी और लोकल जो गाड़ी थी वहां पर सिरोही, गुलाबगंज, पामेरा, पोसीतरा, हाथल, मालगांव, अनादरा और करूटी और रेवदर, माननीय मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी जो शेड्यूल बताया गया है यह बसें बहुत पुरानी 20-25 सालों से चल रही थीं और उसके बाद में अभी भी यह सारी बसें बंद कर रखी हैं और इसका रीजन अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्राइवेट बसों की वजह से यह बंद होने की नौबत आई है। माननीय मंत्री जी, अभी अमृत जी जो बात कह रहे थे वह बात सारी मैं नहीं कहूंगा लेकिन मैंने आपको रूबरू मिलकर दो बार बात कही है। माउंट आबू वाली जो बस है, यहां पर यह पर्यटक स्थल है और वहां कई लोग गुजरात से और बाहर के भी लोगों का आना जाना रहता है और यह वोल्वो बस है इसमें मैं भी 2003 से इस हाउस में जनता के सहयोग से आने का जो मुझे मौका मिल रहा है और मैं लगातार 1993 से भी उसी बस में आ रहा था उसको अभी 2 महीने पहले बिना कारण, उसमें पैसेंजर भरपूर आ रहे थे, उस बस को बंद कर दिया। आपको मैंने व्यक्तिगत रूप से दो बार निवेदन किया उसके उपरांत आज तक बस शुरू नहीं की गई है। माननीय सदस्य समाराम जी भी अभी कह रहे थे और अब हम

(श्री जगसी राम)

विधान सभा के बाद में जाएंगे तो न तो ट्रेन का समय मिलेगा और बस में हम टुकड़ों में कल हमको आबू रोड यहां से गुजरात बार्डर तक पहुंचना पड़ता है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज आप जब जवाब दें उसमें यह माउंट आबू वाली बस विशेष तौर से चालू करें और आपने जैसे यह यूपी वाली वोल्वो बस चालू की है तो उसमें इतनी भीड़-भाड़ न होने के उपरांत भी वह चालू की है तो फिर यह तो रनिंग बस को बंद किया है, यह मेरे हिसाब से उचित नहीं है क्योंकि रोडवेज घाटे से उबर कर मुनाफे में आए इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पर यह चले। इसके अलावा जो रूटीन वाली बसें चलती हैं, छोटी बसें जो गांवों में चलती हैं वहां पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं है अगर सरकार हमें अनुमति दे तो हम विधायक कोष से भी बनाने को तैयार हैं ताकि यात्रियों को बैठने के लिये सुविधा हो सके, ऐसा मेरा मानना है।

दूसरी बात, आबू रोड हमारा ट्राइबल एरिया है, आबूरोड से रेवदर और आबू रोड-अम्बा जी, सुंधा माता, यह जो सारी ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली बसें थीं, आबू रोड से रवाना होती थीं, मूंथला, गिवर, दत्तानी, भटाणा, पादर, मंडर से वापस पादर, भटाणा, दत्ताणी, गिवर और मूंथला और स्टे आबू रोड। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बसें चालू रह जाएं। यह बसें खाली कभी भी नहीं जाती थीं। तकलीफ प्राइवेट बसों की वजह से आ रही है, वहां पर प्राइवेट गाड़ी वाले उनके आगे खड़ी कर देते हैं और उसके बाद सांठगांठ करके यह खाली बसें जाती हैं, इससे घाटे की नौबत आ रही है। रेवदर से सिरोही वाली बस और रेवदर से आबू रोड पर जो तीन-तीन, चार -चार बसें चलती थीं और आबू रोड से सुंधा माता वाली बस को भी बंद कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन सारी गाड़ियों को चालू करें। आबू रोड डिपो में मैकेनिकल स्टाफ की कमी है और विशेष रूप से वाहन चालक डबल ड्यूटी करते हैं, दो-दो, तीन-तीन दिन की रेगुलर ड्यूटियां रहती हैं, आबू रोड आगार में जो स्टाफ की कमी है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि स्टाफ की कमी की वजह से विशेष तौर से रोडवेज घाटे में जा रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखेगी, इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे। मंडार कस्बा हमारा गुजरात बोर्डर पर आया हुआ है। वहां पर आलरेडी बस स्टैंड बना हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): एक मिनट में खतम कर रहा हूं। बस स्टैंड बना हुआ है, मेन हाईवे पर गाड़ी खड़ी रहती है, अगर वह बस स्टैंड पर शिफ्ट हो जाये तो आने वाले यात्रियों को फायदा होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): एक मिनट में मेरी बात कर रहा हूं। मैं खुद भुगतभोगी हूं, हाईवे पर रोडवेज की रात्रिकालीन जितनी भी बसें चल रही हैं, वह बसें यात्रियों को उसी हाईवे पर छोड़ देती हैं, दो-दो किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, यह भी एक कारण होता है, इससे कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी होती हैं और भय भी रहता है। इन सारी बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा का यह चौथा सत्र एक विशेष रूप से याद किया जाएगा। हमारे नियम और प्रक्रिया के नियम 233 में जिन सार्वजनिक उपक्रमों की चर्चा सार्वजनिक उपक्रम समिति किया करती है, आज लंबे अंतराल के बाद सदन में उसकी चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमें आज तक जो प्रगति प्रतिवेदन मिलते रहे हैं, प्रगति प्रतिवेदन पर हमारा तभी ध्यान जाता था जब मंत्री महोदय इसे विलम्ब से प्रस्तुत करते थे और उसके बाद वह प्रगति प्रतिवेदन हमारी लाइब्रेरी की शोभा बन जाता था। मंत्री महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले वर्ष भी आपने प्रगति प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत किया था। आपने उस प्रगति प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर के अलावा उसके पन्ने भी नहीं पलटे होंगे। यह आपका कसूर नहीं है क्योंकि इन प्रगति प्रतिवेदनों के प्रति कभी कोई गंभीर हुआ ही नहीं और मैं समझता हूं कि यह एक नई शुरूआत होगी। प्रगति प्रतिवेदनों पर जब चर्चा प्रारम्भ हो जायेगी तो अधिकारीगण भी सावचेत रहेंगे। इनमें जो आंकड़े देते हैं, जो सूचनाएं देते हैं, उन सूचनाओं पर जब हम ध्यान देना प्रारम्भ कर देंगे तो उसमें सूचनाएं हमें सही और सटीक मिलना प्रारंभ हो जायेंगी। सभापति महोदय, अच्छा यह रहता कि इस 2018-19 के प्रगति प्रतिवेदन की जगह हम 2019-20 के प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा करते। अच्छा यह रहता इसके साथ आय-व्यय निष्पादन भी हमें मिल जाता, हम इस पर सटीक चर्चा कर सकते थे। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह जो आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चर्चा हो रही है, इस चर्चा के माध्यम से राजस्थान का आवाम यह जानना चाहता है कि यह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सार्वजनिक उपक्रम जो आम व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है इसके लिये आपका रोड मैप क्या है। आपने इस विभाग का कार्यभार संभाला, इसके बाद किस दशा में किस दिशा में आप इस विभाग को ले गये। आप भाषण देने में माहिर हैं, अभी आपकी बारी आयेगी, एक भाषण जरूर आप करोगे कि भाजपा के कार्यकाल में टायर बेच दिए, रिम बेच दीं, इंजन बेच दिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा आरोप लगाने से पहले, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा अगर यह टायर बेचने का आरोप लगाते रहे, रिम बेचने का आरोप लगाते रहे ...

श्री सभापति: आप आरोप लगवाना चाह रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सवा साल का समय गुजर गया ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप उनको याद दिला रहे हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर इस बात पर आप गंभीर हो, हममें कोई कमी-खामी रह गई, अगर वह टायर बिक गया, रिम बिक गई तो सवा साल में बरामदगी करके उस रिपोर्ट के आधार पर आते तो अच्छा लगता।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यूनुस भाई से दुश्मनी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जीवन का समय बदला है, जीवन की रफ्तार बदली है। बड़ी मात्रा में गांव शहरों की तरफ दौड़ पड़े। शहरीकरण बढ़ा है और शहरीकरण में अगर पिछले दशक की हम वृद्धि देखें, सभापति महोदय, 14.2 प्रतिशत जनसंख्या गांवों से निकलकर शहर की तरफ पिछले दशक में गई है। सभापति महोदय, जिस पर हम चर्चा करते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, इसकी उपादेयता पर निश्चित तौर पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिये। आपने कल ही परिवहन विभाग का भी जो प्रतिवेदन हमें दिया है, उसके पृष्ठ 22 में आपने एक सारणी दी है, उसमें आपने लिखा है कि राजस्थान का सड़क तंत्र 1,61,135 का हो गया। सभापति महोदय, 31 दिसम्बर, 2019 तक यहां 1,88,38,095 पंजीकृत वाहन हैं और एक हजार व्यक्तियों में वाहनों की संख्या 275 है। यानी अब राजस्थान में एक हजार व्यक्ति अगर रहते हैं तो साढ़े सत्ताइस परसेंट लोगों के पास कोई न कोई वाहन है। जहां शहर की आबादी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर हमें इस पर विचार करना चाहिये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बसों की संख्या 5,025 है जिसमें 4,200 निगम की और 1,025 अनुबंधित बसें हैं। एक, दो नहीं, 28,57,000 यात्री इनमें प्रतिदिन सफर करते हैं और सफर के बाद अनुभव कैसा करते हैं, इनकी आवाज अभी आपने अलग-अलग माननीय सदस्यों से सुनी और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हम निश्चित तौर पर विचार करें, मंत्री महोदय, दोषारोपण से नहीं, आपके प्रगति प्रतिवेदन पर आप मुलाहजा फर्माएं, उसके पृष्ठ 15 में आपने एक तालिका दी है, तालिका संख्या 5 (अ), उसमें 2018 में कितने मार्ग थे और 2019 में कितने कम हो गये क्योंकि दोनों आंकड़ों में अधिकांश समय भाजपा का रहा, 2346 से 2230 हो गये। यानी 4.9 परसेंट कमी आई जिन मार्गों पर रोडवेज ने चलना बंद कर दिया। अब आपने कौनसा मीर मार लिया, अगला आंकड़ा अपने उत्तर में आप भी बताएं। अच्छा रहता अगर हमारे पास यह 2019-20 का प्रतिवेदन होता तो हमारे पास वह आंकड़ें होते। इसी तरह जितने किलोमीटर रोज आपकी यह रोडवेज चलती है, उसमें भी 2018 की तुलना में 2019 में 5.23 की गिरावट आई है। यानी रोडवेज सड़क से उतरती चली जा रही है, रोडवेज में रूटों की संख्या कम होती चली जा रही है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपके निगम में बसों की संख्या कम हुई है। 2017-18 में 5519 से 2018-19 में 5030 हो गयी। इसके साथ ही जो इनकी उपादेयता है। आपने इसी के अंदर यह लिखा कि उपादेयता 2017-18 में 88 से 80 परसेंट हो गयी। सभापति महोदय, एक बस की औसत आयु भी 6.31 वर्ष है। यानी रोडवेज में एक बस आयी और छह वर्ष तीन महीने चली और उसके बाद चलने योग्य नहीं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कह रहे हैं। अगर मैं इसके साथ जोड़कर देखूं। आपने तालिका दी है, उसमें यह कि कितने वर्ष की बसें चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि एक बस की उपादेयता 6 वर्ष 3 महीने से ज्यादा की नहीं है। यह आपका प्रगति प्रतिवेदन कहता है। आपके प्रगति प्रतिवेदन में 7 वर्ष से अधिक की उम्र की बसों की संख्या 1825 बतायी है, यानी 44.98 प्रतिशत। यानी आज रोडवेज के अंदर जितनी बसें चल रही हैं। एक बस की जो औसत आयु है, उसमें से 44.98 प्रतिशत बसें तो ऐसी हैं, जो अनुपयोगी हो गयी हैं, खटारा हो गयी हैं, बिना फिटनेस पर, बिना इन्श्योरेंस के यमदूत की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तरह राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रही हैं। आप उत्तर देंगे कि आपके समय में क्या किया? हमने गलती की होगी, राजस्थान की आवाम ने 0.5 फीसदी वोट देकर हमें यहां बैठा दिया, आपको सरताज बना दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप मुझे अपने उत्तर में बताएं कि आपने मापदंड बना रखे हैं जो एक परिपाटी बना रखी है कि आपके यहां 8 वर्ष की आयु और 10 लाख तक की जो बस चली गयी, उसको आप बस के बेड़े से अलग कर देते हैं। आज की तारीख में आपकी नीति और आपके प्रगति प्रतिवेदन से औसत आयु पर जाएं तो वस्तुस्थिति में आपके बेड़े में कितनी बसें हैं जिनके पास फिटनेस इंश्योरेंस है, जो चलने योग्य हैं, इसके बारे में आप बताएं।

सभापति महोदय, जन घोषणा-पत्र के बारे में मुझसे पहले भी लोगों ने बात की थी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि यह घोषणा-पत्र बनाने में आपकी अहम भूमिका रही है। आप जब यह घोषणा-पत्र बना रहे थे, उससे पहले निश्चित रूप से 17 सितम्बर से 6 अक्टूबर तक रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में एक हड़ताल की। पूरे राजस्थान में आपने जो वातावरण बनाया, जिसकी प्रतिध्वनि अभी कई सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मैं सुन रहा था कि राजस्थान रोडवेज बिक रही है। भाजपा तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बंद कर रही है। इन्होंने क्या भाषण दिया? गलबहियां करके पीसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष को लेकर चले गये। हमारी सरकार तो आ रही है, आपने यह कहा, हमारी सरकार आएगी, फिर आपने चुटकी बजायी और यह कहा कि हम चुटकियों के अंदर आपकी मांगें पूरी कर देंगे, आपका सातवां वेतन आयोग दे देंगे और पांचवें व छठे का एरियर दे देंगे और आपकी जो पेंशन और परिलब्धियां बकाया हैं, वे दे देंगे। अब तो आप सत्ता में हो। दबंग भी हो, मजबूत भी हो। वही जिन्होंने आपको साफा पहनाया था, मुझे आज भी याद है, जब आप कुसुमल साफा पहनकर गर्वित मुद्रा में सिंधी कैम्प से यूं हाथ करके निकले थे, वही लोग हमसे आकर पूछ रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं करो तो साफा तो जरूर लौटा दो।

सभापति महोदय, मैंने यह जो निवेदन किया है। आपने मुझे जो पथ परिवहन निगम का प्रगति प्रतिवेदन दिया है, उसमें एक बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। सभापति महोदय, इन्होंने इसके पृष्ठ 6 पर यह लिखा है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

31 दिसम्बर, 2019 तक राजस्थान में जो नये वाहन खरीदे गये और जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनकी संख्या 11 लाख 28 हजार 146 है और उसी में आपने लिख डाला कि यांत्रिक निरीक्षण जिसको फिटनेस कहते हैं, उनमें 3 लाख 26 हजार 474, यानी सरकार का प्रतिवेदन यह कहता है कि यहां वाहन खरीदे जाते हैं और वाहन खरीदने के बाद वाहनों की फिटनेस मतलब 7 लाख से ज्यादा वाहन बिना फिटनेस दौड़ते रहे। यह जो दुर्घटनाओं का आलम है, वह इसी कारण से बढ़ा है।

आपका मैं एक बात में बड़ा सम्मान करता हूं। आपके मन में जो बात आती है, आप बोल देते हैं। अभी आप नयी सड़कों की हरी झंडी दिखाने गये थे। आपने वहां क्या कर डाला? आपने कहा कि रोडवेज में भ्रष्टाचार का खुला खेल है। मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री महोदय, विरासत आपकी मां है। जिन भैंरोसिंह सिंह जी शेखावत ने कहा था कि भ्रष्टाचार को नाक से निकाल लूंगा। आप उन्हीं के वंशज हैं। भ्रष्टाचार का खुला खेल है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आपके हाथ किसने बांध रखे हैं?

सभापति महोदय, अभी यहां पर बहुत बातें हुई हैं। महामहिम के मुख से भी कहलवा लिया कि हमने 876 नयी सुपर बसें एक्सप्रेस खरीद डालीं, आदेश दे दिया 48 इलेक्ट्रिक बसें भी। मंत्री महोदय, मुझे आप जरूर बताना कि आपने 21 नवम्बर को यह निविदा आमंत्रित की और 22 सितम्बर को आपने तकनीकी समिति बनायी। 22 सितम्बर को तकनीकी समिति बनाते हैं, उसके अंदर किस स्तर के अधिकारी लेते हैं, 2 जे.ईएन. और 3 जूनियर एकाउंटेंट। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दीये के नीचे अंधेरा क्यों? टेलरमेड निविदाएं आमंत्रित करने के लिए स्पेसिफिकेशन बनने थे। इसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सभापति महोदय, उसमें 2 बस निर्माता हिन्दुस्तान के हैं, अशोक लेलैंड और टाटा। 60-40 एवं 50-50 के रेशो में इनसे बस खरीदते हुए आते हैं। जो बस खरीदी जाती है, वे 135 बीएचपी से 160 बीएचपी, ब्लाक हार्स पावर से। इतनी इसलिए खरीदते हैं, आज तक आपने खरीदी। इसलिए खरीदी कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। गर्मी और सर्दी ज्यादा है। आपने इस बार जो निविदाएं आमंत्रित की हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं दो मिनट में कर रहा हूं। 125 बीएचपी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बसें खरीदने के लिए टेलेरमैड शर्तें रख दीं। उसमें बीएस-4, सभापति महोदय, यह मानक पोल्यूशन बोर्ड का निर्धारित किया हुआ है। सभापति महोदय, बीएस-2, बीएस-4, बीएस-5 इनका मंत्री जो को ध्यान है। श्याम सुंदर सिंघवी बनाम यूनियन आफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यह 21 जनवरी, 2020 को आया। इसमें कहा गया कि 31 मार्च के बाद देश भर में बीएस-4 मानक के किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह पोल्यूशन की दृष्टि सही नहीं है और आपने उसी को खरीदने का आर्डर दे डाला। इनसे पूछें तो सही। उसके बाद आपने जो इसका व्हीलबेस लिया, वह आपने 5100 लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 5100 व्हीलबेस की आप बस खरीद रहे हैं, उसमें 47 सीटें होंगी, यह 8 सीटों का नुकसान क्यों? यह जो खरीद-फरोख्त का खेल चला, मंत्री महोदय, इसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर कहां बैठा था? किस दिन बोर्ड आफ डायरेक्टर ने इसकी स्वीकृति दी। निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। सभापति महोदय, आप कह रहे हैं इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा।

मंत्री जी, इलेक्ट्रिक बसों का करंट राजस्थान में दौड़ रहा है। सब जगह चर्चा है, आप जैसा दबंग मंत्री और आपकी फोटो छपे, फोटो में मजा नहीं आया। आपके चेहरे, इनकी फोटो अच्छी छपी। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया अपनायी वह गलत है। आपने कहा सही है। सभापति महोदय, आप मुझे आंखों से देख रहे हैं इसलिए दो मिनट में कन्क्लूड कर डालूंगा। सभापति महोदय, भारत सरकार ने पूरे राज्यों को लिखा कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ग्रीन गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें खरीदें, ऐसा सारे सूबों को लिखा और हमें भी लिखा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक तो निवेदन है कि राजेन्द्र जी का भाषण पूरा मान लिया जाए।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ये जो इलेक्ट्रिक बसें थीं, इनमें 55 लाख रुपये हर बस का अनुदान भारत सरकार दे रही थी। मैं समझता हूं कि आपने जब इसका टेण्डर किया, सितम्बर 2019 को तो एक सिंगल टेण्डर आया। मैं समझता हूं कि श्रीनाथ ट्रेवल्स का एक सिंगल टेण्डर। उसके बाद, इस टेण्डर वाले को कोई अनुभव नहीं, बस निर्माण नहीं करता। बस को इम्पोर्ट करने के लिए इसने किया। 52 रुपये प्रति किलोमीटर और एक हजार किलोमीटर चलायेगा। मैं समझता हूं कि आज आपकी जो बस दौड़ रही है, उसका और इसका अगर हम अंतर निकालें तो आर.एस.आर.डी.सी. को एक वर्ष में 90 करोड़ का नुकसान है, क्योंकि आपको आज 32 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें बाजार में उपलब्ध हैं। किया जो किया। इसके अंदर आपके ही अधिकारी ने यह लिखा है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है, बोर्ड आफ डायरेक्टर का अनुमोदन नहीं, इसलिए चीफ विजीलेंस अधिकारी इसकी जांच करे। मंत्री जी, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करुंगा कि आपने बहुत-बहुत अच्छी बातें कीं। मैं तो बड़ा कायल हुआ जिस दिन आपने 15वीं रोड सेफ्टी काउंसिल के अंदर कहा, दो वर्ष बाद मीटिंग हुई थी और आपने कहा कि 395 ग्राम पंचायते हैं और हर ग्राम पंचायत में 50-50 सुरक्षा अग्रदूत। वे अग्रदूत कहां हैं? हैलमेट भी दे रहे थे, सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित भी कर रहे थे।

आपने यहां कह दिया कि अगर सड़क की खराबी के कारण मौत होगी तो उस अधिकारी की जिम्मेवारी होगी। उस जिम्मेवारी का न तो कोई सर्कूलर निकला, न कोई आदेश निकला। आपने कहा कि सड़क मृत्यु दर में 10 परसेंट की कमी लाएंगे। क्या आपका रोडमैप है? आपने कहा था कि हर ग्राम पंचायत को हम परिवहन सेवा से जोड़ देंगे। मुझसे पहले बोल चुके हैं, 5991 ग्राम पंचायतें आपकी बाट जोह रही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपकी सक्षमता पर कोई सवालिया निशान है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि आपने बड़ी कृपा की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस चूरू की जनता ने सात बार मुझे भेज दिया, उस फोटो को लगाया और इस फोटो को भी लगाया बड़ा अच्छा किया, परंतु इस फोटो पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं।

(18.00 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

यह आपने जो 100 बसें खरीद रखी हैं, खड़ी हुई हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन करवा दो। क्या कारण है कि इन बसों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने का? उसमें यह बस भी खड़ी है। मंत्री महोदय, आप हमारे साथ बहुत वर्षों तक रहे हैं। आपके जुझारूपन से हम बहुत परिचित हैं। अपनी बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। काफी दूर तक साथ चले हैं। यह सफर राजनीति का चलता रहता है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज जब अपना भाषण प्रारम्भ करें, हम रोडमैप जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे प्रार्थना की थी और आपने बड़ी कृपापूर्वक यह नया इतिहास रच डाला, इस प्रगति प्रतिवेदन पर जो हमारी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती थी, उस पर आपने बहस करवा डाली। इस बहस में हमने क्या किया? हमने बहुत गलत किया होगा, रोडवेज के अंदर हमने रिम बेच दी, हमने टायर बेच दिए परंतु आप क्या करना चाहते हैं? राजस्थान की आवाम इस रोडमैप को जानना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन कुछ विशेष मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि रोडवेज कल्याणकारी सरकार के लिए एक आवश्यक अंग है। चाहे वह सरकार हमारी हो, चाहे आपकी हो, इसको कंटीन्यू करना ही है। इसको ठीक करके करना है। जहां-जहां भी कमी है, उसको सुधारिए लेकिन इसमें कभी यह मन मत बनाइए कि हम इसको बंद कर देंगे या खतम कर देंगे क्योंकि ये वास्तव में राजस्थान के हर व्यक्ति की मंशा रहती है। इसमें यह जो चार्ट आपने दिया है, यह सारे के सारे चार्ट इस बात को बताते हैं कि सब दृष्टि से, व्हीकल की दृष्टि से भी, किलोमीटर की दृष्टि से भी और आपके फेरे की दृष्टि से भी, इसमें निरंतर गिरावट आ रही है और इस बार भी आ रही है। इसको ठीक करने के लिए आपको निश्चित रूप से साधन भी बढ़ाना पड़ेगा और इनके फेरे भी बढ़ाने पड़ेंगे ताकि लोगों को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इससे ज्यादा सुविधा मिले। जो बात अभी माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने की, वही बात मैं आपको कह रहा हूं। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि हमारा यह जो बेड़ा है, अभी आप 900 के समथिंग जो बसें खरीद रहे हैं, इसमें एक यूरो-6 माडल होता है और एक यूरो-4 माडल होता है। यूरो-4 माडल जो है, वह रिजेक्ट हो रहा है इसी 31 मार्च, 2020 को और आप वही सारी बसें खरीद रहे हैं जिनकी एंट्री दिल्ली में 31 मार्च के बाद हो ही नहीं सकती। यह जो आपकी गाड़ियां हैं, ये दिल्ली को टच ही नहीं करेंगी तो आपका जो खरीदने का परपज है, जो लेटेस्ट माडल है, जिसके लिए कोर्ट का फैसला है, भगवान के लिए इतना जल्दी भी मत कीजिए कि हमारी गाड़ियां खरीदने के बाद भी उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए वह उपयोग नहीं हो।

एक जो आपका ऑनलाइन टिकट वाला मामला है, पांच करोड़ का, इसको थोड़ा-सा दिखाएं। इसके पीछे भावना यह थी कि रोडवेज का टिकट कहीं भी, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आसानी से निकाला जा सके और वह कहीं भी, किसी भी जगह से यात्रा कर सके। लेकिन इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होना था, वह नहीं हुआ है। केवल जयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर है और दिल्ली के रोडवेज बस स्टैंड पर है। बाकी जितने भी आपके स्टैंड हैं, वह इससे कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद भी आप उस ठेकेदार को, जिसको यह व्यवस्था करनी थी, उसको पांच करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं। आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कि एक हजार टिकट रोज से ज्यादा अभी वह सिस्टम में से नहीं निकाल रहा है। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के या तो सारे के सारे जितने डिपो हैं और जितने भी कंडक्टर आपके रहते हैं, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध हो कि कोई भी, कहीं से भी इस प्रकार का टिकट निकाल सके तो आपकी इस भावना का ठीक तरह से सम्मान हो जाएगा।

दुर्घटना का जहां सवाल है, इसको भी आपने देखा होगा कि हमारी रोडवेज की बस की दुर्घटना कम है बनिस्पत जितनी भी आपने जो बाकी बसें ले रखी हैं, उन बसों को देखने की जरूरत है। ये जो इलैक्ट्रिक बसें आप खरीद रहे हैं, इसे खरीदने को लेकर जो विवाद आपका खड़ा हो गया है, इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइए। प्रोसेस को पूरा कीजिए। अगर प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे तो कहीं भी जाकर हमारी गाड़ी अटक जाएगी और जिस मंशा से आपने प्रयत्न किया कि हम निश्चित रूप से इलैक्ट्रिक बसें चलाएं और जल्दी से जल्दी चलाएं, दिल्ली को हम तुरंत अभी जोड़ लें, भावना में कोई अंतर नहीं है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन जो इसका प्रोसेस होना चाहिए था, चैयरमेन ने जिस प्रकार का आब्जेक्शन रेज किया है, वह आब्जेक्शन वैलिड है। केवल हम इस आधार पर कि ये उसने किया है, नहीं मानें, जिस प्रोसेस से इस प्रक्रिया को होना चाहिए, उस प्रोसेस से यह प्रक्रिया नहीं हुई है। वह कहीं भी बीच रास्ते में जाकर, किसी भी ढंग से कोर्ट के द्वारा या बाकी कहीं अटक जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक आपकी हमारी, सबकी बार-बार इच्छा रहती है, जितने लोग यहां बोले हैं, वे सभी चाहते हैं कि सभी पंचायतों को टच करें। पंरतु सभी पंचायतों को टच नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम आप प्रत्येक जिले से या प्रत्येक स्थान से इस जयपुर को तो जोड़ लें। दूसरा, यह कि जहां-जहां हमारी अन्तरराष्ट्रीय जाती थी, बाम्बे जाती थी, सूरत जाती थी या मध्यप्रदेश जाती थी या द्वारका जाती थी या बाकी जाती थी, जितनी हमारी गाड़ियां चल रही थीं, इसके कारण से लोगों को बहुत सुविधा थी। आज वह बंद हो गई है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर चलाएं ताकि उसके कारण से आपको ट्रैफिक में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाए।

मैं आपको उदयपुर डिपो की जो बात कह रहा हूं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। 2017 में हमारे यहां 144 बसें चल रही थी। आज की तारीख में 89 हैं, उसमें से भी कुछ और आज बंद होने की स्थिति में खड़ी हैं। आपने यहां से 5 गाड़ियां जो नई भेजी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। वह जाकर दफ्तर दाखिल में खड़ी हैं। अगर 15 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन का काम भी पूरा नहीं हो, ये जो 100 ही बसों के लिए है, केवल उन 5 के लिए नहीं है। जो 100 बसें खरीदकर आपने यहां झंडारोहण कर दिया, उसको दिखा दिया है, वह सारी की सारी जाकर दफ्तर में पड़ी हुई हैं, उसको तुरंत देखिए ताकि हमारे पैसे का सही तरीके से उपयोग हो। मैं सोचता हूं कि केन्द्र सरकार ने हमको 5 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्र में इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए दिया था। उसके बाद भी आज की तारीख में उदयपुर के आस-पास के जितने भी हैं, उदयपुर-धरियावद वाया लसाडिया, ये तो सब बंद हो गई। उदयपुर-आबूरोड होकर के झाड़ौल कोटड़ा बंद है, उदयपुर-कोटड़ा अम्बासा बंद हैं, उदयपुर-झाड़ौल-खेड़ब्रह्मा ये बंद है, उदयपुर-आबूरोड़-खैरवाड़ा, सारी की सारी, मतलब जो इस एरिये को टच करती थीं, वे सारी बसें आज की तारीख में बंद हैं। इसको आप प्रायोरिटी के ऊपर शुरू करने का काम कीजिए।

मेरा एक सुझाव है कि यह जो घाटा-घाटा, यह बात तो है ही। यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घाटा है हमारी ईमानदारी पर संदेह के कारण से। अगर कहीं पकड़ना चाहो, इसको पकड़ेंगे तो इसमें से कई चीजें निकल जाएंगी। आपके हर जगह लीकेज इतना भारी होता है, चाहे आपकी हो या हमारी सरकार रही हो, पहले भी रही क्योंकि यह 55 वर्ष का बेड़ा है। 1964 में हमने शुरू किया था। इन 55 वर्षों में आप भी रहे, हम भी रहे सब कुछ रहा, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो कमी हैं, उस कमी के लिए हमको कुछ न कुछ इस पर विचार करना चाहिए। मैं सोचता हूं दो-तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम तुरंत इस रोडवेज के घाटे को कम कर सकते हैं, इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। विशेषकर, ये जो यात्री भार कम हो रहा है, इसको ठीक प्रकार से देखिए। अभी-भी हमारा प्रति गाड़ी का जो एवरेज है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब घट कहां रहा है कि आपके पेरेलल जो गाड़ियां चल रही हैं, उदयपुर से जयपुर जो प्राइवेट व्यक्ति आ रहा है, वह टिकट दे रहा है 200 रुपया और आपका टिकट है 400 रुपया। जो डायरेक्ट इस प्रकार की गाड़ियां आती हैं, उसके टिकट के बारे में आप विचार कीजिए ताकि उनके कम्पीटीशन में आपकी गाड़ी खड़ी रहे। ये बंद होने का कारण आपका आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण से भी है। इसको आप रोकिए। रोडवेज कैम्पस के बाहर जो प्राइवेट गाड़ियों का दबदबा है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, प्रयत्न करके भी थक गए लेकिन वे इतने ताकतवर हैं कि हिलते नहीं हैं। अगर आप कहीं उदयपुर के बस स्टैंड पर रात को दस बजे जाएं तो आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। कम से कम 50 ट्रेवल्स बसें वहां हैं और कम से कम 12 से लेकर 15 उनके सारे आफिसेज लगते हैं ताकि आपका सारा जो ट्रैफिक लोड है, उस ट्रैफिक लोड को लें। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें तो केवल मन और सरकार की मानसिकता हो तो वहां से एक सैकण्ड में हटाकर दूर किया जा सकता है। ये ट्रैफिक लोड नहीं बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, इसको आप आसानी से रोक सकते हैं, अगर इच्छा हो तो। अब उसमें हम भी असफल हुए, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वास्तव में रोडवेज को आप स्टैंड कराना चाहते हैं तो इस बारे में आप जरूर कुछ न कुछ कीजिए।

रोडवेज बस स्टैंड पर भी आप कुछ इकोनोमिक्स आधार बना सकते हो, अपने कैंपस में। उसके कारण भी आपको कुछ अर्निंग हो सकती है। उससे भी आपको मदद मिल सकती है। रोडवेज़ के जितने भी विज्ञापन देते हैं उन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विज्ञापन का भी तथा गाड़ियों पर भी विज्ञापन को अलाउ करके, आप बहुत बड़ी अर्निग कर सकते हो, उसके बारे में आपको निश्चित रूप से सोचना चाहिए। रोडवेज़ की जितनी खरीद होती है, प्रोपर इसकी मोनिटरिंग हो जाए और ईमानदारी से इस काम को करने लग जाए तो आपके घाटे को यह अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। आपने सब प्रकार की छूट तो दे दी, एमएलए साहब को भी छूट है, एक्स फौजी को भी छूट है, महिलाओं को भी छूट है, इसका 20 परसेंट, इसका 30 परसेंट और उसकी भरपाई सरकार नहीं करती है। अगर वास्तव में सरकार या तो छूट दे और छूट दे तो पैसों की वापस से भरपाई करे, जिसके कारण रोडवेज़ की हालत खराब नहीं हो। खुश करने के लिए हम घोषणाएं जरूर कर देते हैं। पैरेलल रोडवेज़ को भी, सैंक्शन करने के लिए आपको उसको जरूर देना चाहिए। लंबे रूट विशेषकर राष्ट्रीयकृत जितने भी रूट हैं, उन पर सौ परसेंट रोडवेज को ही अलाउ करें, तब जाकर आप इसको स्टैंड कर पाएंगे। आप अगर छोटी-छोटी जगह नहीं जा सकते हो तो कम से कम लंबे रूट को तो क्लियर करो, जिसके कारण रोडवेज को नुकसान नहीं हो, जैसा कि सबने कहा आप और हम सब हम रोज देखते हैं हमारी गाड़ी के आगे ही दूसरी गाड़ी निकलती है, वह 250 लेती है और हमारा टिकट 450 रुपये है। हमारी गाड़ी में कौन बैठने वाला है। अगर बस स्टैंड से ही आप उसको कंट्रोल करोगे तो निश्चित रूप से आएगा।

मेरा एक बात का और आग्रह है, हमने खराब किया, इसने किया, आपको सजा देनी हो तो आपके पास ताकत है, हमने गलत किया तो हमको सजा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका वर्णन करते-करते अपने भाव को नहीं कहना। इसको कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। विशेषकर 900 के करीब आप गाड़ियां खरीद रहे हो, यह गाड़ियां 31 मार्च 2020 के बाद कहीं चल पाएंगी और कहीं नहीं चल पाएंगी। जो एरिया आपका रेस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा वहां तो चला लोगे, पर रेस्ट्रिक्शन में जो एरिया आ गया, उस एरिया में यह गाड़ियां नहीं चलेंगी। अच्छा है कि जब खरीद ही रहे हो तो सिक्स वाला माडल खरीदो ताकि आने वाले 10 साल तक हम इन गाड़ियों का उपयोग कर सकें, नहीं तो यह गाड़ियां बीच में ही, आप कह रहे हो कि हमने इतनी गाड़ियां खरीदीं, इतनी तो कंडम हो ही जाती हैं, साल भर में कंडम का अगर ईमानदारी से निकालो, 4500 की स्ट्रैंथ है, उसमें से इतनी गाड़ियां तो खराब होती ही होती हैं, उनको बदलना ही पड़ेगा। उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने खरीदी, नहीं खरीदी यह तर्क देने से कोई अर्थ नहीं है। पर इस पर जरूर विचार करिए जो आपका टेंडर प्रोसेस है और इलैक्ट्रिक बैटरी की गाड़ियां खरीदते हो, उस प्रोसेस को पूरा करो। यूरो-फोर और यूरो-सिक्स इसके बारे में भी पुनर्विचार कर लीजिए, 2 महीने अगर लेट हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आगे जाकर हमारा पैसा फालतू नहीं चला जाए इस बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अंग्रेजी में एक कहावत है प्रैसी करने की। फ्राइड़े है, दो स्टेटमेंट देने हैं। सब माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। कितना ब्रीफली और समराइज करके आप रिप्लाई देते हो, आज टैस्ट है आपका।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करते हुए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आज मुझे एक बात का बड़ा दु:ख हुआ कि दोनों इतने सीनियर सदस्य, जिस ढंग से बोल रहे थे, मेरा यह मानना है कि यह सदन सिर्फ कांग्रेस-बीजेपी का अखाड़ा नहीं है। यहां पर साफ-साफ लिखा गया है, जब हम बोलने के लिए खड़े हों तो ईमानदारी से बोलें, सच बोलें, ऐसा बोलें जो नजीर बने।

मैं कटारिया साहब का बहुत सम्मान करता हूं। आपने आज यह कह दिया कि 31 मार्च के बाद बस घुसेगी ही नहीं। आप तो बहुत सीनियर हैं, समझदार हैं, आपसे हम सीखते हैं। आप चिंतित मत होइए। लोक सभा के अंदर तक भी बस को जाने की परमिशन है। यह आपको किसने कह दिया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सुप्रीम कोर्ट....

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बिलकुल नहीं कहा या तो आप दोनों राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, क्या बात कर रहे हो? कर लो फैसला, दोनों खड़े होकर कह दीजिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। आप बैठिए। रिकॉर्ड नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह खड़े हुए हैं तो आज राठौड़ी तय ही हो जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं, दिल्ली में बस की एंट्री की बातें, मैं आज शपथपूर्वक कह रहा हूं, दिल्ली में बस की एंट्री नहीं होगी, यह गलत है। BS4 के लिए यह नियम है, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं रोज मीटिंग लेता हूं, उसका नियम है। आप खड़े हो गए, कटारिया साहब खड़े नहीं हुए क्योंकि उनमें बड़प्पन है। वह समझते हैं, यह अंतर है, इसलिए आप उप नेता हो और वह नेता हैं, यही तो अंतर है। आप हमारे बड़े भाई हो, हमारे सीनियर हो लेकिन आप उनके सीनियर नहीं हो, आज यह साबित हो गया है।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं आपकी यह चिंता वाजिब है, यह चिंता मैंने भी मीटिंग में रखी थी, हम यह बसें लेने जा रहे हैं, जल्दी चाहिए। भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम जारी किया है, उसमें कहा है कि 31 मार्च तक जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वे गाड़ियां इस दिक्कत में नहीं आएंगी एंट्री में, तो 31 मार्च तक इनका सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी चिंता है, आप निश्चिंत रहिए। यह हमको भी पता है, ऐसी बड़ी गलती हम कर सकते हैं क्या? यह कारपोरेशन है हर अधिकारी जानता है। उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा, उसके सामने तलवार लटक जाएगी। आज एक बात और अच्छी हुई कि माननीय विपक्ष के नेता खुद यह मान रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज़ बस चलनी चाहिए। तो यह राष्ट्रीयकृत मार्ग थे, उन राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किसने किया था? अध्यक्ष जी, यह हमने नहीं किया। अराष्ट्रीयकृत नेशनलाइज रूटों को डिनेशनलाइज करने का काम पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने वहां से रोडवेज़ को बंद करने की तैयारी कर ली। आपने यह तय कर लिया कि जहां पर नेशनलाइज रूट रोडवेज़ के थे, उन रूटों को आपने ही नेशनलाइज करके, आपकी ही सरकार ने, वहां पर लोक परिवहन सेवाओं को परमिट जारी कर दिए। मुझे दुःख होता है इस बात का, पता चलना चाहिए राजस्थान की जनता को। जिस दिन यह रूट नेशनलाइज से डिनेशनलाइज हो रहे थे, उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में आप भी बैठे थे, विपक्ष के नेता भी बैठे थे, उप नेता भी बैठे थे, आप एक शब्द नहीं बोले। आप आज सुझाव दे रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई आदरणीय वसुन्धरा जी को इतना सुझाव दे देते कि साहब, आप जो यह कर रहे हो यह रोडवेज की स्थापना के बाद कभी नहीं हुआ। पिछली सरकार में पहली बार हुआ, जब नेशनलाइज रूट को डी-नेशनलाइज किया गया, आप ही के सामने।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जब आदरणीय राठौड़ साहब ने माना कि हमने रिम बेच दी, हमने टायर बेच दिए, हमने भ्रष्टाचार किया, आप खुद मान रहे हो। मुझे अच्छा लगा कि सदन में खड़े होकर आपने इन सब गलतियों को स्वीकार किया। आपने माना कि 2018-19 यह सब कर्म हमारे किए हुए हैं। यह आप खुद बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला, आपने सदन में बोला है और यह अंकित हुआ है। इन्होंने माना इसमें जो भी गलती हुई है हमसे हुई। हमने यात्री भार बढ़ाया है, 76 परसेंट हुआ है, इसमें पढ़ लेना। हमें कितना टाइम मिला है, 3 महीने हमारे हैं, बाकी सब आपके ही आपके हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। शपथ जब ली जाती है तो यह सोच कर नहीं ली जाती कि मैं कांग्रेस का हूं और आप बीजेपी के हैं। शपथ यह सोच कर ली जाती है कि मैं भी तिरंगे के नीचे खड़ा हूं और आप भी तिरंगे के नीचे खड़े हो। जब आप आरोप-प्रत्यारोप की बात करोगे तो फैसला होगा। यही लोक परिवहन सेवा की बसें, आप रोडवेज़ को जिंदा रखने के लिए, आप खुद मान गए आज। अध्यक्ष जी, पुरानी सरकार के लोगों ने खड़े होकर यहां माना कि रोडवेज़ इस राजस्थान की लाइफलाइन है, जरूरत है। रोडवेज़ चलनी चाहिए, एक भी सदन के सदस्य ने यह नहीं कहा कि रोडवेज़ नहीं चलनी चाहिए। तो फिर रोडवेज़ को रोकने के लिए, पहिये थामने के लिए, रोडवेज़ की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक रोडवेज़ की स्थापना के बाद, आदरणीय विपक्ष के नेता महोदय ने बड़ी साफगोई से कह दिया क्या हो गया, एक हजार बसें खराब होती हैं, तो बसें खरीदी जाती हैं। मुझे रिकार्ड उठा कर दिखा दीजिए, यह अधिकारी बैठे हैं, आज तक रोडवेज़ में कभी भी एक साथ इतनी बसें नहीं खरीदी गई, इतनी बसों का टेंडर हुआ जितनी कि 876 बसें इस बार आ रही हैं। इलेक्ट्रोनिक बसें आ रही हैं, आज तक नहीं हुआ। क्योंकि नीयत है, नीति है और मन में दृढ़ संकल्प है कि जिस रोडवेज में हम चुनाव से पहले गए, उस रोडवेज को खड़ा करना है लेकिन जिस रोडवेज़ को मारने में 5 साल लगा दिए, उस रोडवेज को खड़ा करने में टाइम तो लगेगा ही। उसके लिए बड़ा काम किया रोडवेज ने। जो भी अधिकारी आया, आपको पता है यह कारपोरेशन है, इसको चलाना आसान नहीं है। रोडवेज़ ने लोन लिया, लोन लेकर बसें लीं। यहां पर कुछ साथियों ने खड़े होकर कह दिया, कैसी बात करते हो।

राजस्थान में एक्ट बना हुआ है, टेण्डर होते हैं, टेण्डर के बाद बसें खरीदी जाती हैं। टाटा, अशोक लीलेण्ड, सब बस वाले आते हैं। बड़ी-बड़ी

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

कम्पनियां आती हैं। मजाक है कोई गड़बड़ कर दे, एक रुपये की भी बेईमानी कर ले, कोई मजाक है। कोई आकर चोरी कर ले, कोई नहीं। एक बार नहीं, दो-दो बार टेण्डर कैंसिल हुए। उसके बाद टेण्डर पास हुआ। ऐसे थोड़े ही न है। अगर हुआ है तो आप साबित कर दें। मैं आज कह रहा हूं आप जो कह रहे हैं, आदरणीय विपक्ष के नेता महोदय अगर ये बात कहते कि सदन में कोई बात आ जाये, उसके बाद यदि कोई अधिकारी बयान देता है, सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बी.जे.पी. की हो। मैं आज आपको कह रहा हूं। यह लोकतंत्र का मन्दिर है। आप और हम एक-दूसरे के काम्पीटीशन में सरकारों को कमजोर इसीलिये कर रहे हैं कि आज कांग्रेस की सरकार है तो आज हम इनके खिलाफ बोल लें, हम आपके खिलाफ बोल लें। क्या बात करते हो आप। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्य मंत्री का जवाब आ जाये और सदन से अभिभाषण का प्रस्ताव पारित हो जाये, उसके बाद चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, किसी अधिकारी को यह हक नहीं है कि वह बयान जारी कर दे। बयान जारी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज हम यह कह कर खुश हो सकते हैं कि प्रक्रिया में कोई कमी हुई तो अटक जायेगी। आप यह चिंता मत कीजिये। राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर नहीं है। जो कहेगी, वह करके दिखायेगी, हर कीमत पर करके दिखायेगी।

आप क्यों चिंता कर रहे हैं। जो भी काम किया गया है, सब प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। नियम, कायदे, कानून के तहत किया गया है। सही समय पर बोर्ड मीटिंग हुई है। सही समय पर प्रस्ताव लिये गये हैं। अधिकारी आते और जाते हैं, अधिकारी बदलते हैं, लेकिन अधिकारी बदलने का मतलब यह नहीं है कि उनसे पहले प्रस्ताव नहीं लिये गये हैं। जो अधिकारी बाद में आये हैं, उनसे पहले प्रस्ताव बोर्ड में ले लिये गये। उस बोर्ड का मैं मैम्बर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास सारी रिपोर्ट है। इसलिये मैं आज कहना चाहूंगा कि जब 2018-19 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वह प्रतिवेदन हमारे समय के तो तीन महीने ही हैं, पूरा समय आप ही के कार्यकाल का है। लेकिन आज एक बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन आपने खुद ने यह स्वीकार किया कि आप अपने ही प्रतिवेदन के खिलाफ बोल रहे थे, आप उसमें कमियां निकाल रहे हो।

आज आदरणीय वसुन्धरा जी होतीं तो वे भी देखतीं कि उन्हीं के प्रतिवेदन में इतनी कमियां रह गयीं। तो यह कमी रह गई, आज तो आप बोले कांग्रेस की सरकार के समय, आप अपनी सरकार के समय कभी नहीं बोले।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)
आप अपनी सरकार के समय बोले होते, मैं आज आपको गारण्टी से कह सकता हूं राजस्थान रोडवेज की स्थिति नहीं बिगड़ती।

आप क्या बात करते हो, राजस्थान की रोडवेज को जिंदा रखने के लिये 10 दिन के अन्दर-अन्दर लोक परिवहन सेवाओं के परमिट पर रोक लगाई गई। मन में कोई भावना नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। मन में कोई भ्रष्टाचार करने की भावना नहीं थी कि इस रूट पर हमारी बस चलवा देंगे, हमारे कार्यकर्ता की चलवा देंगे, हमारे जानकार की करवा देंगे।

लोक परिवहन सेवाओं के परमिट में जो खेल खेला गया, वह आपके समय में खेला गया। आपने नेशनलाइज्ड रूट्स को जो कमाई के रूट्स थे, बाहर के, पंजाब के, राजस्थान से बाहर जितने भी थे, वे सब लोग यहां पर आ गये। सारे परमिट बंट गये। वे परमिट आज हम कैंसिल नहीं कर सकते, वे बसें चल रही हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि लोक परिवहन सेवा की बसें हमने बंद की। मैडम, हमने बंद नहीं की हैं। हमने, अब जो परमिट आयेंगे, उस पर रोक लगाई है। अब हम नये परमिट जारी नहीं कर सकते। इन बसों के पहिये हम नहीं रोक सकते। आपने उनकी इतनी पुख्ता व्यवस्था की है कि हम पहिये नहीं रोक सकते। वे चलेंगी लेकिन अब हम नये रूट नहीं खोलेंगे। अब हमने कहा कि रोडवेज को खड़ा करना है। हम रोडवेज को खड़ा करना चाहते हैं।

आप रोडवेज के किन कर्मचारियों की चिंता करना चाह रहे हैं, जिनकी आप पिटाई कर रहे थे लाठियों के जरिये? जिनके लिए सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड के बाहर एक हजार पुलिस वाले लगाये? आपने यह कहा कि लोक परिवहन सेवा की बसें अन्दर घुसेंगी। आज तक, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब राजस्थान की सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि प्राइवेट लोक परिवहन सेवा की बसें सिंधी कैम्प के अन्दर से चलेंगी, राजस्थान के रोडवेज के हर बस स्टैण्ड से चलेंगी। लाठी लेकर पुलिस वाले गये। उन्होंने लाठीचार्ज किया। तभी तो वह आन्दोलन हुआ। तभी हंगामा हुआ। उस वक्त कांग्रेस पार्टी क्यों बीच में आई, इसलिये आई बीच में, तब सचिन पायलट, मैं या अशोक गहलोत जी या सदन के ये कांग्रेस के नेता थे, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट में रोडवेज वालों की मदद करने के लिये मैदान में गये। इसलिये गये कि पुलिस लाठी ले करके खदेड़ रही थी और अन्दर बसों को घुसा रही थी। जब लगा कि अब कांग्रेस पार्टी बीच में आ गई है तो आपको विदड्रा करना पड़ा और लोक परिवहन सेवा

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

की बसें अन्दर नहीं घुस पाईं। नहीं तो आपने तो तैयारी कर ली थी। आज रोडवेज को जो आप कह रहे हो कि जिंदा रहनी चाहिए, वह रोडवेज नहीं चल रही होती। रोडवेज बस स्टैण्ड के अन्दर से लोक परिवहन सेवा की बसें चल रही होतीं। आज मैं आपको गारण्टी से कह रहा हूं। हमारी नीयत पर आप कैसे शक कर सकते हैं।

आज मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली बार इन बसों में अक्टूबर, दिसम्बर में हम रोडवेज को इन दो महीनों में फायदे में लेकर आये। हम पूरी मोनिटरिंग कर रहे हैं। क्या बात करते हो। आप प्रगति प्रतिवेदन उठाकर देखो, दो महीने में हम फायदा भी लाये हैं।

हमारी नीयत पर बात करते हो, एक कम्पनी एक महीने के एक करोड़ रुपये उठा रही थी। हर महीने एक करोड़ रुपया, सारा नाम की कम्पनी, जिसमें हमने दिया है, उसका हमने टेण्डर कैंसिल किया। हमें जरूरत ही नहीं थी। वर्षो से एक करोड़ रुपये ले करके जा रही है, लगातार लेकर जा रही है। हम चाहते हैं लीकेजिंग रुके, चोरी रुके, भ्रष्टाचार रुके। भ्रष्टाचार रुकेगा तो रोडवेज का घाटा भी कम होगा और रोडवेज दौड़ेगी। नई बस भी आयेगी और जनता को सुविधा भी मिलेगी। हम इस बात को जानते हैं। लेकिन आज यह करना, बार-बार बात करना, सिर्फ पोलिटिकल बातें करना और पूरा आरोप-प्रत्यारोप लगाना, मैं इतना कह सकता हूं, अध्यक्ष जी, हमारी नीयत पर, हमारी नीति पर कोई शक नहीं किया जाना चाहिये।

31 मार्च से पहले-पहले राजस्थान में जो हम रोडवेज की नई बसें लेकर आ रहे हैं, रोडवेज की वे नई 876 बसें पूरी आ जायेंगी। इलेक्ट्रिक बसें भी हम 100 प्रतिशत लेकर आयेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें केन्द्र सरकार की सब्सिडी है।

एक बात यहां पर उठाई गई और यह कहा गया कि जो आई.टी. के नाम पर यह हो रहा है कि पांच करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं, आपकी यह सूचना बिलकुल गलत है। ये पांच करोड़ रुपये नहीं दिये जा रहे हैं। ये हमारी सरकार के समय का टेण्डर नहीं है। आप ही ने इस आई.टी. कम्पनी को टिकटिंग के लिये, ऑनलाइन जो ठेका दिया गया था, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय दिया गया था। हमारे पास न तो ऐसी कम्पनियां हैं, न हम ढूंढ कर लाये और यदि हैं, तो इस सदन में विपक्ष के सदस्यों से मैं कहूंगा आप खड़े होकर बताओ कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने या अशोक

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

गहलोतजी ने या धारीवालजी ने या महेश जोशीजी ने या सचिन पायलटजी ने किसी की सिफारिश से कोई रोडवेज में या परिवहन विभाग में कोई आई.टी. कम्पनी लाये हैं या हमने उसको खड़ा किया है। ये तो आप ही की लाई हुई कम्पनियां हैं। हमारी तरफ से तो कोई कम्पनी अभी तक आई नहीं, न हम लाये। ये आप ही की कम्पनी है। इसको 27 पैसे प्रति-टिकट पर, यह आपके टाइम का अनुबंध है। अनुबंध बीच में कैंसिल नहीं किये जाते हैं। पुरानी सरकार अनुबंध करके गई है।

आप चिंतित हो रहे हो। आप चिंता मत करो। आपने जो चिंता दर्शाई है, इससे मैं भी चिंतित हूं और मैंने उनसे कहा है कि ये कौन हैं 27 पैसे भी क्यों? पर आप चिंता मत कीजिये। अब कितना तैयार हुआ, पता नहीं, मैंने कहा हमारा खुद का एप डवलप करो। एप डवलप कर रहे हैं। हमारा एप डवलप हो जाएगा, इस कम्पनी को रवानगी दे देंगे। हमारे एप पर ही टिकट की बुकिंग होगी। इतना मैं भी पढ़ा-लिखा हूं, बहुत ज्यादा नहीं तो इतना तो मैं भी हूं।

आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़कर आये हैं, मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया हूं। वे भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़कर आये हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले इतने भोले नहीं हैं कि हर कोई हमारी जेब काट कर भाग जाये।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): इनको सब जानते हैं। इनको पूरा जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको भी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं इसलिये कह सकता हूं कि हम किसी भी कीमत पर एक रुपया भी किसी को ...(व्यवधान)

सदन की बैठक

विधान सभा की कार्यवाही के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय परिवहन मंत्रीजी के बयान के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी के दोनों बयानों के पूरे होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति है?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 पर विचार

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जो आज यहां पर चिंता प्रकट की गई। आप यह मानकर चलिये कि यह आई.टी. कम्पनी की बात आप हमारे सामने लाये हैं, लेकिन आप ही के द्वारा लेकर आये हैं। आप पता कर लेना। कहीं यह नहीं हो, हम तो हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं कोई नाराज हो जाये, हंगामा हो जाये। लोग आपके पीछे पड़ जायेंगे। वे सारे के सारे आप ही के आदमी हैं। फिर आपके दिक्कत हो जायेगी। आप कह तो रहे हैं लेकिन आप ही का कोई शाम को दोस्त मिल जाये। आप पार्टी में जाओ, वे कहें, आज आप यह क्या कर आये, राठौड़ साहब, हमें ही निपटा दिया। क्योंकि सारे के सारे आपके खास हैं। क्योंकि आप मेरे से बड़े खिलाड़ी हैं, पुराने आदमी हैं। इसलिये मैं (व्यवधान) नहीं खिलाड़ी तो मैं हूं, लेकिन ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपसे बड़े हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, मैं एग्री कर रहा हूं न। (व्यवधान) हां यह बात भी ठीक है। ये रखेंगे नहीं, इन्होंने जिस ढंग से कहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की डिबेट को रोको।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं।

वैसे अध्यक्ष जी, जब ये बोल रहे थे, तब मैं आज एक शब्द नहीं बोला। इसलिये नहीं बोला, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स पढ़ाये हैं लेकिन आप भी स्टूडेंट पोलिटिक्स से निकलकर आये हैं, अध्यक्ष जी। मैं इसीलिये नहीं बोला, अगर मैं बोल जाता तो ये बार-बार खड़े होते। मैंने कहा कि आज बिलकुल नहीं बोलना है, इनको तसल्ली से बोलने दो फिर मैं भी तसल्ली से बोल लूंगा।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. शासन काल का जो घाटा था, वह घाटा इतना बड़ा था यह बात सही है कि नफे और नुकसान से कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के काम नहीं चला करते। लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी सरकार नफे और नुकसान से नहीं चलती पब्लिक वेलफेयर से चलती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार यह मानती है कि रोडवेज यदि घाटे में भी है तो भी रोडवेज को चलाना जरूरी है। रोडवेज जब पैरेलल में चलेगी तो ही प्राइवेट प्लेयर मनमानी नहीं कर पाएगा। यदि आज रोडवेज हट गयी तो फिर प्राइवेट प्लेयर की मनमानी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे और मैं आज आपसे यह कह रहा हूं कि जो दुर्घटनाओं की बात इन्होंने कही, राजस्थान रोडवेज अभी दिल्ली में सम्मानित होकर आई है। दुर्घटनाओं में राजस्थान रोडवेज का रेशो हिन्दुस्तान में सबसे कम है। हम दुर्घटना नहीं करने में नम्बर वन पर हैं, इसलिए आप रोडवेज पर सवाल खड़े कर रहे हैं?

मैं मानता हूं कि रोडवेज के पास संसाधन नहीं है, रोडवेज की बसें खराब हो रही हैं, रोडवेज की हालत खराब है इसके बावजूद रोडवेज का एक्सीडेंट रेशो सबसे कम है पूरे हिन्दुस्तान में। इसका मतलब आप यह मानकर चलिये यही नीयत थी कि कैसे भी रोडवेज की स्थिति दिन पर दिन ठीक हो और हम रोडवेज की स्थिति को सुधार पाएं।

जहां तक नई बसों का सवाल है, लगातार नई बसें आएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। वर्तमान सरकार ने, आज जहां तक दिल्ली का सवाल है, आप यह मानकर चलिए कि दिल्ली का बीकानेर हाउस, हमने वहां से रोडवेज बसों का संचालन बंद नहीं किया है। दिल्ली-जयपुर में रोडवेज बसों का संचालन जो बंद हुआ वह आपके टाइम पर हुआ और वहां बीकानेर हाउस पर इतना झगड़ा हुआ कि राजस्थान की बी.जे.पी. सरकार की पुलिस खुद गयी रोडवेज को बंद करवाने के लिए। पुलिस वाले, नेता, कि बीकानेर हाउस से रोडवेज बस नहीं चलेगी, हटाओ इसको। मैनेजर वगैरह, वहां आंदोलन चल रहा था। कर्मचारी इकट्ठे हो गये। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारा रोडवेज का स्टैंड नहीं हटाएंगे तो वह बोले कैसे नहीं हटाओगे, हमने यह पूरा बीकानेर हाउस ही दे दिया किसी को। वह बोले, साहब, हमारी रोडवेज की आप कैसे दे सकते हो? रोडवेज के पास तो जब से रोडवेज की स्थापना हुई है तब से है। वह माने नहीं और आखिर में उन कर्मचारियों ने मुकाबला किया। यह उस दिन का जो पाप है न बीकानेर हाउस का, आज तक

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

बस शुरू नहीं हो पाई। मैंने जान लड़ा रखी है। मैंने यहां तक कहा कि दस इलेक्ट्रिक बस ले आओ। यह कहा गया कि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहा है कि भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है, मैंने यह नहीं कहा। मैंने रोडवेज की मीटिंग में यह कहा कि स्वीकार करना पड़ेगा यदि रोडवेज की बस खाली बिना टिकट के मिलती है पूरी और रोडवेज के स्टैंड पर कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए मैनेजर जिम्मेदार है।

अब हम नई नीति लेकर आएंगे। हमने भी तैयारी की है। बिना टिकट के कोई यात्री मिलेगा तो अब उस यात्री पर भी हम फाइन करेंगे, चार गुणा फाइन चार्ज करेंगे। आप टिकट लेकर बैठो। कहीं पर तो हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और आप जो चिंतित हैं, हम बसें ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी बुरा लगता है। मैं भी पापुलर पालिटिक्स करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर आदमी मेरे से संतुष्ट हो लेकिन जब बस मांगते हैं, बस हो तब दें। कोशिश कर रहे हैं कि आपको बस मिलें इसीलिए तो 876 बसें लेकर आये हैं। हर आदमी यह चाहता है कि मेरे यहां पर चले। आप भी अपने-अपने जो आपका एम.एल.ए. फंड है, आपको पता है कि रोडवेज की हालत खराब है, आप भी दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये आपके यहां पर दो, आप जहां स्टैंड बनाना चाहोगे, आपको 20 लाख रुपये खर्च करना है, आप बनाओ न, रोडवेज क्यों नहीं रुकेगी, हम रुकवायेंगे और मैं आज सदन में घोषणा करता हूं सबके सामने। सब माननीय सदस्यों की एक शिकायत आई है मेरे पास में कि रोडवेज बस हाईवे से निकल जाती है, अंदर से होकर नहीं जाती है, रुकती नहीं है, यह जो सिस्टम है इसको फुलप्रूफ करने के लिए मैं सदन में यह घोषणा करता हूं कि ड्राइवर, कंडक्टर हाईवे से नहीं निकलेगा, जहां से उसको अंदर से निकलना है, अंदर से सवारियों को लेते हुए निकलेगा और छोड़ते हुए निकलेगा, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। ज्यादा चिंता है इस बात की, हर आदमी यही कह रहा है और इस बात को मैं मानता हूं कि वह भाग रहा है।

आप इस बात को मानकर चलिए कि आप भी विधायक हैं यदि आपको लगता है कि आपके यहां की रोडवेज में कहीं दिक्कत है, डिपो पर दिक्कत है तो आप जाओ न, डिपो मैनेजर से बात करो। एक भी विधायक मुझे ऐसा नहीं मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह कह दें कि यह प्लान है हमारे डिपो का। एक बात मुझे अच्छी लगी, वह मिले मुझे अमीन खां साहब, उन्होंने यह कहा कि जो वोल्वो वहां तक जाती थी यदि वह नहीं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जाएगी तो मुझे उनकी बात सही लगी, एक जरूर वह मिले बीकानेर वाले, उन्होंने यह कहा कि जो वोल्वो यहां से दिन में निकलती है, वह यदि रात को निकलेगी तो फुल जाएगी। हमने अभी इस घाटे को कम करने के लिए ऐसे-ऐसे काम किये, पिछली बार जो एम.डी. थे, वह आये, मेरे पास बैठे और हमने कहा कि क्या करें? तो ऐसी-ऐसी बसें चल रही हैं, यह बात मैं मानता हूं लोक परिवहन सेवा की बस भी उसी रूट पर चल रही है, आगे-आगे चल रही है रोडवेज के और रोडवेज उसके पीछे-पीछे चल रही है। क्या करें? वह परमिट पिछली सरकार के समय लेकर बैठा है। वह चलेगा बराबर में टक्कर में रोडवेज को, ऐसा रोडवेज नहीं कर सकती, सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है क्योंकि वह हाई कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हैं। बात होती है कि प्राइवेट बसें यहां खड़ी हैं, वहां पर खड़ी हैं, मेरे भी मन में इच्छा होती है कि इनको हटवा दूं इस रोड से पर वह हाई कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हैं। कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे पास परमिट है, सरकार ने हमसे समझौता किया है, आप हमको यहां से नहीं हटा सकते इसलिए आप, सिर्फ यह कहना, इतना हम कह सकते हैं कि आपका कोई अच्छा सुझाव होगा तो उस सुझाव को सम्मान देना, उस सुझाव के अनुसार काम करना, यह हमारी जिम्मेदारी है।

जहां तक ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली हमने शुरू कर रखी है, उसमें हमारा काम चल रहा है और हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह जो बात आई प्राइवेट बुकिंग एजेंट्स की और यह कहा गया कि प्राइवेट बुकिंग एजेंट के कारण हमको घाटा हो रहा है। यह सवाल जिन माननीय सदस्यों ने खड़ा किया है मैं उनको यह कह दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट बुकिंग की आप पहले जांच कर लेना, पहले मुझे भी लगता था पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट बुकिंग एजेंट के कारण नहीं, रोडवेज में कर्मचारियों की कमी है, यह हम जानते हैं। कर्मचारी तब लिए जाते हैं जब रोडवेज में बसें आयें। पहले बसें तो लाएं तब ही तो उस एक करोड़ वाली कम्पनी का टेंडर कैंसिल किया है। बसें ही नहीं होंगी तो कर्मचारी क्या करेगा? बिना बसों के कर्मचारियों की भर्ती कर लें? कुछ साथियों ने यह कहा कि कर्मचारियों की भर्ती कर लो, बस तो लाओ। बसों से रोडवेज चलेगी, सिर्फ कर्मचारियों से रोडवेज नहीं चलेगी। कर्मचारी तो भर्ती भी कर लोगे, संविदा पर भी ले लोगे तो चला भी लेगा। अभी रोडवेज की स्थिति कई बसों की बहुत खराब है, उनकी जगह भी रोडवेज की नई बस चलेगी।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

अब यह बात आई, साहब, यात्रियों के लिए सुविधाओं का जहां तक सवाल है, हम रोडवेज के जितने भी बस स्टैंड हैं, हमारी खुद की तैयारी है। सिंधी कैम्प, जयपुर को तो हम आइडियल बस स्टैंड बनाएं और बाकी जितने भी स्टैंड्स हैं उनका वहां पर दूसरी कम्पनियों से टाईअप करके ऐसे कोई मनोरंजन के साधन वहां पर हम करें जिससे पब्लिक का आना-जाना शुरू हो, ऐसा कोई मॉल वहां पर आये और वह पार्टनरशिप करे। मेरी यह इच्छा नहीं है कि हम रोडवेज की प्रोपर्टीज को बेच दें, वह बाद की बात है। मेरी यह इच्छा है कि रोडवेज से टाईअप करें। लोग रोडवेज से मिलें, रोडवेज की जो प्रोपर्टीज हैं, वह बहुत बड़ी है, यह मुझे पता है और उनका सही यूज़ हो, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लेकिन करें क्या? आर्थिक मंदी का ऐसा दौर है कि जहां पर भी रोडवज वाले सोचते हैं इस जमीन का यूज़ कर लें, आगे बढ़ते हैं तो अच्छे-अच्छे बिजनिस प्लेयर कहते हैं कि अभी तो मरे हुए हैं, थोड़े दिन रुक जाओ। बाकायदा टेंडर होगा, पर लोग आते ही नहीं हैं। क्या आप समझते हो कि रोडवेज वाले कोशिश नहीं कर रहे? वह विज्ञापन देते हैं, बुलाएंगे न। पूरे देश के प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाते हैं कि आप आओ, जगह बहुत अच्छी है, रोडवेज के पास बहुत ही वैल्यूएबल लैंड है, सब जगह पर और लोग तैयार होते हैं लेकिन कहते हैं कि साहब, थोड़े दिन रुक जाओ हमारी स्थिति ठीक नहीं है। हम भी माडल जहां पर सक्सेस है, जहां पर बस स्टैंड बहुत अच्छे हैं उन्हीं से नकल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खानापूर्ति कर रहे हैं। ऐसा कोई घमंड भी नहीं है, मैं आपको सब सड़क पर दिख जाऊंगा, ऐसी कोई गलतफहमी भी नहीं है, मैं बस में, सबमें बैठता हूं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं आज भी सुबह खेलने जाता हूं तो मेरी खुद की गाड़ी लेकर ही जाता हूं। वैगनआर में ही जाता हूं चाहे बाद में मेरे पास में भगवान की दया से घर में कोई कमी भी नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई ग़लतफ़हमी हो गयी, मंत्री बन गये। मंत्री कम और संतरी ज्यादा है। आज भी कोई रोककर बात कर लेता है, आवाज देकर रोक लेता है, बुला भी लेता है इसलिए रोडवेज में, जहां तक रोडवेज का सवाल है, रोडवेज वालों को मैं आज से जानता हूं क्या? यहीं मेरी स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी हुई है, मैं खूब जानता हूं इसलिए आप इस मामले में निश्चिंत रहिए, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे।

टायर रिट्रेडिंग की बात पर बलजीत यादव जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। हमारे पास वर्कशाप है, हमारे पास टायर रिट्रेडिंग के कारखाने भी

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

हैं और यह सुझाव इनका अच्छा है। पहले भी यह बात हुई थी लेकिन बीच में दिक्कत यह आई थी कि जब टायर रिट्रेड हो जाता है तो उसके बाद एवरेज कम देते हैं। अभी बात यह भी आई थी तो इस पर भी हम विचार करेंगे। काफी डिस्कस इस पर चल रहा है और काफी काम भी हो रहा है।

जो नई बसें आईं तब यह कहा गया कि साहब, इससे घाटा होगा। इससे घाटा नहीं होगा इससे हमारा एवरेज बढ़ेगा, इससे फायदा होगा। आप निश्चिंत रहिए और जो बस खरीदी गयी है न उस बस में यदि किसी को भी लगे कि इससे सस्ती बस हमें कहीं से दिलवा सकता है तो आ जाना। हम पहले उसका सम्मान करेंगे, फिर वह जो कहेगा हम सज़ा भुगतेंगे, दूसरी सस्ती ले लेंगे, आप यह भी बता देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी इतनी ज्यादा माथा-फोड़ी हुई है।

राजस्व बढ़ाने के लिये हमने हमारी तरफ से पूरे प्रयास किये हैं, लेकिन फिर भी किसी सदस्य को यह लगता है कि रोडवेज का राजस्व यह वैल्यूएबल लैण्ड के जरिये इस ढंग से बढ़ सकता है। आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। वह सुझाव हम आमंत्रित करते हैं कि आपके पास कोई सुझाव हो देना, हम करेंगे।

अब रोडवेज का जो चैकिंग अभियान है, उस चैकिंग अभियान को हमने तेज किया है। चैकिंग अभियान को इसलिए तेज किया है जिससे भ्रष्टाचार रूके और यह भ्रष्टाचार रोकना जरूरी है। यदि यह भ्रष्टाचार रूक जाएगा तो मैं आज गारंटी से कह रहा हूं काफी हद तक सुधार आएगा। मैंने खुद रोडवेज के कर्मचारियों की मीटिंग में कहा। आप क्या समझते हो, पहले मंत्री नहीं जाते थे, मैं रोडवेज के स्टैंड पर रोज जाता हूं। मुझे कोई नहीं पकड़ रहा है। वह सब कर्मचारी मुझे जानते हैं कि अगला खुलकर खेल रहा है, काम करना चाहता है और वहां ऐसे थोड़े ही है कि हम डर रहे हैं कि कर्मचारी हमें पकड़ लेगा, घेर लेगा, नारे लगेंगे। वह आपके समय पर होता था। ऐसा अब कुछ भी नहीं है।

जहां तक रोडवेज में जब भी हमारे यहां कोई बड़े मेले होते हैं तो रोडवेज ही एकमात्र ऐसा साधन है, जो किसी भी मेले में फ्री आफ कोस्ट अपनी सेवाएं देती है, चाहे राजस्थान में कोई भी मेला हो। अभी बीच में बात आयी ऐसा कौनसा वर्ग नहीं है जिसमें रोडवेज में सुविधा नहीं है। महिलाओं को सुविधा, स्टूडेंट को सुविधा, शहीदों के परिवार को सुविधा, टीचर्स को सुविधा, सीनियर सिटीजंस को सुविधा, विकलांग को सुविधा, फ्री में चलता है हमारा

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

दिव्यांग। आप आश्चर्य करेंगे कि सबको हम फ्री में रोडवेज सर्विस दे रहे हैं। यह रोडवेज ही तो है हमारे पास, जहां सरकार कभी भी पापुलर डिसीजन ले सकती है। महिलाओं को तो पहले से ही कर रखा है।

जहां तक केन्द्रीय बस स्टैंड का काम है, वह लगभग इस महीने बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी उसका उद्घाटन करा दें और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, फ्राइडे है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस पांच मिनट में खतम कर रहा हूं। मैंने तो इसलिए ज्यादा लंबा बोला है क्योंकि यह तो आज आपने अच्छा किया है कि सड़क परिवहन पर चर्चा रख दी। नहीं रखते तो खुलकर बात ही नहीं आती, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहां क्या हो गया। इन्होंने तो बस टर्मिनल बना दिया। अब उस बस टर्मिनल को हम खतम करने जा रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बस टर्मिनल का कोई यूज ही नहीं है। वह सिर्फ इसलिए बना दिया कि एक जगह पावर सेंटर आ जाए। कोई भी डिसीजन लेना हो जमीनों का, तो एक साथ सरकार जयपुर में बैठकर फैसला कर ले। कारपोरेशन की पावर खतम करने के लिये तो बस टर्मिनल बनाया गया। वैसे तो कारपोरेशन में इंटरफियर कर नहीं सकतीं सरकारें, बस टर्मिनल बना दिया तो कम से कम यह जितनी भी वैल्यूएबल लैण्ड है, वह बस टर्मिनल के अंडर में आ जाए। हमने मुख्य मंत्रीजी को प्रस्ताव लिखकर भेजा है कि इसका कोई यूज नहीं है तो इस बस टर्मिनल को खतम कर दिया जाए।

इसी प्रकार कर्मचारियों को तनावमुक्त करने के लिये हमने मोटिवेशनल ट्रैनिंग कैम्प भी जगह-जगह लगाये।

इसमें से काफी चीजें तो मैं बोल चुका हूं। जी.पी.सी. आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमने सब जगह जितने भी हमारे बस स्टैंड हैं, वहां पर हम तैयारी कर रहे हैं कि यह रोडवेज में बिजली की बहुत खपत है। हम तैयारी कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा से वहां पर सब जगह, जितने भी हमारे रोडवेज के बस स्टैंड हैं, हम सौर ऊर्जा लगा सकें, उसकी हमारी पूरी तैयारी है।

दुर्घटनाओं में हमारी स्थिति ठीक रही है और रोडवेज बस स्टैंड पर हमारा यह मानना है कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वहां पर सी.सी.टी.वी.

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

कैमरे ही नहीं हैं। जो पब्लिक प्लेस है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सीकर पास पड़ता है जयपुर से। माननीय मंत्रीजी, दो स्टेटमेंट देने हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया है कि जितने भी बस स्टैंड हैं, उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाएं जिससे कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो तो हमें उस बात का पता चल सके। मैं जितने भी सदस्य हैं, उन सबको यह भरोसा देता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार राजस्थान रोडवेज को इस स्टेट की लाइफ लाइन मानती है। राजस्थान रोडवेज के लिये हमारी कोशिश यह है कि रोडवेज में हमारा इतना घाटा होने के बावजूद राजस्थान की जनता को परेशानी नहीं हो। ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर इस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और हम ग्रामीण परिवहन सेवा को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग हमारी तैयारी पूरी है। पिछली बार जो ग्रामीण परिवहन सेवा चालू करके गये थे, वह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण परिवहन सेवा को बंद कर दिया। उससे गांव-गांव में लोग परेशान हैं और लोगों को लगता है, डिमांड रहती है कि ग्रामीण परिवहन सेवा फिर से शुरू की जाए। हम ग्रामीण परिवहन सेवा में ऐसी कोई पालिसी लेकर आ रहे हैं कि जिसमें जनता को तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले लेकिन रोडवेज और सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हो, वह तैयारी हमारी पूरी है। जल्दी ही ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर आपके कोई सुझाव हों, आपके गांव के कोई प्रस्ताव हों, काफी प्रस्ताव मेरे पास आये, आप हमको देना। हमारी पूरी तैयारी है।

मैंने यह साफ कह दिया है कि रोडवेज की बस जहां नहीं रुकती है, वहां रुकेगी फिर भी मान लीजिए नहीं रुके तो आप हमको सूचित कीजिए, आप मुझे लिखकर दीजिए या हमारे आफिस में दीजिए या रोडवेज के जो हमारे अधिकारी हैं, उनको दीजिए।

जिन माननीय सदस्यों ने मुझे नवीन मार्गों पर बस चलाने के संबंध में कहा है, जिन मार्गों पर बसें बंद कर दी गयी हैं, उन सभी पर हम परीक्षण कराकर आपसे प्रोमिस करते हैं कि उन मार्गों पर बसें चलाने के लिये सरकार पूरी कोशिश करेगी। जिन मार्गों पर बसें बंद कर दी गयी हैं और जनता को परेशानी हो रही है और दूसरा कोई अल्टरनेटिव साधन नहीं है वहां हम तुंरत प्रभाव से उनको बसें देकर शुरू करवाएंगे। मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी भावनाओं का सम्मान करती है और राजस्थान रोडवेज की तरफ से राजस्थान की जनता को जितना रिलीफ हम दे सकते हैं वह हम देंगे। समय पर बसें लेकर आएंगे और समय पर लोगों को बसें उपलब्ध करवाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है। आप सबको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय गृह मंत्रीजी, रूपनगढ़ के बच्चे के संबंध में पहला स्टेटमेंट। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ का स्टेटमेंट है।

शासकीय वक्तव्य

पुष्कर के थाना रूपनगढ़ अन्तर्गत मकान को सीज करते समय 9 माह की बच्ची का मकान में बंद होने का प्रकरण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 13.02.2020 को ओमप्रकाश निवासी कास्यां की ढाणी थाना रूपनगढ़ जिला अजमेर ने एक रिपोर्ट पेश की कि उसके लड़के ज्ञानप्रकाश ने एस.के. पिनकोर्प फाइनेंस कम्पनी से मकान का पट्टा रखकर लोन लिया था। उक्त कम्पनी ने मकान की कुर्की की कार्रवाई 13.02.2020 को दिन के 11.00 बजे पहुंचकर मकानों के कमरों को सील करके ताले लगा दिये थे। मकान के अंदर एक कमरे में परिवादी की पोती कृतिका जो करीब 10-11 महीने की है, को एक कमरे में बंद कर चले गये तथा परिवारजनों के साथ कम्पनी के कर्मचारी द्वारा धक्का-मुक्की कर बाहर निकाल दिया गया। परिवादी की रिपोर्ट मुकदमा नंबर 24/2020 धारा 336, 342 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक अनुसंधान में बच्ची के मकान में तीन-चार घंटे बंद होना पाया गया। जब परिवादी द्वारा जिलाधीश अजमेर से इस संबंध में निवेदन किया गया तो तत्काल एस.डी.एम. रूपनगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया। इस पर थानाधिकारी रूपनगढ़ ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए मकान का ताला तोड़कर बच्ची को कमरे से बाहर निकाला और बच्ची को तुरंत एम्बुलेंस से रूपनगढ़ अस्पताल भिजवाया। बच्ची स्वस्थ है और सुरक्षित है तथा परिजनों के पास है।

उक्त कब्जा लेने की कार्रवाई एस.के. पिनकोर्प फाइनेंस कम्पनी के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जिलाधीश अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/सरिस्ता/484-85 दिनांक 03.02.2020 की पालना में पुलिस इमदाद के सहयोग से की गयी थी। अब तक जांच में यह पाया गया है कि कब्जा लेने की कार्रवाई करते समय किसी के द्वारा भी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया कि बच्ची मकान के अंदर है। कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् मौके से फाइनेंस कम्पनी के कर्मियों के चले जाने के बाद परिवादी के ध्यान में यह बात आने पर उसने प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क किया, जिस पर तत्काल बच्ची को निकालने की कार्रवाई की गयी।

फाइनेंस कम्पनी के खिलाफ 342 आईपीसी रोंगफुल कम्फाइनमेंट और 336 मकान में तोड़फोड़ आदि की कार्यवाही की गई है। रोडा एक्ट के तहत बैंक की रिकवरी के लिए जिलाधीश परमिशन देता है, जिलाधीश कर्मचारी भी उपलब्ध कराता है और उसी के तहत में यह कार्यवाही की गई है।

बच्ची किस प्रकार से अन्दर रह गई, यह उसके परिजनों ने बाहर आकर भी नहीं बताया, जब वो लाक लगाया जा रहा था तब भी नहीं बताया कि साहब, वहां पर बच्ची रह गई है। वो भी झगड़े ही झगड़े में रह गये कि मत करो, मत करो, बंद मत करो, बंद मत करो, कुर्की मत करो, कुर्की मत करो, इसी में दो-तीन घंटे निकल गये। बाद में उनको होश आया कि बच्ची तो वहां पर रह गई तो उनकी शिकायत पर फौरन प्रशासन ने कार्यवाही की।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब मंगाया, पहले तो प्रशासन ने इनके खिलाफ ज्यादती की और यह जवाब भी सरासर गलत है, 11 बजे बच्ची को अन्दर बंद कर दिया गया, उसकी मां रोती रही चिल्लाती रही लेकिन साथ में जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि यह तो झूठ बोल रही है, अगर बच्ची होती तो आवाज आती। उन्होंने ताला खोलकर देखने की जरूरत नहीं समझी।

उसके बाद उसकी मां, उसकी ममता रोती हुई एसडी.एस. आफिस में गई, एस.डी.एम. से बात की तो एस.डी.एम. बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, एक एप्लीकेशन लिखो, वो अर्जी थाने में मार्क की और जब थानेदार के पास उसकी मां गई तो बोलते हैं कि कलेक्टर के पास जाओ, हमने कलेक्टर के आदेश से आपके घर में ताला लगाया है। जब मां रोती हुई कलेक्टर के पास गई तो उसको ताला खुलवाने और एम्बुलेंस भेजने में रात के सात बज गई।

जब 11 बजे की बच्ची अन्दर थी तो आप रिकार्ड उठाकर देख लो,

(श्री सुरेश सिंह रावत)
माननीय मंत्री महोदय, आप जांच कराओ, यह मानवता को शर्मसार करने वाली बहुत बड़ी घटना है। इससे पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की बदनामी हुई है और आपको यह जो गलत जवाब भेजा है उसके खिलाफ भी आप कार्यवाही करिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): जब 11 बजे की सीलिंग की कार्यवाही है और जब 7 बजे बच्ची को बाहर निकाला तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्ची चार घंटे अन्दर रही? बच्ची पूरे आठ घंटे अन्दर रही। क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र है, सुबह 100-150 लोग आये, वो बच्ची विधान सभा में आई थी, मैंने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे लेकिन उन्होंने अन्दर परमिट नहीं किया। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ और फाइनेंस कम्पनी के अधिकारी, कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फाइनेंस कम्पनी के खिलाफ 342 आईपीसी रोंगफुल कन्फाइनमेंट और 336 का मुकदमा दर्ज हो चुका है और मोटे-मोटे तौर पर जो तफ्तीश सामने आई है वो मैंने अर्ज कर दिया कि तीन-चार घंटे जरूर बंद रही और वो बंद रही गफलत में रही। यह संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है इस देश में कि अन्दर अगर कोई बच्ची रो रही हो तो उसके मां-बाप या उसके आसपास में खड़े हुए लोग उसकी आवाज न सुनें और आवाज न सुन करके उसको, प्रशासन को चेतावें नहीं कि साहब, बच्ची अन्दर रह गई और प्रशासन खोले नहीं, यह संभव ही नहीं है।

इसलिए यह बात कहना कि साहब, हत्या का प्रयास था, फलां प्रयास था, यह तो सब बिलकुल गलत है। जांच हो जाएगी और जांच हो करके रिपोर्ट लग जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो मंत्री महोदय से इतना निवेदन है कि यह घटना रोंगफुल कन्फाइनमेंट की नहीं है। आप और हम सब बच्चेदार हैं, कोई भी मां नौ महीने की बच्ची से आधे घंटे अलग नहीं रह सकती। एस.डी.एम. के पास उसकी जो एप्लीकेशन गई उसमें समय लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय। वो ही एस.डी.एम. की एप्लीकेशन को वापस कलेक्टर के पास गई है। आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि पहली बार एस.डी.एम. के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पास परिवादी कितने बजे गये कि हमारी बच्ची अन्दर है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इसकी जांच किसी आई.पी.एस. अधिकारी से कराओ।

मैं समझता हूं कि यह छोटी घटना नहीं है। आप अपने पर देखो, उस बच्ची के चेहरे पर अपनी पोती का चेहरा लगाकर देखो फिर आप फैसला करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर यह आपके रिकार्ड पर आया है कि 11 बजे से लेकर के 7 बजे तक बच्ची बंद रही, अगर यह सच है तो फिर मैं सोचता हूं आपका यह जवाब उचित नहीं होगा। 11 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 8 घंटे का समय है और 8 घंटे के समय में अगर किसी की मां अपनी बच्ची को छोड़कर भी आ गई और उसके बाद उसने जाकर कहीं बात नहीं कही होगी, यह नहीं है।

तो पहला सवाल यही है कि वो एस.डी.एम. के यहां पहुंची उस समय का समय क्या था और उसने अपनी एफ.आई.आर. में जो लिखाया है उसमे उस बच्ची का किस समय से लेकर किस समय तक वो बंद रही? यह दो बात स्पष्ट हो जाएंगी तो अपने आप साफ हो जाएगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सात बजे वाली बात मैंने नहीं कही। मैंने तो यह कहा कि 11 बजे मकान को सील किया गया, उसके तीन घंटे के बाद, तीन घंटे के अन्दर-अन्दर उसको वापस खोल दिया गया। मैंने तो आपसे यह कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, माननीय सदस्य, बैठें। एक मिनट बैठें।

माननीय मंत्री जी, इसमें मोटा इश्यू यह है कि एक प्राइवेट लोनी की रिकवरी के लिए कलेक्टर ने आदेश दिये, तो जब रिकवरी करने गये तो पुलिस अधिकारी भी थे, पुलिस के आदमी भी वहां थे। क्या इसमें यह तो नहीं है, क्योंकि पुलिस की प्रजेंस में ताला लगा, कलेक्टर के कहने से वहां पर रिकवरी हुई तो एस.डी.एम. और कलेक्टर के कार्यवाही करने में तीन घंटे भी लगे हों तो 9 महीने की बच्ची के साथ इतना जो गैप है वो इम्पोर्टेंट चीज है।

मेरा निवेदन यह है कि इस तथ्य का भी गौर किया जाए कि जो रिपोर्ट अधिकारी ने दी है वो इसको स्पष्ट कर ले कि भई 9 महीने की बच्ची है, पुलिस की प्रजेंस में ताला लगा हो और जब एस.डी.एम. के नोटिस में आ

(श्री अध्यक्ष)

जाए फिर कलेक्टर के पास जाना पड़े, फिर वापस आना पड़े, उस तरह की व्यवस्था भविष्य में नहीं हो, उसके बारे में आपको डाइरेक्शन देने चाहिए क्योंकि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसकी तफतीश किसी सीनियर आफिसर से करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अगला स्टेटमेंट। प्लीज, माननीय मंत्री जी, प्रताप सिंह जी को भी मैंने समय की याद दिलाई है।

मालवीय नगर, जयपुर स्थित थड़ी में हुई आगजनी के दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दिनांक 12.02.2020 की रात्रि सैक्टर 3, मालवीय नगर में स्थित थड़ी में हुई आगजनी की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 13.02.2020 को निगम के अधिकारियों को मौके पर तलब कर घटना के सम्बन्ध में वार्ता व मुआवजा दिलाने हेतु श्रीमती सुमन शर्मा मय अपने कार्यकर्ताओं के मौके पर उपस्थित हुई और इस सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शन करने लगी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम रास्ते को रोक करके बीच में बैठ गई।

थाना मालवीय नगर पर आम रास्ता अवरुद्ध करने की सूचना प्राप्त होने पर एसीपी मालवीय नगर, थानाधिकारी मालवीय नगर मय हमराह जाप्ता के मौके सैक्टर 3 मालवीय नगर पर पहुंचा तथा शांति हेतु व्यवस्था कायम करने तथा रास्ता रोकने के बाबत उपस्थित लोगों से समझाइश की। इस दौरान श्रीमती अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता मय अपने कार्यकर्ताओं के मौके पर उपस्थित आईं। श्रीमती सुमन शर्मा व अर्चना शर्मा के कार्यकर्ता आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए उग्र नारेबाजी करने लगे और दोनों पक्षों में आपस में धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई।

थानाधिकारी द्वारा हमराह जाप्ते के साथ दोनों पक्षों को लड़ने से रोका। सुमन शर्मा के साथ आये कार्यकर्ता पुरुष व महिलाओं ने उत्तेजित होकर के आम रास्ते को जाम कर उपस्थित पुलिस जाप्ता के साथ हाथापाई शुरू कर दी और कुछ लोगों ने पथराव भी किया। जिस पर थानाधिकारी द्वारा हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया।

श्रीमती सुमन शर्मा व उनके साथ आये कार्यकर्ताओं द्वारा सैक्टर 3

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
मालवीय नगर की आम सड़क के बीच में बैठकर आम रास्ते को पुन: अवरुद्ध कर दिया गया। इसी बीच बी.जे.पी. के कुछ वरिष्ठ नेतागण भी मौके पर आ गये तथा धरने पर आम रास्ते पर बैठ गए।

इस पर थानाधिकारी की रिपोर्ट पर श्रीमती सुमन शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध राज कार्य में बाधा पहुंचाने, रास्ता रोकने आदि के अभियोग दर्ज किये गये 332, 353, 143, 283, 336 और 354 आईपीसी।

दिनांक 13.02.2020 को श्रीमती सुमन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग, राजस्थान ने रिपोर्ट पेश की कि 13.02.2020 को मेरे पास थड़ी बाजार सैक्टर 3 मालवीय नगर से कुछ थड़ी व्यापारी सुबह 7.30 बजे आये और थड़ियों में आग लगाने के बारे में बताया। एस.एच.ओ. अरुण कुमार पूनिया, एसीपी महेन्द्र शर्मा, भरत सिंह आदि धरने पर बैठे मुझ सहित सभी लोगों से बदतमीजी और अपशब्द कहे। एस.एच.ओ. ने मेरी गिरहबान पकड़ ली, धक्का-मुक्की और बदसलूकी की गई, कपड़े फाड़ दिये और हम लोगों पर ताबड़तोड़ लाठी मारना शुरू कर दिया। गंदी-गंदी गालियां दीं। मेरे हाथ पर चोट आई। धर्मा चौधरी के सिर में गंभीर चोट आई। वह अभी अस्पताल में भर्ती है। अन्य लोगों को भी चोटें आईं। इस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया, जो 323, 341, 354, 504 आईपीसी का है। दोनों प्रकरणों में सहायक पुलिस आयुक्त, सांगानेर, जयपुर पूर्व द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज घटना के विरोध में भाजपा द्वारा मालवीय नगर का बाजार भी आंशिक रूप से बंद करवाया गया।

(19.00 बजे)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पूर्ण रूप से।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से रिप्लाई किया है हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मुझे लगता है कि और भी कोई आईपीसी की धाराएं रह गई हों तो वह भी सुमन शर्मा पर लगा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। प्रश्न पूछें माननीय सदस्या। चर्चा नहीं। केवल प्रश्न पूछें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं कि जिस प्रकार से यह घटना हुई और सब लोगों ने इसको देखा है। रात के समय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

में वहां उन कियोस्क में आगजनी होती है। सुबह कोई आता है। आप भी जन प्रतिनिधि, मैं भी जन प्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष जी आप स्वयं भी जन प्रतिनिधि हैं। कोई भी हमारे पास आएगा और कहेगा कि मेरे साथ में इस तरह कि ज्यादती हो रही है तो हम लोग उसके साथ जाएंगे और वही सुमन शर्मा ने किया। वह उनके साथ में वहां पर गई हैं। जब वहां जाकर सारी चीजों को देखा तो उन्होंने सीधा नगर निगम में फोन किया। नगर निगम वालों से पूछा कि यहां किस प्रकार से, उन्होने कहा कि इनके तो सारे पैसे हमारे यहां पर जमा हैं। हम लोग अभी आकर देख लेते हैं। इतनी देर में उन्होंने थानाधिकारी को भी फोन किया कि आगजनी का मामला है और आप आइए। थानाधिकारी वहां पर पहुंचे। उससे पहले अर्चना शर्मा वहां पर पहुंचीं। वह कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचीं। उसने वहां पर निर्देश दिए उस थानाधिकारी को कि आप इन सब लोगों को यहां से हटाइए। आप इनको ठीक करिये। इनका इलाज करिये। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज हुआ। उन लोगों को पकड़-पकड़कर पीटा गया। उनके कपड़े खींचे गए। वह सारी चीजें हुई हैं। वह बिलकुल शांति से बैठी हुई थी।

जिस प्रकार से आपने यहां पर वक्तव्य दिया, क्योंकि आपको वह पुलिस अधिकारियों ने लिखकर दिया। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी घटनाओं के अंदर संवेदनशीलता रखनी जरूरी है। जब वहां पर ऐसा सब कुछ हुआ है तो उस थानाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। जो थानाधिकारी महिलाओं के कपड़े खींच रहा है। उनके साथ में बदतमीजी कर रहा है। उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आप इतना शांति से कह रहे हैं। इससे पहले वाली घटना में भी आपने बड़ी शांति से कह दिया कि छोटी सी बच्ची कमरे के अंदर बंद रही। यह क्या तरीका हुआ? अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं। प्रश्न पूछना है कि नहीं? श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। क्या यह सही नहीं है कि धर्मा चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वह आज जयपुरिया हास्पिटल में भर्ती है? उसके नौ टांके आए हैं। हल्का बल प्रयोग आप इसी को कहते हैं, जहां नौ-नौ टांके आएं? क्या यह सही नहीं है कि अर्चना शर्मा ने वहां से आपके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यालय में टेलीफोन किया? आपने निर्देश दिया कि इनको मारकर भगाओ। अगर इस तरह की बात होगी न, यह प्रजातंत्र है, मैं समझता हूं कि आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह कर रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कालीचरण जी नहीं। खाली मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धर्मा चौधरी, सात तो केस हैं इनके खिलाफ। छह में चालान पेश हो चुका है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक भी केस में नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। नहीं सुनना है? माननीय सदस्य, नहीं सुनना चाहते? चर्चा समाप्त हुई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 19.04 बजे सोमवार, दिनांक 17 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

खेडली (कठूमर) में उप परिवहन कार्यालय की पुन: स्थापना

81. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कस्बा खेडली में कई वाहन डीलर हैं किन्तु वाहन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण 80 कि.मी. दूर अलवर शहर में वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु जाना पड़ता है? यदि हां तो क्या खेड़ली में सरकार द्वारा उप परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वाहनों के पंजीयन का कार्य डीलर द्वारा किया जाता है। (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है) वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से वाहन स्वामी के पते पर भेजा जाता है।

विभाग में स्वीकृत पदो से कम कर्मचारी कार्यरत हैं जिससे वर्तमान में संचालित कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। अत: खेड़ली में बन्द उप परिवहन कार्यालय को खोले जाने के संबंध में सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बिलाड़ा क्षेत्र में अवैध खनन

95. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कितनी खानें पट्टा शुदा होते हुए खनन मानदण्डनुसार संचालित हो रही हैं व कितनी अवैध हैं? अवैध खनन के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी खानें कार्यरत हैं जिनमें रिक्टर स्केल व कम्पन्न स्केल लगा रखे हैं व कितनों में नहीं हैं? जिन खानों में उक्त उपकरण नहीं लगा रखे हैं उनमें कब तक लगा दिए जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अप्रधान खनिज के 185 खनन पट्टे एवं 20 क्वारी लाइसेंस प्रभावशील हैं, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रियां में स्थित 8 खनन पट्टों में नियमानुसार अर्हता प्राप्त प्रबंधकों की नियुक्ति नहीं होने से खनन कार्य बंद करवाया गया है, 01 खनन पट्टे में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की गई है तथा इसमें खनन कार्य बन्द है, विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। शेष में नियमानुसार खनन कार्य संचालित हो रहा है। विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में अवैध खनन के 09 प्रकरण पाये गये जिनमें नियमानुसार कार्यवाही कर शास्ति राशि रुपये 15,50,995/- वसूल किये गये, विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। क्षेत्र में अवैध खनन यदा-कदा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा चोरी-छुपे किया जाता है, जिसकी रोकथाम हेतु कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र में संचालित खानों में ब्लास्टिंग से उत्पन्न सतही कम्पन को नापने हेतु कोई यंत्र यथा सिस्मोग्राफ नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि खनन अधिनियमों/विनियम एवं नियमों में उक्त उपकरण लगाये जाने की बाध्यता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ के काश्तकारों की ऋण माफी

96. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अल्पकालीन ऋण को माफ किया गया है? यदि हां, तो ऋण माफी के तहत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि के ऋण माफ किये गये हैं? ग्राम पंचायतवार ऋण माफी का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों के ऋण माफी के आवेदन की समय सीमा निर्धारित की गई थी? यदि नहीं, तो कितने काश्तकार कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में अभी तक ऋण माफी के आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो उक्त किसानों के खाते में दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी, 2020 तक कितनी-कितनी राशि काश्तकारों के खाते में जमा करवाई गई है? ग्राम पंचायतवार ऋण माफी का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिनांक 25.01.2020 तक राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 में 11155 किसानों को राशि रुपये 36.94 करोड़ तथा राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 में 11214 किसानों को राशि रुपये 65.96 करोड़ की ऋण माफी की गई है। ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऋण माफी हेतु किसान को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ऋणी किसानों का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाकर ऋण माफी की कार्यवाही की जाती है एवं किसान स्वयं आकर आधार आधारित सत्यापन कराते हैं। इस क्रम में गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनूपगढ विधान सभा के सभी पात्र किसानों के आवेदन पोर्टल पर दर्ज हो चुके हैं।

(3) जी हां। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गंगानगर केन्द्रीय सहकारी

(सहकारिता मंत्री)

बैंक द्वारा दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी, 2020 तक राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 में 11214 किसानों को राशि रुपये 65.96 करोड रुपये की ऋण माफी की गई है। ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में लोक परिवहन की बसों का अवैध संचालन

97. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लोक परिवहन के नाम से निजी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि लोक परिवहन के नाम से बस संचालन के लिए परमिट जारी किए गए थे? यदि हां, तो कब, किन शर्तों पर एवं कितनी अवधि के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि परमिट की अवधि निकलने के पश्चात् भी नवीनीकरण नहीं करवाने के पर भी बसों का संचालन हो रहा है? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार बस संचालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने लोक परिवहन के नाम से प्राइवेट बसों के संचालन की अनुमति प्रदान की थी। यह सेवा दिनांक 13.12.2015 से प्रारंभ की गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि लोक परिवहन के नाम से बस संचालन के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए परमिट जारी किए गए हैं। शर्तों की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं जारी किए गए परमिटों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। लोक परिवहन सेवा के परमिट 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये गए हैं। इसमें से किसी भी परमिट की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी कार्मिकों को जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त क्लेम

98. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के मानदेय कार्मिकों का जीवन बीमा निगम से जीवन सुरक्षा बीमा कराया जाता है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की समयावधि क्या है? समयावधि पूर्ण होने पर क्लेम में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? पिछले एक वर्ष में कितनी आंगनबाड़ी कार्मिकों को इसका भुगतान प्राप्त हुआ? परियोजना विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशासहयोगिनी का बीमा सुरक्षा कराया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 750 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी का 376 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी को मानदेय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर एक मुश्त 10 हजार रुपये एवं जमा राशि मय ब्याज भुगतान किया जाता है तथा सदस्य महिला के मानदेय सेवा पूर्ण करने पर जमा राशि मय ब्याज देय होती है। पिछले एक वर्ष में एलआईसी से प्राप्त सूचनानुसार 703 आंगनबाड़ी कार्मिकों को भुगतान किया गया है। भुगतान का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में प्रदूषण स्तर के सुधार की योजना

99. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा शहर में वायु गुणवत्ता का औसत स्तर क्या है और प्रदूषण और वायु गुणवत्ता के स्थान में कोटा प्रदेश में कौनसे स्थान पर है? प्रत्येक

(श्री संदीप शर्मा)

जिले में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण का स्तर क्या है? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एनजीटी ने कोटा संभाग में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को विगत 5 वर्षों में क्या निर्देश जारी किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त निर्देशों की पूरी तरह से पालना कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) विगत 3 वर्षों में सरकार ने कोटा में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत 3 वर्षों में सरकार को कोटा में प्रदूषण को लेकर आमजन और जनप्रतिनिधियों से क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में वर्ष 2019 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक मानव संचालित 6 वायु गुणवत्ता जांच केन्द्रों के अनुसार 108.409 है तथा सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र के अनुसार 111.92 है जो मध्यम (Moderate) स्तर दर्शाता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा शहरों को वायु गुणवत्ता के आधार पर श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है।

वर्तमान में राज्य के आठ शहरों में वायु गुणवत्ता जाँच केन्द्र स्थापित हैं जिनकी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मेटर के अलावा सभी मानक मापदंडों के अनुरूप है।

(2) माननीय राष्टीय हरित प्राधिकरण द्वारा कोटा संभाग में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण हेतु विगत 5 वर्षों में विभिन्न प्रकरणों में जारी दिशा निर्देशों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में परिपेक्ष्य में जारी दिशा-निर्देशों की पालना राजस्थान राज्य

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सतत् रूप से की जा रही है। पालना का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोटा संभाग में प्रदूष्ण को रोकने हेतु समय-समय पर उदयोगों का निरीक्षण किया जाता है। नियम की पालना नहीं करने वाले उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण एवं प्रदूषण रोकथाम नियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है। विगत 3 वर्षों में कोटा में पर्यावरण नियमों की पालना नहीं करने पर 6 उद्योगों के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 एवं जल अधिनियम 1974 के अन्तर्गत उद्योग बन्द किये जाने के निर्देश जारी किये गए। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) कोटा में उद्योगों से प्रदूषण को लेकर विगत 3 वर्षों में (01/01/2017 से 31/12/2019 तक) क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(6) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिये किये जाने वाले कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, औषधालयों इत्यादि से जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बनाए गये विभिन्न नियमों व प्रावधानों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इस हेतु समय-समय पर निरीक्षण किये जाते हैं तथा नियमों की पालना होते हुए नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य में पर्यावरण नियमों की पालना नहीं करने पर 3570 उद्योगों को वायु अधिनियम 1981 एवं जल अधिनियम 1974 के अन्तर्गत बन्द किये जाने के आदेश जारी किये गए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

74. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्रीडूंगरगढ विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं? केन्द्रवार, पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 20 पशु चिकित्सालय एवं 28 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र (कुल संस्था 48) संचालित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का केन्द्रवार पदवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर में पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण

75. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अधिकांश राजकीय पशु चिकित्सा इकाइयों में भवन, चिकित्सा उपकरण व अन्य साज समान तथा चिकित्सकों के आवासीय फ्लेट उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त पशु चिकित्सा इकाइयों में पशु चिकित्सकों, पशु सहायकों, नर्सिंग स्टाफ एवं लैब टेक्निशियनों के स्वीकृत पद भी लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधन अनुरूप आवश्यक औषधियां, साज-समान एवं चिकित्सा उपकरण आदि उपलब्ध है। रेवदर विधान सभा क्षेत्र की समस्त क्रियाशील पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए भवन की व्यवस्था उपलब्ध है। इन संस्थाओं को पशु चिकित्सकों के लिए आवासीय फ्लैट उपलब्ध करवाने का प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

"खेती में जान तो सशक्त किसान" योजना में लाभार्थी किसान

76. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बजट घोषणा वर्ष 2019 में "खेती में जान तो सशक्त किसान" में सम्मिलित जिले बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही में उक्त योजनान्तर्गत अब तक कितने किसानों को लाभान्वित किया गया और इस पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2019 में "खेती में जान तो सशक्त किसान" में सम्मिलित जिले बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही में 100-100 कृषकों के तीन कृषक एक्सपोजर भ्रमण तथा बासंवाड़ा जिले में 900 कृषकों को ग्राम पंचायत स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 06.02.2020 तक दिया गया। जिस पर 7.50 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(कृषि मंत्री)

(2) बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की अनुपालना में वर्तमान में तीन जिलों में ही उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगामी समय में आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अन्य जिलों हेतु समुचित निर्णय ले लिया जायेगा।

कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की कार्ययोजना

77. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण प्रति वर्ष खरीफ एवं रबी मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के स्तर से राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार को प्रेषित की जाती है।

खानपुर में पंजीकृत गौशालाएं

78. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कुल कितनी पंजीकृत गौशालाएं हैं? उक्त में कुल कितने गौवंश हैं? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण पंजीकृत गौशालाओं को सरकारी अनुदान मिल चुका है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गौशालाओं में प्रत्येक गौवंश के लिए प्रतिदिन के हिसाब से कितना अनुदान देय होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गौवंश के अनुदान को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर जिला झालावाड़ में 7 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं जिनमें 2111 गौवंश हैं। संख्यावार विवरण निम्नानुसार है -

(गोपालन मंत्री)

क्र. सं.	गौशाला का नाम	संख्या
1.	श्री बांके बिहारी गौशाला अकतासा	360
2.	श्री नारायण गौ सेवा समिति बूढ बागोद	260
3.	श्री कृष्णानन्द गौशाला चान्दखेडी	320
4.	श्री आशुतोष गौशाला शेलीगढी धाम	328
5.	श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति रटलाई	342
6.	भारतीय गौरक्षा संवर्धन समिति समदखेडी	252
7.	श्री गोपाल गौशाला समिति सारोलाकला	249

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर की उक्त समस्त रजिस्टर्ड गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम चरण (अप्रैल, मई, जून 2019) हेतु राशि रु. 67.356 लाख का सरकारी अनुदान दिया जा चुका है।

(3) बड़े गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन की दर से अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(4) वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से सहायता राशि की दरों में वृद्धि की जा चुकी है। पूर्व में बड़े गौवंश हेतु 32 रू. तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रु. की दर से सहायता दी जा रही थी जिसको वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढाकर क्रमश: 40 रु. तथा 20 रु. किया जा चुका है।

कोटा जिले में पंजीकृत गौशालाएं

79. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में कोटा जिले में कितनी पंजीकृत गोशालाएं संचालित हैं? उक्त में से कितनी गौशालाओं को सरकार से अनुदान मिल रहा है तथा शेष को किस कारण से नहीं मिल रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गौशालाओं में गायों की नियमित देखभाल और दवाइयों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत एक वर्ष में कोटा जिले की गौशालाओं में गायों की देखरेख के लिए किन–किन चिकित्सकों को नियुक्त किया गया तथा उक्त चिकित्सकों ने कब–कब उक्त गौशालाओं का निरीक्षण किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(4) क्या सरकार का कोटा शहर में कोई नई गौशाला खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार कोटा जिले की शेष गौशालाओं को भी अनुदान जारी करने तथा अन्य गौशालाओं के अनुदान में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में कोटा जिले में 21 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 में उल्लेखित पात्रता के प्रावधान अनुरूप न्यूनतम 2 वर्ष पुराना पंजीयन तथा 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली पात्र 15 गौशालाओं को सहायता दी जा रही है (परिशिष्ट-1)।

6 गौशालाएं पात्रता की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण सहायता राशि हेतु अपात्र हैं। (परिशिष्ट-2)

(2) गौशालाओं में गायों की नियमित देखभाल पशुपालन विभाग की समीपस्थ पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा किये जाने का प्रावधान है तथा नि:शुल्क दवा योजना अन्तर्गत नजदीकी पशु चिकित्सालय द्वारा गौशालाओं को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवायी जाती है।

(3) विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। गौशालाओं की स्थापना/संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं/ ट्रस्टों द्वारा की जाती है।

(5) गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 में उल्लेखित प्रावधानों को पूर्ण करने वाली गौशालाओं को सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बडे गौवंश हेतु 32 रु. के स्थान पर 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 16 रु. के स्थान पर 20 रु. प्रतिदिन किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में संचालित बजरी खनन की लीजें

80. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला टोंक में कितनी बजरी की लीजें वैधानिक रूप से किन-किन स्थानों पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला टोंक की तहसील निवाई के राजस्व ग्रामों में गैर मुमकिन नदी, नालों के खसरा क्षेत्रों में खनिज बजरी का एक खनन पट्टा क्षेत्रफल 104.7775 हैक्टेयर हेतु प्रभावशील है। उक्त खनन पट्टे में खनन कार्य रिप्लेनिशमेंट स्टडी के अभाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2017 की पालना में बन्द है।

डेगाना में बसों का संचालन

81. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कौन-कौनसे गांव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व ग्रामीण बस सेवा से जुडे हुए हैं तथा कौन-कौनसे गांव उक्त सेवाओं से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति डेगाना, भैरूंदा, रियांबड़ी में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ने उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति डेगाना, भैरूंदा, रियांबड़ी में निजी बस मालिकों को परमिट जारी कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जुडे/वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान परिवहन निगम की पंचायत समिति डेगाना, भैरूंदा, रियांबड़ी में संचालित निगम बसों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है

सरकार की जन घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुये दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु मार्गों का चयन कर लिया गया है। चयनित मार्गों पर वाहन संचालन हेतु 450 मिडी बसों को अनुबंध पर लेने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(परिवहन मंत्री)

(3) पंचायत समिति डेगाना, भैरूंदा, रियांबड़ी में निजी बस मालिकों को जारी परमिटों की सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों का संचालन

82. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवाओं का अभाव होने के कारण लोगों को आवागमन हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को परिवहन की सुविधा देने हेतु रोड़वेज की बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकार की जन घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुये दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु मार्गों का चयन कर लिया गया है। चयनित मार्गों पर वाहन संचालन हेतु 450 मिडी बसों को अनुबंध पर लेने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

जयपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बकाया मानदेय का भुगतान

83. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जयपुर जिले में उक्त बढ़ाये गये मानदेय एवं उसके तथा अन्य एरियर का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) वर्तमान में जयपुर जिले में किन-किन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कितना-कितना वेतन, एरियर अथवा अन्य भुगतान कब से किस कारण से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? क्या सरकार उक्त मानदेय कर्मियों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में की गई वृद्धि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलगन है।

(3) वर्तमान में जयपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बकाया एरियर का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) मानदेय कर्मियों के मानदेय का भुगतान समय पर किया जाता है। मानदेय कर्मियों का मानदेय प्रतिमाह नियमित भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण में पोषाहार का वितरण

84. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार में क्या-क्या वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली प्रसूताओं

(श्री फूल सिंह मीणा)

को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस-किस संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कुल 209 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जी नही। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(2) विभाग द्वारा संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का पोषाहार वितरण का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत सभी पात्र गर्भवती/धात्री महिलाओं को पहले बच्चे के लिए जो 01.01.2017 या इसके बाद गर्भवती हुई है को तीन किस्तों में पांच हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।

गर्भवती/धात्री महिलाओं (शिशु के 6 माह होने तक) को 930 ग्राम पोषाहार (बेबी मिक्स) प्रति सप्ताह दिया जाता है।

(4) प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार का वितरण स्थानीय स्वय सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरिस्का अभयारण्य में सड़क पर मिट्टी डालने पर रोक लगाने की योजना

85. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करके सड़क पर मिट्टी ड़लवायी जाती है जो कि प्रति वर्ष बरसात के दिनों में बह जाती है जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क पर डाली गई मिट्टी, हवा के द्वारा

(श्री कान्ति प्रसाद)

वनस्पतियों पर जम जाती है तथा उक्त वनस्पति को जंगली जानवर खाते हैं जिससे कि जंगली जानवरों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरिस्का से कालीघाटी, पाण्डूपोल, टहला मार्ग की कच्ची सड़क पर पाण्डूपोल मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक दुरस्ती कार्य कराया जाता है। इस कार्य पर वर्ष 2018 19 में 6.40 लाख तथा वर्ष 2019-20 में 3.20 लाख की राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं। उक्त वन क्षेत्र में जंगली जानवरों में इस कारण बीमारी संबंधित कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं है।

श्रीगंगानगर जिले में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर रोकथाम की कार्ययोजना

86. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला श्रीगंगानगर में कौन-कोनसे औद्योगिक क्षेत्रों में कौन-कोनसे उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा है? क्या सरकार द्वारा उक्त के संबंध में निरीक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे उद्योगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रदूषण के संबंध में दिसम्बर 2018 से जनवरी 2020 तक दर्ज मुकदमों की एफआईआर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कौन-कौनसे उद्योगों द्वारा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये हुए हैं तथा कितने उद्योग अनमत्ति प्रमाण पत्र से वंचित हैं? औद्योगिक क्षेत्रानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में विभिन्न औद्यौगिक क्षेत्रों में वायु, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण कारक उद्योगों की सूची परिशिष्ट-अ पर सलग्न है। इन सभी उद्योगों द्वारा जल एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित की हुई है, यद्यपि समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निरीक्षण किया

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

जाता है एवं निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में कोई कमी पाई जाती है तो उद्योग के विरुद्ध जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। दिसम्बर 2018 से जनवरी 2020 तक इन उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण उत्पन्न करने के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। तथापि जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना एवं संचालन हेतु सम्मति जारी की जाती है। श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न औद्यौगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग जिनको वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संचालन सम्मति प्राप्त है अथवा जिनका आवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में विचाराधीन है, की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न औद्यौगिक क्षेत्रों में संचालन सम्मति की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने वाले उद्योगों की सूची परिशिष्ट-स पर सलग्न है। ऐसे सभी उद्योगों के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर जिले में आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र

87. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से कितने प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं? केन्द्रों द्वारा किस-किस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) विगत 5 वर्षों में उक्त केन्द्रों पर कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षण के पश्चात् कितने लोगों को रोजगार उपलबध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्तमान मे राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से 9 प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

है, इनमें संचालित ट्रेडों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षो में अजमेर जिले में विभिन्न कौशल केन्द्रों पर कुल 12826 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण प्रदान किये गये 12826 प्रशिक्षणार्थियों में से 4939 को प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिलों में खेलकूदों को प्रोत्साहन हेतु विशेष बजट का आबंटन

88. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिलेवार खेलकूद हेतु विशेष बजट एवं सामग्री आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार जिले की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु खेल छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिलेवार खेलकूद हेतु बजट एवं सामाग्री आबंटन नहीं की जाती है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संचालित खेल अकादमियों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

सरकार जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हेतु खेल छात्रावास/एकेडमी खोलने के लिए बजट उपलब्धता एवं निम्नांकित सुविधाओं के उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है-

1. उपयुक्त स्तर की आवासीय सुविधा।
2. खिलाड़ियों के दिन-प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं की समुचित उपलब्धता।
3. खिलाड़ियों के आने-जाने से संबंधित रेल, सड़क की उपलब्धता।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों हेतु अभ्यास करने के लिए खेल मैदानों, खेल उपकरणों आदि की उपलब्धता।

5. खेल अभ्यास के लिए प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए प्रतिभाएं।

6. अकादमी में आवासीत खिलाड़ियों को उनके स्तर के समक्ष शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता।

7- खेल पौशाक, किट आदि आवश्यक वस्तुओं की समुचित उपलब्धता।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पद

89. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार, पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं तथा उनमें से कितने छात्र अध्ययनरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 वर्षों में कितने निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बन्द हो गये तथा क्यों? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत 3 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तीर्ण कितने विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी और निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रशिक्षुओं की गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतरी के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं के रोजगार के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में विभिन्न संवर्गों के

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

नियमित स्वीकृत पदों में से कुल 3537 पद रिक्त हैं। प्रश्न में वांछित जिलेवार एवं पदवार रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट-1 से 4 में संलग्न है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में 1718 निजी आई.टी.आई. संस्थान संचालित हैं। जिनके अन्तर्गत 199271 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(3) विगत 5 वर्षों में राज्य में 63 निजी आई.टी.आई. संस्थान बंद हो गये। जिनमें स्वयं की प्रार्थना पर 11 तथा एन सी वी टी मापदंडों की पालना न करने के कारण 52 निजी आई.टी.आई. संस्थान बन्द हो गए। जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(4) विगत 3 वर्षों में आई.टी.आई. उत्तीर्ण 26432 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ, उनमें से सरकारी क्षेत्र में 3607 एवं निजी क्षेत्र में 22825 को रोजगार प्राप्त हुआ।

(5) राज्य में संचालित आई.टी.आई. में डीजीटी नई दिल्ली दवारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(6) जी नहीं। वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संनिर्माण कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

90. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याण योजनाओं में वर्तमान एवं विगत 4 वर्षों में लाभार्थियों की संख्या एवं देय लाभ की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कल्याण मंडल की योजनाओं में उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिले में वर्तमान एवं विगत 4 वर्षों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत किए गए एवं कितने आवेदन निरस्त किए गए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिले में श्रमिक कार्ड के वर्तमान एवं विगत 4 वर्षों में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने कार्ड बनाए गए एवं कितने आवेदन लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल द्वारा वर्तमान एवं विगत 4 वर्षों में लाभान्वितों एवं देय लाभ की राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में उदयपुर संभाग में वर्तमान एवं विगत 4 वर्षों में कुल प्राप्त, स्वीकृत एवं निरस्त आवेदनों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उदयपुर संभाग मे वर्तमान एवं विगत 4 वर्षों में कुल प्राप्त, स्वीकृत एवं निरस्त पंजीयन आवेदनों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)